





2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्वीकृत पाठ्य-पुस्तक

# भारतीय अर्थशास्त्र की रूप-रेखा

(ग्यारहवीं कक्षा के लिए)

लेखक

एस. सी. तैला

एम. ए., एल-एल. बी., आर. ई. एम.,

प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, श्री गंगानगर

तथा

ए. के. जैन

एम. ए., बी. कॉम., आर. ई. एम.,

परिचालक विभाग, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, गंगानगर



"भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा" पुस्तक विशेषकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नव-निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ग्यारहवीं कक्षा के लिए लिखी गई है। अल्प समय में ही पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशित हो जाना इसकी उपादेयता का प्रतीक है।

विषय को रुचिकर बनाने के लिए सरल भाषा और व्यावर्णक शैली का सहारा लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातों को प्रस्तुत किया गया है। विशिष्ट शब्द हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। पद्या स्थान तालिकाएँ, चित्र व मानचित्र भी दिए गए हैं। प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ में किसी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का उद्धरण तथा अन्त में अध्याय का सार और चुने हुए महत्वपूर्ण परीक्षा-प्रश्न दिए गये हैं जिससे विद्यार्थियों को विषय दोहराने में सुविधा हो।

इस पुस्तक में भारत सरकार द्वारा मान्य शब्दावली का प्रयोग किया गया है।

हम उन सभी लेखकों, विचारकों और विद्वानों के आभारी हैं जिनके विचारों व पाठ्य-सामग्री का समावेश इस पुस्तक में किया गया है। आशा है पाठकगण समय-समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव देकर हमें अनुश्रुत करें।

1 जून 1970

एस. सी. सेना

ए. के. जैन

# विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1. ब्रिटिश शासन काल में भारतीय अर्थ व्यवस्था	1- 2
2. भारतीय कृषि	22- 3
3. भारत में कृषि की जोड़ें	37- 5
4. कृषि के साधन I (बीज, खाद, उपकरण व पशु)	51- 6
5. कृषि के साधन II (सिंचाई)	62- 8
6. कृषि के साधन III (ग्रामीण दत्त)	85- 5
7. भारतीय कृषि की पद्धति	100-11
8. सामुदायिक विकास	112-17
9. भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन	126-14
10. कृषि विपणन	149-10
11. ग्रामीण ऋणों में सहायक व्यवसाय	161-17
12. भारतवर्ष में भूमि गुप्तार	172-1
13. कृषि-अधिक	183-1
14. भारतीय औद्योगिक विकास का सामान्य सर्वेक्षण	194-2
15. आधुनिक भारतीय उद्योग	211-2
16. भारतीय विदेशी व्यापार	243-2
17. भारत में बेरोजगारी की समस्या	263-2
18. भारत में आर्थिक नियोजन I	277-2
19. भारत में आर्थिक नियोजन II	296-4

## ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय अर्थ व्यवस्था

जिस समय साधुनिक औद्योगिक प्रणाली की जन्मभूमि पश्चिम यूरोप में भ्रमण्य जातिवा निवास करती थी, उन दिनों भारत अपने शासकों के घन वैभव तथा अपने शिल्पकारों के कौशल के लिए विश्वात था । इसके बहुत समय पश्चात् भी, जबकि पश्चिम से साहूती व्यापारी भारत में पहले पहल आये थे, इस देश का औद्योगिक विकास उन्नत यूरोपीय राष्ट्रों से किसी प्रकार घटिया न था ।

औद्योगिक आयोग, 1918

ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थ व्यवस्था अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थी । यहाँ के उद्योग धान्ये, कलाशिल्प व सम्पत्ता सस्कृति अत्यन्त प्राचीन समय से ही उन्नत थे । जब यूरोप के ये देश जो आज विश्व के सबसे अधिक विकसित देश कहे जाते हैं अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था में थे तब भारत आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था । भारतीय अर्थ व्यवस्था के गौरवशाली अतीत के सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक अंक शास्त्रीय इतिहास तो उपलब्ध नहीं है किन्तु समय समय पर यहाँ आये विदेशी यात्रियों के सस्मरणों, लेखों आदि से भारत की उन्नत अर्थ व्यवस्था की जानकारी मिलती है ।

भारतीय कारीगरों की उत्कृष्ट कला के प्रतीक अत्यन्त कलात्मक वस्त्रों का निर्माण, हीरे जवाहरात का काम, आदि विश्व भर में सुप्रसिद्ध थे । भारत डाका की भ्रमण्य विदेशों को निर्यात करता था । ईसा मसीह के 2000 वर्षों से पूर्व मिस्र की मर्म्मियाँ (Mummies) भारतीय मलमल में लिपटी हुई पायी गई । ऐसा विवरण मिलता है कि 17 वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय मलमल कम कीमत पर ही इंग्लैण्ड भेजी जाती थी । इससे यहाँ के ऊनी व रेशम के वस्त्र निर्माताओं को खतरा



उत्पन्न होने लगा । इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में अनेक कानून पारित हुए जिनके अनुसार भारतीय वस्तुओं के आयात का निषेध किया गया । इन सब निषेधों एवं कानूनों के बावजूद भी भारतवर्ष से प्रतिवर्ष भारी मात्रा में वस्त्र इंग्लैण्ड भेजा करता था ।

इसके अतिरिक्त भारत के अन्य प्राचीन गौरवशाली उद्योगों व इस्पात, पोत निर्माण, बरतनों पर कलात्मक काम, आदि भी विकसित हैं । भारत की कृषि एवं सिंचाई के साधनों की उन्नति अनेक उल्लेख मिलते हैं । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भारत अत्यन्त गौरवशाली था ।

किन्तु धीरे धीरे गौरव की यह परम्परा समाप्त हो गई । भारतीय अर्थ व्यवस्था अर्द्ध विकसित अर्थ व्यवस्था के रूप में पड़ोसी हो गई । इस आर्थिक विघटन के लिए अनेक कारण बताये जा सकते हैं । कुछ पारंपारिक विद्वान भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थिति के लिए उत्तरदायी मानते हैं । श्रीमती बेरा एन्स्टेन जनसंख्या को तथा श्री बेडनपावेल भारतीयों की निर्धनता आर्थिक विघटन के लिए उत्तरदायी मानते हैं । श्री नावेल्स (1907) के अनुसार इसका मुख्य कारण भारत का धार्मिक व सामाजिक अंधविश्वास है । किन्तु हमारे विचार में इस आर्थिक विघटन का मूल कारण भारत की शासन की घातक नीति ही थी ।

ब्रिटिश राज्य का भारतीय उद्योगों एवं अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव हुआ, इसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि पहले हम भारतीय अर्थ व्यवस्था की उन विशेषताओं का अध्ययन करें जो भारत के आगमन से पूर्व विद्यमान थीं ।

ब्रिटिश पूर्ण अधिपति में भारतीय अर्थ व्यवस्था की विशेषताएँ—

1. ग्राम व्यवस्था—अंग्रेजों के पूर्व भारत की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार स्वावलम्बी ग्रामीण इकाइयाँ थीं । 19 वीं

आरम्भ तक प्रत्येक ग्राम सामा-  
जिक एवं आर्थिक दृष्टि से आत्म  
निर्भर था। ग्रामवासियों को तीन  
वर्गों में बाँटा जा सकता है—

(अ) कृषक, (ब) कारीगर या  
दस्तकार एवं श्रमिक तथा (स)

ग्राम अधिकारी Village Officer  
ग्राम में शान्ति व्यवस्था के लिए  
ग्राम मुखिया या पटेल उत्तरदायी

होता था। पटेलारी एवं चौकीदार  
सुरक्षा सम्बन्धी कार्य करते

थे। गाँव की संभावित व्याप  
व्यवस्था के लिए कार्य

करती थी। दस्तकारों को  
गाँव की उपज में से प्रत्येक

कमल पर अनाज मिलता  
था और बस्ते में वे गाँव

वालों का काम करते थे।

प्राचीन ग्राम व्यवस्था  
की मुख्य विशेषता आत्म

निर्भरता (Self sufficient)  
थी। यातायात एवं संचार

वाहन के साधनों के अभाव  
में थम एवं पूँजी की गति-

शीलता (Mobility) का अभाव था। चूँकि ग्राम की आवश्यकताओं

विदित पूर्व भारतीय ग्राम-  
व्यवस्था की विशेषताएँ

1. स्वावलम्बी ग्राम इकाई
2. कृषि
3. उद्योग व हस्तशिल्प
4. नगर
5. व्यापार एवं यातायात व  
संचार वाहन
6. सामाजिक व्यवस्था

कमल: ग्राम के लगान वसूली तथा



भारतीय ग्राम

को ग्राम में ही पूरा कर लिया जाता था इसलिए वस्तु विनिमय प्रण

(Barter System) का प्रचलन था और प्रायः मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। परम्पराओं एवं रीति रिवाजों का प्रभाव, लगन, मनोबल एवं कीमतों के निर्धारण पर पर्याप्त रूप से पड़ता था। व्यवसायों पुनर्जीवनी की स्वतन्त्रता नहीं थी और पैतृकता के भाषार पर ही किये जाते थे।

संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि ग्रामों में जीवन व्यवस्था अत्यन्त सरल थी और प्रतियोगिता का प्रभाव था। परम्पराओं का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता था।

(2) कृषि (Agriculture)—सम्य देशों के अतीत की ही भाँती भारत में भी कृषि व्यवसाय की प्रधानता थी। कृषि वस्तुओं का साम



भारत में कृषि

आश्रय सीमित था। यातायात के साधनों के अभाव में कृषि का व्यापारीकरण नहीं हो पाया था। कृषकों की स्थिति देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न थी कृषि की पद्धति बहुत पिछड़ी हुई थी।

3. उद्योग व हस्तशिल्प (Industries and Handicrafts)—यद्यपि कृषि भारतीय जनता का मुख्य व्यवसाय था फिर भी यहाँ के उद्योग विषय विकसित थे। सूती वस्त्र उत्पादन में ढाके की मलमल तथा बनारस की सादियाँ, कश्मीर व पंजाब के ऊनी वस्त्र, लोह इत्यादि परंपरा की सुनिश्चिता, बर्तन बनाने का व्यवसाय, लकड़ी व धातु पर कारीगरी आदि भारत के कतिपय उद्देश्यमयी उद्योग रहे हैं। गाँवों के उद्योगों की तुलना में कस्बों एवं शहरों के उद्योग अधिक समृद्ध व्यवस्था

में थे । प्रत्येक नगर किसी न किसी व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था । इस प्रकार भारत का औद्योगिक अतीत अत्यन्त गौरवशाली रहा है । कहा भी जाता है—“The Glory that was India”

4. नगर (Town)—प्राचीन काल में भारतीय आर्थिक जीवन में नगरों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है । यद्यपि आंकड़ों के आधार पर यह कहना अत्यन्त कठिन है कि जनसंख्या का कितना भाग नगरों में रहता था किन्तु अनुमान लगाया जाता है कि नगरों में जनसंख्या का 10 प्रतिशत से अधिक भाग नहीं रहता था । नगरों का जीवन प्राचीन जीवन से भिन्न था । यहाँ के निवासी साधारणों के लिए पड़ोसी गाँवों पर निर्भर रहते थे । नगरों में उद्योग सुव्यवस्थित रूप से संगठित थे । बाजार विस्तृत थे और मुद्रा का पर्याप्त उपयोग होता था । सास पत्नों के रूप में हुण्डियों का प्रयोग किया जाता था । प्रो. गाडगिल (Prof. Gadgil) के अनुसार “ये (नगर) भारत के सामान्य जीवन में भिन्नता रखने वाले थे ।” नगरों की उत्पत्ति एवं समृद्धि मुख्य रूप से तीन कारणों पर आधारित मानी जाती थी—

- (अ) वे नगर धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, जैसे—बनारस, गया, पुरी, नासिक आदि ।
- (ब) नगरों के विकास का दूसरा कारण प्रारम्भ की राजधानी या व्यापार के केन्द्र के रूप में स्थापित होना था जैसे—दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, पूना, तंजौर, मुमबई, आका आदि ।
- (स) तीसरे, वे नगर जिनका विकास औद्योगिक या व्यापारिक नगरों के रूपों में हुआ, जैसे—मिर्जापुर, बंगलौर, आदि ।

इस प्रकार एक या दूसरे कारण से नगरों का विकास हुआ ।

5. व्यापार (Trade) यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों की स्थिति—संदेशों के पूर्व भारत में शर्मों की स्थावरगन्धी इकाई के रूप में उपस्थिति एवं यातायात व संदेश वाहन के साधनों में व्यापार की

मिस्रि धरती नदी की । सामाजिक व्यापार की जमी के कारण देश के  
मिस्र विभिन्न भागों में जीवनों में बहुत फाट पड़ा ।

वातावरण व भूमि बाह्य के कारण अत्यन्त गिरती वसा में थे ।  
यद्यपि समय समय पर शासकों ने नदियों के निर्माण में बलि दिलाई  
किन्तु कारण जैसे विनाश देश के लिए थे प्रत्यक्ष नदयों थे ।

6. सामाजिक व्यवस्था—अंद्रेजों के पूर्व भारत की सामाजिक  
व्यवस्था में परम्परा एवं रिवाज का वातावरण व्याप्त था । बर्ष एवं  
रोनि रिवाजों ने हमिन समाज में परिवर्तनों को पुनरागत बहुत कम  
थी । इसका प्रभाव दूरि एवं उद्योगों की वृद्धि पर पड़ा था और  
परम्परागत वृद्धि ही प्रचलित रहती थी ।

संयुक्त परिवार प्रथा एवं जाति प्रथा का प्रचलन था । इनका  
इतिहास जो भी रहा हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस व्यवस्था ने  
बाकी हर एक आर्थिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है ।  
अन्त ही समाज में समता स्थाप, ऊँचा या नीचा, निर्धारित  
करता था । रिवाजों की दशा भी बलिक अच्छी नहीं थी । कुल विस्तार-  
कर अंद्रेजों के पूर्व भारत का सामाजिक जीवन परम्पराओं से बन्ध था  
एवं आर्थिक विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करने में  
असमर्थ था ।

**ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारत में आगमन**

**एवं ब्रिटिश शासन की स्थापना**

पुर्तगालियों द्वारा पूर्वी देशों के स्थित जाने वाले व्यापार की वस्तुओं  
को देखकर अंद्रेज भी आकर्षित हुए । सन् 1600 ई० में ब्रिटेन की  
महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की  
स्वीकृति दी । इस कम्पनी का मूलधन 70,000 पौण्ड था । बैसे यूरोप  
में भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से अनेक  
ईस्ट इण्डिया कम्पनियों की स्थापना हुई । पर इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा

हालेण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनियों को छोड़कर बेष समी असफल हो गई । यहाँ हमारा तात्पर्य इंग्लैण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ॥ ही है ।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सन् 1606 में मुगल-सम्राट जहांगीर से भारत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की । इस कारखाने की स्थापना सन् 1612 में सूरत में हुई । सन् 1639 में कम्पनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जार्ज का निर्माण किया । बम्बई का द्वीप किंग चार्ल्स द्वितीय से खरीदकर सन् 1687 में कम्पनी ने अपने कारखाने वहाँ लगाए । कम्पनी ने सन् 1700 में बंगाल में अपना मुख्य स्थान कलकत्ता में स्थापित किया । कांसिरी पांडीचेरी एवं कलकत्ता के उत्तर में बम्बई नगर पर अपना अधिकार किये हुए थे ।

सन् 1744 से 1763 तक फ्रांस व इंग्लैंड के मध्य यूरोप, एशिया एवं अमेरिका का युद्ध होता रहा । भारत वर्ष में भी अंग्रेज एवं फ्रांसिसी कम्पनियों के बीच कर्नाटक युद्ध चलते रहे । कर्नाटक युद्ध के अन्तिम दौर में फ्रांसिंसियों की हता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई । इस प्रकार सन् 1763 के पश्चात् भारत में अंग्रेजों के कोई भी यूरोपियन प्रति-द्वन्दी नहीं रहे ।

इसर बंगाल में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई । सन् 1756 में नवाब सिराजुद्दीन ने अंग्रेजों से कलकत्ता ले लिया । यूरोप से लौटने पर लार्ड क्लाइव (Lord Clive) ने सन् 1757 में प्रकट रूप में नवाब से संधि की और शुभ रूप से उनके (नवाब के) विरुद्ध पद्धत्य में रत हो गये । नवाब सन् 1757 में प्लासी के युद्ध में पराजित हुए और सन् 1760 में यूरोप जाने से पूर्व लार्ड क्लाइव ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भारत के विनाश लेनीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । इसके पश्चात् भी कम्पनी व नवाबों के बीच संघर्ष चलता रहा । लार्ड क्लाइव भारत में फिर तीसरी और अन्तिम बार सन् 1765 में आये और उन्होंने एक नवीन एवं अविस्मरणीय नीति का प्रतिपादन किया ।

सन् 1765 में भारत के बादशाह की स्थिति बड़ी दवादाहोल हो रही थी फिर भी उन्हें देश का शासक माना जाता था । क्लाइव

जिन्होंने सन् 1757 में बंगाल को शक्ति से प्राप्त किया था, 1765 में भारत के सम्राट से बंगाल प्रान्त के दीवानी अधिकार सम्बन्धी अनुज्ञापत्र प्राप्त कर लिया । इस प्रकार ईस्ट इन्डिया कम्पनी को बंगाल पर शासन करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया ।

सन् 1769 में ब्रिटिश अधिकारियों ने मद्रास में अधिकार स्थापित किया । सन् 1773 में ब्रिटिश संसद ने भारत में स्थिति सुधारने की दृष्टि से एक रेग्युलेशन एक्ट पारित किया । इस एक्ट के अनुसार कम्पनी के सभी अधिकृत क्षेत्रों की देख रेख का प्रशासनिक अधिकार मिल गया और उनकी समुचित व्यवस्था हेतु गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई । लार्ड कारन हेस्टिंग्स जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे, सन् 1774 में प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किये गये । लार्ड हेस्टिंग्स सुधार चाहते हुए भी अनेक कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं कर सके । कम्पनी के प्रशासन को इंग्लैण्ड की राज सत्ता के अन्तर्गत लाने के लिए पिट का इण्डिया एक्ट सन् 1784 में पास हुआ । सन् 1785 में वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए । उनके जाने के समय तक कम्पनी बंगाल, मद्रास, बनारस आदि क्षेत्रों पर सत्ता स्थापित कर चुकी थी ।

सन् 1784 के पिट्स एक्ट के अन्तर्गत कम्पनी के सभी नागरिक, सैनिक एवं राजस्व कार्यों की देख रेख ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त कमिश्नरों के करिये होने लगी । सन् 1793 में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी जमींदारी बन्दोबस्त का प्रबन्ध किया । 1793 में कम्पनी का अनुज्ञापत्र फिर से जारी किया गया । किन्तु इसमें व्यापार पर से कम्पनी के एकाधिकार की समाप्ति हो गई । 1805 तक बंगाल के अनिच्छित बनारस आदि क्षेत्रों पर भी यह कानून लागू कर दिये गये । मैसूर एवं मराठा राज्यों को हरा कर ये क्षेत्र भी कम्पनी ने अपने अधिकार में कर लिए ।

कम्पनी के आर्थिक व प्रशासनिक अधिकारों पर धीरे-धीरे ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया । सन् 1857 में

गदर (स्वतन्त्रता संग्राम) (Mutiny or war of Independence) के कारण कम्पनी का अन्त हुआ । कम्पनी के विपक्षियों से भारतीय राजा अपने अधिकार के प्रति सशक्त हो गए । उनके विद्रोह को समाप्त करते समय ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी को समाप्त करना भी उचित समझा ।

गदर के तुरन्त बाद इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधान मंत्री लॉर्ड पामस्टोन ने कम्पनी के अस्तित्व को ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय की सूचना दी कि भारत सरकार के कार्यों की देखरेख नीचे ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत होगी । अगस्त 1858 में भारत में उत्तम शासन हेतु अधिनियम पारित किया गया । इस प्रकार सन् 1858 में कम्पनी के स्थान पर सीधा शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया ।

सन् 1600 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में विस्तृत व्यापारिक हट्टिकोन लेकर आई किन्तु धीरे-धीरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था को भी अपने हाथों में लेती गई । कम्पनी की इन गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार धीरे-धीरे नियंत्रण स्थापित करती गई । सन् 1857 के गदर के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम पारित करके कम्पनी का कार्य समाप्त कर शासन अपने देखरेख में ले लिया । इस अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के अधिकार एवं कर्तव्य भारत सचिव को सौंप दिये गये । इस अधिनियम ने 75 धाराएं भी जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश शासन की समाप्ति तक चली रहीं ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत 15 सदस्यों की एक परिषद् की सहायता से भारत सचिव द्वारा ईस्ट इण्डिया के प्रदन्धित सभी क्षेत्रों का शासन चलाने की व्यवस्था थी । परिषद् के सदस्यों एवं भारत सचिव से संबंधित सभी व्यव भारत के राजस्व में से चुकाए जाते थे । भारत के गवर्नर जनरल तथा महाराज और बम्बई के गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार इंग्लैंड की रानी को था । इस अधिनियम में भारत के द्वि-विरोधी अनेक बातें भी जिनकी जानकारी सामान्य जनता को नहीं थी ।



भारत में ब्रिटिश शासन (British Rule in India) — भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा । भारत जैसे विनाश देण पर अंग्रेजों का अधिकार ब्रिटिश सामरिक सामुद्रिक के लिए अत्यन्त लाभकारी सिद्ध हुआ । ब्रिटेन के अधिकार में सबसे बड़ा उपनिवेश या जिसका क्षेत्रफल इंग्लैंड से बीस गुना व यूरोप के सभी बड़े देश भारत की ओर भाँस लगाए रहे और जिस द्वारा भारत विजय ही यूरोप में पुँजीवाद के विनाश में महत्वपूर्ण व सिद्ध हुई । भारत उपनिवेश ने ही ब्रिटेन को विश्व की सर्वोच्च सत्ता में मदद की । स्वयं माई बर्जन् ने 1898 में यह स्वीकार कि यदि हम भारत को छोड़ दें तो हमारे शासन का भूयं अस्त हो जाएगा इस प्रकार भारत पर ब्रिटिश शासन बेट ब्रिटेन के हितों के प्रया एवं प्रवर्द्धन में सहायक हुआ ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव — दो शताब्दियों तक तकनीकी एवं औद्योगिक दृष्टि से उन्नत बेट ब्रिटेन शासन भारत वर्ष पर कायम रहा उसका अधिक प्रभाव क्या रहा इसका एक मात्र उत्तर है — भारत की सामरिक स्थिति में गिरा आई । अंग्रेज विद्वान बेरा एन्गस्टे ने यह स्पष्ट रूप से कहा है । जन-जीवन की समृद्धि पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव निस्संदेह अत्यन्त निराशाजनक रहा । इसी प्रकार से अमेरिकन विद्वान् प्रोफेसर एच. बुचनान ने कहा भारतीय औद्योगीकरण पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव अत्यन्त निराशाजनक रहा ।

इस प्रकार यह एक सर्व विदित तथ्य है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । भारत का सम्पूर्ण गौरव ब्रिटिश शासन काल में कम होता गया । यहाँ विभिन्न सामरिक क्षेत्रों पर पड़े प्रभावों का स्वीकार अध्ययन करेंगे —

(1) सम्पन्नता के मध्य गरीबी का प्रादुर्भाव — भारत एक गरीब देश है किन्तु अब उसमें निर्धन लोग निवास कर

है। यह विरोधामास ब्रिटिश शासन की ही देन है। कम्पनी के

आगमन से पहले भारत के औद्योगिक विकास का स्तर बहुत ऊँचा था। यहाँ प्राकृतिक साधनों की भी कमी नहीं थी किन्तु ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय जनता का जीवन स्तर नीचा हो गया। 17 वीं सदी में जहाँ भारतीय गाँवों में चावल, छाटा, मक्खन, दूध, फल, चीनी, मिठाईयाँ आदि प्रचुर मात्रा में प्रयोग किये जाते थे वहीं ब्रिटिश शासन की सवधि से द्वितीय महा-युद्ध के समय भारत की 60 प्रतिशत जनसंख्या की आय रुक आना

ब्रिटिश शासन का प्रभाव

1. सम्पन्नता के मध्य गरीबी का प्रादुर्भाव

2. भारत से धन का प्रवाह

3. भारत पर शून

4. निम्न पदार्थों के निर्यात में कमी

5. आयात में वृद्धि

6. भारतीय उद्योगों का विनाश

7. जमींदारी प्रथा का उदय

8. आर्थिकमोक्ष व मत्स्याचार

9. कुपि पर जनभार में वृद्धि

10. अल्प प्रभाव

प्रति व्यक्ति प्रतिदिन थी। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के सभी साधनों के विनाश हो गये थे वहीं अंग्रेजों की स्वार्थपरता के कारण भारतवासी निर्धन हो गए।

2. भारत से धन का प्रवाह—ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में व्यापार की दृष्टि से आकर्षित हुई। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कुटिल अंग्रेजों ने देश के अनेक भागों का शासन टेवरनियर के राजा संस्मरणों पर आधारित प्रवन्ध की अपने हाथों में ले लिया। शासन हथियाने के बाद कम्पनी नाम मात्र की कीमत पर वस्तुएँ खरीद कर भारत से बाहर भेजती थी। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय पदार्थों की बहुत कम कीमत देकर भारतीय किसानों छोटे व्यापारियों को चूटा और उस धन को भारत के बाहर ले गए।

पर ध्रुण

इण्डिया कम्पनी के भारत में स्थापित होने से पूर्व भारत पर कोई ध्रुण नहीं था किन्तु सामन व्यवस्था एवं कम्पनी के भारत पर ध्रुण होता गया और भारत को लगभग 7 करोड़ राशि केवल कम्पनी के कारण चुकानी पड़ी। इस प्रकार इण्डिया कम्पनी ने भारत का आर्थिक शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

निर्मित पदार्थों के निर्यात में कमी—

1760 के परवाना इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। इस क्रान्ति के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड को ऐसे बाजारों की आवश्यकता पड़ी जो वहाँ के बने हुए माल को खपवा सकें। अंग्रेजों ने भारत को इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया। अहाँ भारतवर्ष निर्मित माल का भारी मात्रा में निर्यात करता था। वहाँ ब्रिटिश शासन में निर्मित पदार्थों का आयातकर्ता देश बन गया। ब्रिटेन के नए उद्योग-धंधों ने भारत के शोषण की अधिक व्यवस्थित योजना बनाकर भारत के निर्मित पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा दिया। अहाँ भारत कमी के सूती वस्त्र, हाथीदाँत व लकड़ी की उत्कृष्ट वस्तुएँ, आदि निर्यात करता था ब्रिटिश सामन बाल में बच्चा माल, जैसे सारंग, घुट, बपास आदि वस्तुओं को निर्यात करने वाला देश बन गया। भारत से बच्चा माल मंगाकर अपने देश में औद्योगीकरण को देने की ब्रिटिश कुदिल नीति ने हमारे उद्योगों को गहरा आघात पहुँचाया।

शासन में वृद्धि—

औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड ने भारत की अपने बाजार के रूप में प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से भारतीय उद्योगों के निर्मित वस्तुओं पर अनेक प्रतिबन्ध लगाए। इससे अंग्रेजों ने अपने देश के भारत में वेचने के लिए अनेक बन्दन उठाए। इस प्रकार भारत को एक प्रमुख निर्यातकर्ता देश या ब्रिटिश नीति के कारण एक गुरु देश बन गया।

## (6) उद्योगों का विनाश—

औद्योगिक क्रान्ति के सूत्रपात के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत के आर्थिक शोषण की एक सुव्यवस्थित योजना बना कर भारत को अपना बाजार बना दिया। 19 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में भारतीय उद्योगों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया। इस नीति के अनुसार इंग्लैंड के पदार्थों को भारत में बिना किसी रोक टोक के आ सकते थे किन्तु भारतीय वस्तुएं इंग्लैंड नहीं जा सकती थीं। इस प्रकार भारत एवं अन्य देशों के बीच भी नौ-बहन कानून के अन्तर्गत व्यापार का निषेध कर दिया गया। इस प्रकार ब्रिटिश टैरिफ नीति भारतीय उद्योगों के लिए घातक एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए हितकारी सिद्ध हुई। उद्योगों के पतन के कारण ढाका, मुजिदाबाद आदि औद्योगिक नगरों का भी पतन हुआ और कारीगरों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। ब्रिटिश नीति के कारण भारतीय उद्योगों के पतन का अध्ययन इसी अध्याय में आगे लिया जाएगा।

## (7) जमींदारी प्रथा का उदय—

ईस्ट इंडिया कंपनी ने सगान बमूनी की एक नवीन पद्धति को जन्म दिया। सन् 1793 में लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल में प्रयोग के तौर पर स्थायी भूमि बन्दोबस्त की प्रथा लागू की। कार्नवालिस ने इस व्यवस्था के अन्तर्गत जमींदारों की कानूनी तौर पर भूमि का स्वामी मान लिया। किसानों पर यह जमींदार वर्ग शासन करने लगा और अनुवस्थित भूस्वामी (Absentee landlord) के रूप में प्रकट हुआ। जैसा हम आगे चलकर पढ़ेंगे। यह वर्ग (जमींदार) किसानों का शोषण करने लगा और भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करने वाला बना। अंग्रेजों की यह पद्धति भी भारत के लिए लगभग बीन्ने दो सौ वर्षों तक सिर दर्द बनी रही।

8. आर्थिक शोषण (Economic exploitation) व अत्याचार—  
जब सन् 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व प्रशासन का अधिकार

शोषण का नवीन द्वार खुल गया। इस मृष्वी पर ईस्ट इंडिया  
शासन (सन् 1765 से 1784 तक) के समान कोई भी घटु  
अथ तक नहीं देखी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के  
अन्तरत्न सगान वृद्धि, गिच्चाई के साधनों तथा सार्वजनिक निर्माण  
उपेक्षा, आदि कारणों से जनता परेशान हो गई। सन् 1770  
के भयंकर प्रकास में लाखों मृत के शिकार हुए। ऐसे समय  
कंपनी ने सगान समूची में हृदयहीनता दिखाई। बीस वर्ष के  
शासन में अन्न, धन और रसम का गन्धार भारत में प्रायः  
कर रह गया। ब्रिटिश शासन काल की सभी नीतियाँ भारत  
के शोषण की रहीं। अंग्रेजों ने भारतीय हितों की सदैव उपेक्षा  
ब्रिटिश सरकार ने अनेक अवसरों पर भारतीय जनता का दमन  
और अत्याचार किये। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास इन  
से भरा पड़ा है।

9. कृषि पर जन भार में वृद्धि—ब्रिटिश सरकार की नीति के  
भारतीय उद्योग धन्धों का ह्रास हुआ। परिणामस्वरूप इनमें  
शरीरगत व अर्थिक बेकार हो गये। करोड़ों कलाकार, दस्तकार,  
कुम्हार, लोहार आदि सहरो एवं गाँवों में रोजगार के साधनों  
भाव में बड़ी दयनीय स्थिति में थे। इन सबका भार कृषि पर पड़ा  
पहले से ही अधिक जन भार वाली कृषि पर इनका और बोझ था।  
भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर एक घोर दूरवासी प्रभाव  
भारत में जो पहले कृषि व उद्योग धन्धों वाली अर्थ व्यवस्था थी  
ब्रिटिश औद्योगिक पूँजीवाद का एक कृषि उपनिवेश मान बनकर  
गयी।

10. अन्य प्रभाव—ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणाम भारत के  
प्रतिकूल ही रहे। यद्यपि महायुद्धों की अवधि में भारत में उद्योग  
की स्थापना कुछ सरकारी प्रयत्न हुए किन्तु भारत की  
स्वतंत्रता प्राप्ति तक कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। अंग्रेजों के  
काल में भारत के नील, चाय, कच्चा व रबर के बागानों पर

विदेशियों का अधिकार स्थापित हो गया। इन उद्योगों में भी भारतीय श्रमिकों का बहुत शोषण किया गया। ब्रिटिश शासन का एक मुख्य परिणाम ब्राह्मण शासकों के अनुसार सामाजिक क्रांति (Social Revolution) के रूप में हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में देश का एकीकरण होकर एक मूल में शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। ब्रिटिश शासन के अन्तिम 50 वर्षों में रेलों, सड़कों और सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ जिससे भारत में आर्थिक संक्रांति (Economic transition) का मूलपाठ हुआ।

तर्जुम में हम यह सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन भारतीय अर्थ-व्यवस्था को प्रायः नष्ट करने में सफल हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत के आर्थिक विकास के लिए कोई रचनात्मक कदम नहीं उठाया। यही कारण है भारतीय अर्थ व्यवस्था अब भी घटते विकसित अवस्था में है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है।

भारत में आर्थिक संक्रांति (Economic transition in India) —

भारत में ब्रिटिश शासन काल में 18 वीं तथा 19 वीं शताब्दी में जो आर्थिक परिवर्तन हुए उन्हें हम आर्थिक संक्रांति के नाम में पुकारते हैं। इस अवधि में गाँवों एवं नगरों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ईंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति, शासन की नीतियों एवं अन्य बातों का आर्थिक जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

आर्थिक संक्रांति की पृष्ठभूमि तथा कारण (Back ground & causes)

इसी अध्याय के प्रारम्भ में हम अर्थ व्यवस्था को उन विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं जो आर्थिक संक्रांति में पूर्व (ब्रिटिश शासन से पूर्व) भारत में विद्यमान थी। इन विशेषताओं से संक्रांति की पूर्ण चोटी का आनकारी मिल जाती है।

आर्थिक संक्रांति के मुख्य कारण निम्नांकित थे—

(1) ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य तथा ब्रिटिश शासन की स्थापना—

आर्थिक संक्रान्ति के मुख्य कारण —

1. ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य व ब्रिटिश शासन की स्थापना
2. इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति
3. उद्योगों व व्यापार में वृद्धि
4. परिवहन के साधनों का विकास
5. पश्चिमी विचारधारा का आगमन

औरंगजेब के समय से मुगल शासन का पतन प्रारम्भ हो गया। अंग्रेजों ने भारत में अपने हितों की रक्षा की। परिणामस्वरूप भारतीय आर्थिक व्यवस्था में गिरावट आती गई। इस प्रकार ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारत की आर्थिक संक्रान्ति पर पराधीनता में हुआ।

(2) इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) — अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में महत्वपूर्ण औद्योगिक परिवर्तन हुए। ब्रिटिश उद्योगों में मशीनों एवं आविष्कारों का प्रयोग किया गया। इस औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप इंग्लैंड में बनने वाले पदार्थों की बिक्री के लिए विस्तृत बाजारों की आवश्यकता हुई। भारत भी औद्योगिक क्रांति के प्रभावों से प्रभुता नहीं रह गया और आर्थिक संक्रान्ति हुई।



3. उद्योगों व व्यापार की दिशाओं में परिवर्तन—भारत में चाय, रबर, नील व कढ़वा बागान, जूट आदि नये उद्योगों का विकास तथा इंग्लैंड से बढ़ते हुए व्यापारिक सम्बन्धों ने भारतीय अर्थ व्यवस्था का नई दिशा दी। इनका प्रभाव आर्थिक संक्रान्ति पर हुआ।

4. परिवहन का विकास—ब्रिटिश शासकों ने राजनीतिक दृष्टि से साक्षात्कार के साधनों का विकास किया। ब्रिटिश अहाजी देशों ने भारतीय समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण योग दिया। इन साधनों ने भारतीय अर्थ व्यवस्था में परिवर्तनों को बढ़ावा दिया।

5. पश्चात्त्य (Western) विचारधारा—भारत में आर्थिक क्रान्ति लाने का मुख्य श्रेय ब्रिटिश शासकों को है जिन्होंने पश्चिमी देशों की सम्मति, रहन-सहन एवं सामाजिक व्यवस्था से भारत का परिचय करवाया। आज भी भारतीय जीवन पर पश्चात्त्य विचारधारा का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है।

संक्षेप में, ब्रिटिश शासन व्यवस्था और उनकी आर्थिक नीतियों ने ही भारत में आर्थिक संक्रान्ति का सूत्रपात किया।

**आर्थिक संक्रान्ति के परिणाम**

आर्थिक संक्रान्ति से भारत के आर्थिक जीवन पर अनेक प्रभाव पड़े। यहाँ हम उन प्रभावों (Effects) का अध्ययन करेंगे।

1. आर्थिक संक्रान्ति द्वारा गाँवों तथा कृषि के क्षेत्रों में परिवर्तन—प्राचीन भारतीय समयों की मूल इकाई ग्राम व्यवस्था में परिवर्तन होने लगी। गाँवों के पृथक्गीकरण एवं स्वावलम्बन की स्थिति समाप्त होने लगी। प्राचीन जीवन में मदीन वस्तुओं की आवश्यकताओं का समावेश होने लगा।

**आर्थिक संक्रान्ति के प्रभाव**

1. गाँवों व कृषि पर
2. उद्योगों पर
3. दुमियों पर
4. बेकिंग पर
5. शहरीकरण
6. नये वर्ग सम्बन्ध
7. अन्य



गाँवों में बाहर से बस्तुएँ आने लगी और गाँव दूगरे स्थानों को पदार्थ भेजने लगे ।

आर्थिक संक्रान्ति के परिणामस्वरूप कृषि की संरचना के निम्न और विस्तृत बाजार जुड़ गये । बाजारों के विस्तार के साथ धानुओं के मूल्य में समानता आने लगी । गाँवों में घीरे-घीरे विनिमय के स्थान पर मुद्रा का प्रचलन होना लगा । गाँवों में संयुक्त परिवार प्रथा के स्थान पर व्यक्तिवादी भावना का विस्तार हुआ ।

कृषि के क्षेत्र में आर्थिक संक्रान्ति के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में घटन हुए । परम्परागत कृषि के स्थान पर कृषि का व्यापारी (Commercialisation) हुआ । परिणतन व मजदूर के भावना विकास, स्वयं नहर के मुक्त जाने से तथा विदेशों में हमारे कृषि की माँग ने कृषि को व्यापारिक ढंग से प्रतिष्ठित करने में सहायता दी ।

हमारे उद्योग धर्मों के नष्ट हो जाने के कारण कृषि पर जनता का भार बढ़ गया । कृषि पदार्थों के मुख्य ब्रम होने और उद्योगों समाप्ति के कारण उत्पन्न बेरोजगारी ने कृषकों पर बहुत भार में कर दी ।

इस प्रकार आर्थिक संक्रान्ति के गाँवों में स्वावलम्बी स्थिति समाप्त कर कृषि पर जन-भार में वृद्धि कर दी ।

2. आर्थिक संक्रान्ति द्वारा उद्योगों पर प्रभाव—इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति, भारत में ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति भारत के विदेशी व्यापार एवं नी-बहुन पर घातक प्रतिबन्ध लगाते भारतीय उद्योग धर्मों का पतन हुआ । भारतीय औद्योगिक को इंग्लैण्ड में बने पदार्थों की भारी स्पर्धा का सामना करना पड़ा । विदेशी सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप हमारे देश में विदेशी पूँजी ( Foreign Capital ) तथा साहस का प्रागमन हुआ । चाय, नील, कच्चा व रबर के बाजारों आदि व्यवसायों में इन्होंने अग्रिम व अन्य देशों के उद्योगपतियों ने अपना अधिकार समाप्त

लिया। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति के स्वरूप भारी मशीनों का आविष्कार हुआ। भारत में भी भारी मशीनों एवं नवीन तकनीक के आगार पर कुछ नये उद्योगों की स्थापना हुई। समुद्र के पास स्थित होने से मद्रास, कलकत्ता एवं बम्बई बड़े व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र बन गये। बड़े नगरों में औद्योगीकरण के कारण अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न हो गईं।

इस प्रकार औद्योगिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और हमारे शरीरों को मजदूर होकर कृषि पर आश्रित होना पड़ा।

3. आर्थिक संज्ञाति का दुर्भिक्षों (Famines) पर प्रभाव— गाँवों के पृथक्कीकरण के कारण वहाँ पहुँचे मकालों को दूर करने में प्रयत्न नहीं किये जा सकते थे वहाँ यातायात के साधनों के विकास एवं कृषि के व्यापारीकरण के पश्चात् मकालों की अमान्यता भी दूर कर पाना सम्भव हो गया। आर्थिक संज्ञाति के बाद लोगों के पास रहने से अधिक क्रय शक्ति (Purchasing power) भी और विस्तृत बाजार से वहाँ से यातायात के तीव्र साधनों द्वारा ग्रस्त क्षेत्रों को साक्षात् पहुँचाये जा सकते थे।

4. रोज़गार पर प्रभाव—विदेशी व्यापार एवं पूँजी के कारण देश में रोज़गार व अन्य सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ। बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास होने के कारण अधिकाधिक रोज़गार व्यवस्था का विकास हुआ।

5. जब शहरों में बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई तो गाँवों से वे बेकार शरीरगर् शहरों की ओर आने लगे। इस प्रकार शहरों और गाँवों से रहने वालों के मध्य एक नये प्रकार के सम्बन्धों का उदय हुआ।

6. नये नये सम्बन्धों का उदय—आर्थिक संज्ञाति के परिणामस्वरूप परम्परागत सम्बन्धों के स्थान पर नये नये का उदय हुआ। कुपण, उद्योगपति, अधिक व प्रशासकों के नये नये का उदय हुआ और इनके सम्बन्धों से नया मोड़ आया।

7. अन्य प्रभाव—इन सबके अलावा आर्थिक संक्रान्ति ने हमारे सदियों से चली आ रही परिवर्तनशील सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। प्रतिष्ठा और रीति-रिवाज के स्थान पर सामेदारी एवं प्रतिस्पर्धा के सिद्धान्तों के आधार पर समाज व अर्थ व्यवस्था की रचना प्रारम्भ हुई।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि आर्थिक संक्रान्ति से कुछ अच्छे एवं अधिकतर बुरे प्रभाव हमारी अर्थ व्यवस्था पर पड़े। भारत जहाँ कुपि एक उदासीन वाला देश था वह ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत आर्थिक संक्रान्ति के कारण केवल कुपि प्रधान देश बन कर रह गया।

### सारांश

प्राचीन भारत अत्यन्त गौरवशाली था, किन्तु धीरे-धीरे उसकी यह गौरव की परम्परा समाप्त हो गई। इस विघटन का मूल कारण ब्रिटिश शासन की घातक नीति थी।

ब्रिटिश पूर्ण अर्थ में भारतीय अर्थ व्यवस्था की विशेषताएँ

(1) स्वावलम्बी ग्राम इकाईयाँ (2) कृषि (3) उद्योग व हस्त-शिल्प (4) नगर (5) व्यापार, यातायात एवं सदेश काहन तथा (6) सामाजिक व्यवस्था।

ब्रिटिश शासन की रणनीति

1600 ई० ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की स्वीकृति दी। सन् 1700 में बंगाल में अपना मुख्य स्थान उभरने शुरुकर्ता में स्थापित किया। 1773 में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेशन एक्ट पास किया। सन् 1784 में पिट का इण्डिया ऐक्ट पास किया।

सन् 1857 के सद्र के कारण इस कम्पनी का अन्त हुआ तथा ब्रिटिश सरकार ने शासन अपने हाथ में ले लिया। भारत में लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा।

### ब्रिटिश शासन का प्रभाव—

(1) सम्पन्नता के मध्य परीबी का प्रादुर्भाव (2) भारत से धन का प्रवाह (3) भारत पर ऋण (4) निर्मित पदार्थों के निर्यात में कमी (5) आयात में वृद्धि (6) भारतीय उद्योगों का विनाश (7) जमींदारी प्रथा का उदय (8) आर्थिक शोषण व भ्रष्टाचार (9) कृषि पर जनश्रम में वृद्धि तथा (10) अन्य प्रभाव

### आर्थिक संक्रान्ति के कारण

(1) ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आगमन व ब्रिटिश शासन की स्थापना (2) इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति (3) उद्योगों व व्यापार में वृद्धि (4) परिवहन के साधनों का विकास तथा (5) पारचात्य विचारधारा ।

### आर्थिक संक्रान्ति के प्रभाव—

(1) गाँवों व कृषि पर (2) उद्योगों पर (3) दुर्मितों पर (4) बेरोजगारी पर (5) सहोदयकरण (6) नये नये सम्बन्ध व (7) अन्य ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता आवश्यक है ।

### प्रश्न

1. ब्रिटिश पूर्व भारतीय अर्थ व्यवस्था की कौन-कौन सी विशेषताएँ थीं?
2. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बारे में आप क्या जानते हैं ? भारतीय अर्थ व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा ?
3. आर्थिक संक्रान्ति किसे कहते हैं ? इसके क्या कारण थे ? इसका क्या प्रभाव हुआ ?
4. आर्थिक संक्रान्ति पर एक निबन्ध लिखिये ।

## अध्याय 2

### भारतीय कृषि

#### (INDIAN AGRICULTURE)

“जब खेती फलती-फूलती है, तब सब घन्वे पनपते हैं, परन्तु जब भूमि को बन्जर छोड़ दिया जाता है, तो घन्वे भी नष्ट हो जाते हैं।”

—मुकुरात

“भारत में दलित जातियाँ ॥ और उन्हीं के समान हमारे दलित उद्योग भी हैं, दुर्भाग्य से कृषि भी उन्हीं में से एक है।”

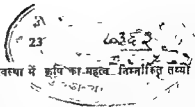
—डॉ. बलाउसद्न

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के निवासियों का सदियों से कृषि ही मुख्य व्यवसाय रहा है। कहा गया ॥ कि कृषि हमारी संस्कृति का आधार है (Agriculture is the basis of our culture)। यह विश्व का प्राचीनतम व्यवसाय है। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका, जर्मनी आदि देश विज्ञान एवम् उद्योगों के क्षेत्र में बहुत विकसित हो गए जबकि कुछ देश कृषि प्रधान ही बने रहे। भारत में कृषि व्यवसाय का ही प्रभुत्व है। कृषि हमारी जीवन प्रणाली (way of life) है। कृषि विकास के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक कार्यक्रम अपनाये गए। यह सर्वमान्य तथ्य ॥ कि कृषि की उन्नति के बिना भारतीय अर्थ व्यवस्था की उन्नति असम्भव है।

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्त्व

#### (Importance of Agriculture in Indian Economy)

भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कहावत है कि “उत्तम भेडी, मध्यम बान, निम्नट चाकरी, भीत निदान।” इस कहावत से भारतीय जीवन में कृषि की उपयोगिता प्रतिभक्षित



होती है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्व निम्नीकृत तथ्यों से स्पष्ट हो जायेगा।

1. जीविकोपार्जन (Livelihood) का मुख्य साधन—सन् 1961 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की 69-8 प्रतिशत जनसंख्या मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। कृषि भारतवासियों का मुख्य व्यवसाय है और इसीलिए भारत को “कृषि प्रधान देश” कहा जाता है।

2. राष्ट्रीय आय (National Income) में महत्वपूर्ण योग—देश की वार्षिक कुल आय का लगभग आधा भाग कृषि से प्राप्त होता है। सन् 1967-68 में कृषि से 14,973 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जो कुल राष्ट्रीय आय का 53.1 प्रतिशत है। \* राष्ट्रीय आय में कृषि का योग सन् 1950-51 में 51.3 प्रतिशत, सन् 1955-56 ■ 45.3 प्रतिशत, सन् 1960-61 में 48.7 तथा सन् 1966-67 में 49.2 प्रतिशत रहा। विश्व में ऐसा कोई अन्य राष्ट्र नहीं है, जिसमें कृषि ने इतने बड़े प्रतिशत एक देश की आय को प्रभावित किया हो।

3. सरकार की आय—राज्य सरकारों की भूमि के लगान (Land Revenue), कृषि आयकर (Agricultural Income Tax) स्टाम्प तथा पंजीयन (Stamp and Registration) शुल्क के रूप में बहुत-सी आमदनी कृषि से प्राप्त होती है। रेलों को भी कृषि पदार्थों के ढोने से आय प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारे देश की सरकारों का अग्रेष्ठ कृषि पर निर्भर है।

4. बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य—कृषि के द्वारा ही भारत के करोड़ों लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध होती है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि हमें आवश्यक भोजन सामग्री प्रदान करने में असमर्थ रही है। यदि हम चाहते हैं कि विदेशों से खाद्यान्न न मंगाने पड़े तो हमें कृषि की उन्नति करनी होगी। सन् 1967-68 में 14.14 करोड़

हेक्टर भूमि पर सादाग्न होए दये दिन पर 955 लाख टन माद्यान्न पैदा हुए ।\*

5. असन्तुलित अर्थ-व्यवस्था (Unbalanced Economy) में कृषि का महत्व—हमारे देश की अर्थ व्यवस्था बहुत असन्तुलित है। हमारी जनसंख्या का लगभग 69-8 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है।

भारतवर्ष में कृषि का महत्व

1. जीविकोपार्जन का मुख्य साधन
2. राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योग
3. सरकार की आय
4. जनसंख्या के लिये भोजन
5. असन्तुलित व्यवस्था में कृषि का महत्व
6. उद्योगों के लिए कच्चा माल
7. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व
8. निर्यात में महत्व
9. सामाजिक व राजनैतिक महत्व

देशी पर अत्यधिक निर्भरता हमारे देश की बहुत बड़ी कमजोरी है। यदि कृषि में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए तो देश पर आर्थिक संकट आ सकता है। अतः कृषि का हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत महत्व है।

6. उद्योगों के लिए कच्चा माल (Raw materials)—कृषि हमें केवल भोज्य वस्तुएँ ही नहीं प्रदान करती बल्कि हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी जुटाती है। कपास सूनी वस्त्रोद्योग के लिए, पटसन रूट उद्योग के लिए, दन्ना चीनी उद्योग के लिए, तिलहन तेल उद्योग के लिये, तथा रबर आदि

कृषि अन्य वस्तुएँ अन्य उद्योगों के साधारण का काम करती हैं। भारत में औद्योगिक आवश्यकता की वस्तुओं के उत्पादन में कृषि की भारी है।

7. अन्तर्राष्ट्रीय महत्व (International Importance)—बड़े कृषि पदार्थों के उत्पादन में भारत का विश्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान

है। भारत चाय, मूँगफली और गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और लाख के उत्पादन में लगभग एकाधिकार (monopoly) है। चावल, जूट आदि के उत्पादन में भारत सप्ताह का दूसरे नम्बर का देश है। कपास, तिलहन, लम्बाकू व एम्बोली के उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

8. निर्यात (exports) में महत्व—भारत से निर्यात होने वाले पदार्थों में कृषि पदार्थों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे यहाँ से जूट, तिलहन, चाय, लम्बाकू, कद्दा आदि पदार्थ बाहरी देशों को भेजे जाते हैं जिनसे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। यह हमारी वस्तुवर्षीय योजनाओं की सफल बनाने में सहायक है। सन् 1967-68 में चाय, कॉफी, कपास लम्बाकू, फल आदि कृषि-जन्य पदार्थों का निर्यात लगभग 293 करोड़ रुपये के मूल्य का हुआ।\*

9. कृषि का सामाजिक व राजनीतिक महत्व (Social and political importance)—कृषि व्यवसाय सुखी हुआ से किया जाता है इसलिए कृषक आत्मसंयमो होते हैं। इससे हमें सैनिकों की प्राप्ति होती है जो देश की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। साथ ही कृषकों के विचार, उनका वक्ता आदि देश की सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता पर विशेष प्रभाव डालते हैं।

इस प्रकार हम कहते हैं कि कृषि भारत का प्राण है, किन्तु वर्तमान समय में कृषि के पिछड़ेपन के कारण यह अत्यन्त आवश्यक व्यवसाय बन गया है।

### भारतीय कृषि का पिछड़ापन (Backwardness of Indian Agriculture)

कहा जाता है कि “भारतवर्ष में पिछड़े हुए वर्ष है और पिछड़े हुए उद्योग भी, दुर्भाग्यवश कृषि भी इनमें से एक है।” इससे यह स्पष्ट है कि अन्य देशों की तुलना में भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। “भारत एक सम्पन्न देश है जिसमें निर्बल जनता निवास करती है” (India is a



rich country inhabited by poor people) वाली कहावत भी यह स्पष्ट करती है कि भारत की भूमि उपजाऊ और जलवायु कृषि के अनुकूल है फिर भी कृषि उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं है।

डॉ. वेस्ट्रो के अनुसार "विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या स्वाधीन रूप से भूखी रहती है और उसकी एक-तिहाई जनसंख्या भारत में रहती है, जिसमें से 30 प्रतिशत जनसंख्या तो भूखे स्तर (Starvation level) पर ही रहती है।" इससे भी स्पष्ट होता है कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान होते हुए भी हमे विदेशों से अनाज एवम् अन्य कृषि पदार्थ मंगाने पड़ते हैं।

कृषि के विद्योपन की जानकारी के लिए हमारे देश की प्रति एकड़ उपज की तुलना अन्य देशों से की जानी चाहिए। गेहूँ के क्षेत्र में भारत की तुलना में अमेरिका और कनाडा में दुगुना तथा मिश्र में तिगुना उत्पादन होता है। भारतीय चावल की प्रति एकड़ पैदावार की तुलना में मिश्र चीन, जापान और अमेरिका तिगुना तथा चीन दुगुना उत्पादन करता है। मिश्र हमसे लगभग सात गुना कपास प्रति एकड़ पैदा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में प्रति एकड़ उत्पादन विश्व के अनेक देशों की तुलना में बहुत कम है। यही हम कृषि के विद्योपन के कारणों पर प्रकाश डालेंगे।

कृषि के विद्योपन के कारण—हमारे देश में कृषि की पिछड़ी दशा के मुख्य कारण ये हैं—

1. जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक भार (Excessive pressure of population on land) - देश की 69.8 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, जिसमें क्षेत्र छोटे-छोटे हो गये हैं और आप कम प्राप्त होती है। क्षेत्रों की बर्द्ध प्रकार की उपज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाती। जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हैं, हमारे देश में प्रति एकड़ उपज भी कम है। भारतीय कृषि की पिछड़ी दशा के मुख्य कारण प्राकृतिक तथा मानवीय हैं।

2. कृषि का वर्षा पर निर्भर होना (Dependence on Monsoon)—हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा अनिश्चित, कम

तथा असमान होती है। अतः अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों से बकाल पट जाते हैं और कृषि को हानि पहुँचती है। बकाल तो भारतीय ग्राम्य क्षेत्रों व्यवस्था के एक घटक बन गये हैं। हमारे देश में अभी तक सिंचाई के साधनों की प्रगति आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही कम है और कृषि योग्य क्षेत्र में से केवल पाँचवें भाग में ही कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होती है। भारतीय कृषि वर्षा में एक जुआ है (Indian agriculture is a gamble in rains)। वर्षा अनिश्चित है। कभी अतिवृष्टि हो जाती है तो कभी अनावृष्टि। टिड्डियों का भी प्रकोप रहता है तथा जानवरों द्वारा फसलों को काफी हानि पहुँचती है। पेड़ों को रोग लग जाते हैं। बहुधा कीड़ों और बीमारी से फसलें लगर हो जाती हैं। इन प्राकृतिक प्रकोपों से कृषि उत्पात कम हो जाती है।

सरकार सिंचाई के साधनों का प्रबन्ध कर प्राकृतिक बारणों पर अधिकार पाने में सफल है।

3. क्षेत्रों का अत्यधिक विखटा (fragmented) और छोटा होना - क्षेत्रों का अत्यधिक छोटे छोटे बिखरे होने के कारण क्षेत्रों की उपज की हानि होती है। क्षेत्रों में अत्यधिक छोटा होने से बुँदा बुँदा बनाने, बाड़ (fence) लगाने और आधुनिक यन्त्रों के प्रयोग पर बल लगे करना असाध्य (un-economic) हो जाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की बीजार और सामान ले जाने में भी व्यर्थ में बहुत सा समय, समय और शक्ति नष्ट होती है।

कृषि की निम्नलिखित दशा के कारण

1. भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार
2. कृषि का वर्षा पर निर्भर होना
3. क्षेत्रों का बिलसरा व छोटा होना
4. भूमि पर स्थायी सुधार का अभाव
5. कृषकों का निर्बल, अशिक्षित, निर्बल और मायबोही होना
6. पूँजी का अभाव
7. बिजली के असंगोपजनक साधन
8. वैज्ञानिक क्षेत्र से कृषि में अभाव
9. सहायक साम-धन्यों का अभाव
10. गाँव का साहूकार
11. उत्तम बीज और ताद की कमी

4. भूमि पर ख़ाई मुषारों का अभाव—भूमि पर ख़ाई मुषारों के अभाव के कारण भी हमारी खेती की दशा हीन है। बिछाई के साधनों जैसे कुएं, तालाब और नहरों की कमी, बाड़ों (fences) का अभाव, दोषपूर्ण पट्टे की प्रणाली आदि खेती के लिये हानिकारक हैं।

5. धमिकों का निर्धन, अज्ञानी, निर्बल और भाग्यवादी (fatalist) होना—हमारे देश के खेती पर काम करने वाले धमिक निर्धन, अज्ञानी, निर्बल और भाग्यवादी होते हैं। उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है। शिक्षा के अभाव के कारण अधिकांश कृषक ग्रन्थ विवासी हैं तथा उनमें उन्नति की भावनाओं का अभाव है। उनकी कृषिविद्या पुर्ण पुरानी है और वे बहुधा परिवर्तनों का विरोध करते हैं। हमारे किसानों की कार्य-कुशलता विदेशी किसानों से बहुत कम है।

6. पूँजी (Capital) का अभाव—खेती की हीनता का एक और कारण पूँजी का अभाव है। दरिद्र होने के कारण किसानों के पास कृषि में पूँजी लगाने की नहीं है। गाय, बैल, पशु आदि ही किसानों की महत्वपूर्ण पूँजी है, जो संख्या में अधिक है परन्तु अकुशल है। पूँजी नहीं होने से कृषक उत्तम साध, उत्तम बीज और उत्तम मीजार काम में नहीं ला सकता। आधुनिक खेती के यन्त्रों और मशीनों के उपयोग के बारे में तो वह विचार भी नहीं कर सकता।

7. बिजली के असन्तोषजनक साधन—बिजली के साधन संतोषप्रद नहीं हैं और अधिकतर किसानों का माल कम कीमत पर गाँव में ही बिक जाता है। ऋणी होने के कारण तथा अन्य कठिनाइयों के कारण उन्हें अपना उत्पादन विवश होकर कम मूल्य पर ही बेच देना पड़ता है जिससे उनकी आय कम होती है, किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं के सूत्रपाठ में स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

8. वैज्ञानिक (Scientific) ढंग से कृषि न करना—कृषि प्रणाली इतनी अविकसित तथा हानिप्रद है, कि जब तक उसे आधुनिक आधार पर संगठित करके इसके तरीकों को बदला नहीं जायगा, हम ख़ाई उत्पादन वृद्धि की कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। भारतीय किसान

दरिद्रता तथा अज्ञानता के कारण आधुनिक वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करने में हिचकिचाते हैं। अतः कृषि एक पिछड़ा उद्योग बन गया है।

9 सहायक काम-धंधों (Subsidiary occupations) का अभाव—भारतीय कृषि मौसमी (seasonal) होने के कारण कृषक को खेतों में केवल 6-8 महीने तक ही काम रहता है और बाकी समय में कोई सहायक धंधा न होने के कारण कृषक बेकार रहता है जिससे उसकी आय कम हो जाती है।

10. गौश का साहूकार—हमारे देश में खेतों की उन्नति में गौश का साहूकार भी बाधक है। यह ऊँची म्याज की दर पर, जो 12% से 40% तक पाई जाती है, खून देकर हिसाब में गड़बड़ी कर किसानों को खुरम में जंवाये रखता है। किसानों की फसल सस्ती दर पर खरीद लेता है और बहुत सी रहन रसी हुई जमीन किसानों से महाजनों के हाथों में चली जाती है। खण्डस्त होने के कारण किसानों के पास खेती की उन्नति के लिए धन नहीं रहता तथा उन्हें अपनी फसल भी साहूकार की ही सस्ती दर पर बेचनी पड़ती है।

11. उत्तम बीज और खाद की कमी—किसान निम्न धेनी के बीज काम में लेते हैं जिससे अच्छी फसल नहीं होती। किसान खाद की ओर भी विशेष ध्यान नहीं देते। प्रतिबन्ध बहुत सा गोबर उरने बनाकर बला दिया जाता है। हरी खाद, रासायनिक, हरी और मछली की खाद का देश में बहुत कम उपयोग होता है। भूमि की उर्वरता गति कम होने से उत्पादन गिरता है।

कृषि उत्पाति में मुषार के उपाय (Remedial measures)—

यदि हम कृषि उत्पादन में वृद्धि चाहते हैं, तो खेतों में मुषार करने होंगे, जिससे कि प्रति एकड़ उत्पादन दर बढ़े और देश खाद तथा उद्योगों के लिए कच्चे माल में आरम निर्भर बन सके।

1. सिबाई की योजना का विकास—कृषि की उत्पाति में मुषार के लिए यह आवश्यक है कि कृषि की मानसून से स्वतन्त्र किया जाय।

अतः सिंचाई के साधनों—नहरों, कुँवों, तालाबों, आदि का तीव्र विकास नितान्त आवश्यक है।

2. चकबंदी ( Consolidation of holdings ) व सहकारी खेती—चकबंदी और सहकारी खेती (Co-operative farming) द्वारा हम खेती की अन्तर्विभाजन और भागबंटन (Sub division and fragmentation) के दोषों से बचा सकते हैं और बड़े पैमाने की खेती के लाभ उठा सकते हैं। खेती की उपज में वृद्धि करने के लिये अच्छी खाद, उत्तम बीज, उत्तम औजारों का प्रयोग होना चाहिये। ट्रैक्टरों द्वारा बेकार जमीन को खेती के योग्य बनाना चाहिए। कल की भाँति जगह-जगह ट्रैक्टर स्टेशनों की स्थापना करनी चाहिये जो आधुनिक औजार और उनके फुटकर भागों का सप्लाई करें। बैलों की नस्ल (breed) सुधार कर उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि करनी चाहिये।

3. कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग—गरु-गरु के कीटाणु भी हमारी खेती को बहुत हानि पहुँचाते हैं। टिट्टियों के रस प्रतिद्वंद्व हरी-

कृषि उत्पादन में सुधार के उपाय

1. सिंचाई की योजनाओं का विकास

2. चकबंदी व सहकारी खेती

3. कीटाणु-नाशक दवाइयों का प्रयोग

4. सहकारी समितियों का गठन

5. फुटीर उद्योगों की उत्पत्ति

6. वृषकों के विचारों में सुधार

7. पशुओं की दशा में सुधार

8. कृषि का वैज्ञानिकरण

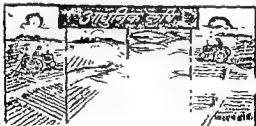
मरी फसल को नष्ट करके बहुत हानि पहुँचाते हैं। इस हानि को रोकने के लिये कीटाणु-नाशक दवाइयों के प्रयोग का प्रचार किया जाय, जिससे कृषक अपनी फसल की रक्षा कर सकें।

4. सहकारी समितियों द्वारा पूँजी व बिजली के अच्छे साधनों की सुविधा—सहकारी समितियों द्वारा उचित ब्याज पर किसानों को पूँजी उधार देने तथा खेती की उत्पादन की बिजली का उचित प्रयोग करने

की सुविधाएँ होनी चाहिये। देश में बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों—साख, विपणन, बहुपक्षी आदि—का गठन अत्यावश्यक है।

5. गांव में कुटीर उद्योगों की उन्नति के द्वारा कृषि पर जन-भार में कमी—गांवों में कुटीर उद्योग चालू करने चाहिये, जिससे लोग भूमि पर ही आश्रित न रहें और भूमि पर जन-भार कम हो जाय। इससे बैकारों को काम मिलेगा, किसान अपने बैकार समय का उपयोग कर सकेंगे तथा उनकी आय में वृद्धि होगी। हमकी केवल कृषि परिस्थितियों में नहीं परन्तु कृषक स्वयं में भी सुधार करना चाहिये। हमें किसानों का जीवन-स्तर ऊँचा करना है, और उनको शिक्षित बनाना है, जिससे प्रगतिशील हों और उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि हो। किसानों को यह विश्वास दिलाया जाय कि बैती के सुधारों से होने वाला लाभ उन्हीं का होगा, जिससे कि वे मन लगाकर अपना कार्य करें, और बैती में सुधार करने के लिए प्रयत्न करें। कृषि विकास में भूमि-व्यवस्था के सुधार का महत्वपूर्ण स्थान है।

6. कृषकों के विचारों में सुधार—शिक्षा ॥ कारण कृषकों में भाग्यवाद तथा पुराने और गुरे रीति-रिवाजों में विश्वास उत्पन्न हो गये हैं। अतः यह आवश्यक है कि उनमें शिक्षा का प्रचार किया जाय जिससे उनके विचारों में सुधार हो और वे नये-नये तरीके अपनाकर अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करें।



7. पशुओं की बसा में सुधार—हमारे देश में किसानों के पशु बहुत दुर्बल है और कम कार्यकुशल हैं तथा बीमारी से घिरे रहते हैं। इन नस्ल में सुधार, खारे का उचित प्रबन्ध तथा पशु-वैद्यशास्त्रों की सुविधाओं का प्रबन्ध करना चाहिये।

8. कृषि का वैज्ञानिकरण (Scientific agriculture)—कृषि विकास के लिए विज्ञान का महत्व बहुत बड़ गया है। विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण को दूर किया जा सकता है। रासायनिक तथा अन्य प्रकार की साधों के उपयोग, उन्नत और सुधरे हुए कृषि औजारों के प्रयोग तथा वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए प्रचार एवं प्रसार करना आवश्यक है।

### भारत में कृषि विकास के लिए कृषि नियोजन ( Agricultural Planning )

“हमारे देश की संस्कृति का आधार कृषि ही है।” स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के सम्मुख कृषि सुधार की समस्या सम्प्रीर रूप से उपस्थित हुई। नियोजन के बिना आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्भव नहीं होता। अतः देश में कृषि नियोजन की आवश्यकता ही नहीं अपितु अनिवार्य है। भारत में कृषि-नियोजन के विस्तृत उद्देश्य हैं। कृषि-नियोजन से तात्पर्य केवल भौतिक वसाधों की पैदावार को बढ़ाना ही नहीं है अपितु देश के प्राकृतिक साधनों का अधिकतम विकास करना, कृषकों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, जोषण का अन्त करना तथा रोजगार का प्रसार और आर्थिक असमानता को दूर करके देश को शक्तिशाली एवं समृद्धिशाली बनाना है। द्वितीय महायुद्ध से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए अनेक योजनाएँ प्रस्तुत की गईं, जिनमें कृषि को महत्व दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)—इस योजना में कृषि विकास को प्राथमिकता (Priority) दी गई। इसके कुल 2,356

करोड़ रुपये के आयोजित व्यय में से कृषि, सिंचाई, विजली आदि के लिए 1,018 करोड़ रुपये रहे गये थे जो कुल व्यय का 43.2 प्रतिशत था। (1) इस योजना में कृषि, सिंचाई एवं शक्ति के विकास पर 884 करोड़ रुपये व्यय किए गए। (2) खाद्यान्नों में 30%, कपास में 45%, तथा तिलहन के उत्पादन में 80% की वृद्धि हुई। (3) सिंचाई की योजनाओं के लिए 518 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। (4) 64.5 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की गई। रासायनिक खाद के लिए सिम्लरी में खाद का कारखाना खोला गया। (5) उत्तम बीज की व्यवस्था, कृषि में नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान, चकबन्दी, सहकारी साख एवं वितरण समितियों का विकास किया गया। (6) पशुओं की मूल में सुधार, सहकारिता, प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा सहकारी कृषि के प्रयोग किए गए और 1,40,000 ग्रामों में सामुदायिक विकास (community development) कार्य आरम्भ किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)—इसमें कृषि के उत्पादन लक्ष्यों (production targets) की प्राप्ति हेतु 666.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इस योजनाकाल के अन्त में कृषि पदार्थों का उत्पादन सूचकांक (index number) (1949-50=100) के आधार पर 135 हो गया। इस योजनाकाल में उन्नत किस्म के बीज, खाद तथा सिंचाई के साधनों के विकास के निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी। उत्पादन लक्ष्यों की भी वर्ष 1957-58 व 1959-60 वर्षों की कसौटी के उत्पादन में कमी के कारण प्राप्ति नहीं किया जा सका। प्रथम योजना में कृषि का उत्पादन 17% बढ़ा जबकि द्वितीय योजना में यह वृद्धि 16% ही थी।

द्वितीय योजना-काल में लगभग 64 लाख हेक्टर भूमि में सिंचाई (Irrigation) का प्रबन्ध किया गया तथा विभिन्न प्रकार की खादों मो. टन खादों (manures and fertilizers) का अतिरिक्त प्रयोग किया गया।



चतुर्थ योजना (1961-66)—इस योजना के अन्तर्गत—(1) सिंचाई साधनों का विस्तार, (2) रासायनिक खाद की पूर्ति का विस्तार, (3) उन्नत बीज, (4) पौधों का रक्षण, (5) सुघरे हुए हल और जोरारों का विस्तार आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इस योजना में कृषि उत्पादन की वृद्धि की दर पहले से दृढ़नी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पाँच उद्देश्यों में से 'खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता प्राप्त करना एवं उद्योगों और निर्यात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि का उत्पादन बढ़ाना' भी एक उद्देश्य है। इस अवधि में खाद्यान्नों का उत्पादन 30 प्रतिशत तथा अन्य फसलों का उत्पादन 31 प्रतिशत बढ़ाये जाने की व्यवस्था थी। सिंचित क्षेत्र 2.82 करोड़ हेक्टर से बढ़कर 3.62 करोड़ हेक्टर हो जाने का अनुमान था। इस योजना में कृषि विभाग पर 1089 करोड़ रुपये खर्च हुए।<sup>१</sup>

चतुर्थ योजना—सन् 1966 से 1971 तक की प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि कार्यक्रमों के लिए 1,944 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। संशोधित योजना-प्राकर में कृषि विकास हेतु 2217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।<sup>२</sup> इस योजना में कृषि को परम्परागत जीवन-यापन की पद्धति के स्थान पर औद्योगिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य रखा गया था। सिंचाई, भू-संरक्षण, भूमि सुधारों आदि कार्यक्रमों की प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई थी।

मध्य में हम यह कह सकते हैं कि सरकार ने अर्थ व्यवस्था में कृषि के महत्व को सुरक्षित कर पंचवर्षीय योजनाओं में इसके विकास पर वर्तमान ध्यान दिया है। फिर भी कृषि के क्षेत्र में अधिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

• Aspects of the Fourth Plan, p. 4

† चतुर्थ योजना तीन वर्षों के लिए स्वर्णिम कर दी गई थी। अब यह योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारम्भ हो गई है।

‡ Yojna, April 20, 1969—p. 16

## सारांश

भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारी जीवन प्रणाली एवम् प्रति का आधार है।

कृषि का अर्थ व्यवस्था में महत्व—औषिकोपार्जन का मुख्य साधन, रोज घाय में योग, सरकार की आय, जनसंख्या के लिए भोजन, मुलित अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्व, उद्योगों के लिए कच्चा माल, राष्ट्रीय महत्व, निर्यात में महत्व, सामाजिक व राजनीतिक महत्व।

कृषि अर्थ व्यवस्था का प्राण है।

कृषि का विप्लवापन—अन्य देशों की तुलना में भारतीय प्रति एकड़ त पैदावार कम है। कारण—भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक, कृषि का षण पर निर्भर होना, घेनों का बिलरा व छोटा होना, वार स्थायी सुधारों का अभाव, कृषकों का निर्धन होना, अक्षितित, न व माल्य-बादी होना, पूजी का अभाव, बिनी की असन्तोषजनक स्वा, बैज्ञानिक कृषि का अभाव, सहायक धर्मों का अभाव, साहूकार शेषपूर्ण कार्यप्रणाली, उत्तम बीज व खाद की कमी।

कृषि में सुधार के उपाय—निर्धार, कचकदी व सहकारी कृषि, लुनामक दवाओं का प्रयोग, सहकारी समितियों का गठन कुटीर ग की उपनि, कृषकों के बिचारों में सुधार, वस्तुओं की दवाओं में, कृषि का बैज्ञानीकरण।

विकास और नियोजन—

प्रथम योजना में कृषि विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। योजना में कृषि विकास पर कुल योजना व्यय का 43.2 प्रतिशत खर्च हुआ।

द्वितीय योजना में 667 करोड़ रुपये खर्चे करते कृषि उत्पादन में 49-50 की तुलना में) 35 प्रतिशत वृद्धि हुई।

तृतीय योजना में कृषि उत्पादन की दर की दुगुना करने का लक्ष्य गया। इस योजना में कृषि विकास कार्यों पर 1089 करोड़ खर्चे हुए।

समूहों योजना में कृषि की औद्योगिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का उद्देश्य रखा गया है ।

सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि विकास कार्यक्रमों पर धोर दे रही है ।

### प्रश्न

1. भारतीय कृषि के प्रमुख दोषों की व्याख्या कीजिये तथा कृषि-सुधार के उपाय बताइये ।
2. भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि का महत्व बताइये । भारतीय कृषि के पिछड़े होने के क्या कारण हैं ? इसके सुधार के उचित उपाय सुझाइये ।  
(राज. बो., हा. से., 1965)
3. भारतीय कृषि की उन्नति के सुझाव दीजिये ।  
(राज. बो., हा. से. 1967)
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—  
(अ) भारत में कृषि उपज कम होने के प्रमुख कारण ।  
(राज. बो., हा. से. 1969)

## अध्याय 3

### भारत में कृषि की जोतें

#### (AGRICULTURAL HOLDINGS IN INDIA)

“भारत में भूमि को ‘आर्थिक भूकम्पों’ के कारण बार-बार उप-विभाजित होना पड़ता है।”

—मावेस्त

“भूमि के उपविभाजन और अपसम्पदन से साहस गह होता है, धम की बड़े पैमाने पर बर्बादी होती है, सीमा बनाने में भूमि का बहुत सा भाग बेकार हो जाता है और गहरी खेती सम्भव होती है।”

—डॉ० मैन

भारतीय कृषि को विकसित करने के उपायों में आर्थिक जोत (Economic holding) का निर्माण करना उद्देशनीय है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में कृषि जोतों का आकार सतोषप्रद नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से इस दिशा में सुधार के कतिपय प्रयास किए गए हैं। यहाँ हम कृषि जोतों के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करेंगे।

कृषि जोत का अर्थ एवं महत्व—कृषि जोत या इकाई का तात्पर्य उस भूमि के क्षेत्र से है जिस पर कृषक द्वारा कृषि की जाती है। कृषि जोत का प्रभाव कृषक एवं कृषि दोनों पर ही पड़ता है। बिना उचित कृषि जोत के अच्छे बीज, खाद, यंत्र आदि का प्रयोग सम्भव नहीं हो सकता। कृषि में रसायनों सुधारों का लागू करना भी कृषि जोत के आकार पर निर्भर करता है। इस प्रकार कृषि जोत का आकार कृषि सम्बन्धी समस्याओं से सम्बन्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

## हृषि जोगों के प्रकार (Types of Agricultural holdings)

हृषि जोगों को मुख्यतः निम्नोक्तिन भागों में बांटा जा सकता है—

1. आर्थिक जोग (Economic holding)—इस भाग के अनुसार "आर्थिक जोग वह जोग है जो इस पर निर्भर रहने वाले परिवार को एक सामान्य प्रकार के जीवन स्तर की सुरक्षाएँ प्रदान कर सके।" यह वह इकाई है जो किसान को सामान्य जीवन स्तर

हृषि जोगों के प्रकार — पाल करने हेतु बांटा जा सकता है—

- |                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. आर्थिक जोग   | प्रदान कर सके। सरकार अनाधिक     |
| 2. बुनियादी जोग | जोगों के स्थान पर इन इकाइयों    |
| 3. आदर्श जोग    | की स्थापना करने के लिए प्रयत्न- |
| 4. अनाधिक जोग   | योग्य है।                       |

2. बुनियादी जोग (Basic Holding)—यह वह जोग है जो आर्थिक जोग से आकार में छोटी है तथा जिससे कम आकार की इकाई आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होती है। यह कृषक को ग्यूनतम जीवन स्तर हेतु आवश्यक भाग प्रदान करती है। देश के अनेक भागों में यह इकाई भी उपलब्ध नहीं है।

3. आदर्श या अनुकूलतम जोग (Optimum holding)—आदर्श जोग कृषि का वह आकार होता है जिस पर कृषक को उसके द्वारा भूमि पर लगाये गये साधनों की तुलना में अधिकतम लाभ मिलता है। राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के पास रखी जाने वाले इस जोग का अधिकतम आकार निर्धारित कर दिया जाता है। सामान्यतः इस जोग का आकार आर्थिक जोग से तीन गुना होता है। आर्थिक विषमताओं को दूर करने की दिशा में आदर्श जोग का निर्धारण सामाजिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

4. अनाधिक जोग (Uneconomic holdings)—ऐसी छोटी इकाईयाँ जिसमें कृषि व्यवसाय का संचालन अलाभदायक हो अनाधिक जोगों के नाम से पुकारी जाती हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार की जोगें

का बाहुल्य है। देश में कुछ स्थानों पर जोतों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें 'सिखोना जोत' (Toy holding) के नाम से पुकारा जाता है। इन जोतों के बारे में हम खेतों के उपविभाजन एवं अपखण्डन की समस्या के अन्तर्गत विस्तार से पढ़ेंगे।

खेतों का उपविभाजन एवं अपखण्डन

(Sub-division and Fragmentation of holdings)

सर्ष—'उपविभाजन' (Sub-division) का सर्ष उत्तराधिकारियों में खेत का बार-बार छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देने से है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी भूमि का वितरण उसके उत्तराधिकारियों में किया जाता है और फिर इसका पुनर्विभाजन किया जाता है। इस क्रिया से भूमि का बार-बार विभाजन होता है और खेतों का आकार छोटा होता चला जाता है।

'अपखण्डन' (Fragmentation) का तात्पर्य भूमि के उन टुकड़ों से होता है जो एक चक्र में न होकर दूर-दूर स्थित होते हैं। संक्षेप में, भूमि का छोटे-छोटे खेतों में बाँटा जाना उपविभाजन और खेतों का दूर-दूर बिखरा होना अपखण्डन कहलाता है।

भारतवर्ष में खेतों का आकार छोटा होने के साथ-साथ दूर-दूर बिखरे होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार भारत में जोत (holding) का औसत आकार 3.2 हेक्टर (7.5 एकड़) है। किन्तु नेशनल सेम्पल सर्वे (N. S. S.) के आभार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में जोतों (holdings) का औसत आकार 5.43 एकड़ है। यदि हम दूसरे देशों की जोतों के औसत आकार से इसकी तुलना करें तो स्पष्ट हो जायगा कि भारत में खेतों का आकार बहुत छोटा है। इतना ही नहीं जोत का औसत आकार भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। जहाँ राजस्थान में जोत का औसत आकार

---

\* कुछ प्रमुख देशों की जोतों का औसत आकार इस प्रकार है—  
संयुक्त राज्य अमेरिका 215 एकड़, ब्रिटेन 66 एकड़, फ्रांस 26 एकड़, युगोस्लाविया 11 एकड़ आदि।

684 हेक्टर (17 एकड़) है वही बिहार में 4 और केरल में 1.05 हेक्टर (25 एकड़) की औसत जोन है। अपसहन के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के अध्ययन किये गये हैं जिनसे पता लगता है कि छेउ छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटे हुए नहीं हैं, वरन् जोन एक स्थान पर न होकर दूर-दूर स्थित है। डॉ० मैन (Mann) ने दक्षिण के एक गाँव का सर्वेक्षण करके पता लगाया कि गाँव के 156 कुपनों के पास 418 छेउ के टुकड़े थे जिनमें से लगभग 535 नेत्रों का घातार 403 हेक्टर (एक एकड़) से भी कम था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में छेउों का उपविभाजन के साथ-साथ अपसहन की समस्या भी पाई जाती है।

उप-विभाजन एवं अपसहन के कारण—जब हम कृषि के विकास को कुठित करने वाली इस समस्या के कारणों का अध्ययन करेंगे।

1. हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है किन्तु औद्योगीकरण का विकास तेजी से न हो सकने के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार (Pressure of population) बढ़ता जा रहा है। परिणाम-स्वरूप छेउों का घातार छोटा होता जा रहा है।

छेउों में उप-विभाजन एवं अपसहन के कारण

1. जन-संख्या की वृद्धि
2. उत्तराधिकार के नियम
3. संयुक्त परिवार प्रथा का अन्त
4. कुटीर-उद्योगों का ह्रास
5. भूमि को साझे पर देने की प्रथा.

2. उत्तराधिकार के नियम (Laws of Inheritance and Succession)—हमारे देश में उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद भूमि उसके पुत्रों में समान रूप से बाँटी जाती है। यहाँ इंग्लैंड की तरह ज्येष्ठाधिकार (Primogeniture) पद्धति का प्रचलन नहीं है। इस प्रकार

- भूमि का विभाजन छोटे-छोटे घनायिक टुकड़ों में हो जाता है।

3. संयुक्त परिवार (Joint family) प्रथा का अन्त—भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से यह प्रथा प्रचलित थी जिसके अन्तर्गत

परिवार के सदस्य साथ-साथ रहते थे और भूमि का बंटवारा नहीं होता था। किन्तु वास्तविक शिक्षा-दीक्षा ने व्यक्तिवादी मर्यादा को प्रोत्साहन दिया है। परिणामस्वरूप अब परिवार के सदस्य भूमि एवं अन्य सम्पत्ति का विभाजन करके अपना हिस्सा अलग रखना चाहते हैं।

4. कुटीर उद्योगों का ह्रास—अनेक कारणों से कुटीर उद्योगों का ह्रास हो गया और जो कारीगर इन उद्योगों में सने हुए थे वे भी कृषि पर आश्रित हो गए। कसस्वरूप क्षेत्रों के टुकड़े छोटे-छोटे हो गये।

5. भूमि के प्रति मोह—भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदण्ड तो है ही, साथ ही स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने के लिए मनुष्य खेती का ही सहारा लेता है। हमारे देश में किसानों का भूमि के प्रति बहुत मोह है और वे भूमि के छोटे से छोटे टुकड़े को भी अपने ही पास रखना चाहते हैं। प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने पिता के सभी क्षेत्रों में हिस्सा लेना चाहता है जिससे क्षेत्रों के दूर-दूर स्थित होने की समस्या को बढ़ावा मिलता है।

6. भूमि को साझे पर देने की प्रथा—बड़े बड़े भूमिपति बहुधा अपनी भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते। वे अपनी भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर अलग-अलग किसानों को साझे पर दे देते हैं। इससे भूमि के जोत का मानिक एक होते हुए भी जोत के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं।

उप-विभाजन एवं अपसंयोजन की हानियाँ (Disadvantages)—  
क्षेत्रों के छोटे-छोटे एवं बिखरे होने से खेती में कई हानियाँ होती हैं और कृषि आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद हो जाती है। इसके मुख्य दोष इस प्रकार हैं—

1. कृषि उत्पादन लागत (Cost of production) में वृद्धि—  
क्षेत्रों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन होने पर किसान अपने साधनों का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकता। कई क्षेत्र तो ऐसे होते हैं जिनमें



बुआई भी नहीं की जा सकती और यदि उनमें खेती की भी जाय तो उत्पादन ही सापेक्ष अधिक हो जाती है ।

2. कृषि सुधारों (Agricultural Improvements) का संभव न होना—खेतों का क्षेत्रफल छोटा होने पर भूमि पर कृषि सुधार नहीं किए जा सकते । छोटे-छोटे खेतों पर कुआँ खोदना, पानी नालियाँ बनाना आदि सामर्थ्यहीन नहीं होता । इन सुधारों के अभाव में कृषि की प्रति एकड़ पैदावार में कमी आती है ।

3. बाड़, मेड़ आदि लगाने में कठिनाई—जानवरों आदि से फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक खेतों की बाड़ (fence) बगैरह लगाई जाएँ । जहाँ खेतों के टुकड़े बहुत छोटे-छोटे और दूर-दूर स्थित हों वहाँ बाड़ लगाने में बहुत सर्वाँ होता है और बहुत बाड़ें लगाने और मेड़ें छोड़ने से ऊपरी भूमि खेती के काम में नहीं भी आ पाती ।

4. यांत्रिक खेती (Mechanised farming) अनाभव हो जाती है—छोटे खेतों पर यांत्रिक खेती सामर्थ्यहीन होती है । ट्रैक्टर, बुनडोजर, प्रेसर, आदि समय और धन बचाने वाले यन्त्र (time and labour saving devices) का प्रयोग छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ों पर नहीं किया जा सकता ।

5. निगरानी (Supervision) में कठिनाई—छोटे-छोटे स्थले दूर खेतों की देखभाल या निगरानी करना न केवल कठिन ही होता है, बल्कि खर्चीला भी होता है ।

6. समय, धन व धन का अभाव (wage) —जब क्षेत्र दूर-दूर स्थित हो तो कृषि के परिवार, पशु आदि माधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने से जाने में समय, धन व धन का अभाव होता है जिससे कृषि सामर्थ्यहीन बन जाता है ।

7. भगड़े और मुकदमेबाजी (litigation)—खेतों के दूर-दूर स्थित होने की दशा में मार्ग, सीमा, पानी, बाढ़ सम्बन्धी अनेक भगड़े पैदा हो जाते हैं। फलस्वरूप किसान आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और मुकदमेबाजी चलती है जिनमें धन, समय व शक्ति की बर्बादी होती है।

8. पूंजी मिलने में कठिनाई—जब खेतों का साकार छोटा होता है तो इनको रहन (mortgage) रख कर ऋण उधार नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो बहुत कम। बिना रहन रखे ऊंची व्याज दर देनी पड़ती है।

9. गहरी खेती (intensive cultivation) सम्भव नहीं—भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में दूर-दूर स्थित होना गहरी खेती को कठिन बनाता है, क्योंकि कृषि सुधार के विभिन्न साधनों को इन टुकड़ों पर नहीं लगाया जा सकता।

10. खेती का अनुविभाजन तथा कृषि योग्य भूमि का बेकार होना—खेतों के दूर-दूर होने तथा उनका साकार छोटा होने से उन पर धम और पूंजी की व्यवस्था करने में कठिनाई होती है और कई खेतों को बिना काफ़ी बिगड़े ही छोड़ना पड़ता है।

उप-विभाजन एवं अपसंजन के लाभ (Advantages)—खेतों के उप-विभाजन एवं अपसंजन के पक्ष में कुछ दलीलें दी जाती हैं जो इस प्रकार हैं—

उप-विभाजन एवं अपसंजन से हानियाँ

1. कृषि उत्पादन लागत में वृद्धि
2. कृषि सुधारों का सम्भव न होना
3. बाढ़-भेड़ लगाने में कठिनाई
4. यांत्रिक खेती असम्भव
5. निधरानी में कठिनाई
6. समय, धन व धन का अपव्यय
7. भगड़े और मुकदमेबाजी
8. पूंजी मिलने में कठिनाई
9. गहरी खेती सम्भव नहीं
10. खेती का अनुविभाजन और भूमि का बेकार होना

1. "सभी अण्डे एक टोकरी में मत रखो" (Do not keep all the eggs in one basket) एक पुरानी कहावत है। टोकरी इसी प्रकार भूमि के विभिन्न-विभिन्न टुकड़ों पर खेती करने का विमान आर्थिक संकट को कम कर सकता है। यदि एक क्षेत्र पर फसल खराब हो जाए तब भी किसान दूसरे क्षेत्रों की उत्पाति से गुजारा कर सकता है। अतः बिगड़े क्षेत्रों पर खेती करने से जोखिम (risk) घट कर कम हो जाता है।

2. डा० राधाकृष्णन मुकर्मों का मत है कि भूमि के जनन-अन्न टुकड़ों पर खेती करने से विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु के विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने से किसान को अधिक दिनों तक काम मिलता है। पर यह दलील अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अणुसंजन का सर्वप्रथम एक ही प्रकार की मिट्टी और जलवायु वाले क्षेत्रों से है।

3. कुछ लोग यह दलील भी देने हैं कि उप-विभाजन से किसान का आर्थिक स्तर समान होता है और पूँजीवादी कृषि (capitalist farming) नहीं बन पाती। परन्तु भारत में भूमि का विभाजन इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में हो गया है कि अब इनसे लाभ होने के बजाय हानि ही अधिक होती है।

### समस्या का उपचार और प्रगति

इस समस्या का शीघ्र निवारण बहुत ही आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार कई उपाय काम में ला रही है जिनसे समस्या का समाधान करके अविध्य में होने वाले भूमि के उप-विभाजन एवं अणुसंजन को रोका जा सकेगा। यहाँ हम इन उपायों और उनकी प्रगति के बारे में भी विचार करेंगे।

1. भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी की जानी चाहिये—देश में औद्योगीकरण का विकास करके भूमि पर जनसंख्या के बढ़े हुए भार को कम करने से क्षेत्रों के भावी विभाजन की समस्या को दूर किया जा सकता है। यह एक दीर्घकालीन उपाय (long term measure) है।

2. उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन—कुछ लोगों का मत है  
 सेतों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए अपने उत्तराधिकार के नियमों

परिवर्तन किया जाना चाहिए  
 इंग्लैण्ड की भाँति ही ज़ेपेन्डा-  
 नार नियम बना लेना चाहिये ।  
 करने से भूमि के स्वामी की  
 के बाद सबसे बड़े लड़के को  
 भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो  
 गा । किन्तु इस प्रकार का नियम  
 नाया जाना भारत में असम्भव-  
 रक प्रतीत होता है । फिर भी  
 नियम तो बनाया ही जा सकता  
 जिसमें सभी उत्तराधिकारियों  
 भूमि पर बराबर अधिकार तो  
 लेन्तु खेरी के लिए भूमि को टुकड़ों में न बाँटा जाय ।

उप विभाजन तथा अपसन्दान  
 की समस्या का उपचार

1. भूमि पर जनसंख्या का  
 भार कम करना चाहिये
2. उत्तराधिकार के नियमों  
 में परिवर्तन
3. चक्रवन्दी
4. कानून द्वारा धार्मिक जोतों  
 का निर्माण
5. जोतों की सीमा निर्धारण
6. सहकारी कृषि

3. चक्रवन्दी ( Consolidation of holdings )—इस समस्या  
 सुलझाने का सबसे प्रभावशाली उपाय चक्रवन्दी है । चक्रवन्दी के  
 विधान को उसके विभिन्न भूमि के टुकड़ों के बदले एक ही स्थान  
 समान कीमत की भूमि दी जाती है । चक्रवन्दी के सम्बन्ध में ब्रिटेन,  
 इ. फ्रांस, डेनमार्क व अन्य में परीक्षण किये गए हैं जिनसे यह स्पष्ट  
 था है कि प्रायः किसान स्वेच्छा से (voluntarily) चक्रवन्दी करने  
 पार नहीं होते ।

भारतवर्ष में सबसे बड़ने  
 दोर उत्तर-प्रदेश प्रादि  
 था । परन्तु इसके

का कार्य बड़ीश,  
 में चारम्व किया  
 १५१७६, बरीहि

निमानों के विरोध करने पर उन्हें चकबन्दी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। धीरे-धीरे ऐसे कानून बनाए गए जिनके अन्तर्गत चकबन्दी में अनिवार्यता का तत्व (element of compulsion) सम्मिलित कर लिया गया। कानूनों के अन्तर्गत यदि सातेदारों का एक निश्चित भाग चकबन्दी करना चाहे तो दूसरे न चाहने वाले कारखानों को भी चकबन्दी करने के लिए बाध्य (force) किया जा सकता है। इस प्रकार के कानून बन जाने पर भी चकबन्दी का कार्य अधिक प्रगति न कर सका। इसलिए ऐसे कानूनों की आवश्यकता हुई जिनके द्वारा चकबन्दी का अधिकार सरकार को मिल सके। सबसे पहले सन् 1947 में बम्बई में इस प्रकार का कानून बना। इसी प्रकार के कानून पंजाब, दिल्ली, उत्तर-प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मैसूर आदि राज्यों में बन गए हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत चकबन्दी कार्यक्रम का महत्वपूर्ण विभाग हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 11.05 हेक्टर (3 करोड़ एकर) भूमि पर चकबन्दी हो चुकी थी। तृतीय योजना काल में 11.245 हेक्टर (3.10 करोड़ एकर) भूमि पर चकबन्दी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक चकबन्दी का सबसे अधिक कार्य पंजाब में हुआ है जहाँ 7.01 लाख हेक्टर (175 लाख एकर) भूमि पर चकबन्दी हो गई है। राजस्थान में लगभग 10.42 लाख हेक्टर (26 लाख एकर) भूमि पर चकबन्दी का कार्य सम्पन्न हो चुका है।

4. आर्थिक क्षेत्रों (Economic holdings) का निर्माण—आर्थिक क्षेत्र बहुत बड़ा है जो एक औसत परिवार (average family) की सम्पत्ति-वस्तुओं और रत्न प्रदान कर सके। इस प्रकार की क्षेत्रों का कानून निर्माण करने से क्षेत्रों की ला-विभाजन और मातृत्व में योगदान रहेगा। आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण करने समय अन्य कई बातों पर ध्यान रखा जाना है जैसे—भूमि की उपजाऊ शक्ति, सिंचाई की सुविधाएँ, बाँझों से दूरी, क्षेत्रों के साधन और बढ़ती माँद। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र का अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार होगा।

### 5. जोतों का सीमा निर्धारण (Ceiling on land holding):—

यह भी सुझाव दिया जाता है कि छोटे-छोटे खेतों की समस्या को दूर करने के लिए जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। जिन लोगों के पास इस सीमा से अधिक भूमि हो, सरकार उन्हें मुआवजा देकर प्राप्त करने और उसे आवधिक जोत से कम क्षेत्र वाले खेतों में मिला दे। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में अधिकतम सीमा निर्धारण के कार्य पर जोर दिया गया। सीमा निर्धारण के भी दो पहलू हैं— (1) वर्तमान भूमिपतिवों के पास जो जमीन है उसकी अधिकतम सीमा का निर्धारण और (2) भविष्य में जो जमीन ली जाये उसकी सीमा का निर्धारण। अधिकतम सीमा निर्धारण में भी भूमि की उर्वरा शक्ति, सिंचाई के साधन आदि बातों का प्रभाव पड़ता है। देश के लगभग सभी राज्यों में सीमा निर्धारण के कानून लागू कर दिये गये। राजस्थान में यह सीमा (साथे तथा वर्तमान दोनों ही जोतों पर) 25 से 336 स्क्वैड्स एकड़\* निर्धारित की गई।

सहकारी कृषि (Co-operative farming)—भूमि में उप-विभाजन एवं प्रपखण्डन की समस्या से बचने के लिए सहकारी कृषि भी अपनाई जा सकती है। छोटी जोतों की वर्तमान समस्या का निराकरण तो चकबन्दी से हो जाएगा, किन्तु भविष्य में विभाजन को रोकने का प्रभावशाली तरीका केवल सहकारी कृषि ही है। इस पद्धति के अन्तर्गत छोटे-छोटे किसान मिलकर सहकारिता के सिद्धान्तों पर कृषि सहकारी समितियाँ (Better Farming Societies) बनाकर ज़िम्मेदारियों को प्रणाली खाद, बीज आदि मेवाएँ दी जाती हैं। द्वितीय योजना में सहकारी कृषि के विनाश पर अधिक बल दिया गया। भारत में पाइलट योजनाओं (Pilot projects) के अन्तर्गत तृतीय योजना के अन्त तक 2,749 सहकारी कृषि समितियों का गठन किया जा चुका था। इनके अतिरिक्त 2,752 सहकारी कृषि समितियाँ पाइलट योजनाओं के क्षेत्र के बाहर

बनाई गई। तृतीय योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा साठ फीस भूमि का वितरण करने में सहकारी कृषि समितियों की प्राथमिकता दी गई। जून 1967 में सहकारी कृषि समितियों की संख्या 7,866 थी।\*

इस प्रकार हम देखते हैं कि उप-विभाजन एवं अपखण्डन कृषि के लिए बहुत हानिकारक है। इसे दूर करने के प्रयत्नों से आर्थिक जोत के निर्माण को बल मिलेगा। प्रसन्नता की बात है सरकार सहकारी कृषि, शकबन्दी एवं अधिनियमों के आधार पर समस्या के हल के लिए आगरुक है।

### सारांश

कृषि के उत्थान के लिए आर्थिक जोतों का निर्माण आवश्यक है।

**आर्थिक जोत**—वह जोत है जिस पर एक परिवार सामान्य जीवन स्तर के लिए साधन जुटा सके।

**बुनियादी जोत**—वह जोत है जिसके बिना कोई भी कृषक न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आय प्राप्त नहीं कर सकता।

**आदर्श जोत**—वह अधिकतम जोत है जिस पर समायें गए साधनों की तुलना में अतिरिक्त लाभ मिलता है।

**अनार्थिक जोत**—वह है जिसके कारण कृषि अलाम्बक व्यवसाय बनी हुई है। भूमि का उप-विभाजन व अपखण्डन ही इसके लिए उत्तरदायी हैं।

उपविभाजन व अपखण्डन के कारण—

(1) जनसंख्या की वृद्धि, (2) उत्तराधिकार के नियम, (3) संयुक्त परिवार प्रथा का अन्त, (4) कुटीर उद्योगों का ह्रास, (5) भूमि के प्रति मोह समा (6) भूमि को साफ़े पर देने की प्रथा।

हानियाँ—उत्पादन लागत में वृद्धि, कृषि सुधारों का सम्भव न होना, बाढ़-पेड़ की कठिनाई, पारिस्थिक सेतो प्रसम्भन, निगरानी की कठिनाई, समय, व्यय और धन का घपघराव, झगड़े और मुकदमेबाजी, पूंजी मिलने में कठिनाई, गड़बड़ी सेतो में कठिनाई, सेतो का समुविधा-जनक तथा भूमि का बेकार होना ।

लाभ—किसान की आर्थिक संकट से रक्षा, भूमि की विनिष्पत्ता का लाभ, पूंजीवादी कृषि का न पनप सकना ।

समस्या का उपचार—भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी, उत्तरा-धिकार के नियमों में परिवर्तन, चक्रवर्दी, वानून द्वारा आर्थिक जोतों का निर्माण, जोतों का सीमा निर्धारण तथा सहकारी कृषि ।

सरकार आर्थिक जोतों के निर्माण के प्रति आवश्यक है ।

## प्रश्न

1. भारतीय अर्थ व्यवस्था में कृषि जोतों के उपविभाजन व अपसंजन के कारणों का उल्लेख कीजिये । इसके दोषों का वर्णन करते हुए उपायों पर प्रकाश डालिए ।
2. भूमि के उपविभाजन एवं अपसंजन के कारण बताते हुए समस्या को सुलझाने के उपायों का विवेचन कीजिये ।
3. उप-विभाजन एवं अपसंजन के दोषों को दूर करने के लिए भारत में दिए गये प्रयासों का उल्लेख कीजिये ।
4. टिप्पणियाँ लिखिए—(घ) चक्रवर्दी (Consolidation) (राज. बोर्ड, हा. से. 1964) (ब) आर्थिक जोत (Economic holdings), (ग) सीमा (Ceiling) निर्धारण ।
5. "छोटी आर्थिक जोतें ही कृषि विकास में जाने वाली अनेक कठिनाइयों की जड़ हैं ।" इस उक्ति की व्याख्या कीजिए ।

(राज. बोर्ड, हा. से., 1961 तथा 1964)



6. धूमि में वा-विमानन व विषयन का क्या अर्थ है ? हमारे वि-  
षयों को समझाये । (राज. बोर्ड, हा. से., 1966)
7. संश्लेष टिप्पणियाँ लिखिए—  
(अ) धूमि जोड़ों की बहवन्दी (राज. बोर्ड, हा. से., 1968)  
(ब) सहकारी धूमि ।
8. भारत में धूमि के अविमानन तथा अविमानन के कारणों का  
विशेषण कीजिये । (राज. बोर्ड, हा. से., 1969)

---

## अध्याय 4 कृषि के साधन ।

### AGRICULTURAL INPUTS—I

“मेरे अनुमान से पुराना हल पिछले 2000 या 3000 वर्षों से काम का रहा है । मुझे साबुत नहीं कि कितने समय से यह प्रयुक्त हुआ है ।” यदि आप बहुत धन्य हल साते हैं तो ईन इतने बलवान नहीं कि वे उसे लीच सकें ।—लेकिन ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल निकाला जा सकता है ।”

—धी अवाहर साल मेहक

भारत की कुल जनसंख्या का 69.8 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है । यह हमारी जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है, और कृषि से राष्ट्रीय आय में बहुत योगदान मिलता है । सन् 1967-68 में कृषि से राष्ट्रीय आय का 53.1 प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ । किन्तु कृषि सामर्थ्यक व्यवसाय नहीं है । इन्हीं बड़ी जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी होने पर ली हुई बिदेसी से अनाज आयात बढ़ता है । विश्व के अन्य देशों की अन्य व्यवस्थाओं के अध्ययन से पता चलेगा कि अमेरिका में केवल 13 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में 12 प्रतिशत, कनाडा में 15 प्रतिशत और स्कॉटलैंड में 25 प्रतिशत, जनसंख्या ही कृषि पर अवलम्बित है फिर भी वे अन्य व्यवस्थाएं स्थापन करी हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद भी वही से लाखों टन अनाज दूसरे देशों को भेज दिया जाता है । इसके अतिरिक्त भारत की तुलना में विश्व के अनेक देशों का प्रति एकड़ औसत उत्पादन कहीं अधिक है । इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि उन्नत व्यवस्था से नहीं है । तीसरे अध्याय में हमने कृषि के पिछड़ेपन के कारणों का विस्तार से अध्ययन किया था । इन

कारणों में से अधिकांश ऐसे हैं जो कृषि के साधनों (Agricultural Inputs) से सम्बन्ध रखते हैं। इस अध्याय में हम उन साधनों का विस्तृत अध्ययन करना चाहेगे जो कृषि की उपज को प्रभावित करते हैं।

**कृषि के साधनों का महत्व**—पर्याप्त कृषि के लिए कृषि-साधनों का महत्व अधिक है। जिसे अर्थ व्यवस्था में कृषि साधन उन्नत अवस्था में है उस अर्थ व्यवस्था की विकास की दर (Rate of growth) संतोषजनक होती है। वहाँ प्रति एकड़ घात उत्पत्ति अधिक होती है और उत्पादन की लागत (Cost of production) काफी कम होती है। कृषि साधनों से सम्पन्न देशों में कृषि लाभदायक (Profitable) व्यवसाय होता है और वह राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योग देती है। इसके विपरीत जहाँ ये साधन पिछड़ी हुई अवस्था में होते हैं वहाँ कृषि लाभदायक व्यवसाय बन जाता है।

भारतवर्ष में कृषि विकास की अत्यन्त आवश्यकता है। कृषि विकास के बिना औद्योगिक विकास की गति को तीव्र नहीं बनाया जा सकता। इन सब दृष्टियों से कृषि साधनों का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत आवश्यक है।

**कृषि के साधन**—भारतीय कृषि साधनों के अन्तर्गत उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि उपकरण, पशु, सिंचाई की सुविधाएँ तथा साख सुविधाएँ सम्मिलित की जाती हैं। इसका कृषि विकास से बहुत गहरा सम्बन्ध है। इस अध्याय में हम उन्नत बीज (Improved Seed), उर्वरक (Fertilizers), कृषि उपकरण (Agricultural implements) तथा पशुओं (Animals) के सम्बन्ध में विचार करेंगे। सिंचाई एवं कृषि साख का अध्ययन आगामी दो अध्यायों में किया जाएगा।

**उन्नत बीज (Improved Seed)**—उत्तम बीजों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना कृषि विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यह कृषि सुधार की विधियों में सबसे सरल एवं कम खर्च वाली है। उन्नत

बीजों को अपनाने से कृषि पैदावार में 10 से 15 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। उत्तम बीजों के चुनाव, शुकर बीजों (Hybrid Seeds) के प्रयोग एवं उन बीजों के प्रयोग करने से सम्बन्धित जानकारी का प्रसार कृषि विकास में महत्वपूर्ण योग देता है।

भारतीय कृषक उन्नत बीजों का महत्व जानता है। किन्तु अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह अपने ही संवर्धित बीजों का प्रयोग कर लेता है जो प्रायः घटिया किस्म के होते हैं। जब तक अधिकांश किसान स्थानीय (Local) किस्म के बीजों का ही प्रयोग करता रहा है। ये बीज न अच्छी प्रकार से साफ हो किये जाते हैं और न इनका उचित संग्रह ही किया जाता है जिससे इनकी किस्म और घटिया हो जाती है। बीज बीने के समय कृषक के पास अच्छा बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं होता और वह साहूकार से घटिया बीज ही उधार पर खरीदने को बाध्य हो जाता है।

विछले कुछ वर्षों से सुधरे हुए बीजों के वितरण एवं गुणन (Multiplication) के कार्य में कृषि विभाग एवं अन्य राजकीय संगठन कार्य कर रहे हैं। किन्तु बीज देने की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होने के कारण अधिकांश कृषक इसमें सार नहीं उठा सके हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बीज गुणन एवं वितरण का व्यवस्थित कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस अवधि में 3,600 बीज-गुणन केन्द्र (Seed Multiplication Centres) खोले गये। तृतीय योजना के अन्त तक साधारणतः के उन्नत बीजों का प्रयोग 4.86 करोड़ हेक्टर क्षेत्रफल में होने लगा था। चतुर्थ योजना में यह क्षेत्रफल बढ़कर 9.75 करोड़ हेक्टर हो जाने का लक्ष्य है। इस योजना में चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा तथा मक्का के उन्नत बीजों का प्रयोग बढ़ाया जाएगा।

उन्नत बीजों का प्रयोग बढ़ाने के लिए निम्नांकित उपाय काम में लाये जाने चाहिये—

1. बीज-गुणन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाए ।

2. उत्तम बीजों के प्रयोग सम्बन्धी जानकारी कृषकों को दी जानी चाहिए ।

3. अच्छे बीज रियासती दर पर कृषकों को दिये जाने चाहिए ।

4. उत्तम बीजों के प्रदर्शन फार्म (Demonstration Farms) स्थापित दिये जाने चाहिए ।

5. अच्छे बीजों को सप्रह करने के लिए गोदामों (Godowns) की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

6. प्रत्येक विकास ब्लॉक एवं जिन्हा स्तर पर बीज भण्डार स्थापित किये जाने चाहिए जो फसल पैदा होने तक कृषकों को ये बीज उपचार दे सकें ।

7. बीजों के घ्रेणीकरण (Gradation), प्रमाणीकरण (Standardisation), मादि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

8. केन्द्रीय स्तर पर गठित "राष्ट्रीय बीज निगम" की भाँति राज्य एवम् जिला स्तर पर ऐसे संगठन स्थापित दिये जाने चाहिए ।

9. विभिन्न राज्यों में भारतीय काँटन मिल फेडरेशन द्वारा संचालित कपास विकास योजना (Cotton Development Project) की ही भाँति अन्य निजी संगठनों द्वारा उत्तम बीजों के प्रसार की योजनाएँ चलायी जानी चाहिए ।

### खाद एवं उर्वरक (Manures and Fertilizers)—

भारतवर्ष की मिट्टियों में अनेक उर्वर तत्त्वों का अभाव हो गया जिसकी पूर्ति खाद व उर्वरकों से की जा सकती है । गोबर की खाद, कम्पोस्ट की खाद, मादि कुछ परम्परागत खादें हैं जिनका विस्तृत

प्रयोग अनेक कारणों से सम्भव नहीं हैं। इसलिए रासायनिक उर्वरकों (Chemical Fertilizers) का उपयोग करना अत्यन्त आवश्यक है। यहाँ हम खाद एवं उर्वरकों की कुछ मुख्य विशेषताएँ एवं उनकी वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में विचार करेंगे—

(अ) गोबर की खाद (Cow dung manure or Farm Yard manure)—घास-पौधों से प्राप्त होने वाली गोबर की खाद अन्य प्रकार के खादों की तुलना में अत्यधिक नाइट्रोजन रखती है। कमल की पैदावार में वृद्धि के लिए आवश्यक सभी तत्व इसमें मौजूद होते हैं। लगभग सिर्फ 100 वर्षों में विभिन्न विद्वानों, आयोगों व समितियों ने इसके दुरुपयोग की बर्बादी की है। अधिकांश गोबर का प्रयोग घरों में ईंधन के रूप में जलाने के लिए कर लिया जाता है क्योंकि गाँवों में जलाने की लान्दी की कमी है। योजना आयोग के प्रतिबन्ध जलाये जाने वाले गोबर की मात्रा 400 मिलियन टन मानी है। इसके अनिवार्य तौर पर गोबर खाद बनाने के लिए काम में लाया जाता है उपर्युक्त सच करने का तरीका भी दीव्यपूर्ण है। इसलिए कुल गोबर का लगभग 20 प्रतिशत भाग नष्ट हो जाता है।

गोबर की खाद का पूर्ण सदुपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि (1) गाँवों के नजदीक भीम जलाने वाले कुँड़े, ईंधन प्राप्त करने लिए लगाए जाने चाहिये। (2) किसानों को खाद सुगन्धित रखने के लिए गड्ढे (Manure pits) बनाने और पशुओं के बाखं जाने वाले भूत व गोबर को संचय करने के तरीकों की जानकारी दी जानी चाहिये।

(ब) कम्पोस्ट द्वारा खाद—घास एवं जड़ों के कूड़े-कचरा, काग, जाली वगैरह कर यह खाद संसार की जाती है। जड़ों की जानिजों के पानी से भी खाद संसार की जाती है। भारत में इन प्रकार की खाद

का उत्पादन बढ़ रहा है। सन् 1965-66 में सामुदायिक विज्ञान गरीबों में 54,13,400 कम्पोस्ट के गड्ढे (Compost pits) भोड़े गये। सन् 1968-69 में ग्रामीण कम्पोस्ट खाद का उत्पादन 14.8 करोड़ टन होने का अनुमान है।\*

भारत में इन प्रकार के खाद के उत्पादन में अधिक प्रगति नहीं हो पायी क्योंकि उचित प्रगतिवित्त कर्मचारियों का अभाव है। इसके प्रतिरिक्त जनता के सहयोग की कमी, किसानों द्वारा इसके प्रति दुष्प्रभाव की भावना, यातायात की कठिनाई आदि कारकों से भी कम्पोस्ट की खाद बनाने के कार्य में अधिक प्रगति नहीं हुई। इन सब बातों को दूर करने के प्रयत्न कर इस खाद के निर्माण की बढ़ाया जाना चाहिये।

(स) दधिर घृत खाद (Manure from Animal waste)—कसाई खानों में व्यर्थ जाने वाला पशुओं का दधिर, पशुओं की हड्डियाँ, बाल, आदि का प्रयोग भी खाद के रूप में किया जा सकता है। हड्डियों में फॉस्फेट होती है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करती है। मछली के बचे हुए पदार्थों का उपयोग भी खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। किन्तु भारतवर्ष में ऐसे खादों को बनाने एवं प्रयोग करने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके मूल में परम्परागत धार्मिक विचार हैं जिनके कारण वे उर्वरता के इन उपयोगी साधनों का प्रयोग नहीं करते।

(द) हरी खाद (Green manure)—भारत में हरी खाद का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन काल से ही होता आया है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने हेतु सर्वोत्तम है। इसमें सन्, चना, ज्वार, आदि सेत में बोए जाते हैं और जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें हारक दिया जाता है। ऐसा करने से मिट्टी में नाइट्रोजन व अन्य तत्व प्राप्त हो जाते हैं जो कृषि पैदावार में भारी वृद्धि कर देते हैं। भारत में इसका अधिक प्रयोग नहीं हो पाता। सन् 1968-69 में हरी खाद का क्षेत्र 1.03 करोड़ हेक्टर हो जाने का अनुमान है।

(४) रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilizers)—ऊपर बनावे गये विभिन्न खाद भारत की कृषि आवश्यकताओं की रासायनिक पूर्ति हो कर पाते हैं। अतः पिछले 15 वर्षों से हमारे यहाँ रासायनिक खाद का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अब इन उर्वरकों की पहलू से किसान मुक्तिप्राप्त हैं। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग सन् 1968-69 में 14 लाख टन का जो सन् 1969-70 में बढ़कर 20 लाख टन हो जाएगा। फास्फोरस युक्त उर्वरक का उपयोग सन् 1968-69 में 24 लाख टन हुआ।<sup>१</sup> किन्तु इसी मौन इस मात्रा में कहीं अधिक है। चौथी योजना में पोटाश का उर्वरक के रूप में प्रयोग भी बढ़ाया जाएगा।

उर्वरकों का उत्पादन मुख्य रूप से तिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, मीनम, मेवेली, टांभे तथा राऊरकेला के कारखानों में होता है। हमारे देश में आवश्यकता से कम उत्पादन होने के कारण उर्वरकों का आयात करना पड़ता है। इनको कीमती भी प्रचिक है। इन कृषि उर्वरकों के प्रयोगों के सम्बन्ध में कुछ जातिपां अब भी फैली हुई हैं। अतः इनके प्रयोग की सही विधि का ज्ञान कृषकों को कराया जाना चाहिये। उर्वरकों का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के हर संभव प्रयत्न लिये जाने चाहिये ताकि इसकी कीमतें भी कम हो सकें सरकारी संस्था 'भारतीय खाद निगम' (Fertilizer Corporation of India) के कारखाने में नये कारखाने बनाये जायेंगे। उर्वरक विनरल जीव समिति ने उर्वरकों की विनरल व्यवस्था में सुधार लाने के निश्चय में कमी करने व उत्तमता पर ध्यान देने की सिफारिश की है। किसानों को उर्वरक खरीदने के लिये ऋण भी दिये जाने चाहिये।

उत्पादक कार्यों के अलावा निम्नलिखित एवम् खली की खाद मानवीय कार्य पशुओं में निम्न खाद, आदि भी प्रयोग की जाती है किन्तु इनका खेद सामान्य सोमिन है।



भारत में खाद के पधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता है जिससे कृषि की प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि लाई जा सके। कहा जाता है—  
‘खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कुडा रेत।’

### कृषि उपकरण (Agricultural Implements)

भारत में अब तक भी प्राचीन काल से चले आ रहे यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग होता है। कृषि के विद्युद्देयन के लिये ये उपकरण भी उत्तरदायी हैं। भारतीय कृषि औजारों की बर्ण करते हुए श्री डार्लिंग (Darling) ने कहा है—“हल भूमि को केवल कुँद देना है; हाथ की दस्तानों जो कृषक की अपेक्षा बालक के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है; पुराने इनकी टोकरी से हवा द्वारा मूँसे को चलान किया जाता है और गन्नास। जिसके प्रयोग से बहुत सा भाग नष्ट हो जाता है, आज भी अपने प्राचीन विष्णु अविकरमयीय जार्यों पर चले हुए हैं।”

इन सब बातों से कृषि औजारों का विद्युद्दायक प्रकट होना है पर-  
न्तु प्राचीन औजारों के स्थान पर सुधरे हुए औजारों की प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि में कृषि की वैज्ञानिक एवं सामुदायिक बनाने की दृष्टि से औजारों में सुधार लाने की आवश्यकता है। कृषक इनका साधनहीन है कि वह स्वयं सभी औजार नहीं खरीद सकता। इसलिए सहकारी समितियों द्वारा सामुदायिक रूप से ग्राम स्तर उन्हें बारी-बारी से काम से लाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। नये औजारों के साथ-साथ कृषि की पद्धति में परिवर्तन लाने आवश्यक है। बीपी योजना से शिक्षा स्तर पर कृषि औजार केंद्र (Agricultural Implements Centre) स्थापित किए जाने की व्यवस्था है। सुधरे हुए औजारों से सम्बन्धित प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी।

### पशु (Animals)—

हमारे देश की खेती व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि “भारत बैलदारी दुन में रह रहा है।” यह कथन हमारी कृषि के विद्युद्देयन के

कारे में तो बताता ही है साथ ही यह भी स्पष्ट होना है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में बैल का बहुत अधिक महत्व है। बैल के अतिरिक्त घोड़ा, ऊँट, बकरी, भेड़, गाय आदि कृषक के लिए बहुत उपयोगी हैं। पशु-पालन व्यवसाय, यातायात, सिंचाई, जुताई, बुवाई आदि में पशु शक्ति का बहुत महत्व है।

भारत में पशुओं की संख्या अत्यधिक है। यहाँ प्रति 40.3 हेक्टर (100 एकड़) जोती-बोई भूमि के पीछे 97 पशु हैं। सन् 1961 की पशु गणना के अनुसार देश में कुल पशुओं की



भारत के पशु

संख्या 33.6 करोड़ थी। हमारी सामीप्य अर्थ-व्यवस्था में पशुओं का महत्व भी एम. एल. बालिग के शब्दों से स्पष्ट प्रकट होता है—“पशुओं के बिना किसान के खेत नहीं जोते जा सकते, उनके खतिहान खाली पड़े रहते हैं, मोर लागे बीजे में स्वाद अमृग रह जाता है, क्योंकि शाकाहारी देश में घी, दूध और भस्मन त मिलने से अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है ?”

भारतीय पशु दुर्बल एवं अकुशल हैं। इसके मुख्य कारण हैं—“कारे की बर्मी, हल्की नस्ल, पशु रखने के दोषपूर्ण ढंग, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, बीमारियाँ तथा पशुओं के स्वास्थ्य की अवहेलना। जयार घोर बेरो के शब्दों में, “भारत में पशुओं से केवल अधिक काम ही नहीं लिया जाता, इसके साथ-साथ उन्हें घर पेद भोजन भी नहीं दिया जाता। यहाँ तो बर्दाश्त ही कोई किसान अपने पशु को स्वस्थ

रखने का प्रयास करता दिखाई देता है।" किन्तु सब पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा पशु-धन उत्पन्न करने के कई प्रयत्न हो रहे हैं। वनस्पति योजना में पशु-पालन के लिए 91७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

पशुधन की हीन दशा में सुधार लाने के उपायों में धाने की कमी को दूर करना, नरसु सुधार के कार्यक्रमों को संपन्नाना, पशुधन के रोगों को रोकथाम करना आदि उल्लेखनीय हैं।

उक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि भारत के कृषि-साधनों को उत्पन्न करने की पर्याप्त आवश्यकता है। कृषि साधनों की उन्नति के बिना कृषि विकास सम्भव नहीं है।

### सारांश

भारत की कुल जनसंख्या का 69.8 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। कृषि हमारी जनसंख्या के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है। तथापि राष्ट्रीय आय में भी बहुत योगदान मिलता है। किन्तु हमारी कृषि पर्याप्त विद्युत् की आवश्यकता में है।

वि के साधनों का महत्व—

विकास की दर संतोषजनक, औसत उत्पत्ति अधिक, उत्पादन लागत कम, लाभदायक व्यवसाय, राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योग।

वि के साधन

- (1) उन्नत बीज, (2) खाद एवं उर्वरक—(अ) गोबर की खाद, (ब) कम्पोस्ट द्वारा खाद, (ग) खजूर पूर्ण खाद, (द) हरी खाद, (3) रासायनिक उर्वरक। (3) कृषि उपकरण, (4) अच्छे पशु।

संक्षेप में, कृषि विकास के लिए उन्नत कृषि-साधनों की आवश्यकता है।

## प्रश्न

कृषि साधनों का महत्व स्पष्ट कीजिये ।

भारतीय कृषि को उन्नत बनाने के लिए किल-बिल साधनों को उपयोग में लाना चाहिये ?

भारतीय कृषि की उन्नति के सुझाव दीजिये ।

(राज. बोर्ड, हा. से., 1967)

टिप्पणी लिखिये—

(अ) खाद एवं उर्वरक

(ब) उन्नत बीज ।

## अध्याय 5

# कृषि के साधन II

## AGRICULTURAL INPUTS—II

भारतवर्ष में सिंचाई

(IRRIGATION IN INDIA)

“भारत की मिट्टी के लिए पानी जादू का काम करता है।”

डॉ० बाँसकर

“सिंचाई सम्बन्धी बाधों ने जीवन को सुरक्षित बनाया है। इनसे उत्पादन, भूमि के मूल्य एवं राजस्व की वृद्धि हुई है। इसने दुर्भिक्ष सम्बन्धी खय को कम कर दिया है।”

—धीमती नविल

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है कृषि के लिए यह आवश्यक है कि कृषक उत्तम बीज (seeds), खाद (manure) तथा भूमि का अच्छी तरह प्रयोग करें, किन्तु उचित और नियमित रूप से पानी मिले बिना खेती की अच्छी पैदावार नहीं हो सकती। उत्तम पैदावार के लिए पर्याप्त मात्रा में समयानुसार पानी की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में पानी दो प्रकार से प्राप्त होता है—(1) मानसूनी हवाओं द्वारा, जो इस देश में कुछ महीनों में ही चलती हैं, और (2) सिंचाई के साधनों द्वारा। देश की खेती के लिए पानी की कुल आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत भाग इन्हीं मानसूनी हवाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। इन्हीं हवाओं द्वारा देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। पश्चिमी समुद्री तट व बंगाल के पश्चिमी भागों में वर्षा की अधिकता के कारण सिंचाई के साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, परन्तु देश के

अन्य भागों में वर्षों की मात्रा, समय तथा स्थान अनिश्चित है। यदि इन स्थानों में वर्षा समय पर हो जाती है तो पैदावार भी अच्छी होती है अन्यथा नहीं।

### सिंचाई की आवश्यकता (Need of Irrigation)

सन् 1815 में लार्ड हेस्टिंग्स ने भारत के लिए सिंचाई की योजनाओं की बड़ी आवश्यकता प्रकट की थी। सन् 1850 में लार्ड क्लाइवी ने लिखा था, "मैं सर्वत्र देखता हूँ कि इस देश की जमीन में उपजाऊन विरहमान है, निम्नु वह बर्बाद पड़ी है। इन मैदानों को बहुमुख्य क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए देखल जल की आवश्यकता है।" ब्रिटिश सरकार ने सिंचाई के साधनों की उपधि पर बहुत कम ध्यान दिया।

कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिये जल की प्राप्ति की आवश्यकता है। भारत में अपने प्राकृतिक साधनों का अब तक पूरा सदुपयोग नहीं किया है। परिणाम यह है कि करोड़ों व्यक्ति घनेक पातनाओं से ग्रस्त रहते हैं। प्रति वर्ष देश की अनाज (famine) और बाढ़ों (floods) का सामना करना पड़ता है। जो देश आधे दिन प्रकृति के प्रयोगों का प्रामाण्य बने, वह कैसे बन सकता है? प्रकृति की इस शक्ति परमशी (Permanence of force) का एक ही उपाय है और वह है नदियों के जल का उपयोग। जल समुद्र में बँका जाता है या जमीन में गिर जाता है उसका विकास बाँधों द्वारा सदुपयोग करना चाहिये। साथ ही जो नदियाँ मार्ग बदलकर दूसरे प्रायों को कुबोती हैं उनके मार्गों पर नियन्त्रण करना चाहिये।

हमारे देश के लिए सिंचाई की आवश्यकता निम्नान्वित कारणों से स्पष्ट है—

1. वर्षा की अनिश्चितता (uncertainty)—हमारे देश में वर्षा असाध्यिक (unusually) तथा अनिश्चित होती है। कभी अनिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि (draught) और प्रायः इनके कारण देश के कई

स्थानों में दुमिल पड़ जाते हैं। अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हानिकारक हैं। किसान की आय का एक मात्र साधन-कृषि-मण्डल हो जाता है।

### निचाई की आवश्यकता के कारण

1. वर्षा की अनिश्चितता
2. वर्षा का असमान वितरण
3. मर्रा में वर्षा का अभाव
4. कुछ कमलों की अधिक पानी की आवश्यकता
5. बगलों में रक्षा
6. बढ़ती हुई जनसंख्या

2. वर्षा का असमान वितरण (inequitable distribution) भारतवर्ष एक विशाल देश है। यहाँ पर सब जगह वर्षा का वितरण समान नहीं है। कुछ ऐसे स्थान हैं—जैसे बंगाल, पंजाब, हिमालय के दक्षिण ढाल, छत्तीस गढ़ान, मरवाड़ व तापी की घाटी जहाँ पर वर्षा निश्चय एवं समीचीन

माना में होती है। इसके विपरीत ऐसे स्थान भी हैं जैसे, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा तथा दक्षिणी भारत के पठार, जहाँ पर वर्षा अनिश्चित है और कम माना में होती है।

3. मर्रा में वर्षा का अभाव—पश्चिम में कुछ जिलों को छोड़कर जाड़े के दिनों में प्रायः वर्षा का अभाव रहता है। पनः जाड़े की कमी के लिये कृषि साधनों द्वारा निचाई करना अनिवार्य साधन है। निचाई के साधन मिलने पर कुछ मिश्र-मिश्र प्रकार की पनमें पैदा कर सकेगा। सेहू, चना, आदि कमसे जो जाड़े की कमी है, निचाई के साधनों के बिना नहीं उगाई जा सकती।

4. कुछ कमलों की अधिक पानी की आवश्यकता होती है—जन्मा चावल, पटसन (Jute), आदि कमलों की अत्यधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। दक्षिण-पश्चिम मानसून का पानी इन्हें ही पड़ता है। पनः के कमसे जिसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, कृषि निचाई साधनों के बिना नहीं उगाई जा सकती।

5. अकालों से रक्षा—सिंचाई के साधन देश में सकाल पड़ने को रोक कर हमारी रक्षा करते हैं ।

6. बढ़ती हुई जनसंख्या—देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को पान्नों और अन्य प्रकार की वस्तुओं की बढ़ती माँग की पूर्ति करने लिए भी सिंचाई के साधन आवश्यक हैं ।

अतः भारत जैसे विशाल देश की उपजाऊ भूमि का सिंचाई के बिना लाभ उठाना असम्भव है । वर्षा पर निर्भरता बहुत हानिकारक है । देश में पानी हो सब कुछ है ।

भारत में सिंचाई की सुविधाएँ (Irrigation facilities in India)

1. भारत कृषि-प्रधान देश है और यहाँ की 69.8 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है । कृषि की उत्तम पैदावार के लिये सुव्यवस्थित सिंचाई के साधनों का होना अत्यन्त आवश्यक है और इन साधनों की सुविधाएँ देश की प्राप्ति हैं ।

2. सिंचाई के साधनों के लिये हमारे देश में प्रकृति ने बड़ी सहायता प्रदान की है । देश की भूमि का अधिकांश भाग ऐसा है जिसमें पानी का जल सन्दरभला जाता है । आवश्यकता पड़ने पर वह जल स्रोतों द्वारा निकाला जा सकता है । हमारे देश की मिट्टी नरम होने के कारण बूँद छोड़ने ■ लिए उपयुक्त है ।

3. भारतवर्ष के उत्तरी मैदान में नदियों का जाल सा बिछा हुआ है और साथ ही यह मैदान समतल और बालू होने के कारण नहरें खनने के योग्य भी है । भूमि के नरम होने के कारण खोदने में समुविधा मिलती होती ।

4. उत्तरी भारत की प्रायः सभी नदियाँ हिमालय की हिमश्रृङ्खला की चोटियों से निकलती हैं, जिन सदैव जल से पूर्ण रहती हैं । वर्षा के दिनों में जब वर्षा पिघलती है तो इनसे पानी निरन्तर बढ़ता है और वे भूमि में नहीं पड़ती । नदियों के जलपूर्ण रहने के कारण इनसे



निकाली जाने वाली नहरों को भी पानी मिलता रहता है और इन नहरों का पानी आवश्यकतानुसार सिंचाई के लिये उपयोग किया जाता है।

5. देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर दक्षिणी भाग में, वर्षा का पानी तात्कालिक बनाकर रोका जा सकता है।

6. देश के कई भागों में कुछ बनाने की बहुत सम्भावनाएँ हैं।

### सिंचाई से लाभ (Advantages of Irrigation)

भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश में, जहाँ 69.8 प्रतिशत जनता खेती

#### सिंचाई से लाभ

1. अकाल से बचाव
2. निरन्तर खेती
3. प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि
4. विस्तृत खेती सम्भव
5. जनसंख्या का ठीक बंटवारा
6. विशेष फसलों का उत्पादन
7. किसानों की आय में वृद्धि
8. आवागमन के साधनों में वृद्धि
9. सरकार की आय में वृद्धि
10. आंतरिक व विदेशी व्यापार में वृद्धि
11. देश के उद्योग धर्मों को प्रोत्साहन
12. गहरी खेती-कृषि भाग में वृद्धि

उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

3. उपज में वृद्धि—सिंचाई साधनों द्वारा आवश्यकतानुसार पानी मिलने से भी भूमि की प्रति हेक्टर उपज में वृद्धि होती है, और साथ ही गुण उत्तम बढ़ती है।

पर निर्भर है। और जहाँ खेती की सफलता का प्रभाव व्यापार, उद्योग वाणिज्य तथा सारे देश के आर्थिक जीवन पर पड़ता है। सिंचाई के साधनों का बड़ा भारी महत्व है। सिंचाई के मुख्य लाभ निम्न हैं—

1. अकाल से बचाव—सिंचाई अकाल से बचने का अनुपम साधन है। सिंचाई साधन होने से भारतीय कृषि वर्षा का जुमा नहीं रहेगी।

2. निरन्तर खेती (Continuous cultivation)—सिंचाई से वर्ष भर निरन्तर खेती का व्यवसाय चलता रहता है और कई प्रकार की फसलें उत्पन्न कर साथ के

4. विस्तृत, खेती सम्मन (Extensive cultivation)—खेती की भूमि के लिये क्षेत्र में वृद्धि होती है। शुष्क परती और र्वजर (barren) भूमि पानी से खेती के योग्य बन जाती है। इस प्रकार लाखों एकड़ अतिरिक्त भूमि खेती के प्रयोग में आ गई है और खेती का प्रसार हुआ है।

5. जनसंख्या का सरंचारा—नयी आबादी वाले भागों से सिंचाई की सुविधाओं वाले नये भागों में मनुष्य जाकर बस जाते हैं, जैसे नहरों के किनारे बस्तियाँ (Canal Colonies) बस गई हैं।

6. विविध फसलों की उपज सम्मन—सिंचाई से चावल, गन्ना, कपास, आदि कीमती फसलें जिनकी अधिक व बार-बार पानी की आवश्यकता होती है, पैदा हो सकती हैं। ये फसलें देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे किसानों की आय बढ़ती है।

7. दृष्टियों की आय—किसानों की आय, बुधहासी, कमशक्ति और रहन-सहन के स्तर में वृद्धि होती है।

8. आवागमन के साधनों में वृद्धि—कुछ नहरें सिंचाई के अतिरिक्त आवागमन के लिये भी उपयुक्त साधन होती हैं, जिनसे माल एवं यात्री सस्ते क्रिया पर इपर-उपर पहुँचाये जा सकते हैं।

9. सरकार की आय में वृद्धि—सिंचाई सुविधाओं से फलस्वरूप परती जमीन विकने से, पानी से, ख़मान से, रेलों के पुलों के बढ़ने से, प्रजा की आय और कर देने की शक्ति बढ़ने आदि से सरकार की आय बढ़ती है। साथ ही अनाज पर किये जाने वाले धर्म की बचत होती है क्योंकि अनाज नहीं पड़ते हैं।

10. व्यापार में वृद्धि—उत्पादन बढ़ने से देश के आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है।

11. उद्योग धर्मों की प्रोत्साहन—कच्चा श्रुद्ध अधिक और सस्ता मिलने से तथा वस्तुओं का उपयोग व माँग बढ़ने से उद्योग धर्म पनपते हैं और देश की उन्नति होती है ।

12. गहरी खेती—सिचाई से गहरी (Intensive) खेती संभव होती है जिससे कृषि उत्पादन और आय बढ़ती है ।

### हानियाँ (Disadvantages)

1. जल रसावन (Water logging)—नहरों के बनने से कभी-कभी भूमि में पानी की अधिकता हो जाती है जिससे कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होने लगती हैं । इनके कारण उपज की मात्रा और किस्म को हानि होती है ।

#### सिचाई से हानियाँ

1. पानी की अधिकता
2. भूमि क्षार
3. कीचड़, दल-दल, रोग
4. पानी वितरण समस्या
5. जन-धन की हानि

2. भूमि बेकार होना—पानी की अधिकता से कालान्तर में भूमि बेकार हो जाती है । भूमि पर क्षार (salt effervescence) फैल जाता है और पौधे नहीं पनप सकते । पंजाब में इस कारण से

हजारों हेक्टर उपजाऊ भूमि खेती के अयोग्य हो गई है ।

3. बीमारियाँ—नहरों के आस-पास कीचड़ और दल-दल रहने से मलेरिया व अन्य संक्रामक बीमारियों के कीड़े उत्पन्न होकर बीमारियाँ फैलना बहुधा पाया जाता है ।

4. नहरों के पानी की किसानों में वितरण करने की समस्या—बहुत सा पानी बेकार नष्ट होता है और पानी के बँटवारे में लिये किसानों में ईर्ष्या-द्वेष और झगड़े होते हैं ।

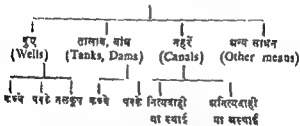
5. प्राकृतिक हानि—कभी कभी नहरें या तालाब टूटने से जन धन की क्षति हो जाती है ।

सिंचाई के अनगिनत साधन हैं। सिंचाई की व्यवस्था घोर साधनों से भारतीय कृषि को निश्चित, अच्छा और सफल बनाने में बहुत सहायता दी है। भूमि को उपजाऊ बनाकर और उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि की उत्पत्ति को प्रोत्साहन देकर देश में सम्पन्नता बढ़ाने में सहायता दी है। सिंचाई की हानियों का आसानी से निवारण हो सकता है। सारे देश में सिंचाई के विविध साधनों को खूब बढ़ाना चाहिये, ये देश के हित में हैं।

### सिंचाई के साधन (Means of Irrigation)

देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक स्थिति का कारण अलग-अलग प्रकार के साधन पाये जाते हैं। मुख्य साधन निम्न हैं—

#### कृत्रिम सिंचाई के साधन (Artificial Means of Irrigation)



कुएँ (wells) — भारतवर्ष के बहुत से भागों में कुओं द्वारा सिंचाई

सिंचाई के साधन

1. कुएँ (Wells)
2. तालाब (Tanks)
3. नहरें (Canals)
4. अन्य (Others)

होती है। पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, बंगाल और बिहार का उत्तरी भाग कुओं द्वारा सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। इन कुओं की भूमि में पानी की सतह (water level) ऊँची है और मोड़ने से

## भारत सिंचाई के साधन



बहुतांश पर पानी मिल जाता है। अतः इस प्रकार की भूमि एवं खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहीं-कहीं पर 2-44 मीटर (8 या 10 फीट) खोदने पर ही पानी निकल आता है। इन क्षेत्रों को बनवाने में कृषकों को अधिक ध्यान नहीं करना पड़ता।

वर्ष में कुल लगभग 25 लाख कुएं हैं जिन पर लगभग 100 करोड़ की लागत लगी है। भारत में कुल सिंचित भूमि के क्षेत्रफल पर कुओं से सिंचाई होती है। कुएं प्रायः व्यक्तिगत होते हैं सरकार भी तकाबी (Taccavi) ऋण देकर कुओं के बनाने में सहायता देती है। 'अधिक घन उपजाऊ-समयोत्तम' (Grow More Food Campaign) के अन्तर्गत हजारों कुएं बनवाये गये। सीमांत 2-08 (5 एकड़) भूमि को सींच सकता है और प्रति एकड़ अतिरिक्त (additional) उत्पादन होता है। कुओं के बनवाने के लिए सरकार सहायताएं ऋण देती है। सरकार ने साधारण बसाने के लिए अमेरिका के विशेषज्ञों की राय के अनुसार ट्यूब-वells (tube wells) का निर्माण करा। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार प्रदेश ट्यूब-वells के लिये उपयुक्त बताये गये हैं। इन कुओं को चलाने के लिये पंपों की आवश्यकता है, जिसकी प्राप्ति करने के लिये भारत में योजनाएँ चल रही हैं। सस्ती बिजली से ट्यूब वेल्स निर्माण में विवेका।

तालाब (Tanks)—तालाब प्रायः राज्य सरकार के होते हैं। लगभग 35,000 तालाब हैं और वे सभी यावज के हैं। कई तालाब अत्यन्त प्राचीन काल के बने हुए हैं तथा कुछ पट्टा-घट्टा हैं। इनको साफ करते रहने (desilting) की आवश्यकता है। मैसूर, मद्रास और राजस्थान के उदयपुर विभाग में तालाबों के लिये बनाये गये हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि इन क्षेत्रों में भूमि पचती है तथा पट्टा-घट्टा की बनी हुई है और वहाँ तालाबों से बनाये जा सकते हैं। सिंचने वाले क्षेत्रों में मद्रास सरकार

ने नये तालाबों के निर्माण और पुरानों की मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दिया है। भारत में सिंचित भूमि के लगभग 20% भाग पर तालाब से सिंचाई होती है।

**नहरें (Canals)**—नहरों का निर्माण सर्वे-प्रथम मुगलों के समय काल में हुआ। इन नहरों के द्वारा पानी की कमी किसी हद तक दूर हो गई, किन्तु भारत में नहरों, कुओं तथा तालाबों से सिंचाई के लिये वर्षा काल में ही पानी मिल सकता था और गर्मों के दिनों में प्रायः सूखा पड़ जाता था। अंग्रेजों ने भारतवर्ष में इस प्रकार नहरें बनवाईं जिनमें वर्ष भर पानी बहा रहता है और किसानों को व्यापारकृतानुसार पानी मिल जाता है। सन् 1854 ई० में सबसे पहली नहर गंगा नदी पर बनवाई गई। वर्तमान काल में नहरों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक महारण्ड है, किन्तु नहरें सब स्थानों पर नहीं लोदी जा सकी और न उनको सब जगह बनाने से लाभ हो हो सकता है। नहरों की गोशे के लिये निम्नलिखित बातों की आवश्यकता है।

(1) भूमि समतल तथा समूची होनी चाहिये। खरीली तथा उबड़ खाबड़ भूमि में नहरों की लोदना कठिन है और खप भी अधिक लगता है।

(2) नहरें उन नदियों से निकाली जायें जो सदैव पानी से भरी रहती हों ताकि नहरों को सदा पानी मिलना रहे। बरसाती नहरें गर्मों के दिनों में सूख हो जाती हैं और सिंचाई के काम की नहीं रहती।

(3) जिन भूमि में होकर नहर निकाली जाय वह मझी होनी चाहिये, वरना नहर लोदने का कोई लाभ न होगा।

भारतवर्ष में तीन प्रकार की नहरें मिलती हैं

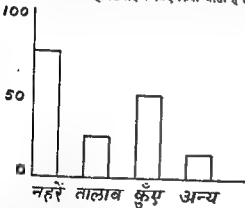
1. स्थाई नहरें (Perennial canals)—ये सदैव जल से भरी रहती हैं। नदियों में बांध बांधकर पानी एकत्रित किया जाता है और पानी फिर नहरों में बहता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हिमालय काश में बहते निचलने के कारण बलपूर्वक रहती हैं और इन नदियों से निकलने वाली नहरों में भी जल बहाव रहता है।

2. बाढ़ाई नहरें (Inundation canals)—इन नहरों में केवल वर्षा में पानी रहता है और वर्ष के शेष महीनों में ये शुष्क रहती हैं। इनके सिंचन के लिए इन्हें बाढ़ाई नहरें भी कहते हैं। इनका वर्षा में ही उपयोग किया जा सकता है।

3. तालाबी नहरें—(Storage Works Canals)—किसी घाटी या तराई में बांध बना कर एक बड़ा तालाब बना दिया जाता है। जमा किया हुआ पानी नहरों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता है। इन्हें गोदामी नहरें या तालाबी नहरें कहलाती हैं। इस प्रकार की नहरें दक्षिण भारत तथा मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं।

जल क्षेत्र (Irrigated Area)—

हमारे देश में लगभग 15.49 करोड़ हेक्टर भूमि कृषि योग्य है— इसमें से लगभग 19 प्रतिशत अर्थात् 2.64 करोड़ हेक्टर भूमि पर सिंचनी होती है। † अनुमान लगाया जाता है कि भारत के जल क्षेत्र लगभग 168 लाख घन मीटर है जिनमें से लगभग 5.55 लाख मीटर का प्रयोग ही सिंचाई के लिए किया जाता है। ‡



India 1969, p. 225

India 1969, p. 275



भारत में सन् 1965-66 में सिंचाई के विभिन्न साधनों से अनुसार सींची गई भूमि का क्षेत्रफल इस प्रकार था—

सिंचाई के साधन	कुल सिंचित भूमि का क्षेत्रफल	
	(करोड़ हेक्टर में)	प्रतिशत
महरें	1.10	41.7
तालाब	0.44	16.6
बुएँ	0.84	31.8
अन्य साधन	0.26	9.9
—योग	2.64	100.0

सब कुल सिंचित क्षेत्रफल 2.64 करोड़ हेक्टर है जो सन् 1950-51 की तुलना में 55 लाख हेक्टर अधिक है। † सन् 1950-51 में सिंचित क्षेत्र 2.08 करोड़ हेक्टर तथा सन् 1955-56 में 2.26 करोड़ हेक्टर था।

बहुमहंगीय नदी घाटी योजनाएँ—

भारत सिंचाई की दृष्टि से संसार के समस्त देशों में आगे है फिर भी सही सिंचाई के साधनों में कृषि की वास्तव्य आवश्यकता है। भारत की नदियों तथा भूमि में बहुत कम निहित है और देखा कहा जाया है कि सभी तरह से प्राकृतिक जल सञ्चार के 7 प्रतिशत मात्र का ही

† *India 1969*, p. 226

‡ *India 1969*, p. 226

हो सका है और शेष या  
 द में व्यर्थ चला जाता है  
 बाढ़ इत्यादि से जनसंख्या  
 की सम्पत्ति को हानि  
 है। इस जलराशि को  
 और विद्युत उत्पादन में  
 जा सकता है। अतः  
 क युग में भारत सरकार  
 में ऐसी योजनाएँ चालू  
 जिनमें (1) सिंचाई की

बहुउद्देशीय योजनाओं के उद्देश्य

1. सिंचाई
2. विद्युत शक्ति का उत्पादन
3. बाढ़ पर नियन्त्रण
4. भूमि का कटाव रोकना
5. मछली उद्योग को पनपाना
6. यातायात के साधनों में वृद्धि
7. स्वास्थ्यवर्द्धक व रमणीक स्थानों का निर्माण

होगी, (2) विद्युत शक्ति का उत्पादन होगा जिससे देश के  
 लम्बे चलेंगे, (3) बाढ़ पर नियन्त्रण होगा, (4) भूमि के कटाव  
 रोका जायगा, जिससे देश की होने वाली जन-जन की शक्ति को  
 जा सकेगा, (5) एकत्रित जल में मछलियों का पालन किया  
 (6) यातायात के साधन बढ़ेंगे और (7) स्वास्थ्यवर्द्धक व  
 स्थानों का निर्माण किया जाएगा। उद्देश्यों की इस बहुसंख्या के  
 उन्हें बहुपक्षी अथवा बहुउद्देशीय योजनाएँ कहते हैं। अतः  
 योजनाओं से अनिप्राय ऐसी योजनाओं से है जिनके द्वारा घनेक  
 की पूर्ति हो सकती है।

भारत की कुछ प्रमुख नदी-घाटी योजनाएँ

(River Valley Projects)

1) दामोदर घाटी योजना—इस घाटी योजना में बिहार व  
 बंगाल के क्षेत्र सम्मिलित हैं। योजना के अन्तर्गत तिलैया,  
 मादपान और पंचेत नामक चार बाँध बनाये गये हैं। योजना  
 अन्तर्गत लगभग 1.9 लाख हेक्टर (4.7 लाख एकड़) भूमि की  
 तथा 1.39 लाख सहस्र किलोवाट बिजली का उत्पादन  
 होगा।

2. **भारत-नागल योजना**—यह भारत की सबसे विहास बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना के अन्तर्गत सतलज नदी पर 222.3 मीटर ऊँचा बांध, नागल बांध, दो बिजली घर, हाइडल चैनल और उस पर दो बिजली घर, नहरों द्वारा सिंचाई की योजना आदि पर कुल 175.6 करोड़ रुपये खर्च होना सबसे पंचाव तथा राजस्थान की प्रतिस्थापित क्षमता की 6,04,000 किलोवाट विद्युत प्राप्त होगी। केवल दाहिने विद्युतगृह के प्रतिरिक्त योजना का लगभग सभी कार्य पूरा हो चुका है।

3. **हीराकुण्ड योजना**—उड़ीसा में महानदी पर बनाए गए इस



बांध की अनुमानित लागत 70-78 करोड़ रुपये हैं। यह विश्व का सबसे लम्बा मुख्य बांध है और इसके विद्युत-गृह में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। 1,23,000 किलोवाट की प्रतिस्थापित क्षमता वाले विद्युत गृह ने रूरकेला इस्पात कारखाना, अस्पृन्धियम फँक्ट्री हीराकुण्ड, सीमेंट फँक्ट्री राजगंगापुर, पेपर मिल बृजराजनगर तथा अन्य अनेक उद्योगों को विद्युत देना प्रारम्भ कर दिया है। बिजली की बढ़ती हुई माँग को

पूरा करने के लिए योजना का दूसरा चरण प्रारम्भ किया गया है जिससे चिपलिया स्थान पर विद्युत निर्माण कार्य किया जाएगा। इस योजना के दूसरे चरण की लागत 14.32 करोड़ रुपये होगी।

(4) तुंगभद्रा योजना—मध्य और मैसूर राज्यों की इस संयुक्त योजना की लागत 60 करोड़ रुपये आंकी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया गया है और 99,000 किलोवाट विद्युत शक्ति पैदा करने वाले तीन विद्युत-गृह बनकर तैयार हो चुके हैं।

(5) रिहन्द बांध योजना—उत्तर प्रदेश की रिहन्द नदी पर एक बांध बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार को भी सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। 3 लाख किलोवाट प्रतिस्थापित क्षमता वाले विद्युत-गृह का निर्माण किया गया है यह योजना अनुसूचित व अन्य छोटे-बड़े उद्योगों को बिजली प्रदान करती है। जल-विद्युत का प्रयोग कृषि और सिंचाई के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश में पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में किया जाएगा। इस योजना की अनुमानित लागत 46.5 करोड़ रुपये है।

(6) कोयना योजना—महाराष्ट्र में बैसमुल बाढ़ी नामक स्थान पर 42.7 करोड़ की लागत का एक बांध बनाया जा रहा है जो विद्युत इकाइयों के द्वारा 2.4 लाख किलोवाट विद्युत का निर्माण करेगा। इसमें से 2.3 लाख किलोवाट बिजली बम्बई व पुना को दी जाएगी। शेष निकटवर्ती भागों में पहुँचाई जाएगी।

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई—

(Irrigation under the Five Year Plans)

कृषि साधनों से सिंचाई करना भारत की एक प्राचीन विशेषता है। प्राचीन समय में कई नहरें और तालाब बनाए गए थे। समय समय पर विभिन्न भाषाओं, कमेटियों भी सिंचाई के विकास की योजनाएं प्रस्तुत करती रही। सन् 1919 के सुधारों में अन्तर्गत सिंचाई एक

प्रांतीय विषय बन गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को विकसित करने के कार्यक्रम तैयार किए।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में केवल 203.5 लाख हेक्टर (515 लाख एकड़) भूमि पर सिंचाई होनी थी। इस योजना के अन्त तक सिंचित भूमि का क्षेत्रफल बढ़कर 226 लाख हेक्टर हो गया। इस योजना काल में सिंचाई के विकास पर 380 करोड़\* रुपये व्यर्ष हुआ। इस योजना काल में सिंचाई की छोटी-बड़ी 170 योजनाएँ (projects) प्रारम्भ की गईं।

द्वितीय योजना काल में सिंचाई की बड़ी व मध्यम योजनाओं† पर 370 करोड़ रुपये खर्च किए गए। छोटी सिंचाई योजनाएँ (Minor Irrigation schemes) दम तेज से बाहर हैं। ये छोटी योजनाएँ सामुदायिक विकास (Community Development) कार्यक्रम का ही एक अंग हैं। इस अवधि में सिंचाई की छोटी बड़ी 195 योजनाएँ प्रारम्भ की गईं। इस योजनाकाल में 55.5 लाख हेक्टर भूमि की अधिक सिंचाई होने लगी। कई नदी घाटी योजनाओं एवं सिंचाई की अन्य योजनाओं पर कार्य पूरा हो गया।‡

तृतीय योजना काल में सिंचाई, बाढ़-नियंत्रण, खादि कार्यक्रमों पर 661 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। योजना काल में 95 नई मध्यम योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया। इस योजना काल में सिंचाई क्षमि (Irrigation potential) का लगभग

\* Third Five Year Plan—Final Draft, p. 382

† बिन सिंचाई योजनाओं की लागत 5 करोड़ रुपये या अधिक होती है। ये बड़ी योजना (Major), तथा दम काल रुपये और पाँच करोड़ रुपये के बीच की योजनाएँ मध्यम योजनाएँ (Medium Schemes) कहा जाती हैं।

‡ प्रारम्भ की मुख्य नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार के संस्करणों 1971 की पुस्तक में बड़ बूके हैं।

उपयोग किए जाने की व्यवस्था थी। इस प्रकार कुल सिंचित क्षेत्र बढ़ कर 362 लाख हेक्टर हो जाने का लक्ष्य था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों पर 963.8 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था रखी गई है।\*

### राजस्थान में सिंचाई (Irrigation in Rajasthan)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय निम्नवाही केवल एक नहर—गगननहर (बीकानेर में) थी जिसके द्वारा प्रतिवर्ष 6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती थी। राजस्थान के उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर है। इसलिए यहाँ सिंचाई का बहुत महत्व है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में राज्य में सिंचाई के विकास हेतु 754 लाख रुपये खर्च किये गये। इस योजना में 96 मध्यम परियोजनाओं पर कार्य पूरा कर लिया गया।

द्वितीय योजना में सिंचाई विकास पर 1972 लाख रुपये खर्च किये गये और राज्य में सिंचित भूमि का क्षेत्र 413.8 हजार एकड़ भूमि\*\* हो गया जबकि 1955-56 में केवल 56 हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई होती थी।

तृतीय योजना की समाप्ति तक छोटी सिंचाई योजनाओं 170 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई। चतुर्थ योजना काल में सिंचाई विभाग ने राज्य में 3 करोड़ रुपये की लागत के कार्य करने का प्रस्ताव किया है।

● Aspect of the Fourth Five Year Plan, Plan in outline, p. 5

●● प्रगतिशील राजस्थान : सिंचाई, फरवरी 1966, जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान; पृ० 8

## राजस्थान की मुख्य योजनाएं

**चम्बल घाटी योजना**—इस योजना के अनुसार विद्युत उत्पादन केन्द्रों सहित तीन बांधों और एक पाले ( सिंचाई बांध ) का निर्माण किया जा रहा है। साथ में आवश्यक नहरों का निर्माण हो रहा है। राजस्थान-मध्य प्रदेश सीमा पर चम्बल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है जो कोटा से दक्षिण में 64.25 कि० मी० (40 मील) दूर है। दूसरा बांध "राणा प्रताप सागर बांध" प्रथम बांध से 32.2 कि० मी० (20 मील) नीचे राजस्थान के एक ग्राम रावत मट्टा के समीप बनाया जा रहा है। तीसरा बांध "कोटा बांध" कोटा से लगभग 16.1 कि० मी० (10 मील) दूर है। इनके अतिरिक्त कोटा नगर ॥ 9.65 कि० मी० (6 मील) की दूरी पर "कोटा बैरेज" बनाया गया है, जिससे दो नहरें निकाली गई हैं। योजना के कलस्वरूप 4 43 लाख हेक्टर ( 11 लाख एकड़) भूमि की सिंचाई होगी और 2 लाख सहस्र किलोवाट बिजली का उत्पादन सम्भव होगा जिससे कोटा, सादेरी, जयपुर, भजमेर आदि क्षेत्रों को लाभ पहुँचेगा। योजना पूर्ण होने पर लगभग 4.825 लाख मी० इन अतिरिक्त अन्न उत्पादन होगा और कृषि का रूप ही बदल जायगा। योजना के प्रथम चरण पर लगभग 63.59 करोड़ तथा द्वितीय चरण पर 17.21 करोड़ रुपये व्यय होने हैं।



**जवाई योजना**—राजस्थान में एरिनपुरा रेलवे स्टेशन ॥ पास जवाई नदी पर यह बांध बनाया गया है। यह सन् 1956 में तैयार हो गया था। इससे लगभग 24180 हेक्टर (60 सहस्र एकड़) भूमि की सिंचाई

होगी और (20 हजार टन) अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न होगा।

**राजस्थान नहर परियोजना—हरीके (Hariké Barrage)** से जो सतलज नदी पर बनाया गया है, एक नहर, जिस पर लगभग 66.47 करोड़ रुपये व्यय होंगे, निकालने की परियोजना जुलाई, 1957 में स्वीकृत की गई थी। इस परि-

योजना को दो भागों में विभक्त किया गया है—

(1) मुख्य नहर 215 कि. मी. (134 मील) लम्बी होगी जिसमें से 178 कि. मी. (110.8 मील) पंजाब क्षेत्र में होगी (Rajasthan Feeder) और (2) निचली नहर जो 467 कि. मी. (291 मील) लम्बी होगी और राजस्थान के क्षेत्र में होगी इसे राजस्थान नहर कहते हैं। इसे मुख्य नहर से पानी मिलेगा। सन् 1968-69 तक सम्पूर्ण राजस्थान



की ओर और राजस्थान नहर का 196 कि. मी. (122 मील) लम्बा भाग तैयार हो जाने की आशा है। परियोजना का शेष भाग सन् 1971-78 तक पूरा होगा। सूरतगढ़ शाखा और रावतसर डिस्ट्रीब्यूटरी बन कर तैयार हो गई है।

प्रारम्भ में इस नहर को रावी और व्यास नदियों से पानी दिया जायेगा। बाद में इन दोनों नदियों पर बनाये जाने वाले बाँधों से पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी दिया जायेगा। प्रारम्भ में इससे



बीनामेर, जैमनमेर तथा श्री गंगानगर के जिनों की 10.5 लाख हैक्टर (26.20 लाख एकड़) भूमि में सिंचाई होगी जिनमें 5.8 बी० टन (5.7 लाख टन) साधारण उष्ण होना जिनका मूल्य करीब 156 करोड़ रुपये होगा। राजस्थान नहर बोर्ड की देग-रेव में यह कार्य चल रहा है। राजस्थान नहर प्रदेस की सबसे बड़ी सिंचाई योजना है। सन् 1966 तक इस योजना के कुल व्यय 86500 हैक्टर (2.15 लाख एकड़) भूमि की सिंचाई प्रारम्भ हो गई। राजस्थान नहर पूरी कुर्ब की होगी तथा इसकी कुल लम्बाई 693 कि० मी० (425 मील) के लगभग होगी। आगामी 20 वर्षों में योजना के पूरे होने के अनुसार लगभग 3 हजार मए गाँव बस आयेंगे तथा 27.4 लाख बी० टन (27 लाख टन) पनिरिक्त अन्न पैदा होगा। प्रत्यक्ष रूप में लगभग 25899 वर्ग कि० मी० (10 हजार वर्ग मील) का क्षेत्र इस योजना से प्रभावित होगा।

### सारांश

सिंचाई का महत्व—भारतीय कृषि वर्षा का जुमा मानी जाती है। अनिश्चितता से बचने के लिए सिंचाई को विशेष महत्व देना आवश्यक है। भारत में सिंचाई की आवश्यकता के मुख्य कारणों में—वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा का असमान वितरण, सड़ी में वर्षा का अभाव आदि उल्लेखनीय है।

सिंचाई से लाभ (1) जलाल से बचाव (2) निरन्तर खेती (3) प्रति हैक्टर उपज में वृद्धि, (4) विस्तृत खेती सम्भव, (5) जन-संख्या का ठीक बंटवारा, (6) विशेष पदमनों का उत्पादन, (7) किसानों की आय में वृद्धि, (8) आयातमन के साधनों में वृद्धि, (9) सरकार की आय में वृद्धि (10) व्यापार में वृद्धि, (11) उद्योग पन्थों को प्रोत्साहन तथा (12) गहरी खेती।

सिंचाई में हानियाँ—(1) पानी की अधिकता (water logging),

(2) भूमि का बेकार हो जाना, (3) रोगों की प्रचलता, (4) जल वितरण समस्या तथा (5) जन-जन की हानि ।

सिंचाई के साधन—(1) कृष्ण—पूर्वी पंजाब, उ० प्र० के पूर्वी भाग, बिहार के उत्तरी भाग तथा अन्य राज्यों में कुओं से सिंचाई की जाती है । (2) ताप्ताय—मुख्यतः मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और राजस्थान (उदयपुर इञ्जीन) में पाये जाते हैं । (3) नहरें—उत्तर प्रदेश, पंजाब व मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं ।

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई—प्रथम योजना काल में सिंचाई के विकास पर 380 करोड़ रुपये खर्च हुआ । योजना काल में सिंचाई का क्षेत्र 209 लाख हेक्टर (1950-51) से बढ़कर सन् 1964-65 में 263 लाख हेक्टर हो गया ।

द्वितीय योजना काल में सिंचाई व मध्यम योजनाओं पर 370 करोड़ रुपये खर्च किए गए । तृतीय योजना में सिंचाई के विकास ■ लिए 661 करोड़ रुपये की व्यवस्था की । चतुर्थ योजना में सिंचाई व बाई निरन्तरण कार्यक्रमों के लिए 963 8 करोड़ रुपये रखे गये हैं ।

### प्रश्न

1. भारतीय कृषि में सिंचाई का क्या महत्व है ? भारत के भिन्न-भिन्न भागों में सिंचाई के कौन-कौन से साधन प्रयोग किये जाते हैं ?

इनका तुलनात्मक महत्व भी बताइए ।

(राज. बोर्ड, इन्टर, 1952 तथा म. प्र. बोर्ड, हा. से., 1961)

2. भारत की भिन्न-भिन्न सिंचाई व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए और नहरों की सिंचाई से होने वाले लाभ-हानियों का विवेचन कीजिए ।

(मजमेर बोर्ड, इन्टर, 1962 तथा सागर वि. वि., 1952)

3. "बहुउद्देशीय योजनाओं" से घाप क्या समझते हैं ? किन्हीं दो योजनाओं के बारे में विस्तार से लिखिए ।  
(राज. बोर्ड, इन्टर, 1960 तथा हा. से., 1960 व. 1962)

4. निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए—  
(अ) राजस्थान नहर (राज. बोर्ड, हा. से., 1967), (ब) मादाग नौगल, (६) चम्बल योजना, (ई) दामोदर घाटी योजना तथा (उ) पंचवर्षीय योजनाओं में, सिंचाई, (ऊ) नल-कूप (राज. बोर्ड, हा. से., 1969)

5. भारतीय कृषि के लिए सिंचाई का महत्व समझाइये । भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए ।  
(राज. बोर्ड, हा. से., 1966)

## अध्याय ६

### कृषि के साधन III

#### AGRICULTURAL INPUTS-III

भारत में ग्रामीण वित्त

#### (RURAL FINANCE IN INDIA)

“भारतीय कृषक जन्म सेता है, जन्म में रहता है और मृत्यु ही मरता है।”\*

—शाही कृषि आयोग

“जन्म मरतता ही कृषि की असफलता का कारण है।”

—कुल्कर्णी

प्रत्येक व्यवसाय को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। कृषि व्यवसाय के लिए भी साख्त (Credit) के सस्ते एवम् सुलभ साधनों का बहुत महत्व है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में कृषि साख्त की कमी सतोषजनक नहीं है। गाँवों में रहने वाले कारीगरों की भी संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय ग्रामीणों का वित्त का अधिकांश भाग कृषि से संबंधित है।

#### साख्त की आवश्यकता (Need of Agricultural Credit)

कृषक को खेती के लिए साख्त की जो आवश्यकता होती है उसे तीन प्रकार में बाँटा जाता है—

\*“Indian Farmer is born in debt, lives in debt and dies in debt”—Royal Commission on Agriculture.

### 1. अल्पकालीन साख (Short term credit)—

इसकी आवश्यकता कृषक के दिनप्रति दिन के कार्यों के लिए होती है। खाद, बीज, आदि साधनों की प्राप्ति के लिए आवश्यक इस साख की अवधि लगभग 9 मास से 15 मास तक होती है।

### 2. मध्यकालीन साख (Medium-term Credit) —

इस साख की आवश्यकता सामान्यतः कृषि के लिए पशु बंधन खरीदने, कुमा, बाड़ (Fence) तथा मकान बनाने एवं भूमि पर मुघार करने के लिए होती है। कृषक द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भी जो ऋण लिए जाते हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं। इस साख की अवधि सामान्यतः षेड़ से पाँच वर्ष तक की होती है।

### 3. दीर्घकालीन साख (Long-term credit)—

लम्बी अवधि के साख की आवश्यकता भूमि खरीदने, पुराने ऋण का मुगतान करने, भूमि में स्थायी मुघार करने आदि के लिए होती है। किसान धीरे-धीरे इन ऋणों का मुगतान करता है। यह ऋण प्रायः पाँच वर्ष से बीस वर्ष तक की अवधि का होता है।

कृषि कार्यों के अतिरिक्त भी कृषक को ऋण की आवश्यकता होती है। विवाह, धार्मिक उत्सव, आदि कार्यों के लिए जो ऋण लिए जाते हैं वे अनुत्पादक (unproductive) होते हैं। किसान ऐसे ऋणों पर अधिक व्याज देता है।

### ग्रामीण साख के साधन (Agencies of Rural credit)

ग्रामीण साख प्रदान करने के साधनों में साहूकार (Money lender) का स्थान मुख्य है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने (All India Rural Credit survey committee) सन् 1951-52 में अपने प्रतिवेदन (Report) में बताया कि भारतीय ग्रामीण साख के विभिन्न स्रोत एवं उनके द्वारा प्रबंधित राशि का प्रतिशत निम्न प्रकार है—

# स्रोत

# साल पुति का प्रतिपात

1. वेशेवर साहूकार	44.8
2. किसान साहूकार	24.9
3. रिश्तेदार तथा मित्र	14.2
4. सरकार	3.3
5. सहकारी संस्थाएं	3.1
6. व्यापारिक बैंक	0.9
7. अन्य साधन	8.8

योग 100.0

उपयुक्त तालिका से पता लगता है कि सर्वोत्तम के समय ग्रामीण साल की पुति का मुख्य स्रोत साहूकार था । साहूकारों की कार्य-पद्धति में दोष होते हुए भी किसान उन्हें से अपनी अधिराज आवश्यकताओं की पूति करते हैं । किन्तु सब स्थिति में परिवर्तन आ रहा है । सहकारी का स्थान धीरे-धीरे सहकारी संस्थाएं के रही हैं । सन् 1968-69 में सहकारी संस्थाओं के द्वारा कृषकों को 559 करोड़ रुपये का ऋण दिया



गाँव का साहूकार

मया । इस राशि में 450 करोड़ रुपये मध्य एवं प्रत्यक्षकालीन तथा 100 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण सम्मिलित है । अब हम साख के विभिन्न साधनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे—

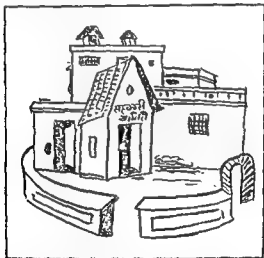
✓ (1) साहूकार (Money Lender)—ग्रामीण साख का लगभग 70 प्रतिशत भाग साहूकारों (पेशेवर और किसान) से प्राप्त होता है । महाजन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं । महाजन उस्तादक और अनुस्तादक सभी कार्यों के लिए ऋण देता है । उसकी कार्य पद्धति सरल होती है, और किसान को किसी भी समय जमानत (security) न होने पर भी ऋण मिल जाता है । साहूकार ऋण से सीधा सम्बन्ध रखता है और स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने के कारण वह प्रत्येक ऋणी की आर्थिक स्थिति को जानता है । इन कार्यों के कारण ही साहूकार ग्रामीण साख का सर्वोपरि साधन है । साहूकारों की कार्य पद्धति में कई दोष पाए जाते हैं, जैसे (क) ब्याज की दर बहुत ऊँची होती है । (ख) ब्याज की अग्रिम (advance) वसूली करता है । (ग) हिसाब किताब में गड़बड़ी करके किसानों को ठगता है । (घ) ऋणी पर अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उसकी फसल कच दामों पर खरीद लेता है । (ङ) किसानों से तरह-तरह की भेंट लेता है और उन्हें अपने दावों की भाँति समझता है ।

सरकार द्वारा साहूकारों की दूषित कार्य पद्धति पर रोक लगाई जा रही है । लगभग सभी राज्यों में साहूकारों के साखसेम्स लेने, हिसाब-किताब रखने, ब्याज की दर निर्धारण करने और बैंक शान्दनी बावों पर रोक लगाने के लिए अधिनियम पास किए जा चुके हैं । गाँव में साहूकार का एकाधिकार होने के कारण किसान अब भी अपनी साख सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए उन्हीं के पास जाता है ।

(2) रिश्तेदार एवं मित्र (Relatives and friends)—ग्रामीण साख की दूसरी महत्वपूर्ण एजेंसी रिश्तेदार और मित्र है । इनकी कार्य प्रणाली का कोई कानूनी रूप नहीं है । इनमें साधारणतया कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती और ब्याज भी नहीं लिया जाता । भारत सरकार द्वारा

किए गए सर्वेक्षणों से पता लगता है कि पड़ोस की तुलना में अब इस साधन का महत्व कम होता जा रहा है ।

(3) सरकार (Government) —सरकार भूमि सुधार अधिनियम तथा कृषक ऋण अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को तकावी (Taccavi) ऋण देती है । सरकारी ऋणों की माया बहुत कम ली जानी ही है, साथ ही इन्हें मिलने में बहुत समय लग जाता है इन ऋणों की कानूनी पद्धति (procedure) भी जटिल होती है इसलिये ये ऋण ग्रामीण साक्ष में बहुत अधिक महत्व नहीं रखते ।



### सहकारी समिति

(4) सहकारी संस्थाएँ (Co-operative Institutions) —यद्यपि सहकारी संस्थाओं का प्रारम्भ भारत में सन् 1904 में हो चुका था फिर भी इन समितियों द्वारा ग्रामीण साक्ष का बोझ सा-साग हो प्रदान



किया जाता है। इतना ही नहीं अधिकांश सहकारी संस्थाएं किसानों को अल्पकालीन ऋण ही देती हैं इसलिए वांछ्य होकर किसान को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण के लिए साहूकार के पास जाना पड़ता है। चिन्नु धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और ग्रामीण साख के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। सहकारी समितियों का विस्तृत अध्ययन अपने अध्याय में किया जाएगा।

✓(5) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)—हमारे देश में व्यापारिक बैंक ग्रामीण साख प्रदान करने का कार्य नहीं के बराबर करते हैं, क्योंकि इनकी शाखाएं गहरों और ऊँचों में स्थित हैं। जैसे-जैसे बैंक साहूकारों, व्यापारियों, आदि को ऋण देकर परोक्ष में ग्रामीण साख में योग देते हैं तथापि किसानों को साख प्रदान करने में ये सहाय्य हैं। व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण (Social control) स्थापित होने के पश्चात् उनके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग कृषकों को समर्पित देने हेतु निर्धारित कर दें।

(6) अन्य साधन—जमींदार, व्यापारी एवं अन्य साधनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों को इस समूह में सम्मिलित किया गया है। अब जमींदार का महत्व कम होता जा रहा है। व्यापारी फसल खरीदने के लिए ही रुपया समर्पित (advance) देता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में ग्रामीण वित्त की एक उचित और सुव्यवस्थित साख प्रणाली का अभाव है। ग्रामीण साख सुविधाओं के विस्तार के लिए सहभागिता का विकास करना होगा। व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण साख में योग देना चाहिए। महाजनो का प्रभुत्व कम करने के लिए कृषि के सभी कार्यों में सहकारिता की उन्नति की जानी चाहिए।

### ग्रामीण ऋण प्रस्तुता (RURAL INDEBTEDNESS)

“भारतीय किसान ऋण में जन्म लेते हैं, ऋण में जीवन व्यतीत करते हैं और ऋण में ही मर जाते हैं।” भारत में यह बहावत सदा-सर्वदा के

लेए सत्य सी बन गई है। किसान स्वयं ऋण में डूबा हुआ रहता ही है किन्तु उनकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी भी ऋण में डूबे रहते हैं। ऋण-प्रस्तुता किसान को धनमंथ्य व उदासीन बनाती है और निरंकुश दृष्टि से गिराती है। ऋणी को अपने जीवन में कोई आनन्द नजर ही भाता।

### ✓ ऋण प्रस्तुता के कारण (Causes of Indebtedness)

✓ अब प्रश्न यह है कि भारत में ग्रामीण ऋण इतना क्यों है? इसके निम्न कारण हैं:—

1. किसान की निर्धनता— भारतीय किसान बहुत गरीब है और उसकी आय भी कम है। इसलिए फसल खराब हो जाने की स्थिति में दूसरे साधनों से ऋण लेना होता है क्योंकि उसकी वचन-शक्ति नहीं के बराबर है।

2. भनायिक, सामाजिक व धार्मिक कार्य—किसान धार्मिक होता है और वह सामाजिक व धार्मिक कृत्यों पर अपना पानी की देव बहाता है। किसान की स्वयं की आय बहुत कम होती है इसलिए उसे इन कार्यों के लिए ऋण लेना पड़ता है।

### ऋण-प्रस्तुता के कारण

1. किसान की निर्धनता
2. किसान का अज्ञान व फिजिकल खर्ची
3. पुर्नर्जनी ऋण
4. माहूशार की दूधित पद्धति
5. खेती की पैदावार में कमी
6. भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बाँटा होना
7. भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ना
8. प्राकृतिक परिस्थितियाँ
9. दुर्बल पशुधन
10. अधिक लगान
11. कृषक की अस्थिरता
12. व्याज की उँची दर

3. पंचक ऋण—(Ancestral debt)—एक पिता की मृत्यु के बाद साधारण उत्तराधिकारियों को ऋण हो वंशोपारण (inheritance) मिलता है। किसान अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए ऋण लेते हैं। इस प्रकार वे अत्यधिक ऋण-प्रस्तुता के मगर में फँस जाते हैं।

4. साहूकार की कुवित पद्धति—ग्रामीण साक्ष के क्षेत्र में साहू-  
कार के एकाधिकार होने के कारण किसान को ऋण के लिये उसी सा-  
निभर रहना पड़ता है। साहूकार अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग कर  
किसानों को मन माने ढग से ठगता है, मूद की दर बहुत अधिक वसूल  
करने के अतिरिक्त ऋणी किसान की फसल कम दामों पर खरीदने का  
पहला अधिकार उसी का होता है, जिससे किसान अपने उत्पादन का  
अर्धित मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप उसके ऋण भार  
में और भी वृद्धि हो जाती है।

5. खेती की पैदावार में कमी—भारतीय कृषि बहुत निम्न  
हुई अवस्था में है, और प्रति एकड़ पैदावार बहुत कम है। ऐसी स्थिति  
में किसान कृषि भाय से अपना भरण-पोषण नहीं कर सकता है और  
बाध्य होकर उसे ऋण लेना पड़ता है।

6. भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा होना—खेती का उप-  
विभाजन व अपसंजन कृषि को अलाभदायक बनाता है और किसान को  
अपने प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी ऋण लेना पड़ता है।

7. भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ना—भारत में जनसंख्या  
बहुत तीव्र-गति से बढ़ रही है और दूसरे घण्टों के प्रभाव में उनका  
अधिकतम भाग भूमि पर ही निर्भर रहता है। आवश्यकता से अधिक  
जनसंख्या के भूमि पर आश्रित होने से कृषि से प्राप्त होने वाली आय कम  
हो जाती है और परिवार का भरण-पोषण करने के लिए कृषकों को  
ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

8. प्राकृतिक परिस्थितियाँ—भारतीय कृषि प्राकृतिक परिस्थि-  
तियों पर निर्भर करती है। यह ठीक ही कहा जाता है कि भारतीय कृषि  
मानसून का पुत्र है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी, हिमपात, बाढ़ी,  
आदि कई प्राकृतिक कारणों से फसल नष्ट हो जाती है और किसानों  
को अन्न भी उपहार लेकर खाना पड़ता है।

9. दुर्लभ पशु—भारत में पशुधन कमजोर है और अधिकतम

किसानों पर भार स्वरूप है। पशुओं में बीमारी फैलने पर बहुत अधिक संख्या में पशु मर जाते हैं और नए पशु खरीदने के लिए किसान को ऋण लेना पड़ता है।

10. अधिक लगान—भूमि के लगान की दर ऊँची है। जिस पर कमल नष्ट हो जाती है उस वर्ष तो किसान के लिए लगान चुकाना और भी कठिन हो जाता है और मजबूर होकर उसे साहूकार की शरण लेनी पड़ती है।

11. दुधक की अस्वस्थता—किसानों का जीवन-स्तर बहुत नीचा होने के कारण वे दुर्बल होते हैं और अनेक बीमारियों के शिकार होने रहते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। ऐसी दशा में उनकी धांध और कम हो जाती है और विवश होकर उन्हें ऋण लेना पड़ता है।

12. व्याज की ऊँची दर—ग्रामीण साख ऋणधारियों में साहू-कार का स्थान प्रमुख है। वह किसानों की साखारी का अनुचित लाभ उठा कर व्याज की बहुत ऊँची दर वसूल करता है जो ऋण-व्ययता में वृद्धि करती है। इसका ही नहीं सरकारी संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की व्याज दर भी अधिक होती है।

**ऋण-व्ययता के प्रभाव—**

ग्रामीण ऋण-व्ययता के कारण देश में अनेक बुराईयाँ उत्पन्न हो गई हैं। सदियों से ऋण मार में दबे रहने के कारण किसान का दृष्टि-बोध निराशावादी (pessimistic) बन गया है। ऋण-व्ययता के निम्न प्रमुख दोष हैं—

1. दुधक की कार्यक्षमता में कमी—ऋण-व्यय किसान मईव सिंगावों से बिना रहता है। ऋण में डूबे रहने के कारण उसका उत्पाद कम हो जाता है। परिणामस्वरूप उसकी कार्य-शुक्लता कम हो जाती है और वह अपने परिवार का व्यव-भोदन भी नहीं कर सकता।

2. कृषक को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता। साहूकारों से खपवा उधार लेने की महत्वपूर्ण शक्ति यह भी होती है। यानी अपनी फसल उन्हीं के हाथ बेचेगा। परिणाम यह होता है साहूकार किसान की पैदावार को बाजार मात्र से कम कीमत पर खरीद लेते हैं और किसान को अपनी खपद का उचित मूल्य नहीं मिल पाना।

3. किसान का भूमि पर अधिकार से संबंधित होना—बहुधा किसान अपनी भूमि की जमानत पर ऋण लेता है और जब वह ऋण को सफलतापूर्वक चुकाता नहीं कर पाता तो विपन्न होकर उसे अपनी भूमि बेचना पड़ती है। अतः कृषक भूमि-हीन हो जाता है।

ऋण-प्रस्तुता के परिणाम	पड़ती है। अतः कृषक भूमि-हीन हो जाता है।
1. कृषक की कार्यक्षमता में कमी	4. किसान का नैतिक पतन
2. कृषक को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना	ऋण-प्रस्तुत रहने के कारण किसान को साहूकार का दास बनकर रहना पड़ता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है।
3. किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता	5. किसान का शोषण—
4. किसान का नैतिक पतन	(exploitation) —ऋण-प्रस्तुता के कारण किसान का विभिन्न प्रकार से शोषण होता है। जिससे गरीब किसान और अधिक गरीब हो जाता है।
5. किसान का शोषण	

के कारण किसान का विभिन्न प्रकार से शोषण होता है। जिससे गरीब किसान और अधिक गरीब हो जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋण-प्रस्तुता ने किसान को निराशा-वादी, निर्धन, भूमि-हीन और दुर्बल बना दिया है। अतः इस समस्या को शीघ्रतापूर्वक दूर करना अति आवश्यक है।

समस्या का हम एवं प्रगति—

ऋण-प्रस्तुता की समस्या के हल पर विद्युती जनता ने विचार प्रारम्भ हुआ, किन्तु समस्या का व्यवहारिक हल प्राप्त करने के आवश्यक

प्रयत्न स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही किये गए । यहाँ हम ऋण-वस्तुता को दूर करने के उपायों और उनकी प्रगति के बारे में विचार करेंगे ।

1. ऋणों को कम करना—ऋण-वस्तुता को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि पुराने ऋणों में कुछ कटौती की जाय । इन कटौतियों के लिए समझौता कमेटीयाँ (Conciliation Boards) बना दी जाएँ अनेक राज्यों में पुराने ऋणों में अनिवार्य रूप से कटौती करने में कुछ कानून बन चुके हैं और कई जगह समझौता परिषदें कायम हो चुकी हैं ।

2. साहूकारों की दूषित कार्य पद्धति पर रोक—कृषि साल के क्षेत्र में साहूकार ही मुख्य स्रोत है । इनके एकाधिकार से अनेक बुरा-इयाँ बन गई हैं । इसलिये सरकार को साहूकार पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिये । हिसाब-किताब की जाँच पड़ताल, लाइसेंस पद्धति आदि को प्रभावशाली बनाकर किसानों की रक्षा की जानी चाहिये । सन् 1930 के पश्चात् महाजनों की दूषित कार्य पद्धति को रोकने ■ लिए विभिन्न राज्यों में कानून पारित कर दिए गए हैं । इन कानूनों के अन्तर्गत महाजनों के लिए लाइसेंस लेना हिसाब-किताब रखना और जाँच करवाना, ज़मीनी की समय-समय पर मूँचघन व ब्याज की सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है । कई राज्यों में इनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर भी निर्धारित कर दी गई है । इन कानूनों का सक्ती से पालन करवाना चाहिये ।

3. भूमि ■ हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध—कई राज्यों में ऐसे कानून बन गये हैं जिनके अनुसार साहूकार किसान की भूमि पर कब्ज़ा नहीं कर सकता । परन्तु उनका प्रभावशाली उपयोग नहीं किया है । सन् 1910 का पंजाब भूमि हस्तांतरण नियम इस दिशा में बहुत प्रयास था ।

4. कृषि-साल व्यवस्था का विकास—वर्तमान कृषि साल में आमूलकूल परिवर्तन करके साल के नवीन ढाँचे का विकास आवश्यक है । पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए अधिकाधिक भूमि विकास

बैंक (Land Development Banks) खोलने जाने चाहिये। इस देश में भूमि विकास बैंकों की संख्या 726 (केन्द्रीय और प्राथमिक मित्रा कर) है। अल्पकालीन व मध्यकालीन भाव के लिए सुदृढ़ सरकारी समितियों का तीव्र गति से विस्तार आवश्यक है। सभी सहकारी समितियों का कार्य संचालन कुशल नहीं है। किसानों की भाव, बिना उत्पादन घाटि बायों में महंगारी सम्भाव्यों की सेवाएं उपलब्ध करना चाहिये जिससे वे साहूकारों के बंधन से निरस्त सकें। किसानों की भूमि सुधार एवं अधिक उत्पन्न के लिए सरकारी 'लकाबी' अथवा भी-सुगम से और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने चाहिये। देश में बैंकों की ग्रामीण स्तर में भाग लेना चाहिये। प्रसन्नता की बात है कि रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया इस ओर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। व्यापारिक बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण स्थापित होने के पश्चात् इन बैंकों ने कृषि स्तर के क्षेत्र में बहुत सहयोग दिया है।

#### अधुन प्रसन्नता को दूर करने के उपाय

1. अर्थों को बच करना
2. साहूकारों की दूषित प्रवृत्ति पर रोक
3. भूमि के हस्तान्तरण पर रोक
4. कृषि भाव व्यवस्था का विकास
5. कृषकों की आय में वृद्धि
6. फिजूल खर्चों पर रोक

5. कृषकों की आय में वृद्धि—अधुन-प्रसन्नता की समस्या को दूर करने के लिए यह निश्चित आवश्यक है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जाय। इस सम्बन्ध में यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार संबंधपूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत कृषि की उत्पत्ति के विभिन्न कार्यक्रम चला रही है जिससे कृषि की हालत धीरे-धीरे सुधरेगी।

6. फिजूल खर्चों पर रोक—उन सभी सुधारों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि गाँव बाजारों में मितव्ययता की भावना का संसार किया जाये। किसान अपने-अपने आर्थिक और सामाजिक व्यवहारों पर दृष्टि

विधिवे तीन वर्षों से कृषि विकास बैंक का नाम बदल कर भूमि विकास बैंक कर दिया गया है।

सुधार लेकर पानी की तरह बहाना है। अनाधिक व्यय की रोकना बहुत आवश्यक है। ग्राम पंचायतों, जीवन सुधार-सङ्घकारी समितियाँ, शिक्षा का प्रसार और किङ्कल जर्मी के विरुद्ध प्रचार, इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लाने में समर्थ होंगे।

कुछ समय से सरकार ने उन्मुखित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इति उन्नत वृद्धि, साल-व्यवस्था सुधार तथा सङ्घकारिता आन्दोलन की तीव्र गति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

रिजर्व बैंक, जो देश का केन्द्रीय बैंक है, ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण हिस्सा ले रहा है। रिजर्व बैंक का इति साल विभाग (Agricultural Credit Department) इति वित्त समस्याओं का

इशारा

विवाह

मोसर

ब्याज

मुकदमों

लगान

रवाद

बीज

वैल





अध्ययन करने, राज्य सरकारों एवं बैंकिंग संस्थाओं को ग्रामीण साख प्रदान करने के क्षेत्र में सहभागिता करने एवं अपने एजेंट 'स्टेट बैंक' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साख प्रदान करने का काम करता है।

ग्रामीण वित्त की सुविधाओं के लिए सहकारी संस्थाओं का विस्तार, साहूकारों की कार्य प्रणाली में सुधार, अशिक्षा का निवारण, राज्य सरकारों, बैंकिंग संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों द्वारा सहयोग किया जाना चाहिये।

### सारांश

कृषि के लिए तीन प्रकार की साख की आवश्यकता होती है—

- (1) मत्स्यनालीन, (2) मध्यकालीन, तथा (3) दीर्घकालीन।

ग्रामीण साख के साधन

साहूकार 69.7% रिजर्वेशर आदि 14.2%, सरकार 3.3%, सहकारी समितियाँ 3.1%, व्यापारिक बैंक 0.9 तथा अन्य 8.8%। इन साधनों में साहूकार ग्रामीण साख व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। किन्तु उसकी कार्य पद्धति में कई दोष हैं। इन दोषों को दूर किया जाना जरूरी है। अब सहकारी संस्थाओं का महत्व बढ़ता जा रहा है।

ग्रामीण ऋण-प्रस्तुता—भारतीय किसान ऋण में जन्य सेना है, ऋण ही रहता है और ऋण में ही मरता है—ऋण-प्रस्तुता का अनुमान ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार 283 रु० प्रति परिवार है।

कारण—(1) किसान की निर्धनता, (2) अज्ञानता और किरान्त सघर्ष, (3) पुर्तुगेनी ऋण, (4) साहूकार की दूषित पद्धति, (5) मेनी की पैदावार में कमी, (6) भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा होना, (7) जनसंख्या का भार बढ़ना, (8) प्राकृतिक परिस्थितियाँ, (9) दुर्बल पशु, (10) अधिक मगान, (11) कृषक की अस्वस्थता, (12) ग्राह्य की ऊँची दर।

**शून्य-वस्तुता के परिणाम—**(1) कृषक की कार्यक्षमता में कमी, (2) कृषक को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना, (3) किसान का भूमि पर अधिकार नहीं रहता (4) किसान का शोषण ।

**समस्या का उपचार—**(1) शून्यों को कम करना, (2) साहूकारों की वृद्धित कार्य पद्धति पर रोक (3) भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, (4) कृषि साल व्यवस्था का विकास, (5) कृषकों की आय में वृद्धि, तथा (6) किसान संघों पर रोक

सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए गए रहे हैं ।

### प्रश्न

1. ग्रामीण साक्षर किसे कहते हैं इसके कौन-कौन से साधन हैं ।
2. शून्य-वस्तुता से धान क्या समझते हैं ? कारण सहित स्पष्ट कीजिये तथा परिणाम भी बताइये ?
3. शून्य वस्तुता को दूर करने के उपाय बताइये । भारत सरकार इसने लिए क्या कदम उठा रही है ?
4. भारत में ग्रामीण शून्य-वस्तुता के कारणों का वर्णन कीजिये ।

(राज. बोर्ड, हा. से., 1966 तथा 67)

## अध्याय 7

### भारतीय कृषि की पद्धति

“भारतीय कृषक अनेक बातों में उतना ही अच्छा है जितना कि ब्रिटिश किसान और कुछ बातों में तो यह उससे भी श्रेष्ठ है। यदि उसकी कुछ कुराहियाँ हैं तो वे कृषि पद्धति में सुधार की सुविधाओं के अभाव के कारण हैं।”  
—डॉ. बॉयलर

कृषि हमारी अर्थ व्यवस्था का आधार है। यह हमारे जीने का तरीका (way of life) भी माना जाता है। किन्तु जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है कृषि अभी एक असाधनायक व्यवसाय के रूप में चलता जा रहा है। विदेशों से भारी मात्रा में अन्न का आयात, कृषि पर आश्रित जनसंख्या की तुलना में कृषि से प्राप्त राष्ट्रीय आय का भाग कम होना तथा अन्य देशों की तुलना में यहाँ की प्रति एकड़ औसत पैदावार का कम होना इसके पिछड़ेपन के प्रमाण हैं। कृषि के पिछड़ेपन के कारणों को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है—

1. कृषि के ढाँचे से सम्बन्धित—इसमें भूमि अधिकार की प्रणाली आती है।
2. संगठन सम्बन्धी—इसमें कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े, उचित संगठन का अभाव, आदि बातें आती हैं।
3. कृषक से सम्बन्धित कारण—इसमें कृषक की अशिक्षा, असामान्य रुढ़िवादिता, भाग्यवादिता आदि कारण सम्मिलित किये जाते हैं।
4. कृषि के साधनों से सम्बन्धित—इसमें कृषि उपज के लिए आवश्यक साधनों का पिछड़ापन आ जाता है। ये साधन हैं—बीज, खाद, पशु, सिंचाई, विद्युत, औजार आदि।

5. कृषि की पद्धति से सम्बन्धित कारण—इस वर्ग में कृषि की परम्परागत शैली एवं पद्धति से सम्बन्धित दोषों का समावेश होता है।

उक्त दोषों के प्रथम चार वर्गों के बारे में हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम कृषि पद्धति से सम्बन्धित बातों का अध्ययन करेंगे।

**उन्नत कृषि पद्धति का महत्व—**

किसी भी देश की कृषि-स्थिरता में सुधार लाने के लिए उसकी पद्धति में आमूल मूल परिवर्तन करने पड़ते हैं। अधिकतम कृषि पद्धति कृषि विकास का मार्ग अवरोध कर देती है। उन्नत कृषि पद्धति से प्राप्त होने वाले लाभ निम्नांकित हैं—

1. कृषि उत्पादन की वृद्धि में उन्नत कृषि पद्धति बहुत सहायक होती है।

2. किसम सुधार की दृष्टि से भी उन्नत शैली कृषि पद्धति का बहुत महत्व है। कृषि पैदावार बढ़ने के साथ वस्तु की उत्तमता में सुधार की दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

3. उन्नत शैली कृषि पद्धति के द्वारा उत्पत्ति लागत (Cost of production) में कमी आकर कृषक व उपभोक्ता दोनों को पहुँचाया जा सकता है।

4. उन्नत कृषि पद्धति सदैव कृषक का समर्थ व धन बचाती है जिसका उपयोग अन्य आर्थिक व सामाजिक कार्यों में किया जा सकता है।

5. उन्नत कृषि पद्धति के अन्तर्गत देश में उपलब्ध सभी प्राकृतिक साधनों—मिट्टियों, जलवायु तथा सिंचाई के साधनों का सदुपयोग समभव होता है।

6. कृषि पद्धति में उपयोग लाने वाली दोहरी फसल प्रणाली, फसल चक्र आदि प्रणालियों के द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति में होने वाली क्षति को पूरा किया जा सकता है।

उन्नति कृषि पद्धति के साम

1. उत्पादन की मात्रा में वृद्धि
2. उत्पादन की उन्नत किस्म
3. उत्पादन व्यय में कमी
4. समय व धन की बचत
5. प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग
6. भूमि की उर्वरा शक्ति का कम ह्रास
7. रोजगार में वृद्धि
8. दूरियों की धार में वृद्धि
9. उद्योग पेशों को उत्तम व पर्याप्त सामग्री
10. विदेशों पर से कृषि सामग्री की निर्भरता में कमी

7. रोजगार में वृद्धि प्रदान करने का बहुत बड़ा काम जो उन्नत कृषि की प्रणाली कर देती है। सघन खेती योजना एम्प्लॉयमेंट कार्यों में अधिकाधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है।

8. उन्नत कृषि प्रणाली के प्रयोग से दूरक कम लागत में ही अधिक कृषि पेशों का उत्पादन करने लग जाता है। परिणामस्वरूप दूरियों की धार में वृद्धि होती है जिसका उपयोग अधिक विकास के लिए किया जा सकता है।

9. उन्नत कृषि पद्धति अपना-

कर देता है उद्योग-पेशों के लिए आवश्यक उत्तम किस्म का कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में तैयार दिया जा सकता है।

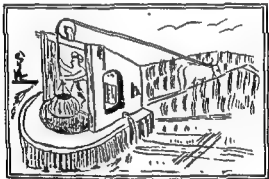
10. उन्नत कृषि पद्धति से ही देश में आत्मरक्षणा के अनुसार कृषि पर्याप्त तैयार किये जा सकते हैं। इससे विदेशों पर आश्रितों एवं कृषि सामग्री के सन्तुलन में निर्भरता कम हो जाती है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उन्नत कृषि पद्धति अपनाकर देश के बहुमुखी विकास में योग दिया जा सकता है।

भारतीय कृषि पद्धति—

प्राचीनकाल में भारतीय जीवन व्यवस्था गरम होने के कारण कृषि की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई। गाँवों में कृषि कार्य स्थानीय

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता था। गाँव एक स्वावलम्बी इकाई के रूप में था और जो कुछ उत्पादन होता था उसका उपयोग वहीं कर लिया जाता था। इस सबके लिए परम्परागत कृषि पद्धति ही ठीक थी। किन्तु समयों के विकास के साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गईं। भारत में भी गाँवों का पृथक्करण (Isolation) समाप्त हुआ और कृषि में व्यापारीकरण (Commercialisation) की प्रवृत्ति का उदय हुआ। विशिष्टीकरण (Specialisation) के इस युग में उत्पादन पद्धतियों में सामूल-मूल परिवर्तन लाये बिना उत्पादन क्षेत्र में अपना प्रमुख काम करना कठिन हो गया। भारत में इस सताव्वी के मध्य तक कृषि की प्राचीन पद्धति का ही धोल-बाला था।



### कुँपे से सिंचाई

और यही का कृषि व्यवसाय अत्यन्त घाटे (Loss) का घन्या बन कर रह गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये गए। कृषि विकास की दृष्टि से ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय कृषि पद्धति की नवीन प्रवृत्तियाँ—

भारत की कृषि पद्धति की कतिपय उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ निम्नांकित हैं—

1. विस्तृत खेती (Extensive Cultivation)—भूमि एक ऐसा प्राकृतिक साधन है जिनमें मानव प्रयत्नों से वृद्धि नहीं की जा सकती। किन्तु कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि की जा सकती है। ऐसा करना तभी सम्भव है जब देश की बेगार पड़ी हुई भूमि को वैज्ञानिक साधनों की सहायता से कृषि योग्य बनाया जा सके। इस प्रकार से कृषि भूमि के क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयत्नों को हम विस्तृत खेती कहते हैं। इससे भूमि पर भाषित जनसंख्या को अधिक रोजगार व बड़ी हुई आमदनी प्राप्त होती है।

भारतवर्ष में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् विस्तृत खेती के अनेक प्रयास किये गये। बौद्ध जंगलों को साफ करके, रेगिस्तान में सिंचाई की व्यवस्था करके तथा नये कृषि भूखण्डों का पत्ता लगाकर खेती करने के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं। लद्दाख की दण्डकारण्य योजना, तराई की स्लावर योजना व राजस्थान में उत्तरी नहरों द्वारा सिंचाई की योजनाएँ विस्तृत खेती की कतिपय महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। भारत में 1950-51 में यहाँ 13.15 करोड़ हेक्टर भूमि पर खेती की जाती थी वहाँ 1965-66 में यह क्षेत्रफल 15.49 हेक्टर हो गया।\*

अब भारतवर्ष में विस्तृत खेती की अधिक व्यापक क्षेत्र में लागू करना सम्भव नहीं है क्योंकि एक ओर तो जंगलों को साफ करना अथवा आविर्क दृष्टियों से लाभदायक नहीं है और दूसरी ओर अब अधिक भूमि उपलब्ध ही नहीं है। इसलिए कृषि विरास की दृष्टि से विस्तृत खेती पद्धति का सहारा लेना अब अधिक लाभदायक नहीं होगा।

2. यंत्रिक खेती (Mechanised Farming)—भारतीय कृषि के साधनों के विद्युत्पन का अध्ययन करते समय हमने यहाँ के परम्परागत

कृषि उपकरणों की उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार किया जा। कृषि विकास में उन्नत यंत्रों एवं उनके द्वारा की जाने वाली यांत्रिक सेती का महत्वपूर्ण स्थान है।



यांत्रिक कृषि का साक्ष्य यह है कि पशुओं एवं मनुष्यों द्वारा किये जाने वाले कुछ कार्य यंत्रों की सहायता से किए जाए। यह यांत्रिक कृषि पूर्ण अथवा आंशिक हो सकती है। पश्चिमी देशों में मानवीय श्रम के अभाव में पूर्ण यांत्रिक सेती की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। यांत्रिक कृषि में ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो छोटे छोटे कार्य कर सकें और कृषि के लिए सुविधाएँ प्रदान कर सकें। कुछ यंत्र हैं—  
**ट्रैक्टर** जिसका प्रयोग पशुशक्ति हलों के स्थान पर किया जाता है;  
**कम्बाइंड ड्रिल (Combined Drill)** जिसकी मदद से खाद व बीज एक साथ बोले जा सकें, **हार्वेस्टर** जो फसल की कटाई में सहायक है, कपास चुनने का यन्त्र, धानू निकालने का यन्त्र, पन्ना पेरने का आधुनिक यंत्र, बिजली की मोटर, डीजल व तेल से चलने वाले पम्पिंग सेट आदि।

भारतवर्ष में यांत्रिक कृषि के पक्ष एवं विरुद्ध में अनेक तर्क दिए जाते हैं। यांत्रिक सेती के पक्ष में दलीलें दी जाती हैं कि इससे (1) कृषि



उत्पादन में वृद्धि (2) धमिकों की कुशलता में वृद्धि (3) लागत व्यय में कमी (4) निचोई की व्यवस्था में सुधार (5) व्यापारिक कृषि को प्रोत्साहन (6) सामाजिक व्यवस्था में सुधार (7) दीर्घकाल में अधिक रोजगार, आदि लाभ प्राप्त होये। इसके विपरीत यह कहा जाता है कि यांत्रिक खेती से भारतीय अर्थ व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो जाने का भय है। ये संभावित कठिनाइयाँ हैं—(1) कृषकों में बेरोजगारी, (2) भारत में कृषि जोत का छोटा होना, (3) कृषकों का निर्धन होना, (4) यंत्रों की चलाने के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की कमी, (5) शक्ति के साधनों का अभाव (6) जनसंख्या के बढ़ते हुए आकार को काम देना सम्भव नहीं (7) भारत में यंत्रों का अभाव आदि।

उपरोक्त कठिनायियों को देखने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि सिद्धान्त रूप में कृषि का यांत्रिकरण लाभदायक है किन्तु हमारी अर्थ-व्यवस्था की कुछ कठिनाइयों को देखते हुए इसे अभी कुछ सीमित क्षेत्रों में ही लागू किया जाना चाहिये। यंत्रों का उद्देश्य मानव की प्रश्रयपना करना नहीं बल्कि कृषक की सहायता करना है। सरकारी कृषि एवं सार्वजनिक क्षेत्र में कृषि कार्य यांत्रिक कृषि के उपयुक्त क्षेत्र हैं।

भारतवर्ष में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान यांत्रिक कृषि के अनेक प्रयत्न किये गये। देश में चार बड़े यंत्रीकृत कार्य जम्पू कश्मीर, गोवा (मध्य प्रदेश), मुरतगढ़ व जेतलरे (दोनों राजस्थान) में हैं। देश में विश्व बैंक की सहायता से एक 'केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन' की स्थापना की गई है। भारतीय कृषकों ने अनेक यंत्रों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है। सन् 1961 की गणना के अनुसार भारत में उच्चत इस्पात के हलों (Ploughs) की संख्या 5,83,72 हजार थी। शक्ति से चलने वाले गन्ना पेरने के यंत्र 33,000 टन तथा बिजली से चलने वाले निचोई के पम्प क्रमशः 2-30 लाख तथा 1-60 लाख एवं कृषि के कार्यों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ट्रैक्टरों की संख्या 31 हजार थी।

सामान्य कृषक की विदग्धता एवम् कृषि जोनों का उचित आकार न होने के कारण यांत्रिककरण के मार्ग में कठिनाइयाँ हैं। इसलिए अभी सहकारी एवम् सरकारी स्तर के बड़े फार्मों को छोड़कर कृषि के क्षेत्र में आंशिक यांत्रिक कृषि को लागू करना ही उचित होगा।

### 3. फसलों का हेर फेर (Crop Rotation)—

कृषि भूमि पर निरन्तर फसलें उगाते रहने में मिट्टी में पकावट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मिट्टी की उर्वराशक्ति में इस कमी के परिणामस्वरूप कृषि पैदावार में ह्रास होने लगता है। इस कमी को दूर करने की एक वास्तव्यमान पद्धति है—फसलों का हेरफेर या फसल चक्र (Rotation of crops)। हमारे किसान सदियों से इस पद्धति को जानते हैं और आवश्यकताानुसार इसका प्रयोग भी करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत एक ही भूमि पर अनेक फसलें बारी-बारी से बोई जाती हैं। ऐसा करने से एक फसल में होने वाले उर्वराशक्ति में ह्रास की दूसरी फसल से क्षतिपूर्ति करली जाती है। उदाहरण के लिए खाद्यान्नों के निरन्तर बोते रहने की अपेक्षा यदि बीच में दालें बोई जाती हैं तो खाद्यान्नों की प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि हो जाती है।

फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बढ़ने के साथ-साथ मिट्टी का कटाव रूकता है। इस हेर फेर से फसलों की कीटाणुसो व रोगों से भी बचत होती है। भारत में यह पद्धति बहुत अनुकूल है।

### (4) मिश्रित फसलें (Mixed Cropping)—

भूमि की उर्वराशक्ति में होने वाली कमी की क्षति पूर्ति के लिए मिश्रित फसलों की पद्धति का भी अनुसरण किया जाता है। इस फसल मिश्रित पद्धति में एक ही साथ दो या अधिक फसलें बोई जाती हैं। सरीस में बाजरा, भूँग, मोठ, ज्वार, अमरुह, उरद, सबका आदि तथा रबी में गेहूँ, चना, जौ, ज्वार आदि फसलों का एक साथ बोया जाना फसल मिश्रण के ही उदाहरण हैं। इस प्रकार दोहरी या अनेक फसल

सत्यादः  
में कमी  
प्रोत्साह-  
रोजगार  
सांख्यिक  
का मध्य  
(2) जा  
होना, (4  
(1) शक्ति  
को काम

सपरः  
सिद्धान्तः  
व्यवस्था  
में ही सा  
करना न  
सार्वजनिक

भार-  
प्रयत्न वि-  
(मध्य प्रदेश)  
विश्व बैंक  
गई है। क-  
सद 1961  
(Plough  
गन्ना पेरने  
पम्प -

[illegible][illegible]

१. प्रस्तावना - विद्युत् प्रवाह के कारण उत्पन्न होने वाले ताप को ही विद्युत् ताप कहते हैं।  
 २. विद्युत् ताप का मात्रक जूल होता है।  
 ३. विद्युत् ताप का सूत्र  $H = I^2 R t$  है।  
 ४. विद्युत् ताप का सूत्र  $H = \frac{V^2}{R} t$  है।  
 ५. विद्युत् ताप का सूत्र  $H = V I t$  है।  
 ६. विद्युत् ताप का सूत्र  $H = \frac{W}{J}$  है।  
 ७. विद्युत् ताप का सूत्र  $H = \frac{P}{J}$  है।  
 ८. विद्युत् ताप का सूत्र  $H = \frac{E}{J}$  है।  
 ९. विद्युत् ताप का सूत्र  $H = \frac{Q}{J}$  है।  
 १०. विद्युत् ताप का सूत्र  $H = \frac{W}{J}$  है।

*[Faint handwritten notes in Devanagari script, mostly illegible due to blurriness.]*

पीप संरक्षण कार्यक्रमों में विदेशी मुद्रा की कठिनाई को दूर करने, प्रशिक्षण की व्यवस्था करने व स्थानीय संगठनों का सहयोग लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

#### (6) सघन कृषि कार्यक्रम (Intensive Agricultural Programme) —

भारत में विस्तृत क्षेत्रों की सम्भावनाएं बहुत कम हैं। सघन कृषि पैदावार में वृद्धि के सघन कृषि कार्यक्रमों की अनिवार्य अनुमति को माने ली है। सघन कृषि में सिंचाई के उन्नत साधन, उन्नत बीज व खाद उन्नत कृषि उपकरण, माल की सुविधा आदि साधनों का आदर्शमय प्रयोग करके कृषि पैदावार में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है।

भारतवर्ष में सघन कृषि के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से प्रयत्न किये जा रहे हैं। सन् 1961-62 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम (Intensive Agricultural District Programme तथा (IADP) का आरम्भ किया गया। सन् 1964-65 में सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम (Intensive Agricultural Area Programme) की शुरुआत की गई। इस समय देश के 15 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है।\*

कृषि पद्धति की वर्तमान प्रवृत्तियों में कृषि अनुसंधान, सू-संगठन, आदि की भी सम्मिलित किया जा सकता है जिससे कृषि विकास में बहुत महत्व प्राप्त मिलती है। भारतीय कृषि पद्धति में अब भी काफी प्रयत्न करने की सम्भावना है।

#### सारांश

कृषि हमारे जीने का तरीका (Way of life) भी माना जाता है।

कृषि के निष्प्रेषण के कारण —

(1) कृषि दौब से मरचिपु। (2) मरचिपु से मरचिपु (अ) भूमि के छोटे छोटे टुकड़े, (ब) उचित मरचिपु का उपयोग (3) कृषक से

संबंधित (अ) कृषक की अनिष्टता, (ब) अज्ञानता, (स) रुढ़िवादिता, (द) माय्यवादिता (4) कृषि के साधनों से संबंधित—(ब) बीज, (ब) खाद, (स) पशु, (द) सिंचाई, (य) वित्त, (र) बीमार। (इ) कृषि पद्धति से संबंधित।

उन्नत कृषि पद्धति के साम—

(1) उत्पादन मात्रा में वृद्धि, (2) उत्पादन की उन्नत विधि, (3) उत्पादन समय में कमी, (4) समय व धन की बचत, (5) प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग, (6) भूमि की उर्वराशक्ति का कम ह्रास, (7) रोजगार में वृद्धि, (8) कृषकों की आय में वृद्धि, (9) उद्योग धर्मों को उत्तम व पर्याप्त सामग्री, तथा (10) विदेशों पर से कृषि सामग्री की निर्भरता में कमी।

भारतीय कृषि पद्धति की नवीन प्रवृत्तियाँ—

(1) वित्तृत होती—भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इसके अनेक प्रयास किये गये किन्तु अब कृषि विकास की दृष्टि से यह पद्धति अधिक लाभदायक नहीं है।

(2) पंजीक होती—इसमें ऐसे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जो छोटे 2 कार्य कर सकें व कृषि के विकास के लिये सुविधायें प्रदान कर सकें। भारत में चार बड़े यंत्रीकृत फार्म हैं।

(3) फसलों का हेरफेर—भारत में यह पद्धति बहुत अनुकूल है।

(4) मिश्रित फसलें—इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। यह पद्धति कृषि की उन्नति के लिये लाभदायक है।

(5) पौध संरक्षण—भारत में फसलों की रोगों, कीड़ों आदि से लगभग 600 करोड़ रु० की हानि होती है। इस दिशा में "पौध संरक्षण, संगरोध, तथा मंहार निर्देशावली" के निर्देशन में पौध संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं।

(6) सघन कृषि कार्यक्रम—सन् 1961-62 में "जिला सघन कृषि कार्यक्रम" (IADP) को प्राथम्य दिया गया। सन् 1964-65 में 'सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम' (IADP) की शुरुआत की गई। देश के 15 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है।

### प्रश्न

1. भारत में कृषि के विछोड़ने के क्या-क्या कारण हैं ?
2. "उत्पन्न कृषि पद्धति का महत्व स्पष्ट कीजिये।
3. भारतीय कृषि पद्धति को समझाते हुये उसकी नवीन पद्धतियों का वर्णन कीजिये।

## अध्याय 8

### सामुदायिक विकास

#### COMMUNITY DEVELOPMENT

"समस्त भारत में मानव क्रियाओं के ये (सामुदायिक विकास) केन्द्र ऐसे ज्योति स्तम्भ (Lamp Posts) हैं जो घने अंधकार प्रकाश फैला रहे हैं। यह प्रकाश उस समय तक फैलना रहेगा जब तक कि भारत भूमि আলোচিত न हो सके।" — श्री जवाहरलाल नेहरू

भारत में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय सेवाओं का प्रारम्भ अमेरिका की प्रेरणा से हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय प्रगति के लिए 'ग्रो मोर फूड एनक्वायरी आर्गनिसम' (Grow More Food Enquiry Committee) की विचारितों पर, सामुदायिक विकास योजनाओं का आरम्भ हुआ।

अर्थ—

'सामुदायिक' शब्द संस्कृति भाषा के 'कम्युनिटी (Community)' शब्द का हिन्दी रूपान्तर है, जिसका अर्थ किसी विशेष 'संज्ञा अथवा समूह' से है। सामुदायिक विकास से हमारा सामान्य विचार गाँव या नगर के विकास की सामूहिक योजना से है। 'रिपोर्ट' 1967 के अनुसार "सामुदायिक विकास आत्म-सहायता का यह कार्यक्रम है जिसे ग्रामबासी स्वयं नियोजित करें और स्वयं ही क्रियान्वित करें तथा विभिन्न स्तरों की ओर से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मिले।"

"It is a programme of aided self to be planned and implemented by the villagers themselves, the Government offering only technical guidance financial assistance."

योजना आयोग (Planning Commission) के अनुसार "सामुदायिक विकास यह पद्धति है जिसे ग्रामीण विस्तार एजेंसी द्वारा प्रायश्चित्तों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को पूर्ण रूप से सुधारने की प्रक्रिया संवर्धनीय योजनाएँ प्रारम्भ करना चाहती हैं।

इस प्रकार सामुदायिक विकास योजनाओं से काव्यव्यव है जिनके द्वारा जन सहयोग (Public Co-operation) के माध्यम पर ग्रामीण व परिवर्धन व प्रगतिशील को शुरू करना है।

सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं में भेद—

सामान्यतः इन दोनों का अर्थ ग्राम या कृषि विकास के सदर्भ में ही प्रयुक्त किया जाता है। फिर भी इन दोनों में कुछ भिन्नता है—

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का क्षेत्र राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रमों की अपेक्षा बड़ा होता है।

2. सामुदायिक विकास योजना एक पद्धति है किन्तु राष्ट्रीय विस्तार सेवाएँ एक साधन हैं।

3. सामुदायिक विकास योजना सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन के व्यापक विकास पर धार देती है जबकि राष्ट्रीय विस्तार योजना केवल कृषि विकास कार्यक्रमों से ही सम्बन्धित होती है।

4. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं की अपेक्षा अधिक ध्यान होता है।

सन् 1958 में बलरामनाथ देवड़ा समिति की सिफारिशों पर इनका अन्तर मन्त्रालय कर दिया गया।

इन योजनाओं का महत्व (Importance)

ग्रामीण विकास के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्राथमिक साधन है। इनके अन्तर्गत सामाजिक न्याय के माध्यम से उत्पादन बर्तने के प्रत्यक्ष लिए आते हैं जिन्हें एक इन्फ्लुएन्स ग्रामीण समाज तथा विकासोन्मुख कार्य प्रदर्शक का विचार हो सके। इस अन्वितन



ये गरीबी व अमीरी के भेद को दूर करने के प्रयत्न किए जायें जिससे हमारे गांवों में रहने वाले वास्तविक स्थितियों के प्रभाव अनुभव कर सकें। ग्रामों के बहुमुखी विकास के महान् उद्देश्यों के ये योजनाएँ चलायी जा रही हैं। श्री एस. के. डे के अनुसार दायिक विकास योजना एक ऐसा उद्योग है जिसका परिणाम चतुर मात्मी बाल्युड सावधानी से करता है। यह योजना जंगल के समान नहीं है जिसमें मुक्त व्यापार की तरह वृद्धि वनस्पतियों की है।”

इन कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्र की जनता की विकास के लिए मिलती है, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, यातायात, पशु सहकारिता, सिंचाई योजनाएँ आदि का विस्तार होता है तथा महत्वपूर्ण उपलब्धि जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की है।

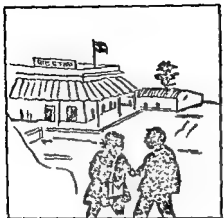
योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रम—

ये योजनाएँ अपनी सहायता प्राप्त करी (Help your self) कार्यक्रम है जिसको प्रोत्साहित करने का भार स्वयं ग्रामवासियों पर सरकार तो केवल मार्ग दर्शन, प्राविधिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन परियोजनाओं का संचालन संघायत राज संस्था ऐच्छित संगठनों एवं राज्य की देखरेख में चलता है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत निम्नोक्त कार्यक्रम चलाये जाते हैं—

1. कृषि विकास—नवीन यंत्र व पद्धतियों की सहायता उत्पादन वृद्धि, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था, भूक्षरण (Erosion) की रोकथाम, सहकारी विपणन, पशु-पालन आदि का विकास करके कृषि की सहायता की जाती है।

2. शिक्षा का प्रसार—देश के दूरस्थ भागों में बच्चों को शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास की शिक्षा का प्रबन्ध किया जाता है।

3. यातायात सांघुदायिक विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण सड़क एवं यातायात के साधनों का विकास उल्लेखनीय है।



## शिक्षा प्रसार

4. ग्रामीणों का विकास—भारतीय वर्ष व्यवस्था में इन उद्योगों को पुनर्जागृत कर अधिक रोजगार देने का प्रयत्न किया जाता है।

5. स्वास्थ्य सेवाएँ—इन योजनाओं के जरिये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रकाश किया जाता है।

6. आवास व्यवस्था—ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण कार्यक्रमों को चलाया जाता है।

7. प्राथमिक प्रशिक्षण—ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

8. समाज एवं महिला कल्याण कार्य—इन योजनाओं के द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों, स्त्रियों एवं बालकों के कल्याण के कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम इन योजनाओं में सम्मिलित किये जाते हैं।



## स्वास्थ्य सेवाएँ

**सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की प्रगति**

भारत सरकार ने अमेरिका की पीईए पाउण्डेशन से आर्थिक सहायता लेकर सर्व प्रथम इन योजना का प्रारम्भ उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सितम्बर सन् 1948 में पाइलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के रूप में किया। सेवाग्राम, बम्बई तथा मद्रास में भी इसी प्रकार के शिवाय प्रयोग किये गए। इन सब की सफलता से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर सन् 1952 को भारत के विभिन्न भागों में 55 केंद्रों पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया। ग्राम-सभाओं में स्वास्थ्यमन्त्र एवं स्वशिक्षा के आचार पर स्वयं चलाया द्वारा चलाये

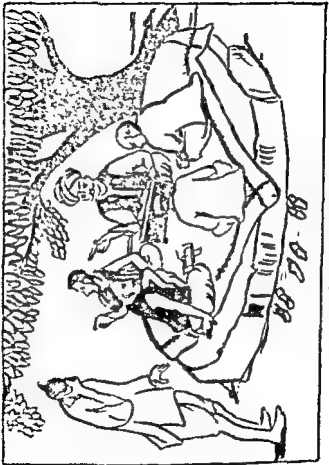
जाने वाले इस कार्यक्रम को पंचायतों, सहकारी समितियों एवं विकास मण्डलों द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था की गई।

ये कार्यक्रम खण्ड की इकाइयों (Units of block) में चलाये जाते हैं। इस खण्ड इकाई में लगभग 100 गाँव आते हैं जिनका क्षेत्रफल 190 से 520 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या लगभग 60 से 70 हजार होती है।

प्रथम योजना के अन्तर्गत 1200 खण्ड स्थापित करने का लक्ष्य था। योजना में इन पर 46.02 करोड़ रुपये खर्च किया गया। प्रथम योजना के अन्त में देश में 1,069 खण्ड थे जिनके अन्तर्गत 1,06,00 गाँव तथा 6.9 करोड़ जनसंख्या आ चुकी थी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों को देश भर में फैलाने का प्रस्ताव किया गया। योजना के अन्त में 3,100 खण्ड थे जिनके अन्तर्गत 20.9 करोड़ जनसंख्या आ चुकी थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन पर लगभग 288 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। योजना के अन्त तक लगभग 40 करोड़ जनसंख्या इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ चुकी थी। इस योजना में अतिरिक्त रोजगार देने के हस्तक्षेपीय प्रयत्न किये गए। तृतीय योजना की अवधि में 12 जनवरी सन् 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) ने 'सामुदायिक विकास अध्ययन दल' द्वारा प्रस्तावित 'पंचायत राज (सोशलाइज्ड डिसेंट्रीकरण)' की स्थापना सम्बन्धी सिफारिश स्वीकार कर ली। तदनुरूप जम्मू-काश्मीर, केरल तथा मध्यप्रदेश के अतिरिक्त सभी राज्यों में 'पंचायती राज' की व्यवस्था की लागू कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत ग्राम, खण्ड एवं त्रिभा-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को विकास एवं प्रशासन सम्बन्धी विशिष्ट अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ग्राम स्तर पंचायत राज का मुख्य आधार तीन संस्थाएँ पंचायत, सहकारी समिति तथा पाठशाला है। विकास ... निर्वाचन प्रणाली से चुनी हुई



संघायित उत्तरदायी होती है। वार्षिक कार्यों के क्षेत्र में सहकारी समिति तथा गैरशासिक, सांस्कृतिक एवं अन्य प्रवृत्तियों के लिए पाठशाला सामुदायिक केन्द्र के रूप में कार्य करती है।

वर्तमान स्थिति—31 जनवरी सन् 1969 को देश में 5,265 सामुदायिक विकास सङ्घ के जिनके अन्तर्गत 5,66,900 गांवों में बसने वाली 40-46 करोड़ जनसंख्या लाभ उठा रही थी।\*

वित्तीय व्यवस्था—सामुदायिक विकास योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था जनता एवं सरकार दोनों ही मिलकर करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामवासी किसी एक कार्य को प्रारम्भ करते हैं और उसमें अपना रुपया, धन या सामान देते हैं। इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय व राज्य सरकारें आवर्तक खर्च (Recurring expenses) का साधा-आधा तथा अनावर्तक व्यय (non recurring expenses) का 3:1 के अनुपात में बांटती हैं। 31 मार्च सन् 1966 तक जन-सहयोग की राशि 151-30 करोड़ रुपया आई थी है जो सामुदायिक विकास पर किए गए कुल सरकारी खर्च का 32 प्रतिशत है। प्रारम्भ से लगाकर तृतीय योजना के अन्त तक इन कार्यक्रमों पर 502-22 करोड़ रुपये सरकार द्वारा व्यय किये गये हैं।

संयोजन (Organisation)—

सामुदायिक विकास योजनाओं का संयोजन विभिन्न स्तरों पर इस प्रकार किया जाता है—

केन्द्र स्तर पर (At the Centre level)—भारत सरकार का कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय इन कार्यक्रम के लिए पूर्ण उत्तरदायी है। मूल नीति के प्रश्नों का निर्धारण उच्च-स्तरीय समिति द्वारा होता है। अन्य मंत्रालयों से सहयोग स्थापित करने के लिए विभिन्न समितियाँ हैं।

**राज्य स्तर पर (At the State level)**—राज्य स्तर पर इन कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व राज्य विकास समिति पर होता है जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। कतिपय मंत्रीगण इस समिति के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष (Development Commissioner) इस समिति का सचिव होता है। विभागाध्यक्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है तथा विभिन्न विभागों के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।

**जिलास्तर पर (At the District level)**—जिलाधीन (Collector) की अध्यक्षता में गठित जिला विकास समिति एवं जिला परिषद् जिला विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिले की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, जिले के विधान सभा के सदस्य व समस्त तहसील जिला परिषद् के सदस्य होते हैं। जिला परिषद् एवं जिला विकास समिति विकास कार्यों का संचालन करते हैं।

**ब्लॉक स्तर पर (At the Block level)**—ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति इन कार्यक्रमों के निर्माण संचालन के लिए उत्तरदायी है। पंचायत समिति के सदस्य उस क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष (अध्यक्ष) तथा कुछ सदस्य (Co-opted) किये गये महिला एवं निम्नश्री जातियों के प्रतिनिधि होते हैं। ब्लॉक का प्रशासन चलाने के लिये एक विकास अधिकारी (B. D. O.) तथा कुछ प्रसार अधिकारी होते हैं।

**ग्राम स्तर पर (At the Village level)**—ग्राम स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (V. L. W.) उत्तरदायी होते हैं। ग्राम स्तर पर विकास कार्यों में निम्न श्रेणियों का भागदार होना है और वह हैं ग्राम के समाजिक कार्य क्षेत्रों में श्री कार्यकर्ता की सहभागिता करना है।

इस प्रकार हमारे देश में सामुदायिक विकास योजनाओं का संचालन जनता जनशक्ति (Democratic) है।

## कमियाँ (Shortcomings)—

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की भारत में शान्तिकारी आन्दोलन की संज्ञा दी जाती है। किन्तु अभी इन योजनाओं की सफलता के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं—

1. प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी—देश में इन योजनाओं के लिये प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी है। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास अध्ययन एवं अनुसंधान परिषद् अब देश भर में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की देख-रेख करती है। आशा है यह कमी शीघ्र ही दूर हो जायेगी।

2. कर्मचारियों का दल—जन-साधारण के इस आन्दोलन में कार्यकर्ताओं का उचित व्यवहार आवश्यक है। किन्तु इस आन्दोलन में लगे कुछ कर्मचारियों के व्यवहार से जनसाधारण इस ओर आकर्षित नहीं हो पाता। अतः इन कर्मचारियों के उचित व्यवहार के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिये।

3. कार्यक्षमता की आवश्यकता—इन योजनाओं के कार्यक्रम व उद्देश्य यदि विस्तृत एवं व्यापक हैं। परिणाम स्वरूप किसी भी क्षेत्र में सर्वांगीण प्रयत्न करके निश्चित करने की शक्ति नहीं की जा सकती।

### कमियाँ—

1. प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव
2. कर्मचारियों का दल
3. कार्यक्षमता की आवश्यकता
4. शोधपूर्ण प्राथमिकताएँ
5. निजीय साधनों पर अधिक जोर
6. जन सहयोग का अभाव
7. संघायत राज संस्थाओं के दोष

4. शोधपूर्ण प्राथमिकताएँ—यह आन्दोलन मूलतः यदि विस्तृत है सम्पूर्ण चलने वाला है किन्तु उचित नीति-नीति के अभाव में सर्वत्र



एवं अन्य निर्माण कार्य ही अधिक हुए हैं और कृषि विकास के कार्यक्रम गौण हो गये हैं ।

5. वित्तीय साधनों पर अधिक जोर—इन योजनाओं में अधिक-तर वित्त प्राप्ति के उपायों एवं वित्तीय साधनों के उपयोग पर ही अधिक जोर दिया गया है । इन योजनाओं का सकल जन-साधारण में जागृति करना होना चाहिये ।

6. जन सहयोग का अभाव—जन-साधारण में चेतना का अभाव है इसलिये ये कार्यक्रम जनता में सक्रिय नहीं हो पाये । मूल रूप में वही इन कार्यक्रमों का सत्य स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता है वही ये योजनाएं अधिकांश क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं बनकर रह गई हैं और वांछित जन-सहयोग का अभाव रहा है ।

7. पंचायत राज संस्थाओं के दोष—ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव और अनुचित दलबन्धियों के कारण जनता का पूरा विश्वास नहीं जम पाया है । परिणाम स्वरूप पंचायत राज संस्थाएँ इस क्षेत्र में वांछित कार्य नहीं कर पाई हैं ।

सफलता के लिए सुझाव—

जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है ये कार्यक्रम सभी वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं । यह हमारे युग का एक बहुत बड़ा प्रयोग है और इसकी सफलता की ओर विश्व की धींख है । इसलिये हमें कुछ रचनात्मक प्रयत्न करके आंदोलन को सफल बनाना चाहिये । यहाँ हम कुछ सुझाव दे रहे हैं—

1. इन आंदोलन में सम्मिलित दिये जाने वाले सभी कार्यक्रम सुनिश्चित होने चाहिये । अत्यधिक महत्वाकांक्षी (over ambitious) योजनाओं का निर्माण बन्द कर देना चाहिये ।

2. कार्यकारियों को उचित प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उनके लिए आचार संहिता ( Code of conduct ) बानि बना दिये जाने चाहिये ताकि जनता उनके व्यवहार से संतुष्ट रह सके ।

3. जन सहयोग प्राप्त करने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन योजनाओं का महत्व एवं महत्व जनता में अधिक से अधिक प्रचारित किया जाना चाहिये ।

4. विभिन्न सरकारी विभागों में समन्वय ( Co-ordination ) स्थापित किये बिना सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को तेजी से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता । इसके लिए केंद्र, राज्य, जिला एवं समूह स्तर पर समन्वय समितियाँ स्थापित की जानी चाहिए ।

5. शिक्षा का प्रसार किये बिना प्रजातन्त्र में किसी भी आन्दोलन को सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सकता । संघायत राज संस्थाओं की सफलता का रहस्य शिक्षा के प्रसार में ही निहित है । कुछ समय तक प्रौढ़ शिक्षा व समाज शिक्षा के कार्यक्रमों को युद्ध-स्तर ( War level ) पर चलाया जाना चाहिये ।

6. सामुदायिक विकास के नाम पर किये जाने वाले अनावश्यक व्यय रोकना, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को इसमें सम्मिलित करना एवं विस्तृत जन-सहयोग प्राप्त करने के उपाय भी इस विभाग में सहायक होंगे ।

वक्तव्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम अधिक सफल नहीं हुए हैं किन्तु यह सम्भन्धा भूल होगी । ये कार्यक्रम सर्वथा असफल रहे हैं । इनसे भारतीय ग्रामों में एक नया वातावरण तैयार हुआ है । यदि इस देश में प्रजातन्त्र एवं आर्थिक नियोजन को सफल बनाना है तो इन कार्यक्रमों को मुद्द-आधार पर प्रतिस्थापित करना होगा क्योंकि "विस्तार सेवाओं एवं सामुदायिक संस्थाओं लोकतन्त्र के प्राण हैं ।"

### सुझाव—

1. सुनिश्चित योजनाएं
2. कर्मचारियों का प्रशिक्षण
3. जनता में प्रसार
4. विभिन्न विभागों में समन्वय
5. शिक्षा का प्रसार
6. अन्य सुझाव

## अध्याय 9

### भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन

---

#### CO OPERATIVE MOVEMENT IN INDIA

“यदि सहकारिता अस्तित्व हो जाय तो वासीय भारत की सबसे बड़ी आशा समाप्त हो जायगी।”

शाही कृषि भाष्य

“सहकारिता लोकतन्त्र की सम्पत्ति एवं संरक्षित है।”

भारत का युग सहयोग का युग है। विश्व की समूची समस्याओं का हम आन्तिमपूर्ण सहयोग के आधार पर सम्भव है। भारतवर्ष में भी सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में सहकारिता का उदय हुआ है। यहाँ हम सहकारिता का अर्थ एवं उसके महत्व का अध्ययन करेंगे।

#### सहकारिता का अर्थ (Meaning of Co-operation) —

जब अधिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से (Voluntarily) मिलकर प्रयत्न करें तो इसे हम सहकारिता अथवा सहयोग (Co-operation) कहते हैं। यह पद्धति पूँजीवाद (Capitalism) तथा समाजवाद (Socialism) दोनों ही पद्धतियों से उत्तम मानी गई है। इसमें अधिक मिलकर उत्पादन के सब उपादान (factors) जुटाते हैं। शक्तिहीन तथा अकेले व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सहयोग से भी भौतिक सुविधाएँ प्राप्त करके जीवन स्तर (standard of living) को ऊँचा बना सकते हैं। सहकारिता के द्वारा समाज में फैली हुई रुढ़ियों को भी हटाया जा सकता है। इस प्रणाली में व्यक्तिगत लाभ का स्थान सामूहिक सेवा (Social good) के सेती है। प्रतिस्पर्धा (Competition) को जनह सहयोग का-

उदय हो जाता है। सहकारिता एक विस्तृत और व्यापक विचार-धारा है। माजकल की सम्प्रदा में यह हमारे जीवन का ढंग (way of life) बन गया है।

सहकारिता के सम्बन्ध में दी गई कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं—

1. प्रो. सेलिगमेन के अनुसार—“सहकारिता का पारिभाषिक अर्थ उत्पादन और वितरण में प्रतियोगिता का परिहारा तथा सभी प्रकार के मध्यस्थों (Middlemen) की आवश्यकता समाप्त कर देना है।”

2. संबंधी गौडन तथा ब्रौडन के शब्दों में—“सहकारिता आर्थिक संगठन का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें लोग सुनिश्चित व्यावसायिक नियमों के अनुसार निश्चित व्यावसायिक उद्देश्य (Business purposes) के लिये मिलकर काम करते हैं।”

3. सर हारोस प्लग्रेट के अनुसार—“सहकारिता वह भाव्य सहायता है जो संगठन द्वारा अधिक प्रभावशाली (effective) हो पाती है।”

4. सहकारी आयोजन समिति (Co-operative planning Committee) ने सहकारिता को इन शब्दों में परिभाषित किया है—“सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जिसमें व्यक्ति समानता (equality) के आधार पर आर्थिक हितों की उन्नति के लिए स्वेच्छा से (voluntarily) सम्मिलित होते हैं।”

5. श्री सी. आर. फे. (C. R. Fay) के मतानुसार—“सहकारी समिति हीन व्यक्तियों की संस्था है जो व्यापारिक कार्यों के लिये प्रारंभ की जाती है और जिसमें हीन व्यक्ति सम्मिलित रूप में अपनी तथा अन्य व्यक्तियों की दुर्बलता त्याग करके नयी शक्ति प्रदान करते हैं।” एक अन्य स्थान पर श्री फे (Fay) ने कहा है कि, “सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो हीन (poor) व्यक्तियों के द्वारा व्यापारिक

उद्देश्यों के लिए स्थापित की जाती है। उसका संचालन सर्वोच्च वि-  
 रूप में होता है और जिनने भी व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते  
 समिति के साम को उसी अनुपात (proportion) में विभा-  
 करने को प्रस्तुत रहते हैं जिस अनुपात में उन्होंने समिति को से-  
 प्राप्त (in proportion to patronage) की हों।”

**सहकारिता की विशेषताएँ (Characteristics of Co-operation)**

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँ-  
 हैं कि सहकारिता की निम्नोक्ति विशेषताएँ हैं:—

1. **सदस्यता की एच्छिकता (Voluntary character)**—सह-  
 कारी संस्थाओं का मूल आधार सदस्यता की एच्छिकता है। समिति  
 की सदस्यता ग्रहण करने के  
 लिये किसी व्यक्ति को बाध्य  
 नहीं किया जा सकता।

2. **सदस्यता की स्वतन्त्रता (Freedom of membership)**—प्रत्येक व्यक्ति बिना  
 किसी जाति, वर्ग, अवस्था, लिंग  
 भेद के समिति का सदस्य बन  
 सकता है। इसकी सदस्यता सब  
 लोगों के लिए खुली होती है  
 क्योंकि इनमें रोक रहित नीति  
 की अपनाया जाता है।



3. **समानता (Equality)**—सहकारी समिति के सभी सदस्य  
 का स्तर बराबर होता है और वे सभी संचालन में समान रूप से भा-  
 ले सकते हैं।

4. एक सबके लिये व सब एक के लिये (Each for all and all for each) — यह सिद्धान्त सहकारिता की मुख्य विशेषता है। इसी आदर्श पर सहकारी समितियाँ कार्य करती हैं।

5. प्रजातन्त्रात्मक संगठन (Democratic set up) — सहकारी समितियों का संगठन व प्रबन्ध प्रजातान्त्रिक ढंग पर होना है और बैठकों में एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार होता है (One member one vote principle)।

6. आर्थिक आवश्यकताओं (Economic necessities) को पूरा करने का उद्देश्य — सहकारी समिति एक विशेष आर्थिक उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। इससे समाज के विच्छेद हुए छोटे-छोटे व्यक्तियों को संरक्षण मिलता है और वे अपनी आर्थिक उन्नति करते हैं।

7. नैतिक गुणों (Moral qualities) पर जोर — यह आन्दोलन सदस्यों में निष्ठा, सहृदयता, पारस्परिक विश्वास और नैतिक गुणों के उत्थान पर ध्यान देता है।

सहकारिता की विशेषताएँ

1. एकिकृतता
2. स्वतन्त्रता
3. समानता
4. एक सबके लिए व सब एक के लिये
5. प्रजातन्त्रात्मक संगठन
6. आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का उद्देश्य
7. नैतिक गुण
8. प्रतियोगिता का अन्त
9. मध्यस्थों का नाश
10. सेवा भावना

8. प्रतियोगिता (Competition) का अन्त — सहकारी समितियों के निर्माण से कलाघोट प्रतियोगिता (Cut throat Competition) का अन्त हो जाता है।

9. मध्यस्थों का नाश (Elimination of Middlemen) — सहकारी समितियों द्वारा व केवल प्रतियोगिता का अन्त होकर उत्पन्न

वृद्धि होती है वरन् उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों का भी घन्ट हो जाता है ।

10. सेवा भावना (Spirit of Service)—ये समितियाँ मौखिक साम की अनेसा समाज तथा सदस्यों की सेवा पर अधिक जोर देती हैं । समाज सदस्यों या उपभोक्ताओं पर दबाव या थोका डालकर साम कमाना सहकारिता आन्दोलन का उद्देश्य नहीं होगा ।

सहकारिता का महत्व (Importance of Co-operation)—

“सहकारिता” पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों ही प्रणालियों में उत्तम मानी गई । इस पद्धति में व्यक्तिगत साम का स्थान सामूहिक हित में लेता है । इसके द्वारा शक्तिहीन तथा अनेके व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सभी मौखिक सुविधाएं प्राप्त करके अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सकते हैं । सहकारिता एक व्यापक और विस्तृत विचारधारा है जिसे आश्चर्य की सम्पत्ता में जीने का तरीका (way of life) माना जाता है । सहकारिता उत्पत्ति तथा वितरण के क्षेत्र में होने वाली अनायासक प्रतियोगिता (Competition) को समाप्त कर देती है । विदेशों में सहकारिता अनेक क्षेत्रों में सफल रही है सहकारी समितियाँ समाज में कड़े हुए लोगों को दूर कर नए जीवन की मांगवाओं को प्रेरित करने में सहायता करती हैं । सहकारिता से समाज के दुर्बल व्यक्तियों में आत्म विश्वास की भावना बढ़ती है और उनका सामान्य बन्द हो जाता है । ये समितियाँ सदस्यों को नैतिक, सैकण्डर, प्रसाव-निक एवं सामाजिक लाभ भी प्रदान करती हैं ।

सर मैकडम डार्लिंग (Sir Malcom Darling) के शब्दों में—

“एक अच्छी सहकारी समिति में मुद्रमेवारी, दिव्य लक्ष्मी, सगंधकारी और सुगंधकारी सभी कम हो जाते हैं और उनके स्थान पर विश्वास, आत्म विश्वास, ईमानदारी, मित्रता, विनम्रता, स्वायत्तता और वास्तविक भावना पाया जाता है ।”

## भारत में सहकारी आन्दोलन का इतिहास (History of Co-operative movement in India)—

सन् 1882 में लार्ड रिपन को सर विलियम वेडरबर्न और म्याया-चौध राणाड़े ने ग्रामीण ऋण की समस्या को हल करने के लिये सहकारी कृषि बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया था। सन् 1897 में सर फ्रेडरिक निकलसन ने तथा 1901 में दुमिल जीव समिति ने ग्रामीण साख के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया।

भारत में सहकारी आन्दोलन का वास्तविक सूत्रपात सन् 1904 में ही हुआ जबकि सरकार ने सहकारी साख समिति अधिनियम (Co-operative Credit Societies Act 1904) बनाया। इस कानून के अन्तर्गत केवल सहकारी साख समितियाँ बनाई जा सकती थीं जिनका उद्देश्य ऋण देना और जमा प्राप्त करना ही था। सहकारी साख समितियों की दो जातों में बांटा गया—(1) ग्रामीण, और दूसरी कुछ समय बाद ही इस कानून में कमियाँ नज़र आने लगीं जिनके कारण आन्दोलन की व्यवस्था, साम वितरण की व्यवस्था व केन्द्रीय संस्थाओं की स्थापना की व्यवस्था इस कानून के अन्तर्गत नहीं थी।

अतः इस कानून में सुधार करने के लिए सन् 1912 में दूसरा सहकारी अधिनियम पास किया गया जिसके अन्तर्गत गैर-साख समितियाँ (Non credit Societies) भी स्थापित की जा सकती थीं। केन्द्रीय साख संस्थाओं का गठन तथा समितियों का नए सिरे से वर्गीकरण इस नियम की दो और उल्लेखनीय बातें हैं। इन सुधारों के परिणाम-स्वरूप सहकारी आन्दोलन तेजी से फैलने लगा। सन् 1914 में सर एडवर्ड मेकलेन के नेतृत्व में एक समिति सहकारी आन्दोलन की जांच के लिए बनाई गई जिम्मे अनेक सुझाव दिए। सन् 1919 में मोन्टेग्यू के अन्तर्गत सहकारिता प्रान्तीय विषय बना दिया

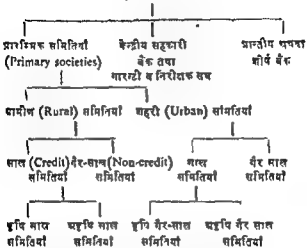


गया। अमग-फलन प्राप्ति में इससे सम्बन्धित कानून बनाए गए। सन् 1926 के शाही कृषि धाधोग (Royal Commission on Agriculture) तथा सन् 1931 की भारतीय बैंकिंग जाँच समिति (Indian Banking Enquiry Committee) के प्रतिवेदनों से भी आन्दोलन को बल मिला। सन् 1929-33 की विवश्यापी घड़ी ने आन्दोलन को बहुत पक्का पहुँचाया। कृषि पदार्थों का मूल्य बहुत कम होने से समितियों का क्षण हूबने लगा। परिणामस्वरूप कई समितियों को अपना कार्य बन्द करना पड़ा। सन् 1935 में रिजर्व बैंक के कृषि सास विभाग (Agricultural Credit Department) की स्थापना की गई जिसने आन्दोलन की विस्तार से जाँच की।

द्वितीय महायुद्ध काल में सहकारी आन्दोलन का विकास हुआ। इस अवधि में अनेक सहकारी संस्थाएँ खोसी गईं जो लोगों की उचित मूल्य पर वस्तुएं बेच सकें। वस्तुओं की कीमत बढ़ने से किसानों की हालत सुधरी और सहकारी संस्थाओं का विकास हुआ। सन् 1945 की सहकारी नियोजन समिति ने आन्दोलन की कमियों का पता लगाया और सुझाव दिया कि प्रारम्भिक सहकारी समितियों को बहुवर्षी सहकारी समितियाँ (Multipurpose Co-operative societies) में बदल देना चाहिए।

सन् 1945 के बाद सहकारी आन्दोलन का तेजी से विस्तार हो रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजना आयोग (Planning Commission) का गठन किया गया जिसने सहकारिता के विकास पर बहुत जोर दिया। सन् 1957 में सर मेल्कम डालिय ने सहकारिता के प्रगति एवं भावी विकास के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। सन् 1960 में श्री बंकिमलाल मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने आधुनिक काल पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत में सहकारी संस्थाओं का वर्तमान उर्ध्व इस प्रकार है—

## सहकारी समितियाँ



उपरोक्त श्रमिका से स्पष्ट होता है कि हमारे देश की सहकारी संस्थाओं को छोटे स्तर पर तीन भागों में बाँटा जाता है—

1. प्राथमिक सहकारी समितियाँ—इन समितियों में सरस्वों का सीधा सम्बन्ध रहता है। केन्द्रीय संस्थाएं इन समितियों की मदद करती हैं। ये समितियाँ सात व वैर-मास सभी कार्यों के लिए बनाई जा सकती हैं। ये समितियाँ फिर दो भागों में बाँटी जा सकती हैं—(क) ग्रामीण और (ख) शहरी। द्वितीय योजना के अन्त में इन समितियों की संख्या 2 लाख 10 हजार को अब देश में 3,32,400 समितियाँ हैं।\*

2. केन्द्रीय संघटन—ये संघटन प्राथमिक समितियों को संपर्क करने और उनकी मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। सन् 1966-67 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 346 † थी।

\* India 1969 p. 268

† India 1969—p. 269

3. राज्य अथवा शीर्ष बैंक—केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं की सहायता करने के लिए राज्य स्तर पर एक शीर्ष बैंक होता है। भारत में ऐसे बैंकों की संख्या 25 है।

भारतवर्ष में साख सहकारिता (Co operative Credit Movement)

भारतवर्ष में ग्रामीण साख का महत्व सर्व विदित है। परन्तु ग्रामीण साख के साधनों की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। जिनको कृषि गुप्तार एवं अन्य कार्यों के लिए साख की आवश्यकता होती है जिनको पूरा करने में सहकारी साख (Co-operative credit) संस्थाएँ भी किमान की सहायता करती हैं। हमारे देश में पाई जाने वाली कुल सहकारी समितियों का संयोजन 79 प्रतिशत मात्र सहकारी साख समितियों के रूप में है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हमारे यहाँ सहकारी आन्दोलन मुख्यतः किसानों को सस्ते ऋण दर पर ऋण दिलाने के लिए ही प्रारम्भ हुआ था। सन् 1904 का सहकारी कानून वेदम साख समितियों के गठन पर ही प्रकाश डालता था। इस प्रकार हमारे देश के सहकारी ढाँचे में साख सहकारी समितियों का विशेष स्थान है, इसलिए यहाँ हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

कृषि सहकारी समितियों का संगठन एवं कार्य-प्रणाली

भारत में सहकारी संस्थाओं को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—ग्राम्य या राज्य के स्तर पर राष्ट्रीय बैंक या शीर्ष बैंक (Apex Banks) जिला, तहसील या ताल्लुका स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक, तथा गाँव अथवा सहरी में मनुष्य के स्तर पर प्रारम्भिक सहकारी साख समितियाँ यहाँ हम प्रारम्भिक कृषि (ग्रामीण ग्रामीण) सहकारी साख समिति के संगठन एवं कार्य पद्धति पर विचार करेंगे जिनमें कृषि क्षेत्र की साख समितियों की कार्य प्रणाली की सामान्य जानकारी मिल जाएगी।

गाँवों में पाई जाने वाली ये समितियाँ रेडियन (Raidien) विभागों पर आधारित हैं। इनकी कार्य प्रणाली एवं संगठन के बारे में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

(1) सदस्यता (Membership)—एक ही गाँव प्रचारा जाति के 10 वर्ग (15 वर्ष की आयु के ऊपर) इयक मिलकर समिति प्रारम्भ

कर सकते हैं। सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं होती है, किन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार बड़ी समितियों की सदस्य संख्या 500 तक कर दी गई है। सदस्य संख्या सीमित होने से सदस्यों में पारस्परिक सहयोग स्थापित हो जाता है।

2. कार्य क्षेत्र (Area of operation)—प्रायः एक गाँव में एक ही सहकारी साज समिति की स्थापना हो सकती है। किन्तु व्यवहारिकता में कुछ राज्यों में कई गाँव एक समिति के अन्तर्गत आ जाते हैं। श्री ईंदुलाल मेहता कमेटी 1960 का मत था कि एक समिति के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की दूरी समिति के प्रधान कार्यालय से 3-4 मील से अधिक नहीं होनी चाहिये। व्यवहार के दृष्टिकोण से इसका क्षेत्र “पंचायत का कार्य क्षेत्र” होना अधिक उत्तम रहेगा।

3. रजिस्ट्रेशन (Registration)—समिति का गठन करने हेतु 10 या अधिक वयस्क (major) व्यक्ति राज्य के सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्र देकर समिति का पंजीयन (registration) करा सकते हैं।

4. उद्देश्य (Aims)—इनका उद्देश्य सदस्यों के भौतिक तथा नैतिक स्तर (material and moral standards) दोनों को ऊँचा उठाना है। सदस्यों की सहायता करने के साथ-साथ उनके नैतिक गुणों, जैसे—मिथव्ययता (thrift), समय की पादम्बी (punctuality) मिलनसारी, स्वावलम्बन (self-help) आदि की भावनाओं को जागृत करती हैं।

5. दायित्व (Liability)—प्रारम्भिक कृषि साज समितियों के सदस्यों का दायित्व मसीमित होता है। अपरिमित दायित्व (unlimited liability) के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सदस्य समिति के ऋण को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से चुकाने के लिये बाध्य होता है। सदस्य प्रायः एक गाँव के होते हैं इसलिये आपसी विश्वास बना रहता है। इस कारण से वे मसीमित दायित्व स्वीकार कर लेते हैं। जब पामीन क्षेत्र में भी सीमित दायित्व समितियाँ बड़ी संख्या में स्थापित हो गई हैं।

6. प्रबन्ध (Management)—इन समितियों का प्रबन्ध प्रजा-सन्धारमक (democratic) तथा अवैतनिक (honorary) होता है। इनके प्रबन्ध का उत्तरदायित्व दो समितियों पर होता है—(घ) साधारण सभा (General Meeting) तथा (आ) कार्यकारिणी समिति या प्रबन्ध समिति (Managing or Executive Committee)। साधारण सभा में समिति के सभी सदस्य सम्मिलित हैं। साधारण सभा की बैठक साधारणतया वर्ष में एक बार होती है। साधारण सभा पदाधिकारियों का चुनाव करना, वैतनिक सेक्रेटरी की नियुक्ति करना, बजट पास करना, रजिस्ट्रार और आय-व्यय निरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना आदि कार्य करती है। यह समिति वार्षिक लाभ के वितरण और रक्षित कोष (Reserve fund) के उपयोग निर्धारित करने के प्रतिरिक्त सदस्यों को दिये जाने वाले आदि प्रश्नों पर भी विचार करती है।

कार्यकारिणी सभा के कार्यों में प्रमुख हैं—साधारण सभा के आदेशों का पालन करना, ऋण देना, ऋण वसूली तथा धन की व्यवस्था करना, वार्षिक हिसाब-किताब साधारण सभा में प्रस्तुत करना आदि।

7. पूंजी (Capital)—समिति प्रवेश शुल्क, अथ पूंजी (Share capital), जमाएं (Deposits) तथा ऋण के द्वारा कार्यशील पूंजी (Working capital) का प्रबन्ध करती है। कहीं-कहीं समितियों के अंश (Shares) नहीं होते। बाह्य साधनों से प्राप्त पूंजी में केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्यकीय बैंक तथा अन्य समितियों का योगदान उल्लेखनीय है।

8. निरीक्षण एवं जाँच (Audit and supervision)—इन समितियों के काम का निरीक्षण एवं हिसाब किताब की जाँच का उत्तरदायित्व राज्य के सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार पर होता है। यह निरीक्षक तथा अवेक्षकों की नियुक्ति करता है जो इस कार्य को करते हैं।

9. ऋण का उद्देश्य (Object of loans)—साधारणतया ऋण उत्पादन कार्यों (Productive purposes) के लिए दिये जाते हैं,

जैसे—बीज, साद औजार आदि खरीदना । किन्तु कभी-कभी किसानों को साहूकार ॥ चुंगल से बचाने के लिये अनुत्पादक बायों तथा पुराने ऋण को चुकाने के लिए भी ऋण दिए जाते हैं ।

10. ऋण की वसूली (Recovery)—ये समितियाँ अपने सदस्यों से ऋण वसूली के लिये कित्तों (instalments) कर लेती हैं और भुगतान ऐसे समय पर माँगा जाता है जबकि सदस्यों के लिये चुकाना सुविधाजनक हो । ऋण वसूली ठीक समय पर होनी चाहिए । केवल वास्तविक कठिनाई होने पर ही वसूली स्थगित (postpone) की जाती है ।

11. अमानत (Security)—सैद्धान्तिक रूप से इन सहकारी समितियों में ऋण के लिए वास्तविक अमानत सदस्यों की ईमानदारी और चरित्र (honesty and character) है । परन्तु व्यवहार में ऋण के लिये समय-समिति अन्य दो सदस्यों की अमानत लेती है जिससे ऋणों के हूबने का डर कम हो जाता है ।

12. व्याज की दर—इन समितियों की व्याज दरें महाजन एवं बाजार की प्रचलित दरों से काफी कम होती हैं । परन्तु ये दरें अत्यन्त नीची हों तो नीच जाने अनावश्यक ऋण लेने को प्रेरित होवे ।

13. लाभ का वितरण—जहाँ अंश पूँजी नहीं होती, उस समिति का सारा लाभ रक्षित कोष में जमा कर दिया जाता है । जहाँ अंश पूँजी होती है वहाँ लाभ का कम से कम ३ भाग रक्षित कोष में जमा करने के बाद शेष लाभ 10% शिक्षा, परीक्षण और अन्य सामाजिक बायों के लिए व्यय हो सकता है । बचे हुए लाभ को निश्चित सीमा तक सदस्यों में सामाजिक (dividend) के रूप में बाँटा जा सकता है ।

14. पचायत (Arbitration)—समिति और सदस्यों के बीच होने वाले झगड़े या मतभेद को निपटाने के लिये पचायत का गठन होता है । इससे न्यायालयों से नहीं जाना पड़ता है और समय, शक्ति तथा धन में बचत हो जाती है ।

15. संविनि का भग होना—(Dissolution)—रजिस्ट्रार के यह अधिकार है कि यदि यह किसी समिति के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उसे भंग कर दे।

**भारतवर्ष में कृषि सहकारी संस्थाओं की वर्तमान स्थिति—\***

भारतवर्ष के सहकारी ढांचे में कृषि सहकारी संस्थाओं का बाहुल्य है। यहाँ हम कुछ कृषि सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली एवं वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेंगे।

1. सहकारी कृषि साख्त (Agricultural credit) समितियाँ—भारत में इन समितियों का महत्व बहुत है। ये समितियाँ कृषकों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती हैं। सन् 1966-67 में इन समितियों की संख्या 1-97 लाख थी। इन समितियों की सदस्य संख्या 2-70 करोड़ थी।

2. भूमि विकास बैंक (Land Development Banks)—ये बैंक कृषकों को दीर्घकालीन साख्त ऋण प्रदान करने का कार्य करते हैं। राज्य स्तर पर एक केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक होता है जो उस राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित प्राथमिक बैंकों को ऋण देता है। देश में 18 केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक (Central Land Mortgage Banks) हैं। प्राथमिक भूमि बन्धक बैंकों की संख्या 707 है। इन बैंकों की सदस्य संख्या 12-55 लाख तथा कार्यभार पूंजी 173-59 करोड़ रुपये है। 1966-67 में इन बैंकों ने 40-84 करोड़ रुपयों का ऋण दिया।

3. सेवा सहकारी समितियाँ (Service co-operative Societies)—यह ग्रामीण व्यक्तियों का यह संगठन है जो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये

पारस्परिक सहायता एवं सहकारिता के सिद्धान्त के आधार पर संगठित हुए हैं। द्वितीय योजना के अन्तर्गत बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को अधिक व्यापक रूप में संगठित कर सेवा सहकारी समितियों में परिणत कर दिया गया। ये समितियाँ कृषकों के लिए साख, विपणन, सिंचाई, कृषि-उपकरण, आदि की व्यवस्था करती हैं। ये समितियाँ कुटीर उद्योगों के कारीगरों की मदद भी करती हैं। ये समितियाँ सहकारी कृषि (Co-operative Farming) का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इन समितियों का सामोला ग्रंथ व्यवस्था में बहुत महत्व है।

4. विपणन समितियाँ (Marketing Societies)—कृषि में सहकारी विपणन समितियों का महत्व बहुत है। इनके द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में भ्रष्ट, सक्की उपज का उचित मूल्य एवं पदार्थों को सुरक्षित रखने की सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। देश में 3,295 प्राथमिक विपणन समितियाँ हैं जिनकी सदस्य संख्या 20 92 लाख एवं कार्यशील पूंजी 76.49 लाख रुपये हैं।

5. गन्ना विषय (Sugarcane Supply) समितियाँ—किमान जब गन्ना बोला है तो उसका उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये इन समितियों की सहायता ली जाती है। ये समितियाँ मुख्यतः बिहार एवं उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हैं। प्रारम्भिक समितियों की संख्या 6,488 है जिनकी सदस्य संख्या 26.61 लाख है।

6. सहकारी, शेती (Co-operative farming) समितियाँ—जब कृषि विकास के लिए सहकारी शेती का महत्व स्वीकार कर लिया गया है। उपविभाजन व अपसंयोजन को रोकने, कृषि धर्मिकों में पुनर्वास एवं पौष्टिक शेती के लिए ये समितियाँ बहुत उपयोगी हैं। मार्च सन् 1968 में इन समितियों की संख्या 8,582 थी।\*

7. अन्य समितियाँ—इन समितियों में दुग्ध विषय समितियाँ, सिंचाई समितियाँ, मकान निर्माण समितियाँ, मछियारों की समितियाँ,



चरबन्दो समितियों, आदि उत्तेजनीय है जिन्होंने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है।

**कृषि के विकास में सहकारी समितियों का योग—**

*(Role of Co-operative Societies in Agricultural Development of India)*

भारतवर्ष में सहकारिता आंदोलन मुख्यतः कृषि साधन की सुविधाओं के विस्तार हेतु ही प्रारम्भ किया गया। सत्यवात् कृषि सहकारिता के क्षेत्र में अन्य मूल साधन (Non-credit) समितियों की भी स्थापना की गई। कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों से निम्नांकित लाभ प्राप्त हुए हैं—

1. **आर्थिक लाभ (Economic Advantages)**—के रूप में इन समितियों द्वारा सबसे पहला लाभ व्याज दर में कमी के रूप में कृषकों को प्राप्त हुआ है। जहाँ पहले साहूकार मनमाजी व्याज दर वसूल करता था वहाँ अब 6 से 8 प्रतिशत व्याज की दर पर ऋण प्राप्त हो जाता है।

2. **ऋण प्राप्तता से मुक्ति**—सहकारी समितियों एवं भूमि बचक (भूमि विकास) बैंकों से सामीप्य ऋण प्रशस्तता में बहुत बड़ी की है। इससे किसान की स्वयंसेवक रूप में धाने बाँटने के व्यवहार मिले हैं।

3. **मुक्त साधन**—आमान दिनों में ऋण की आवश्यकता एवं अन्य मुक्त साधनों के आधार पर सहकारी संस्थाओं ने साधन प्रदान कर किसानों की बहुत सेवा की है।

4. **बचत**—सहकारी समितियों के सदस्यों में अनुशासक मंच (hoarding) की प्रवृत्ति को रोक कर कृषकों में बचत की भावना (Thrift) की प्रोत्साहन दिया है। यह बचत देश के आर्थिक विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

5. **कृषि विप्लव समितियों द्वारा किसान की अपनी छात्र का उचित मूल्य मिलना प्रारम्भ हो गया है। इन विप्लव समितियों ने कृषकों को कचल की बोझों में मुक्ति दाने, उचित मूल्यों के प्राप्त**

होने तक स्वयं उपार देने एवं अन्य दृष्टियों से कृषि की महान् सेवा की है। मात्र देश में लगभग 3,196 कृषि विपणन समितियाँ हैं।

6. कृषि उत्पादन में वृद्धि—  
सहकारी कृषि, पशु पालन समि-  
तियाँ, सहकारी कुचकुट मालाएं  
एवं अन्य सहकारी संगठनों से  
कृषि एवं परसंबंधी व्यवसायों के  
उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है।

7. उपभोग सहकारिता  
(Consumers Co-operation)  
के लिए कृषक ने उपभोक्ता के  
रूप में बहुत लाभ उठाये हैं। सस्ती  
एवं पर्याप्त मात्रा में उपभोग की  
वस्तुओं के उपलब्ध होने से कृषक  
की अच्छा जीवन बिताने का  
मंससर मिला है।

### कृषि सहकारिता के लाभ—

1. व्याज दर में कमी
2. ऋण प्रत्यता से मुक्ति
3. सुलभ साध
4. बचत की जायत
5. कृषि उपज का उचित मूल्य
6. कृषि उत्पादन में वृद्धि
7. उपभोग सहकारिता
8. समाजवाद की ओर
9. सामाजिक विकास
10. शिला सम्बन्धी लाभ
11. प्रशासनिक लाभ
12. नैतिक लाभ

8. समाजवाद की स्थापना में इन सहकारी संस्थाओं का बहुत  
महत्व है। गोपन मुक्त समाज की स्थापना बिना सूची नाशित के  
हमो आन्दोलन के करिये संभव है। सहकारी समितियों ने समानता के  
सिद्धान्त से आर्थिक विषमताओं को दूर करने में बहुत प्रयत्न किये हैं।

9. सहकारी समितियों ने सामाजिक कुशानों को दूर करने में  
कृषकों की बहुत सहायता की है। अनेक सहकारी समितियों ने अपने  
सदस्यों की सामाजिक व्यवहारों पर दिये जाने वाले व्यय में कमी करने  
के निर्देश दिये हैं। सहकारी समितियाँ कृषि क्षेत्रों में शिला, चिकित्सा,  
रोजनी, सफाई एवम् समाज बह्वाण के अन्य कार्य भी करती हैं।

10. **गिज्ञा संबंधी लाभ (Educative advantages)**—सहकारी समितियों ने लोगों के ज्ञान वृद्धि में भी सहायता की है। समिति के नियमों व उपनियमों के सम्बन्ध में उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए साधार (literate) होना आवश्यक है। यदि सदस्य को किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसका पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। इस प्रकार समितियाँ वनु गिज्ञा का विकास करती हैं। ये समितियाँ अनुरा को बतलाती हैं कि 'समष्टि ही शक्ति है' (Unity is strength)।

11. **प्रशासन संबंधी लाभ (Administrative advantages)**—ये समितियाँ प्रजातांत्रिक ढंग पर अपना कार्य करती हैं जहाँ सदस्यों के वोट की बहुत कीमत होती है। ऐसी स्थिति में वे अपने मतधिकार (franchise) का उचित उपयोग करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इससे प्रशासन अधिक कुशल हो जाता है। सब सदस्यों के अधिकार समान होते हैं। इसके अतिरिक्त इन समितियों में काम करने वाले व्यक्ति ही मालिक होते हैं, इसलिये सबसे पारस्परिक मेलमेल होता है और हड़ताल या टालाबंदी (strikes & lock-outs) का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है।

12. **नैतिक लाभ (Moral advantages)**—धार्मिक लाभों के साथ-साथ समितियाँ सदस्यों का नैतिक स्तर (moral standard) भी ऊँचा करती हैं क्योंकि अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति ही इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं। सर मेलकॉम डार्लिंग (Sir Malcolm Darling) के अनुसार "एक अच्छी सहकारी समिति में मुकदमेबाजी (litigation) किन्तु लचों, शराब खोरी और जुमाबाजी (gambling) सभी कम हो जाते हैं और उनके स्थान पर परिश्रम, धार्मिकविश्वास, ईमानदारी शिक्षा, पंचायतें, मितव्ययता (thrift), स्वावलम्बन (self help) और पारस्परिक सहायता (mutual assistance) पायी जाती है।

इस प्रकार कृषि के उत्थान में सहकारिता ने बहुत योगदान दिया है।

सहकारी आन्दोलन में कमियाँ—

भारतवर्ष में कृषि सहकारिता का विकास तो हुआ है किन्तु अब भी अनेक कमियाँ हैं जिनका निराकरण किये बिना यह आन्दोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता ।

1. सहकारी समितियों द्वारा कृषक की आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति हो हो पाती है ऐसी स्थिति में यह सहकारियों के अंगुल से छुटकारा नहीं पा सकता ।

2. समितियों के पास पूँजी की कमी—सामान्यतया सहकारी समितियों के पास अंग पूँजी छोड़कर अपनी पूँजी नहीं होती । उसे ऋण के लिए अन्य संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है और ऋण नहीं मिलने की स्थिति में समिति का कार्य ठप्प हो जाता है ।

3. सहकारिता का समाज विस्तार नहीं है—वैसे ही सहकारी संस्थाओं की कमी है और इन संस्थाओं का क्षेत्रीय वितरण भी असमान है । जैसे बम्बई, मद्रास आदि राज्यों में तो इन समितियों की बहुतायत है परन्तु अन्य राज्यों में कमी है ।

4. सहकारिता के सिद्धान्तों की अनभिज्ञता—इन समितियों के कर्मचारी और प्रबन्धकों का सहकारिता के सिद्धान्तों से अनभिज्ञ होने के कारण आन्दोलन का अधिक विकास नहीं हो सका है ।

5. ध्यात्र की ऊँची दर—सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ध्यात्र दर भी ऊँची होती है क्योंकि समिति को भी अन्य संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है ।

6. प्रबन्धकों की स्वायत्तता—समिति का प्रबन्ध कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ में आ जाने पर किसानों की ऋण लेने के लिए रिकवट देनी पड़ती है ।

7. ऋण की जटिलता—सदस्यों को ऋण प्राप्त करने के लिए कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है और ऋण बहुत देर से मिलता है । परिणामस्वरूप सदस्यों की सहकार से ऋण लेना पड़ता है ।

8. बीयंजालीन सास का प्रभाव—सहकारी समितियों किसानों

की केवल धनदायीन या मध्यस्थीन ऋण ही देती हैं। भूमि बन्धन बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण भी दी जाती है किन्तु वह नगण्य है।

9. समितियों का राजनीतिक प्रयोग—कई सहकारी समितियों के प्रबन्ध राजनीतिक प्रयुक्त प्राप्त करने के लिए इन समितियों का उपयोग करते हैं जिससे सहकारिता का विकास करता है।

10. कृषकों की शिक्षा—किसी भी आन्दोलन की सफलता के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। भारत में किसानों की शिक्षा

सहकारी आन्दोलन की कृषि

1. किसान की आवश्यकताओं

की आर्थिक पूर्ति

2. पूर्ण की कमी

3. साक्षर सहकारिता का असमान विस्तार

4. सहकारिता के सिद्धांतों की अनभिज्ञता

5. व्याज की ऊँची दर

6. प्रबंधकों की स्वायत्तता

7. ऋण पद्धति की जटिलता

8. दीर्घकालीन साक्षरता का अभाव

9. समितियों का राजनीतिक उपयोग

10. कृषकों की शिक्षा

11. बनावटी हिमाचल-किताब

12. कृषकों में आत्म-विश्वास की कमी

13. असाक्षर समितियों का अभाव

उन्हें सहकारी कार्य प्रभावी को समझने से रोकती है।

11. बनावटी हिमाचल किताब अधिकांश सहकारी समितियाँ समय पर ऋण का भुगतान (क्रेडिट सहकारी बैंकों को) नहीं कर पाती। सदस्यों पर समय पर ऋण का भुगतान न प्राप्त कर सकने की स्थिति में समिति अवधि से अधिक बकाया (over due) करार दे दी जाती है और वह नया ऋण प्राप्त नहीं कर सकती। ऋण प्राप्त करने के लिए प्रबन्धक सूटे हिमाचल-किताब तैयार करते हैं जिससे बेईमानी और जालसाजी बढ़ती है जो सहकारिता के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

12. कृषकों में आत्म-विश्वास की कमी—भारत में सहकारिता-

मान्दोलन राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाता है जिससे स्वयं कृषकों ने आत्म विश्वास की भावना पनप नहीं सकती है।

13. कृषि क्षेत्रों में अब भी गैर साक्ष्य समितियों का अभाव है जिसके बिना कृषि का संपूर्ण विकास संभव नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक कारण हमारे सहकारी साक्ष्य आन्दोलन के मार्ग में रुकावटें डालते हैं लेकिन इन कर्मियों को दूर करना ही होगा। अखिल भारतीय ग्रामीण साक्ष्य सर्वेक्षक (1951) ने ठीक ही बताया है, "सहकारिता असफल रही है, परन्तु इसे सफल होना ही चाहिये।"

मान्दोलन की कमियों को दूर करने के उपाय एवं प्रगति—

सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साक्ष्य सर्वेक्षण समिति ने निम्नांकित सुझाव दिए हैं—

1. सहकारिता को पनपाने के लिए सरकार केवल निर्देशन का कार्य ही न करे बल्कि सहकारिता आन्दोलन में सामेदारी भी करे।

2. सहकारी प्रशिक्षण का व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाए।

3. बड़े आकार की प्राथमिक साक्ष्य समितियाँ बनाई जाएं। पर अब इस विचार को ठीक नहीं समझा जाता।

4. सहकारी संस्थाओं को पूँजी प्रदान करने के लिए इम्पीरियल बैंक की स्टेट बैंक में बदल दिया जाए। सन् 1953 से ऐसा कर दिया गया है।

इनके अलावा कुछ और भी सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. जो समितियाँ निर्धारित आदर्श तक न पहुँची उन्हें समाप्त कर दिया जाए।

2. इन समितियों को अधिक पूँजी प्राप्त करवाने के लिए सरकार, बैंक व अन्य संस्थाएँ कम व्याज दर पर अधिक उधार दें।

3. समितियों के प्रबंधकों के गैर-वास्तवीय कार्यों को रोकने के लिए विधायी ढाँचा सुव्यवस्थित किया जाए।

4. इन समितियों का कार्य शीघ्र पंचायतों के सहयोग से प्रभावशाली बनाया जाय ।

ऊपर बताए गए उपायों में से कई मान लिए गए हैं और तेजी से काम हो रहा है । द्वितीय योजना काल में कई सरकारी धान केन्द्र खोले गए हैं । पूँजी की सुविधाएं बढ़ाने के लिए रिजर्व में उधार ऋण नीति का निर्धारण किया है । इस प्रकार भारत सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल है । ठीक ही कहा गया है कि "सहकारिता असंशय रही है" परन्तु सहकारिता प्रवाय सकल चाहिये ।"

### सारांश

सहकारिता का अर्थ एवं महत्व—आर्थिक व सामाजिक जीवन की प्रगति के लिए कुछ व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर प्रयत्न करें तो वह सहकारिता कहते हैं ।

सहकारिता आर्थिक जीवन की सम्पत्ति में हमारे जीवन का अंग बनना चाहति है । वितरण में प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर सहकारिता व्यक्तियों में प्रशाननमूलक तथा सामाजिक काम प्रदान करती है ।

भारत में सहकारी आन्दोलन का इतिहास—

आन्दोलन का वास्तविक सुरुवात 1904 में हुआ । 1912 में सहकारी समिति एक्ट बना, जिसके अन्तर्गत अनेक सहकारी समितियाँ बनाई जा सकती थीं । 1919 के मोंटगोरी सुधारों के अन्तर्गत सहकारिता प्रान्तीय विषय बना दी गई । 1929-1933 की विफल मंदी के कारण किसानों की कीमतें कम हुईं जिससे सहकारी आंदोलन को बड़ा पट्टा मिला । द्वितीय महायुद्ध के समय किसानों की स्थिति सुधरी और आंदोलन विकसित हुआ । 1945 की सहकारी नियोजन समिति अधिनियम सहकारी समितियों के गठन की विधायिका को । स्वतन्त्र भारत के बाद सहकारी आन्दोलन का तेजी से विकास हुआ ।

**वर्तमान ढाँचा—**हमारे देश की सहकारी संस्थाएं तीन भाग में बांटी जा सकती हैं—(1) प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ, (2) केन्द्रीय संस्थाएं और (3) राष्ट्रीय या शीर्ष बैंक।

**भारतवर्ष में साख सहकारिता—**हमारे यहां कुल सहकारी समितियों का 70 प्रतिशत भाग साख सहकारी संस्थाओं के रूप में है।

**प्रारंभिक कृषि सहकारी साख समिति का संगठन एवं कार्य पद्धति—**ये समितियाँ रेकमन-पद्धति पर आधारित होती हैं। इनका कार्य क्षेत्र प्रायः एक गांव होता है। इन समितियों के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। जब सीमित दायित्व वाली कृषि साख समितियाँ भी स्थापित हो गई हैं। प्रबन्ध सामान्यतया ध्वैतानिक होता है। इनको खूण केन्द्रीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है। भारत में इन समितियों की संख्या 1.97 लाख है। इन समितियों ने गांव में साहूकार का एकाधिकार समाप्त कर व्याज की दरें कम कर दी हैं।

**सहकारी साख आंदोलन की कमियाँ—**ये समितियाँ किसानों की आंशिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकती हैं क्योंकि इनके पास पूँजी की कमी है। साथ सिद्धांतों की अनमिश्रता, व्याज की ऊँची दर कुप्रबन्ध, अनिष्ठा, जालसाजी आदि कुछ और सस्तेसनीय कमियाँ हैं।

**सुझाव—**सहकारिता पनपाने के लिए राज्य की सक्रिय साझेदारी, सहकारी प्रशिक्षण व पूँजी की सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिये और जो समितियाँ आदर्श तक नहीं पहुँची हैं उन्हें भंग कर देना चाहिये।

### प्रश्न

- 1.—'सहकारिता' से आपका क्या तात्पर्य है? इसकी विशेषताएं बताइए।
2. सहकारी समितियों के मुख्य भेदों पर टिप्पणी लिखिए।
3. सहकारी समितियों का राष्ट्र की सर्व-व्यवस्था में महत्व निर्धारण



- कीजिए । उनसे होने वाले मुख्य कामों का वर्णन कीजिए ।
4. किसी प्रारंभिक कृषि सहकारी साख समिति के कार्य एवं प्रणाली का वर्णन कीजिए ।
  5. सहकारी साख भान्दोलन की कमी का उल्लेख करते हुए सुझाव बताइये ।
  6. टिप्पणियाँ लिखिए—  
 (अ) सेवा सहकारी समितियाँ  
 (आ) नेशनल सहकारी बैंक  
 (इ) राज्यीय या शीर्ष बैंक
  7. "सहकार" का क्या अर्थ है ? सहकारी समितियों के लाभ समझाइये । (राज. बोर्ड, हा. से, 1)
  8. भारत में सहकारी साख भान्दोलन की उपलब्धियों का कीजिए । (राज. बो., हा. से. 1)
-

## अध्याय 10 कृषि विपणन

### AGRICULTURAL MARKETING

“जब तक कृषि पैदावार के विपणन की समस्या को हल नहीं किया जाता तब तक कृषि की अन्य समस्याओं का हल भी मंजूर रहेगा।”

साही कृषि आयोग

“एक अच्छा किसान अपना एक मेज हल पर रखता है और दूसरा बाजार पर।”

कृषि विपणन का उद्देश्य—

प्राचीन भारत में, जबकि प्रत्येक गाँव एक स्वावलम्बी इकाई (Self sufficient unit) था, कृषि उत्पादन के विपणन की कोई समस्या नहीं थी। स्वावलम्बी इकाइयों के विघटन के साथ-साथ कृषि अन्य पदार्थों के विपणन का उद्भव हुआ। कृषि के व्यापारीकरण (Commercialisation) के पश्चात् तो विपणन की प्रक्रिया अधिक जटिल हो गई। यातायात एवं संचारवाहन के साधनों के विस्तार के साथ-साथ कृषि पदार्थों के विपणन का क्षेत्र विस्तृत होता गया। कृषि को व्यापारिक आधार पर प्रोत्तिष्ठ करने के बाद किसानों और उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों (Middlemen) का एक नया समूह बन गया। आज के इस वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील युग में भी भारतीय कृषक की अज्ञानता के कारण कृषि पदार्थों के विपणन से उसे पूरा लाभ नहीं मिलता। वर्तमान भारतीय कृषि पद्धति दोषपूर्ण है। इस बारे में हम विस्तार से इसी अध्याय में आगे विचार करेंगे।

कृषि विपणन का अर्थ—

कृषि अन्य पदार्थों को उचित मूल्य पर बेचने की पद्धति को कृषि विपणन कहा जाता है। किसान को अपने पदार्थों का उचित मूल्य मिल

सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उचित समय, स्थान और साधन के द्वारा इन पदार्थों को बेचा जाये। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपणन के अध्यापकों के राष्ट्रीय संगठन के अनुसार "विपणन के अन्तर्गत वे व्यावसायिक क्रियाएँ आती हैं जिनके द्वारा माल, सेवाएँ आदि उत्पादन से अपभोग तक पहुँचते हैं।"

इस प्रकार हम, संक्षेप में, कह सकते हैं कि कृषि उपज को किसान से उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए जिन प्रक्रियाओं (Processes) की आवश्यकता होती है वे सब कृषि विपणन के अन्तर्गत आती हैं। ये क्रियाएँ निम्नांकित हैं—

- (1) कृषि उपज का संग्रह करके गोदामों में सुरक्षित रखना;
- (2) परिवहन के साधनों की व्यवस्था;
- (3) वस्तुओं का अंशोकरण (Grading)
- (4) वस्तुओं का प्रसिद्धिकरण (Processing)
- (5) माप-तौल की सुव्यवस्थित प्रणाली;
- (6) मूल्य-निर्धारण की सुव्यवस्थित पद्धति तथा;
- (7) विक्री का स्थान व पद्धति का निर्धारण।

कृषि विपणन की उक्त क्रियाओं के सम्बन्ध में जोखिम उठाने (Risk bearing) का काम भी कृषि विपणन में सम्मिलित किया जाता है।

**कृषि विपणन का महत्व—**

*(Importance of agricultural marketing)—*

भारत में कृषि अधिकता व्यक्तियों के जीविकोपार्जन का साधन है। कृषि विपणन की सुव्यवस्था किसानों के लिए सामयिक है जबकि कृषि विपणन की दोषपूर्ण पद्धति किसानों एवं उपभोक्ताओं, दोनों के लिए हानिकारक है। यदि विपणन की सुव्यवस्था हो तो किसान को उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और कृषि विकास की सम्भावनाएँ बढ़ेंगी। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में साधन

एवं अन्य कृषि पदार्थ मिल सकेंगे । विपणन की मिश्र-मिश्र क्रियाओं में अनेक लोगों को रोज़मर्रा मिलता है । कृषि विपणन की समुचित व्यवस्था से उत्पादकों को कच्चे माल की उपलब्धि में कोई कठिनाई नहीं होती है । इस प्रकार मुख्यस्थित कृषि विपणन की प्रणाली देश के अधिकांश वर्गों के लिए लाभदायक है । कहा जाता है कि भारत में कृषि का महत्व ठो है ही किन्तु उससे भी अधिक महत्व कृषि उपज के विपणन का है । भारतवर्ष में कृषि-पदार्थों के विपणन की प्रणाली—

भारतवर्ष में कृषि उत्पादन का बहुत बड़ा भाग गाँवों में ही बेच दिया जाता है । छोटे-छोटे किसानों के पास अपनी जरूरत के मालवा बहुत ही थोड़ी उपज बचती है जिसे बहुधा गाँव में ही महाजन के हाथ बेच दिया जाता है । कुछ किसान निकटवर्ती मण्डियों में भी जाकर अपनी उपज को बेचते हैं । मण्डियों में बिक्री के लिए वे दलाल, भाड़िए, एजेंट आदि की मदद लेते हैं । ये मध्यस्थ गाँवों में जाकर किसान की उपज को प्रचलित मूल्यों से भी बहुत कम दर पर खरीद लेते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान अपनी उपज चाहे गाँव में बेचे या मण्डी में, उसे पूरी कीमत नहीं मिलती । कुछ सहकारी बिक्री समितियाँ भी कृषि बिक्री का उचित प्रवन्ध कर रही हैं किन्तु इसकी संस्था आवश्यकता को देखते हुए बहुत कम है ।

**भारत की वर्तमान कृषि-विपणन व्यवस्था के दोष (Defects)**

कृषि पदार्थों की विपणन प्रथा में कई दोष हैं । इन्हीं दोषों का कारण भारतीय कृषक अपनी उपज का पूरा मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता । कुछ प्रमुख दोष इस प्रकार हैं—

1. वस्तुओं का वर्गीकरण का अभाव—हमारे देश में कृषि पदार्थों के वर्गीकरण (Grading) पर ध्यान नहीं दिया जाता । अतः बढ़िया किस्म का माल भी बर्तिया माल की दर पर ही बिकता है जिससे कृषक को हानि होती है ।

2. बिक्री की अस्थि—किसान निर्धन है और वह पदार्थों की

निकी के लिए उचित व्यवस्था की प्रतिष्ठा किए बिना ही विफल होकर उन्हें बेच देता है। इस कारण से वह अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं पा सकता।

3. कृषक की प्रतिष्ठा—जीवन के सभी पहलुओं में शिक्षा का बड़ा महत्व है। कृषि पदार्थों के विपणन में भारतीय कृषक की निरक्षरता का स्थायी और मध्यस्थ अनुचित काम चलावे है और हिमान का शोषण होता है।

विपणन व्यवस्था के बीच

1. वस्तुओं के श्रेणीकरण का अभाव
2. बिक्री की जल्दी
3. कृषक की प्रतिष्ठा
4. साहूकार का अनुचित दबाव -
5. सघट्ट की गुविधाओं का अभाव
6. मान्य गुविधाओं का अभाव
7. बाजार मूल्यों से संबंधित जानकारी का अभाव
8. मरम्मत की अविकला
9. भार लोड की विपत्ति ---
10. बाजार की बुगारों
11. सीमित निर्यात की मुन प्रथा
12. मानावान्त की गुविधाओं की कमी ---

4. साहूकार का अनुचित दबाव—प्रायः किसान साहूकार के देनदार (debtors) होते हैं इस लिए महाजन किसान की उपज की कम कीमत पर ही सामान्य से हथिया लेता है।

5. सघट्ट की गुविधाओं का अभाव—कृषि की देनदार को सुरक्षित रखने के लिये गोदामों (Godowns) की गुविधाएँ नहीं हैं इसलिए हिमान देनदार को बेचने की जल्दी करता है।

6. साम्य-गुविधाओं का (Credit facilities) अभाव—हम पहले देख चुके हैं कि भारत में साम्य साम्य गुविधाओं की एक मध्यस्थित प्रणाली का अभाव है किसान निर्धन है उसे ऐसी संस्था

की आवश्यकता है जो उसकी उपज की जमानन पर कुछ रकम उधार दे सके और बीमरों में वृद्धि होने तक उसकी पैदावार को सुरक्षित रख सके। भारतवर्ष में ऐसी सम्पत्तियों की कमी है, इसलिए किसान को कम बीमर पर ही पैदावार बेचना पड़ती है।

—7. बाजार-मूल्कों से सम्बन्धित जानकारी का अभाव—मण्डी में प्रचलित भावों की जानकारी किसानों तक पहुँचाने में साधनों के अभाव में महाजन किसानों की उपज को बहुत कम मूल्यों में खरीद लेने है।

8. मध्यस्थों की अविद्यता—किसान और उपभोक्ता के बीच में कई मध्यस्थ होते हैं। ये मध्यस्थ खरीददार और विक्रेता दोनों ही बर्मीशन लेते हैं। ये मध्यस्थ कई प्रकार के होते हैं, जैसे कच्चा आइ-रिमा, परका आइरिमा, दलाल, एजेंट आदि। ये मध्यस्थ अनेक प्रकार का कमीशन लेते हैं जिससे किसान को उपज का बहुत कम मूल्य मिल पाता है।

9. माप-तौल की भिन्नता—हमारे यहाँ अनेक प्रकार के तौल प्रचलित रहे हैं। कई व्यापारी और मध्यस्थ बाँट और तौल की भिन्नता के कारण किसानों को ठगते हैं। अब सरकार ने सारे देश में दशमलव प्रणाली के समान माप-तौल प्रचलित कर दी है।

—10. बाजार में प्रचलित कुराइयाँ—विमान की मण्डी की पर-स्पर्धों के अनुसार अनेक प्रकार की लागत-वर्षात, बाटा, गुनई, चत्तेदारी, गीजाला, प्याऊ-सर्ब, चुंगो आदि देने पड़ते हैं। यही-यही ही किसान को अपनी उपज का सारा मूल्य भी नहीं मिल पाता।

11. बीमर निर्धारण की गुण प्रणाली—मण्डी में दलालों और आइरिमाओं द्वारा बीमर निर्धारण के लिए चस्मर 'हावा' प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें खरीददार और आइरिमा करने वाले हाव करने के नीचे रख कर हमलों से बीमर का निर्धारण करते हैं। इस पद्धति में बेईमानी की जा सकती है जिससे किसान को ही हानि होने की सम्भावना रहती है।

12. यातायात की सुविधाओं की कमी—ग्रामीण क्षेत्रों में अभी यातायात में समुचित साधनों का विनाश हो नहीं हो पाया है। इसलिये किसान अपनी उपज को मण्डो तक ले जाने में कठिनाई अनुभव करता है और पैदावार को गाँवों में ही महाजन के हाथ बेचने को बाध्य हो जाता है।

समस्या को हल करने के उपाय एवं प्रगति—

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिए यह आवश्यक है कि मध्यम्यों की संख्या कम हो, बाजार की कुप्रथाएँ हटाई जाएँ, यातायात के साधनों का विकास हो और मण्डियों की कार्य प्रणति पर नियंत्रण रखा जाए। यहाँ हम उन उपायों का वर्णन करेंगे जो कृषि पदार्थों के विपणन के दोषों को दूर करने में सफल हो सकेंगे।

1. सहकारी विपणन (Co-operative Marketing)—सहकारी विपणन संस्थाओं के विस्तार से बिन्दी के वर्तमान दोषों को दूर किया जा सकता है। इन समितियों के द्वारा किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल सकेगा। किसानों को व्यक्तिगत रूप से बिन्दी में जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं वे सभी इन संस्थाओं द्वारा आसानी से दूर की जा सकती हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों के माल को, उचित कीमत आने तक, अपने पास सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करती हैं और अकृतमंद सदस्यों को कुछ रुपया उधार भी देती हैं। ये समितियाँ वस्तु का श्रेणीकरण (grading) भी कर सकती हैं जिससे उत्तम किस्म की वस्तु का अधिक मूल्य प्राप्त होता है। इन समितियों को भी तीन भागों में बाँटा जाता है—(क) प्रारम्भिक सहकारी विपणन समितियाँ, (ख) केन्द्रीय-बिन्दी-संगठन तथा (ग) राज्यीय (state) बिन्दी संगठन। इन तीनों का आपसी मेल-जोश व समन्वय होना आवश्यक है। प्रारम्भिक समितियों की आर्थिक स्थिति प्रायः बहुत सुदृढ़ नहीं होती इसलिये इनका केन्द्रीय-बिन्दी संगठन से सम्बन्ध होना वांछनीय है।

इन समितियों से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं—

- (अ) विपणन के क्षेत्र में सहकारिता के धा जाने से किसानों और सरीददारों के बीच मध्यस्थों की लम्बी शृंखला समाप्त हो जाती है, जिससे उत्पादक को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल जाता है।
- (आ) ये संस्थाएँ किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य दिलाती हैं और जब तक माल न बिक जाए तब तक के लिए साख सुविधाएँ भी प्रदान करती हैं।
- (इ) सहकारी बिजली संस्थाएँ अपने सदस्यों की पैदावार गोदामों में तब तक सुरक्षित रखती हैं जब तक कि पदार्थों का उचित मूल्य न मिल जाए।
- (ई) ये समितियाँ अपने सदस्यों की उपज का उचित खेपणीकरण कर सरीददारों को भी लाभ पहुँचाती हैं।
- (उ) ये समितियाँ उत्पादकों को भी निश्चित समय पर कच्चा माल प्राप्त कराती हैं जैसे उत्तर प्रदेश एवं बिहार की गन्ना बेचने वाली सहकारी समितियाँ यहाँ की शक्कर मिलों की गन्ने की पूर्ति (Supply) करती हैं।
- (ऊ) ये समितियाँ अपने सदस्यों को अन्य लाभ भी पहुँचाती हैं जैसे अच्छे बीज, खाद, औजार, कीटनाशक औषधियाँ देना आदि। इन समितियों के लाभ (Profits) का उपयोग भी सदस्यों के हित के लिए ही किया जाता है।

इस प्रकार सहकारी विपणन समितियाँ किसानों के बिजली सम्बन्धी दोषों के निवारण का अचूक इलाज है। परन्तु भारत में अब भी इन समितियों के निर्माण के मार्ग में बाधाएँ हैं। प्रथम समितियों के पास पूँजी की कमी होती है तथा गोदाम की कमी है। यह है कि



समितियों की स्पर्धा (Competition) का मा-  
 करना पड़ता है। सरकारी मंडलों की प्रभावितता का के समिति को  
 का प्रभाव करने हैं जिनके मध्य सरकारी समिति के प्रति सचेत नहीं  
 और फिर स्पर्धाओं के अनुभव में कम आने हैं।

■ बटिनाओं की दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि स-  
 मितियों की पूंजी बढ़ाई जाए। मंडलों के लिए भी यह अनिवार्य  
 दिया जाय कि के अपनी वैसाधार केवल सहकारी समिति के द-  
 ही रहे।

**भारत में सहकारी विपणन समितियों की प्रगति—**

सहकारी विपणन के सम्बन्ध में व्यवस्थित प्रयत्नों का आर-  
 म्भ 1951 में हुआ। उत्तर प्रदेश व बिहार तथा की सहकारी विप-  
 समितियों, महाराष्ट्र और गुजरात की बचाम विपणन समितियों का  
 कार्य राज्यों में कुछ समितियों स्थापित की गई। द्वितीय योजनाकाल  
 1,869 प्रारम्भिक सहकारी विपणन समितियों को 'राष्ट्रीय सहका-  
 विकास तथा मोदाम प्रमोदल' के महापदा दी गई। इन सन् 1967  
 भारत में देश में विपणन समितियों की संख्या 3,476 थी।\* इनमें  
 राष्ट्रीय विपणन समितियों की संख्या 24, केन्द्रीय मंडलों की सं-  
 156 तथा प्रारम्भिक समितियों की संख्या 3,295 थी। इन समितियों  
 की सम्पूर्ण संख्या 21,86,197 तथा कार्यशील पूंजी (working  
 capital) 15,350 लाख रुपए थी।

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में 600 प्रारम्भिक विपणन समिति-  
 का गठन किया जाने का लक्ष्य था। सभी सहकारी विपणन की कु-  
 माना 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सम्पत्ति जानी है जो तीसरी योजना

\*India 1969—p. 272 इसमें मन्ना व दूध विक्रय समितियों  
 की संख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है।

के अन्त में बढ़कर 400 करोड़ हो जाने का अनुमान था। योजनाबद्ध ढंग से इन समितियों को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एवं अन्य संस्थाओं द्वारा साधन भी प्रदान की जाएगी।

■ नियन्त्रित बाजार—कृषि विपणन के दोषों को दूर करने का हमारा उपाय नियन्त्रित बाजारों (Regulated markets) की स्थापना है। इन बाजारों की स्थापना का उद्देश्य बाजार में प्रचलित अनुचित व्यवहारों को दूर कर विपणन को घबिरा चुपचा बनाना है। इन बाजारों में प्रमुख व्यापारियों, उपभोक्ताओं तथा सरकार के प्रतिनिधियों की एक समिति के हाथों में होता है। देश में अब नियन्त्रित बाजारों की संख्या\* 1,880 है।

3. पदार्थों का श्रेणीकरण (Grading) तथा मानकीकरण (standardisation)—कृषि विपणन को लाभदायक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पदार्थों के विभिन्न प्रकार एवं श्रेणियाँ कायम की जाएँ जिससे उत्तम किस्म की वस्तु का उचित मूल्य मिल सके। हमारे देश में श्रेणीकरण का कार्य 'कृषि उत्पादन' (श्रेणीकरण) अधिनियम, 1937 के अन्तर्गत किया जाता है। विदेशी व्यापार के महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों का श्रेणीकरण करना अनिवार्य है। घरेलू व्यापार की कुछ वस्तुएँ जैसे धान, चावल, मूँगे आदि के लिए 'एगमार्क' (Agmark) का चिह्न भी शुद्धता तथा अच्छी किस्म का प्रतीक है, निर्धारित किया जा चुका है। पर अभी यह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। अब तक श्रेणीकरण की 444 इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं।\*\*

4. गोदामों (Godowns) का निर्माण—कृषि पदार्थों के उचित मूल्य पाने तक अवधि को संयोज करने के लिए गोदाम होने चाहिये।

\*India 1969—

सरकार ने सन् 1956 में 'कृषि उत्पन्न (विकास व भोडाम) अधिनियम' बनाया, जिसके अन्तर्गत एक केन्द्रीय गोदाम निगम (Central Warehousing Corporation) तथा प्रत्येक राज्य में एक गोदाम निगम स्थापित किए गए। इन निगमों ने मार्च सन् 1961 तक 40 तथा 266 गोदाम बनाए। द्वितीय योजना के अन्तर्गत मंडियों में 16,70 गोदाम तथा गाँवों में 4,100 गोदाम बन चुके हैं। तृतीय योजना काल में गाँवों में 2,200 तथा मंडियों में 9 गोदाम और बनाए गए।

5. मूल्य अम्बन्धी जानकारी का विस्तार—किसानों को अपने उत्पाद के बाजार भाव से परिचित करवाने के लिए मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अब रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम द्वारा भी मूल्य की सूचनाएँ देश के सभी भागों पहुँचाई जाती हैं। प्रतिदिन निश्चित समय पर आकाशवाणी के 'दार्शनिक कार्यक्रम' के अन्तर्गत विभिन्न मंडियों में प्रचलित कृषि पदार्थों के भाव की सूचना रेडियो द्वारा दी जाती है।

6. यातायात के साधनों का विकास—किसान को अपने बाजार तक अपना माल पहुँचाने के लिए सस्ते और कुशल यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत यातायात के विकास की बहुत महत्व दिया है। तीसरी योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि विकसित हुई क्षेत्र में कोई भी गाँव पक्की सड़क से 6.43 कि० मी० और घने जंगल प्रकार की सड़क से 2.41 कि० मी० (1½ मील) से अधिक दूर नहीं होगा।

7. मापतौल की सममसख प्रणाली (Metric System)—राज्य सरकारें लौह के बाटों व मात्रा के माप की विभिन्नता का दूर करना दिया गया। इससे विपन्न में सुगमता हो गई है।

## सारांश

भारतीय कृषि विपणन व्यवस्था अत्यन्तोपजनक है ।

**विपणन का अर्थ**—कृषि-जन्य पदार्थों को उचित मूल्य पर बेचने की पद्धति को विपणन कहा जाता है । विपणन के अन्तर्गत गोदामों की व्यवस्था, यातायात के साधन, वस्तुओं का अंगीकरण माप-तोल, मूल्य निर्धारण, बिक्री का स्थान, व पद्धति आदि कियाई जाती है ।

**कृषि विपणन का महत्व**—इससे किसानों, उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को लाभ, अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिलता है ।

भारतीय विपणन व्यवस्था के दोष - (1) वस्तुओं के अंगीकरण का अभाव, (2) बिक्री की जल्दी, (3) कृषक की अशिक्षा, (4) सहकार का अनुचित दबाव, (5) मण्ड की सुविधाओं का अभाव, (6) साह्य सुविधाओं का अभाव, (7) बाजार मूल्यों से तबयित जानकारी का अभाव, (8) मध्यस्थों की अधिकता, (9) माप-तोल की विषमता, (10) बाजार की बुराईयाँ, (11) कीमत निर्धारण की गुप्त प्रथा व (12) यातायात की सुविधाओं में कमी ।

**समस्या का हल एवं प्रगति**—

(1) सहकारी विपणन—जून 1967 के अन्त में सहकारी विपणन समितियों की संख्या 3,476 थी । तृतीय योजना में 600 नई विपणन समितियाँ बनाई गयीं ।

(2) नियन्त्रित बाजार-संख्या 1880

(3) पदार्थों का अंगीकरण तथा मानकीकरण ।

(4) गोदामों की स्थापना—तीसरी योजना में गाँवों में 2,200 तथा महियों में 980 गोदाम खोल बनाए गए ।

## प्रश्न

1. कृषि विपणन किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है ? उसके दोषों को दूर करने के सुझाव दीजिये ।

सरकार ने सन् 1956 में 'कृषि उपज (विशाल व गोदाम) अधिनियम' बनाया, जिसके अन्तर्गत एक केन्द्रीय गोदाम निगम (Central Warehousing Corporation) तथा प्रत्येक राज्य में एक-एक गोदाम निगम स्थापित किए गए। इन नियमों ने मार्च सन् 1961 तक क्रमशः 40 तथा 266 गोदाम बनाए। द्वितीय योजना के अन्तर्गत मण्डियों में 16,70 गोदाम तथा गाँवों में 4,100 गोदाम बन चुके थे। तृतीय योजना काल में गाँवों में 2,200 तथा मण्डियों में 980 गोदाम जोर बनाए गए।

5. मुख्य जम्हायों जानकारी का विस्तार—किसानों को बाजार उपज के बाजार भाव से परिचित करवाने के लिए मुख्य जम्हायों सूचनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अब रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम द्वारा भी मुख्य की सूचनाएँ देश के सभी भागों में पहुँचाई जाती हैं। प्रतिदिन निश्चित समय पर आकाशवाणी के 'बाजार कार्यक्रम' के अन्तर्गत विभिन्न मण्डियों में प्रचलित कृषि पदार्थों के भावों की सूचना रेडियो द्वारा दी जाती है।

6. यातायात के साधनों का विकास—किसान को अपने बाजार तक अपना माल पहुँचाने के लिए सस्ते और कुशल यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने पक्करीय योजनाओं के अन्तर्गत यातायात के विकास को बहुत महत्व दिया है। तीसरी योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि विकसित कृषि क्षेत्र में कोई भी गाँव पक्की सड़क से 6-43 कि० मी० और अन्य प्रकार की सड़क से 2-41 कि० मी० (1½ मील) से अधिक दूर नहीं होगा।

7. मापतोल की वसमलय प्रणाली (Metric System)—को लागू करके तौल के माटों व मात्रा के माप की विभिन्नता का अन्त कर दिया गया। इससे विपणन में सुगमता हो गई है।

## ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक व्यवसाय

### SUBSIDIARY OCCUPTIONS IN RURAL AREAS

“भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में सहायक उद्योगों का स्थान गीढ़ की हड्डी के समान है।”

प्रस्तावना—

अत्यन्त प्राचीनकाल से ही हमारे आर्थिक जीवन में सहायक व्यवसायों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कृषि के अनिश्चित किये जाने वाले फल-फसल व्यवसाय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। यद्यपि ये व्यवसाय अनेक प्रकार के हो सकते हैं किन्तु भारतीय ग्रामों में इनकी विद्यमानता तीन बातों पर निर्भर करती है—(क) व्यवसाय के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण, (ख) व्यवसाय के लिए आवश्यक कच्चे माल का गाँव में उपलब्ध होना तथा (ग) निश्चित बस्तु के बिक्रय (Marketing) की सुविधा।

गाँवों में ये परिस्थितियाँ विभिन्न-विभिन्न होने के कारण इन व्यवसायों की प्रकृति विभिन्न-विभिन्न होती है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो सामान्यतः सभी गाँवों में मिलते हैं, जैसे, दूध तथा घी का व्यवसाय, रस्सा-बुनने का काम, मूल खातने का काम आदि। अन्य व्यवसाय ऐसे हैं, जैसे रेशम के कीड़े पालने का व्यवसाय, ताड़-मुड़ उद्योग आदि। इस प्रकार कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न-विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की विद्यमानता। चौथे बड़ा की विविध परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे ये अन्य व्यवसायों के सहायक हैं—प्रधान व्यवसाय नहीं।

सहायक उद्योगों का महत्व—

ये व्यवसाय हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को समृद्धिदायी बनाते हैं। भारतीय अर्थ व्यवस्था जैसी अर्द्ध-विवर्तित स्थिति वाले देशों में

2. माग्रीय विमान की इन कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए जिससे  
उने अपनी उड़ान की बिंदी के सम्बन्ध में सावधान करना पड़ा है।  
इन कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर दृष्टान्त डालिए ।
3. माग्रीय बाजारों में प्रचलित मुख्य दोषों का वर्णन कीजिए।  
इन दोषों को दूर करने के उपाय बताइए ।
4. टिप्पणियाँ लिखिए—  
(अ) महंगी बिक्री, (आ) नियंत्रित बाजार तथा (इ) खोले-  
बाजार और मानकीकरण ।
5. माग्य में कृषि पशुओं की विषय-व्यवस्था के दोषों का वर्णन  
कीजिये ।

(राय. मोहं, हा. से., 1968)

5. आर्थिक समानता—ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले ये व्यवसाय बड़े उद्योगों की मांगि घन के केन्द्रीयकरण को बढ़ावा न देकर विकेन्द्रित एवं व्यवस्था को जन्म देते हैं। आय एवं मन के वितरण समानता पर आधारित ये व्यवसाय सच्चे समाजवाद के प्रवर्तक हैं।

6. कृषि के पूरक—जैसा पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है ये उद्योग के पूरक (Complimentary) हैं। ये कृषि पर ही आधारित होते हैं और कृषि को भी लाभ पहुँचाते हैं। इन उद्योगों से कृषि विकास में सहायता मिलने के साथ-साथ कृषक की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है।

7. स्वयं लाभ—इन व्यवसायों में नैतिक व आर्थिक उत्थान, कलात्मक गौरव की वस्तुओं के निर्माण, कारखाना प्रणाली के दोषों से मुक्ति आदि लाभ भी प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार से व्यवसाय भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में पर्याप्त महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

**कतिपय सहायक व्यवसाय—**

यहाँ हम भारतीय ग्रामों में पाये जाने वाले कतिपय महत्वपूर्ण सहायक व्यवसायों का अध्ययन करेंगे—

1. दूध तथा घी का व्यवसाय (Dairying)—बहुते हैं कि प्राचीन भारत में घी और दूध की नदियाँ बहती थीं किन्तु अब इनकी बहुत कमी है। भारत सदा से ही प्रधानतः शाकाहारी (Vegetarian) देश रहा है इसलिए यहाँ दूध-घी का बहुत महत्व है। यद्यपि भारत का प्रति पशु औसत दूध का उत्पादन कम है फिर भी कुल मात्रा की दृष्टि से यहाँ ब्रिटेन का चार गुना, डेनमार्क का पाँच गुना, आस्ट्रेलिया का छः गुना तथा न्यूजीलैण्ड का सात गुना दूध तैयार किया जाता है। सन् 1961 में भारत में दूध का उत्पादन 220 लाख टन था जो तृतीय योजना के अन्त तक बढ़ कर 250 लाख टन हो जाने का अनुमान था।\*



लिए ये व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संदर्भ में हम इन व्यवसायों से प्राप्त होने वाले लाभों का अध्ययन करेंगे।

1. अर्द्ध-बेकारी की समाप्ति—भारतीय कृषक को साफ़ जरूरी काम करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष में बहू बार उन्हें बिना काम के बिताना है। ऐसे सालों समय की परिवार की आर्थिक समृद्धि के लिए इन व्यवसायों में संलग्न जा सकता है। इस प्रकार ये व्यवसाय हमारे देश में फैली अर्द्ध-बेकारी (partial unemployment) को समाप्त करने में सहायक हैं।

सहायक उद्योगों का महत्व

1. अर्द्ध-बेकारी की समाप्ति
2. कृषकों को अतिरिक्त आय
3. स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति
4. कार्य प्रणाली की सरलता
5. आर्थिक समानता
6. कृषि के पूरक उद्योग
7. अन्य लाभ

काम करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष में बहू बार उन्हें बिना काम के बिताना है। ऐसे सालों समय की परिवार की आर्थिक समृद्धि के लिए इन व्यवसायों में संलग्न जा सकता है। इस प्रकार ये व्यवसाय हमारे देश में फैली अर्द्ध-बेकारी (partial unemployment) को समाप्त करने में सहायक हैं।

2. कृषकों को अतिरिक्त आय—ये व्यवसाय किसानों को कृषि के अतिरिक्त भी आय प्रदान कर कृषकों के जीवन-स्तर को ऊँचा रखने में सहायता करते हैं।

3. स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति—कुछ वस्तुएं जिनकी सीमित या स्थानीय होती हैं। इन व्यवसायों के द्वारा पूरी की जा सकती हैं। बड़े उद्योग या पूर्ण समय के उद्योग इन वस्तुओं के लिए उपयोगी नहीं होते क्योंकि इनकी सीमित अत्यन्त सीमित होती है। इन व्यवसायों के द्वारा कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

4. कार्य प्रणाली की आवश्यकता—ये व्यवसाय बड़ी सरलता से बिमान, बिजली, खेत या बाड़ों में चलाये जा सकते हैं। इनके द्वारा परिवार के सदस्य भी अपना योग देते हैं। इनके लिए बड़े यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। एवं प्राचीन माथा में पूर्ण की आवश्यकता न होने के कारण दिनों द्वारा सरलता से अपना लिये जाते हैं।

2. ऊन व्यवसाय—भारतवर्ष में 4 करोड़ भेड़ें हैं जिनसे 720 लाख पौण्ड ऊन प्राप्त होती है। उत्तरी भारत की भेड़ों की ऊन सफेद तथा लम्बे रेशे वाली होती है। अब देश में 22 ऊनी कपड़े बनाने के कारखाने हैं जो गल्लोचे, कम्बल, जाल व ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं। सन् 1967-68 में हमने 1,142 लाख किलो\* के मूल्य की कच्ची ऊन (Raw wool) का आयात किया। हम घास्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से कच्चा ऊन तथा इंग्लैण्ड और इटली से ऊनी वस्त्र मंगाते हैं। देश के कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग हम कालोन-ऊन के रूप में निर्यात कर देते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।\*\*

भेड़ों से ऊन प्राप्त करने का व्यवसाय पंजाब, उत्तर-प्रदेश, मद्रास, राजस्थान, मसूर, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों में होता है। समुद्रमर, बेंगलोर, धीनगर, आगरा, मिर्जापुर व कानपुर ऊनी-वस्त्राद्योक्त के केन्द्र हैं।

प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष में भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के तरीकों के विज्ञान एवं नस्ल सुधारने के कार्यक्रमों पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तृतीय योजना के अन्त में ऊन का उत्पादन 900 लाख पौण्ड हो जाने का अनुमान था। योजना काल में ऊन के अथेणीकरण एवं भेड़ों की नस्ल सुधार के कार्यक्रमों की प्राथमिकता दी गई है।

3. चमड़े व छाल का व्यवसाय—भारतवर्ष में करोड़ों पशु मरते हैं और कुछ माँस प्राप्ति के लिए मारे जाते हैं जिनसे खालें प्राप्त होती हैं। हमें प्रतिवर्ष लगभग 250 लाख पशुओं की खालें प्राप्त होती हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गुजरात से बड़िया निस्म की खालें प्राप्त होती हैं। हम अधिकांश खालों को बाहर भेज देते हैं। रंगी हुई खालों का मुख्य माहक इंग्लैण्ड एवं बिना रंगी खालों का मुख्य आयातक का देश संयुक्त राज्य अमेरिका है।

\* India 1969, p. 371

\*\* Third Five Year Plan—P. 350

दूध उपभोग की दृष्टि से भारत की स्थिति अर्धतोषजनक है। एक व्यक्ति के सन्तुलित साह्वार में कम से कम 10 लीटर दूध प्रतिदिन होना चाहिये पर दुर्भाग्यवश भारत में प्रति व्यक्ति दूध का उपभोग लगभग 5 घोल प्रतिदिन है।\* पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड में अन्य राज्यों की तुलना में दूध का अधिक उपभोग किया जाता है।

भारतवर्ष में दूध उत्पादन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात और मध्यप्रदेश उल्लेखनीय हैं। दूध उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य पंजाब, बिहार, राजस्थान, मद्रास व मध्यप्रदेश हैं। अब कुछ व्यापारिक संस्थान बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन भी करने लगे हैं। हमारे यहाँ अब बड़े पैमाने पर दुग्ध-आम्रण सोयी जा रही है। भारतीय दुग्ध व्यवसाय के पिछड़ेपन के कारणों में पशुधों की कटिना मरुत, मिलावट की समस्या, पशुधों का दुर्बल एवं रोग-ग्रस्त होना, व्यवसाय का अल्पवस्थित होना आदि उल्लेखनीय हैं। दुधरी को सह-यक धन्यों में सबसे अधिक आय देने की व्यवसाय से मिलती है।

पचवर्षीय योजनाधों के अन्तर्गत डेयरी व्यवसाय के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम रखे गये हैं। प्रथम योजना में 781 माग रुपये खर्च करके बड़े शहरों में दुग्ध-वितरण योजनाएं चलाई गईं। द्वितीय योजना काल में डेयरी-विकास कार्यक्रमों पर लगभग 12 करोड़ रु० खर्च किए गये। अब डेयरी प्लांट्स की संख्या 29 है। दुग्ध वितरण की पाण्ड योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। पशु-वस्तियों तथा पशु-बोर्डन कार-खानों के विस्तार से डेयरी उत्पादों का विकास होया। दुग्ध-शालाओं के सम्बन्ध में छः प्रशिक्षण केन्द्र खोए जा रहे हैं। ये केन्द्र बरनाल, बैंगलोर, ऐरे, पानन्द, इमाहाबाद तथा हरिनाटा में स्थित हैं। तृतीय योजना काल में डेयरी कार्यक्रमों पर 36 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था थी।

2. ऊन व्यवसाय—भारतवर्ष में 4 करोड़ भेड़ें हैं जिनसे 720 लाख पौण्ड ऊन प्राप्त होती है। उत्तरी भारत की भेड़ों की ऊन सफेद तथा लम्बे रेशे वाली होती है। अब देश में 22 ऊनी कपड़े बनाने के कारखाने हैं जो गलीचे, कम्बल, जाल व ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं। वर्ष 1967-68 में हमने 1,1×2 लाख कच्चे\* के मूल्य की कच्ची ऊन (Raw wool) का आयात किया। हम घास्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से कच्चा ऊन तथा इंग्लैण्ड और इटली से ऊनी वस्त्र मंगते हैं। देश में कुल उत्पादन का लगभग आधा भाग हम कस्तीन-ऊन के रूप में निर्यात कर देते हैं जिससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।\*\*

भेड़ों से ऊन प्राप्त करने का व्यवसाय पंजाब, उत्तर-प्रदेश, मद्रास, राजस्थान, मंसूर, महाराष्ट्र व पुत्रगत राज्यों में होता है। प्रमृत्तमर, बेगनौर, श्रीनगर, आगरा, मिर्जापुर व कानपुर ऊनी-वस्त्राद्योप के केन्द्र हैं।

प्रमसना की बात है कि भारतवर्ष में भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के तरीकों के विकास एवं नस्ल सुधारने के कार्यक्रमों पर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तृतीय योजना के अन्त में ऊन का उत्पादन 900 लाख पौण्ड हो जाने का अनुमान था। योजना काल में ऊन के खेती करण एवं भेड़ों की नस्ल सुधार के कार्यक्रमों की प्राथमिकता दी गई है।

3. चमड़े व छाल का व्यवसाय—भारतवर्ष में करोड़ों पशु मरते हैं और कुछ मांस प्राप्ति के लिए मारे जाते हैं जिनमें खालें प्राप्त होती हैं। इन्हें प्रतिवर्ष लगभग 250 लाख पशुओं की खालें प्राप्त होती हैं। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गुजरात से बढ़िया किस्म की खालें प्राप्त होती हैं। हम अधिकांश खालों को बाहर भेज देते हैं। रंगी हुई खालों का मुख्य ग्राहक इंग्लैण्ड एवं बिना रंगी खालों का मुख्य आयातक का देश समुक्त राज्य अमेरिका है।

• India 1969, p. 371

•• Third Five Year Plan—P. 350

भारत से सन् 1967-68 में लगभग 7-39 करोड़ रुपये के मूल्य का चमड़ा और लाखों अन्य देशों को भेजा गया ।\*

भारतवर्ष में चमड़ा साफ करने और चमड़े की वस्तुएं बनाने का काम उत्तर प्रदेश के बानपुर व धागरा, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश में बहुतायत से होता है । कमाये हुए चमड़े से सूटकेस, दस्ताने, बूट, जूते-जूतियाँ, चप्पल, घट्टे, बैग, घंटे, बटुए, मशक, खरस, मोटर की सीटें, तबले, डोल, मंगाड़े, पुस्तकों की जिल्दनामी, कमर पेटीयाँ, सिलारी कपड़े आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं । दुर्भाग्यवश भारत में लाखों प्रांत करने व चमड़ा रंगने के तरीके बहुत पुराने हैं जिनसे उत्पत्ति की किस्म घटिया होती है और विदेशों में इनका मूल्य कम मिलता है । राष्ट्रीय योजना में इस सम्बन्ध में उचित कार्यक्रम अपनाये गये ।

4. खादी उद्योग—गाँवों में किसानों के परिवारों द्वारा कपास की रुई बनाने, सूत कातने एवं हाथ से कपड़ा बुनने का काम बहुतायत से होता है ।

भारतवर्ष में खादी का बहुत महत्त्व है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रपिता गाँधीजी ने जब राजनैतिक आन्दोलन का श्री गणेश किया तब उन्होंने इसके साथ ही देश की बेकारी को दूर करने के लिए खादी-प्रचार का आन्दोलन भी चलाया । पूरे राष्ट्र के शब्दों में “हाथ से कटाई भारतीय किसान के लिए आमदनी का एक स्थायी साधन है क्योंकि भोजन के पश्चात् मनुष्य को सबसे अधिक कपड़े की ही आवश्यकता होती है । घतः यह शास्वत और सार्वभौम है । इसके लिए किसी विशेष पूँजी और मंहंगे औजारों की जरूरत नहीं पड़ती । इसमें शारीरिक श्रम भी कम करना पड़ता है । अतः देश के ग़रीब और वृद्ध सभी समान रूप ॥ इस काम को कर सकते हैं ।”

ऊन एवं सूत कातने के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग

किया जाता है। सूनी कपड़े के लिए गरवदा चक, देशी चरखा, बिगान चक, अम्बर चरखा आदि अनेक प्रकार के चरखे काम में लाये जाते हैं।

5. हाथ में चावल साफ करने का उद्योग (Hand Pounding of Rice)—यह गाँवों में किया जाने वाला महत्त्वपूर्ण उद्योग है। सोसली या हाथ की चक्की द्वारा चावल से छिपका अलग किया जाता है। हाथ से साफ किया गया चावल अधिक शुद्ध और वीष्टिक माना जाता है। मिलों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य करने पर नियंत्रण हेतु 1958 में चावल मिल कानून का निर्माण किया गया जिससे इस उद्योग को प्रतिबन्धित नहीं कर सके। ग्रामीणों को रोजगार देने हाथ में कुटे चावल को लोकप्रिय बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए हैं।

#### 6. गुड़ एवं खंडसारी (Gur & Khandasari)

उद्योग—भारतवर्ष में चीनी मिलों के खुलने से पहले ही गाँवों में खाँड़ और गुड़ बनाने का व्यवसाय बहुत अधिक विकसित था। अब भी मुख्य गन्ना उत्पादक क्षेत्रों,



जैसे—उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में यह व्यवसाय प्रचलित है। इसमें गन्ने को कोल्हू में पेल कर रस निकाला जाता है फिर बड़े-बड़े कड़ाहों में उबाला जाता है और खाँड़ बनाने के लिए इस गाढ़े द्रव्य को बोरी में भरकर भारी वस्तु से दबाया जाता है। गुड़ बनाने के लिए इसकी शेलियाँ बना ली जाती हैं। गाँव में अब भी गुड़ का प्रयोग बहुत होता है।

7. ताड़ गुड़ उद्योग (Palm Gur Industry)—ताड़ के पेड़ों से गुड़ बनाने का यह व्यवसाय देश के अनेक भागों में होता है। यह कहा जाता है कि इस व्यवसाय में रोजगार देने और उत्पादन बढ़ाने की

बहुत सम्भावनाएँ हैं। अनुमानतः हमारे देश में 5 करोड़ ताड़ के पेड़ हैं। सारी तथा राष्ट्रीय उद्योग बोर्ड इस क्षेत्र में तकनीकी सहायता, मार्ग दर्शन, प्रदर्शन तथा वित्तीय सहायता दे रहा है। शराब बन्दी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए इस व्यवसाय का विस्तार करना आवश्यक है। इससे प्राप्त रकम—'नीरा' स्वास्थ्यवर्धक मस्तका पेय है।



ताड़-गुड़ उद्योग

8. मधु मक्खनी पालन (Bee keeping)—अधिकतर राज्यों में दिया जाने वाला यह व्यवसाय बहुत लाभदायक है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, केरल, मद्रास आदि राज्यों में यह व्यवसाय दिया जाता है। मधु मक्खनी पालन व्यवसाय से जहर, शीश आदि वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं। इस व्यवसाय में लगे हुए लोगों को प्रशिक्षण, मार्ग दर्शन एवं वित्तीय सहायता देने हेतु सारी-राष्ट्रीय कमीशन के कुछ कीटनाएँ बनाई हैं।

9. घासी तेल उद्योग (Ghee-Oil Industry)—घास तिलहन उत्पादक देशों में विश्व भर में दुबारा स्थान रखा है। इसके लो

नगरों में तेल प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े कारखाने चलाये जा रहे हैं फिर भी गाँवों में सेती के साथ-साथ घाणी (कोल्ह) से तेल निकालने का काम किया जाता है। कृषि कार्यों में खने बैलें एवं देशी कोल्ह की सहायता से यह व्यवसाय चलाया जाता है।

10. रस्सा एवं टोकरियाँ बनाने के व्यवसाय—किसान अपने अवकाश के समय में बटसन के रस्से बनाने का व्यवसाय करते हैं। ये रस्से कुपों से पानी निकालने, वस्तुओं को बाँधने, चारपाइयाँ बुनने व अन्य कृषि कार्यों में प्रयुक्त किये जाते हैं।

घरों में कृपकों की रिनयाँ देत के अनेक भागों में बाँस या बेंत की टोकरियाँ एक समय उपयोगी सामान बनानी हैं। यह व्यवसाय मुख्य रूप से उन भागों में किया जाता है जहाँ बाँस व बेंत आसानी से उपलब्ध होते हैं।

11. रेशमी कीड़े पालने का व्यवसाय (Sericulture)—भारत-वर्ष में 50 हजार से भी अधिक कुपक परिवार रेशम के कीड़े पालने का व्यवसाय करते हैं। मैसूर, पश्चिमी बंगाल, पच्छिम प्रदेश, बिहार तथा मद्रास में यह व्यवसाय बहुत प्रचलित है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त पदार्थ से री सिल्क तथा आर्ट सिल्क (Raw silk & Art Silk) बनाई जाती है जो बहुत उत्तम होती है। भारत में रेशम के कीड़े चार प्रकार के होते हैं—रेशम, टसर, अंडी और मूंगा। इनका पालन मुख्यतः गहलूड के पेड़ों पर किया जाता है।

12. जटा (Coir) उद्योग—भारियल की छरा के रेशों से अनेक प्रकार की सुन्दर वस्तुएँ तथा धटाइयाँ, बेंके, दरियाँ आदि बनाई जाती हैं। यह मोटर की राइयाँ, सोफासेट वहाँ आदि बनाने के काम भी आती है। भारतवर्ष का यह व्यवसाय मुख्य रूप से केरल में होता है जहाँ भारियल की सबसे अधिक उपज होती है। मैसूर, मद्रास, पं० बंगाल



व उद्योगों में भी जटा उद्योग प्रचलित है। इससे बनी वस्तुएं विदेशों में भेजकर अधिकाधिक विदेशी मुद्राएं प्राप्त की जा सकती हैं।

13. अन्य व्यवसाय—कृषि सहायक पन्थों में बैलगाड़ी किराने पर चलाने का काम, सब्जी व फल उगाने का व्यवसाय आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं। ये व्यवसाय कृषक की आय में वृद्धि करते हैं।

जैसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में इनका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु इनको अविश्व रक्षने के लिए यह आवश्यक है कि कृषक को कृषिपथ नवीन तकनीकियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सहायता एवं तकनीकी मार्ग दर्शन इन व्यवसायों की उत्पत्ति में सहायक होगा।

### सारांश

कृषि के अतिरिक्त किये जाने वाले व्यवसाय से ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को समृद्धि प्राप्त होती है। यह तीन बातों पर निर्भर करती है—  
(1) सामाजिक व धार्मिक दृष्टिकोण, (2) आवश्यक करने मान की उपलब्धि, (3) विपणन की सुविधा।

सहायक उद्योगों का महत्व—

1. अर्थ-बेकारी की समाप्ति, (2) कृषकों को अतिरिक्त आय, (3) स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति, (4) बायें प्रणाली की तर-सहा, (5) आर्थिक समानता, (6) कृषि के गुरुक तथा (7) अन्य लाभ।

मुख्य सहायक उद्योग—

1. दूध तथा घी का उद्योग, (2) ऊन उद्योग, (3) चमड़े व ताम का उद्योग, (4) लोदी उद्योग, (5) हाथ से चारन बाँध करने का उद्योग, (6) मृद एवं लकड़ी का उद्योग, (7) ताड़ गुड़ उद्योग, (8) मधु मक्खी पालन, (9) चानी हेतु उद्योग,

(10) रस्सा व टोकटियाँ बनाने का उद्योग, (11) रेशमी कीड़े पालने का व्यवसाय, (12) जूटा उद्योग, (13) अन्य व्यवसाय ।

### प्रश्न

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक उद्योगों का क्या महत्व है ? स्पष्ट कीजिए ।
  2. प्रमुख सहायक उद्योगों का वर्णन कीजिये ।
  3. टिप्पणियाँ लिखिए—
    - (अ) दूध तथा घी का व्यवसाय,
    - (आ) ऊन व्यवसाय,
    - (इ) चमड़ा उद्योग तथा
    - (ई) सादी उद्योग ।
-

## अध्याय 12

# भारतमें भूमि सुधार

## LAND REFORMS IN INDIA

“भूमि सुधार का सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विद्यान के महत्त्व है।”

—हेनरिच चानर

आर्थिक विद्यान में भूमि की सुधारण व्यवस्था (System of Land Tenure) तथा भूमि सुधारों (Land Reforms) का बहुत प्रभाव पड़ता है। भूमि पर किसान के उचित अधिकार ■ बढ़कर कृषि विद्यान की ओर कोई प्रेरणा नहीं हो सकती। श्री आर्थर यंग ने ठीक ही कहा है “अधिकार का जादू रेत को भी सोने में परिवर्तित कर सकता है।”●

भूमि सुधारों का अर्थ एवं महत्त्व (Meaning and Importance of Land Reforms)

भूमि सुधार का अर्थ उन परिवर्तनों से है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सामाजिक न्याय की प्रेरणा देता है। ये परिवर्तन सुधारण की प्रथा, कृषि जोत का प्रकार, काश्तकारी सुधार, लगान, उत्पादन वृद्धि ■ प्रयत्नों आदि से सम्बन्ध रखने वाले होते हैं।

आर्थिक विकास के लिए भूमि सुधारों का बहुत महत्त्व है। भूमि सुधारों से कृषि में विकास होता है भूमि सुधार का तीन दृष्टियों से

●“The magic of property can turn sand into gold.” — Arthur young.

महत्व है—(1) कृषक की आय बढ़ाने के लिए, (2) कृषि के उत्पादन में वृद्धि आने के लिए, तथा (3) सामाजिक न्याय दिखाने के लिए ।

डॉ. वायलकर ने भूमि सुधारों का महत्व केवल उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से ही अधिक माना है । डॉ० आर. के. मुकुर्जी ने इनका महत्व कृषक के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए माना है । डॉ० दातात्राया के अनुसार भूमि सुधार 'सामाजिक न्याय' की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है । प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधारों की आवश्यकता सामाजिक न्याय तथा आर्थिक प्रगति के लिए अनुभव की है ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि सुधारों की आवश्यकता आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दृष्टि से होती है । भूमि सुधारों से ही कृषि विकास की प्रेरणा, अधिक साधनों व कच्चे माल की प्राप्ति, ऊँचा जीवन स्तर, अधिक आय, बचत व पुँजी निर्माण का स्तर एवं समानता का वातावरण तैयार होता है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भूमि व्यवस्था—

भारत में प्राचीन काल की भूमि व्यवस्था का विवरण मनुस्मृति में मिलता है । उस समय भूमि की उपज में से राज्य सामान्यतः  $\frac{1}{6}$  भाग और विपत्तिकाल में  $\frac{1}{3}$  भाग लेता था । मुगलकाल में भूमि व्यवस्था में शेरशाह तथा टोडरमल ने सुधार किये । तदीपरान्त लार्ड कार्नवालिस ने स्थायी बन्दोबस्त ( Permanent Settlement ) की प्रथा चालू की ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भू-धारण की तीन प्रथाएँ प्रचलित थीं—

1. रयतवाड़ी (Ryotwari) प्रथा—यह प्रथा स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले बम्बई (अब महाराष्ट्र), दक्षिणी मद्रास, मद्रिदास प्रान्त व बिहार के कुछ भागों में प्रचलित थी । इस प्रथा में किसान मालगुजारी (land revenue) सीधे सरकार को देता था । यह प्रथा सन् 1792 में कॅप्टेन रॉड व बॉमिस मुनरो द्वारा चालू की गई थी ।

2. **महलवाड़ी (Mahalwari) प्रथा**—इस प्रथा का जन्म सन् 1833 में रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अन्तर्गत मायरा व अवध में हुआ। इस प्रथा में सरकार द्वारा भूमि उस ग्राम के कुछ व्यक्तियों को समुदाय के रूप में दी जाती थी जो भूमि को किसानों में विभक्त कर देता था। समुदाय का मुखिया सरकार को सगान देता था। यह प्रथा पंजाब, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती थी।

3. **जमींदारी (Zamindari) प्रथा**—इस प्रथा में एक व्यक्ति (जमींदार) कई गांवों या एक गांव अथवा उसके किसी हिस्से का स्वामी माना जाता था। जमींदार सरकार को मालगुजारी चुकाने के लिए उत्तरदायी होता था। जमींदार कृषकों को भूमि लगान पर देता था। इस लगान में से कुछ अपने पास रख कर शेष सरकार को दे देता था। इस प्रकार जमींदार किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ (middleman) का काम करता था। सरकार को इस प्रथा से यह लाभ था कि उसे किसान से लगान वसूल करने का कठिनाई वाला काम नहीं करना पड़ता था। किन्तु इस पद्धति में धीरे-धीरे घने कुरादियों का समावेश हो गया। इस प्रथा के अन्तर्गत कृषकों का शोषण, उत्पादन में प्रेरणाओं का अभाव, जोतों का घनामकारी होना, राजनीतिक शोष आदि अनेक कुरादियाँ उत्पन्न हो गईं।

इन्हीं अनेक दोषों के कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहिले जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का निर्णय लिया गया।

**भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम—**

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने कृषकों की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से भूमि सुधार के अनेक कार्यक्रम बनाये।

1. **जमींदारी प्रथा एवं मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति**—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाये गये। जमींदारी उन्मूलन का कार्य अत्यन्त दूर तक निभा गया है। इससे लगभग 2 करोड़ रुपये वाले कारागार सीधे सरकार के नियन्त्रण में आ गए।

सहकारी कृषि एवं चकबन्दी कार्यक्रमों में इस सुधार से सहायता मिली। जमींदारों को मुद्यावजा एवं पुनर्वासि के लिए अनुदान के रूप में लगभग 320 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। अनुमान है कि लगभग 250 करोड़ रुपये और दिया जाएगा।\*

2. कास्तकारी सुधार (Tenancy Reforms)—एक मई-विकसित देश में जहाँ भूमि पर जनसंख्या का भार बहुत अधिक हो तथा जमींदारों द्वारा शोषण होता हो वहाँ कास्तकारी सुधार सामाजिक न्याय की दृष्टि से वांछनीय है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विविध राज्यों में कास्तकारी कानून बनाये गये।

समान नियमन (Regulation of rent) के अन्तर्गत कास्तकारों से लिये जाने वाले अधिकतम लगान की सीमा तय कर दी गई। प्रथम योजना में गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान में कुल उपज का  $\frac{1}{6}$ , दिल्ली में  $\frac{1}{6}$  तथा उड़ीसा में  $\frac{2}{3}$  भाग लगान के रूप में लिये जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई।

लगभग प्रत्येक राज्य में कास्तकारों की सु-धारण की सुरक्षा के सम्बन्ध में कानून बनाये गये जिससे किसान को मनमाने तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता।

कास्तकारी पुनर्ग्रहण (Resumption of tenancies) एवं कास्तकारों को स्वामित्व (ownership) के अधिकार दिलाने के सम्बन्ध में भी अनेक कानून बनाये गये। तृतीय योजना में कास्तकारों को भू-स्वामित्व दिलाने का अधिक कार्य किया गया।

3. सीमा निर्धारण (Ceiling of Land Holdings)—समाजवादी समाज की रचना की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के अधिकार में रहे जा सकने वाली भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। इससे आर्थिक व सामाजिक न्याय की प्राप्ति है। इसी दृष्टि से अनेक राज्यों में सीमा निर्धारण कानून बनाये गये।

कानून दो प्रकार के हैं (1) भविष्य के जोतों पर सीमा निर्धारण तथा (2) वर्तमान जोतों पर सीमा निर्धारण। भूतपूर्व पंजाब राज्य को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों में ये कानून बन चुके हैं। सीमा निर्धारण कानूनों को लागू करने में सरकार को जो अतिरिक्त भूमि मिलेगी उसका उपयोग भूमिहीन अधिकों के लिए किया जायगा। भिन्न-भिन्न राज्यों में यह सीमा भिन्न भिन्न है।\* सीमा निर्धारण करते समय भूमि की विरम आदि का ध्यान रखा गया है।

● विभिन्न राज्यों की वर्तमान एवं भविष्य की जोतों का सीमा निर्धारण निम्नांकित प्रकार से किया गया है—(Source : India 1969 ■. 253)

राज्य	भविष्य (ए० ई० में)	वर्तमान
आंध्र प्रदेश	18 से 26	27 से 324
बिहार	20 से 60	20 से 60
जम्मू-काश्मीर	22 3/4	22 3/4
मध्य प्रदेश	25 से 75	25 से 75
महाराष्ट्र	18 से 126	18 से 126
उड़ीसा	20 से 80	20 से 80
राजस्थान	25 से 336	25 से 336
प० बंगाल	25	25
मणिपुर	25	25
असम	50	50
गुजरात	19 से 132	19 से 132
केरल	15 से 36	15 से 36
मद्रास	24 से 120	24 से 120
मैसूर	18 से 141	27 से 216
पंजाब	20 से 248	20 से 248
सत्तर प्रदेश	12 1/2	40 से 80
...	24 से 60	24 से 60
...	25 से 75	25 से 75

4. **चकबन्दी**—दूरस्थ छोटे-छोटे क्षेत्रों की समस्या के हल का प्रथम उपाय चकबन्दी (consolidation) है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिल, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में चकबन्दी कार्यों में काफी प्रगति हुई। हरियाणा एवं पंजाब में चकबन्दी का कार्य लगभग पूरा हो गया है। वर्ष 1968-69 के अंत तक 2,957 करोड़ हेक्टर भूमि पर चकबन्दी की गई।

5. **सहकारी कृषि**—प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी कृषि को गुरुत्व आधार पर बढ़ा करने का निश्चय किया गया। तृतीय योजना में पाँचवटी योजनाओं के अंतर्गत 2,749 सहकारी कृषि समितियाँ तथा साइलेंट योजनाओं के माध्यम से 2,752 सहकारी कृषि समितियाँ बनाई गईं। साथ ही वर्ष 1968 के अंत में इन सहकारी समितियों की संख्या 8,582 थी। अनुसंधान में इस विचारधारा को अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सहकारी कार्यक्रमों को नियोजन एवं प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी कृषि स्नातक संशोधन का गठन किया गया है सहकारी कृषि कार्यक्रमों में प्रविष्टि की भी व्यवस्था की जा रही है।

6. **भूदान (Bhoodan)**—स्वच्छता से भूमि की रेंट का वह राष्ट्रीय वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने चलाया। आन्दोलन में बहोली को लक्ष्य करते हुए भावे ने कहा है कि "एक स्थाय एवं सम्पत्ति के निदाओं पर आधारित समाज में भूमि पर सभी को अधिकार होना चाहिए। इसीलिए हम भूमि की विधा नहीं मानते बल्कि इसे की देना करते हैं जिस पर निषेधों का सही अधिकार होता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि सभी विभागों का प्रतिपादन किया जाने लिये बिना किसी प्रकार के अनाधिकार एवं अधिकार का दावा को ही किया जा सके।" अतः हमें भूदान वह आन्दोलन है जो स्वच्छता के सिद्धि से भूमि के दान पर आधारित है। आनन्द दत्त



मान्योपन के अनेक रूप हैं, यथा-व्याप्तिसदान, बुद्धिसदान, जीवन दान, साधन दान, दुह दान व दान दान । मार्च 1967 तक 42.7 लाख एकड़ भूमि भूदान में प्राप्त की गई जिसमें से 12 लाख एकड़ भूमि निर्धन भूमिहीनों में बाँट दी गई थी । अगस्त सन् 1967 तक 39,672 गाँव 'दामदान' मान्योपन में सम्मिलित हो गये हैं ।\*

7. **भूमि सुधार**—उत्प्रेषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमि के संलग्न व भूमि के साधन एवं पद्धति को उत्तम करने के अनेक प्रयत्न किये गये हैं । भूमि के उर्वरिमात्रन एवं अलग-अलग की रोहने के लिए हस्तांतरण, उत्तराधिकार एवं लीज (Leases) के सम्बन्ध में अंशुल सगाने के कानून भी लगभग सभी राज्यों में पारित हो गये हैं ।

**भूमि सुधार कार्य कर्मों का मूल्यांकन (Evaluation)**—

भारत में भूमि सुधार के अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किये गये किन्तु अनेक कारणों से इनका प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितनी आशा की गई थी ।

कृषि उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से जमींदारी उन्मूलन, कामगारी सुधार, थक श्रमी, सरकारी कृषि एवं साधन व पद्धति में किये गये प्रयत्न उत्तेजनीय हैं । इन कार्यक्रमों से कृषिजन्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

सामाजिक न्याय की दृष्टि से भूमि सुधारों से बहुत अपेक्षाएं थी किन्तु उनकी आंशिक पूर्ति ही सम्भव हुई है । जमींदारी प्रथा के उन्मूलन एवं भू-धारण की सुरक्षा से जहाँ कृषक को निश्चिन्ता प्रदान करने के प्रयत्न किये गये वहाँ सीमा निर्धारण, भूदान एवं अन्य सौजन्यात्मक उपायों से निर्धन भूमि-हीन धर्मिकों को अपने आर्थिक विकास के अवसर प्रदान किये गये । भूमि सुधारों से सामाजिक न्याय व समानता की प्रेरणा मिलती है ।

हमारे यहाँ अनेक कारणों से भूमि सुधारों के वांछित परिणाम नहीं मिले । इस सम्बन्ध में योजना आयोग ने अनुभव किया है और कहा

है कि "वह बात बहुत ही कम समझी गई कि भूमि सुधार एक सचेष्ट विराम कार्यक्रम है। यह मनी-पाति अनुभव नहीं किया जाता है कि भू-स्वामित्व में सुधार करना तथा जोत की अधिकतम सीमा सीमा लागू करना सहकारिता पर आधारित ग्राम्य एवं व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकताओं हैं। यही नहीं भूमि सुधारों के प्रशासनिक ढंग की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। मिल-मिलाकर कानून की उपेक्षा करने या अमल न करने की चेष्टाएं के-रोक-टोक बस रही हैं। कानून की कारगर छोर पर लागू करने के लिए ग्राम समाज का समर्थन तथा अनुमति भी हासिल नहीं की जा सकी है।"

भारत में भूमि सुधारों की वांछित सफलता न मिल सकने के कारणों में भूमि सुधार कानूनों की दुर्बलताएं, कार्यान्वयन में निविमता, कारतुषारी सूचनाओं (Tenancy Records) का अभाव आदि उल्लेखनीय हैं।

इस प्रकार भारत में भूमि सुधारों की दिशा सही होते हुए भी प्रशासनिक एवं अन्य कारणों से ये अपना अधिक प्रभाव नहीं दिखा सके हैं। विधि में सुधार लाने के लिए भूमि सुधारों पर कोई फोर्सेफाउन्डे-शन के दम की रिपोर्टें तथा भूमि सुधारों पर मागपुर-प्रस्ताव (1959) में वर्णित उपाय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये सुझाव हैं—कृषि व्यवस्था में सीब, रोजगार के वैकल्पिक साधन, आर्थिक प्रेरणार्थ, ग्राम संगठनों का सहयोग, जागी व्यवस्था का स्वल्प, सहकारी कृषि, कीमतों का निर्धारण आदि।

भूमि सुधारों के सम्बन्ध में अधिक विस्तार नहीं किया जाना चाहिये। यही कृषि विकास एवं सामाजिक न्याय में क्षेत्र में जाया की दिशा है।

**राजस्थान में भूमि सुधार (Land Reforms in Rajasthan)**

ग्राम राज्यों की भांति भूमि सुधार के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक प्रयत्न किए गए। (1) जमींदारी समाप्त करने के

‘नए सन् 1952 में ‘भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गठन अधिनियम’ पारित हुआ। इस कानून के अन्तर्गत 17,000 गांवों में बसने वाले काश्तकारों को लाभ मिला और जमींदारी उन्मूलन के कारण 80 प्रतिशत भूमि पर सरकार का सीधा अधिकार स्थापित हो गया। सरकार ने जागीरदारों को लगभग 36 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिये। अब तक लगभग सभी जागीरें समाप्त कर दी गई हैं।

2. जमींदारी व बिस्वदारी उन्मूलन के लिए सन् 1958 में अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम सन् 1959 में लागू किया गया जिसके अनुसार राज्य के 8 जिलों में श्याम दल प्रजा का उन्मूलन हो गया।

3. सन् 1955 में राजस्थान काश्तकारी कानून (The Rajasthan Tenancy Act) पारित हुआ। इस कानून के पारित होने से पूर्व मल्ल-मल्ल देशी रियासतों के अलग-अलग कानून थे। काश्तकारी कानूनों में मुख्य उल्लेखनीय हैं—काश्तकारी रक्षा अध्यादेश, 1949 (बेइसमी रोकने हेतु), राजस्थान उपज लगान नियमन अधिनियम, 1952 (मध्य-स्थों द्वारा 1/6 उपज से अधिक लगान नहीं लिया जा सकता), काश्तकारी कानून, भू-राजस्व कानून 1955 आदि। इन कानूनों के पारित होने से राजस्थान में काश्तकारों की भू-धारण की सुरक्षा, उचित लगान, बेजार से मुक्ति आदि लाभ प्राप्त हुए हैं।

4. ज़ोनों का सीमा निर्धारण (ceiling on land holdings) — करने में कानून बना दिये गये हैं। सीमा निर्धारण सामाजिक न्याय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में वर्तमान तथा यात्री ज़ोनों पर 25 से 336 एकड़ की सीमा निर्धारित कर दी है।

5. अन्य सुधार—भूमि सुधारों में अन्य उल्लेखनीय बातों में भूदान सहकारी दृष्टि एवं चरबन्दी हैं। राजस्थान में भूदान से प्राप्त 417-450 एकड़ भूमि में से 92,623 एकड़ भूमि का वितरण—कर दिया गया है। चरबन्दी कानून के अन्तर्गत राज्य में 585 गांवों में चरबन्दी

की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त राजस्थान में भू-अभिलेख (Land Records) भी नियमित रूप से रचे जा रहे हैं।

इस प्रकार पिछले 20 वर्षों में राजस्थान में भूमि सुधार के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

### सारांश

भूमि सुधारों का अर्थ और महत्व—भूमि सुधार का अर्थ उन परिवर्तनों से है जो कृषि उत्पादन में वृद्धि कर सामाजिक न्याय की प्रेरणा देता है। भूमि सुधार का तीन दृष्टियों से महत्व—(1) कृषक की आय बढ़ाने के लिये (2) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा (3) सामाजिक न्याय दिलाने के लिए।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भूमि व्यवस्था—स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व भू-पारण की तीन प्रथाएँ प्रचलित थी—(1) रैयतवाड़ी (2) महलवाड़ी (3) जमींदारी—जमींदार किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ का काम करता था। इससे छः प्रकार की बुराइयाँ होती थी—(1) कृषकों का शोषण (2) कृषि उत्पादन में कमी (3) कृषक की ज़ूत पस्तता (4) जोत का असामयिक होना (5) देश हितों के प्रतिवृत्ति (6) अनाधिक पद्धति।

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम—स्वतन्त्र भारत में भूमि सुधार के अनेक कार्यक्रम बनाये गये। जिनमें प्रमुख इस प्रकार से हैं—(1) जमींदारी प्रथा एवं मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति (2) कालांतरकारी सुधार (3) सीमा निर्धारण (4) पक्कवादी (5) सहकारी कृषि (6) भूदान (7) अग्र सुधार।

भूमि सुधार कार्यक्रमों का मूल्यांकन—अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के बावजूद अनेक कारणों से उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ा जितना कि पड़ना चाहिये था।

राजस्थान में भूमि सुधार—राजस्थान में इस प्रकार भूमि सुधार प्रयत्न किए गए—(1) जागीरदारी समाप्त करने के लिए 1952 का

अधिनियम, (2) जमींदारी व बिस्वेशरी उन्मूलन के लिए 1958 का अधिनियम, (3) 1955 का राजस्थान काश्तकारी कानून, (4) क्षेत्रों का सीमा निर्धारण, (5) अन्य सुधार ।

इस प्रकार राजस्थान में भूमि सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम चलाये गए ।

### प्रश्न

1. "भूमि सुधार का सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास से गहरा सम्बन्ध है"—डेनियल पार्नर—आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं ?
2. भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था में इसका क्या महत्व है ?
3. स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में हुए भूमि सुधार का वर्णन कीजिये ।
4. सक्षित टिप्पणी लिखिये—
  - ( i ) दैयतवाड़ी
  - ( ii ) महसुवाड़ी
  - ( iii ) जमींदारी
  - ( iv ) बकबन्दी
  - ( v ) सहकारी कृषि
  - ( vi ) भूदान ।

## अध्याय 13

### कृषि श्रमिक

#### AGRICULTURAL LABOUR

“पञ्चवर्षीय योजनाओं का एक मूल उद्देश्य यह भी है कि ग्रामीण जनता के सभी वर्गों को रोजगार और अच्छे जीवन के सभी अवसर प्रदान किए जायें और खास कर खेतिहर श्रमिकों और पिछड़ी हुई जातियों को शेष व्यक्तियों के स्तर तक आने के अवसर प्रदान किए जायें।”

—भारतीय योजना आयोग

किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि वहाँ के स्वास्थ्य एवं परिवर्तन निवासियों पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में यहाँ भारत की स्थिति का अध्ययन कर लेना उचित होगा। 32,68,090 वर्ग किलोमीटर\* क्षेत्रफल वाला भारत देश जिसमें लगभग 51½ करोड़ जनसंख्या रहनी है अपनी अनेक विशेषतायें रखता है। यह जनसंख्या सम्पूर्ण विश्व की जनसंख्या की 16 प्रतिशत है। हमारे देश में लगभग 68.9 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि सम्बन्धी अन्य व्यवसायों पर आधारित है।

कृषि व्यवसाय पर आधारित जनसंख्या में अधिकांश कृषक प्रचाराईय श्रमिक ही हैं। कृषि श्रमिकों का मात्र एक अल्प वर्ग बन गया है।

19 वीं शताब्दी के पूर्व इनका स्पष्ट वर्ग अलग से नहीं था। 19वीं शती के अन्त में इनकी संख्या अधिक नहीं थी। किन्तु 20 वीं शताब्दी

में उनकी संख्या में वृद्धि हुई। इसी समय इनकी अनेक समस्याओं ने  
उप रूप धारण कर लिया। नौशा जीवन स्तर, निर्पेनडा, बेकारी,



## कृषि श्रमिक

भूत-बेकारी आदि आज भी इन श्रमिकों की मुख्य समस्याएं हैं।  
सरकार ने भी इन समस्याओं के निराकरण के प्रयत्न प्रारम्भ  
दिये हैं।

अर्थ—

सन् 1951 की जनसङ्ख्या में कृषि श्रमिक उन्हें माना गया जो ज़ेठों पर मजदूरी लेकर काम करे। लेकिन इस परिभाषा में उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया जिनके पास थोड़ी बहुत भूमि भी है चाहे वे ज़ेठों में मजदूरी ही करते हों। इस प्रकार 1951 तक कृषि श्रमिकों में केवल 'भूमि हीन' (Land less) श्रमिकों को ही सम्मिलित किया गया।

सन् 1950-51 में गठित प्रथम खेतिहर श्रम आँख समिति (First Agricultural Labour Enquiry) ने कृषि श्रमिक उन्हें माना है जो वर्ष में अपने काम के कुल दिनों में आधा से अधिक दिन सन्ताने में श्रमिक के रूप में कार्य करें।

सन् 1956-57 की खेतिहर श्रम आँख समिति (द्वितीय) ने कृषि के अतिरिक्त पशुपालन बागवानी एवं दुग्ध व्यवसाय में लग्न श्रमिकों को भी कृषि श्रमिक माना है जिनमें कृषि कार्यों में मजदूरी मास का प्रमुख साधन हो।

कृषि श्रमिक आँखों (Agricultural Labour Enquiries) के परिचाय—

कृषि श्रम की प्रथम आँख सन् 1950-51 में की गई। इस आँख में 300 गाँवों के 11,000 कृषि श्रमिक परिवारों का अध्ययन किया गया। इस आँख के प्रतिवेदन (Reports) सन् 1954-55 में प्रकाशित हुए।

द्वितीय आँख सन् 1956-57 में सम्पन्न हुई जिसका प्रतिवेदन सन् 1960 में प्रकाशित हुआ। इस आँख में 3,600 गाँवों के 28,560 परिवारों के आँखें एकत्रित किये गए।



एक अन्य जाँच—ग्रामीण श्रम जाँच (Rural Labour Enquiry)—सन् 1963 में की गई जिसकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं हुई है।

प्रथम एवं द्वितीय जाँच के तुलनात्मक परिणाम नीचे दिये जा रहे हैं।

1. सन् 1956-57 में कृषि श्रमिक परिवारों की संख्या 1.63 करोड़ आंकी गई जबकि सन् 1950-51 में यह संख्या 1.79 थी। इस कमी का कारण समभवतः इन दोनों जाँचों में 'कृषि श्रमिक' की परिभाषा का अंतर है।

2. भूमिहीन कृषि श्रमिकों का प्रतिशत सन् 1956-57 में 57 था जबकि सन् 1950-51 में यह प्रतिशत 50 था।

3. सन् 1950-51 में स्थायी श्रमिकों (Attached Labour) तथा मसंघायी श्रमिकों (Casual Labour) का अनुपात 10 : 90 था सन् 1956-57 में स्थायी श्रमिकों का प्रतिशत 27 था।

4. कृषि श्रमिक परिवार के सदस्यों की औसत संख्या सन् 1950-51 (4.30 सदस्य) की तुलना में सन् 1956-57 में बढ़ (4.40 सदस्य) गई।

5. सन् 1950-51 में 3.5 करोड़ कृषि श्रमिक (जिनमें से 1.9 करोड़ पुरुष, 1.4 करोड़ स्त्रियां, 20 लाख बच्चे) थे जबकि सन् 1956-57 में कृषि श्रमिकों की संख्या 3.3 करोड़ थी (जिसमें 1.8 करोड़ पुरुष-स्त्रियां तथा 30 लाख बच्चे शामिल हैं)।

6. कृषि श्रमिकों के (मसंघायी) रोजगार की तुलनात्मक स्थिति निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाती है—

श्रमिक (अस्थायी)	मजदूरी पर जाने के दिन		स्वयं के काम में लगने के दिन		बकारी के दिन	
	1950-51	1956-57	1950-51	1956-57	1950-51	1956-57
पुरुष	200	197	75	40	90	128
स्त्रियाँ	134	141	×	×	×	×
बच्चे	165	204	×	×	×	×

7. सन् 1950-51 में कृषि एवं गैर कृषि मजदूरी से कृषि श्रमिकों की आय का 76 प्रतिशत भाग हुआ वहीं सन् 1950-51 में यह प्रतिशत 81 था। सन् 1950-51 की तुलना में द्वितीय आँक में मजदूरी की दर में कमी का सामास मिला। सन् 1950-51 में वहाँ प्रति श्रमिक परिवार की औसत वार्षिक आय 447 थी वहीं सन् 1956-57 में यह घटकर 437 हो गई।

8. कृषि श्रमिक परिवारों का औसत वार्षिक उपभोग जहाँ सन् 1950-51 में 461 रुपये के मूल्य का होता था वहीं सन् 1956-57 में बढ़कर 617 हो गया। इस प्रकार जहाँ पहले 14 रुपये का घाटा था वहाँ दूसरी आँक में यह घाटा 180 रुपये प्रति परिवार हो गया। इस बड़ी हुई घाटे की रकम को प्राप्त करने से जून दस्तगा में वृद्धि हुई। पहले जहाँ सन् 1950-51 में प्रति परिवार 47 रुपये का खर्च था वहाँ बढ़कर सन् 1956-57 में 88 रुपये हो गया।

उक्त दोनों आँक प्रतिवेदनों के परिणामों का अध्ययन कर लेने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि सन् 1950-51 की तुलना में हुए मजदूर परिवारों की समस्या में कमी हुई है। भोजन, आवास एवं मजदूरी की दरों में गिरावट आई है। जून आर एवं निर्धनता की वृद्धि हुई है। ये सब परिणाम इनकी समस्या की गम्भीरता को प्रमाणित करते हैं।

× आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कृषि धमिकों की संख्या में वृद्धि—

विद्यमान 70-80 वर्षों में कृषि धमिकों की संख्या एवं समस्याओं में वृद्धि हुई है। इनके वृद्धि के कारणों की जानकारी नीचे दी जा रही है—

कृषि धमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण

1. जनसंख्या में वृद्धि
2. भूमि पर जन भार में वृद्धि-उपविभाजन
3. कुटीर उद्योगों का पतन
4. सामाजिक कारण
5. शिक्षा का अभाव
6. अन्य कारण

1. भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 125 लाख से जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की वही दर रही तो लगभग 45 वर्ष बाद भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। "इस तेज गति से बढ़ने वाली जनसंख्या ने कृषि धमिकों की संख्या में वृद्धि कर दी है।

2. भूमि पर जन भार में वृद्धि एवं उपविभाजन की समस्या ने भी कृषि धमिकों के इस वर्ग में संख्या को वृद्धि की है। ग्रामीण जीवन में अन्य व्यवसायों का अभाव होने से गांव की सम्पूर्ण जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रहना चाहती है किन्तु भूमि के अभाव में अधिकांश व्यक्तियों को कृषि धमिक बन जाना पड़ता है।

3. कुटीर उद्योगों का पतन—कुटीर उद्योगों के पतन के कारण इन व्यवसायों में लगे कारीगर भी कृषि धमिक बन गये। लघु उद्योगों के अभाव में इन कारीगरों को कृषि के प्रतिरिक्त किसी भी व्यवसाय में रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसलिये कृषि धमिकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

4. सामाजिक कारण—वर्तमान ग्रामीण समाज में फँसी हुई रुढ़ियों के कारण सामान्यतः भूमिहीन धमिक गाँवों को छोड़कर सामग्र

श्रवणार्थों में रोजगार प्राप्त करने में हिचकिचाता है। पत्रिणाभस्वल्प गाँव में ही कृषि श्रमिक के रूप में अपने जीवन यापन का कार्य करता है।

5. शिक्षा का अभाव—हमारे समाज एवम् देश का सबसे बड़ा शत्रु अनिज्ञा है। गाँवों में अनिज्ञा के कारण अज्ञानता, रुढ़िवादिता आदि के दलदल में फना व्यक्ति अपने को नहीं छुड़ा सकता और बाध्य होकर कृषि श्रमिक बन जाता है।

6. अन्य कारण—छोटे-छोटे सेतो के मालिक किसान पूँजी के अभाव में अपनी कृषि विकास योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर पाते। माण्यवादी दृष्टिकोण एवम् भ्रष्ट प्रवृत्तता ऐसे अन्य कारण हैं जिनसे भारतीय किसान केवल कृषि श्रमिक बन कर अपना जीवन यापन करता है।

उपरोक्त कारणों ने भारतीय कृषि श्रमिकों की समस्या में वृद्धि कर अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं। डॉ० राधाकमल मुकुर्जी ने तेजी से बढ़ते चले कृषि श्रमिकों की संख्या के कारणों को इस प्रकार स्पष्ट किया है—“ग्रामीण सर्व-व्यवस्था में सम्मिलित अधिकारों का नष्ट होना, सामूहिक उपक्रम का विघटन, जोतों का उपविभाजन, कुटीर कंधोगों का पतन, लगान लेने वालों की संख्या में वृद्धि, भूमि की गिरवी रखने तथा स्थानांतरित करने पर प्रतिबन्ध न होना। इन बातों ने छोटे कृषकधारियों की स्थिति को दुर्बल बनाकर कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि कर दी है।”

कृषि श्रमिकों की समस्याएँ—

जैसा ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है भारत में कृषि श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। आज जिन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है वे हैं—बेकारी, एवम् धड़-बेकारी, नीची मजदूरी, नीचा जीवन स्तर, भ्रष्ट प्रवृत्तता, अनिज्ञा, बेगार, कृषक दासता, बाय के निर्दमित पध्दे एवम् प्रवृत्ति, लगान का अभाव, आवास समस्या, आदि।

सुझाव—कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि शीघ्र ही राज्य एवं समाज सेवा संस्थाएँ आवश्यक प्रयत्न करें। कृषि श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने की दिशा में निर्माकित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं—

1. औद्योगिक विकास—देश में परम्परागत उद्योगों के पुनर्र्थान के अतिरिक्त मूल एवं नारी उद्योगों का विस्तार दिया जाना परम्परा आवश्यक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अनिश्चित जन शक्ति (Man power) का प्रयोग किया जा सकेगा।

2. वैज्ञानिक एवं गहरी कृषि को अपना कर भूमि की उत्पादन शक्ति में वृद्धि की जानी चाहिये ताकि भूमि होन श्रमिकों को भी उनके काम का समुचित मान मिल सके।

### श्रमिकों की स्थिति सुधारने के उपाय

1. औद्योगिक विकास
2. वैज्ञानिक एवं गहरी कृषि
3. मूलतम मजदूरी का निर्धारण
4. श्रमिकों के संगठन
5. अधिक रोजगार
6. कार्य-व्यवस्था में सुधार
7. शिक्षा व प्रशिक्षण
8. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था
9. भुदान
10. सामुदायिक विकास का दिग्दर्शन

3. मूलतम मजदूरी के निर्धारण संबंधी कानूनों का सख्ती से वाक्यन कराया जाना चाहिये ताकि स्थायी एवं अस्थायी कृषि श्रमिकों को उचित मजदूरी मिल सके।

4. श्रमिकों के संगठन को प्रोत्साहन दिया जाय ताकि वे संगठन करने लखवों। लिए उचित मजदूरी पर कार्य की व्यवस्था कर आवश्यक मानव के मुक्ति दिलावें।

5. अधिक रोजगार-प्राप्ति के लिए निर्माण कार्य, निर्माण के लिए बाध एवं नहरों का निर्माण एवं अन्य कार्य में

रोजगार के नये अवसर प्रदान किये जाने चाहिये ताकि इन श्रमिकों की मदद-रोजगार एन्ड बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके ।

6. कामें बरामदों पर सुधार—इन श्रमिकों के कार्य करने की दशाओं एवं कार्य करने की अवधि का उचित निर्धारण किया जाना चाहिये । महिला एवं बाल कृषि श्रमिकों को भारी कामों से मुक्ति दिलाने का यत्न किया जाना चाहिये ।

7. शिक्षा व प्रशिक्षण—शिक्षा का महत्व तो सर्व विदित है ही हाथ में इन श्रमिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि वे अपने कार्य में अधिक दक्षता प्राप्त कर सकें ।

8. सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बेकारी के दिनों में भरण-पोषण के लिए भत्ते की व्यवस्था कर दी जानी चाहिये । कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी की जानी चाहिये ।

10. भूदान—देश में भूमि रहित सामाजिक न्याय (Bloodless Social Revolution) का सूत्रपात सन् 1951 में श्री विनोबा भावे ने किया । ग्वाय और समानता के सिद्धांत पर आधारित इस आंदोलन में भूमिपतिवर्गों से निर्धन एवं भूमि रहित श्रमिकों के लिए भूमि प्राप्त की जाती है । ऐसी प्राप्त भूमि को भूमिहीन या स्वल्पभूमि वाले किसानों में बांट दिया जाता है । इस कार्यक्रम से इन भूमि रहित कृषि श्रमिकों की स्थिति में बहुत सुधार आया है । भूदान कार्यक्रम को अधिक व्यापक एवं गतिशील बनाया जाना चाहिये ।

11. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का विस्तार—ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के बस्तान एवं समृद्धि के लिए सामुदायिक विकास कार्यों को अधिक व्यापक बनाया जाना चाहिये ।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि श्रमिक—

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कृषि श्रमिकों को सुरक्षा अधिन की सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा स्थिति सुधारने के प्रयत्न किये गये । भूमिहीन मजदूर, श्रमिक सहकारीताओं एवं

पुनर्वास योजनाओं के अतिरिक्त धमिकों के लिए सहकारी फार्म स्थापित करने के प्रयत्न किये गये । परन्तु कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई ।

द्वितीय योजना में कृषि धमिकों की कठिनाइयाँ दूर करने हेतु चार सूची कार्यक्रम हाथ में लिया गया । पहला प्रयत्न कृषि उत्पादन में वृद्धि कर बेतम दरों में बढ़ोतरी से संबंधित था । दूसरे, ग्रामीण एवं छोटे उद्योगों के विकास एवं विस्तार से अतिरिक्त रोजगार प्राप्त किये जायें । भूमि के पुनः वितरण, मिट्टी विस्तार एवं अन्य कार्यक्रमों से कृषि धमिक के षड, क्षमता, प्रेरणा और योग्यताओं में वृद्धि करने का तीव्र कार्यक्रम अपनाया गया । चौथा प्रयत्न सैतिहर मजदूरों की रहने की स्थिति में सुधार करने से सम्बन्धित है । दूसरी योजना काल में भूमि रहित धमिकों के पुनर्वास पर 5 करोड़ रुपये खर्च किये गये ।

तृतीय योजना में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर विशाल राशि विनियोग करने की व्यवस्था की गई थी । कृषि धमिकों के पुनर्वास पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 8 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकारों द्वारा 4 करोड़ रुपये खर्च होने की व्यवस्था थी । केन्द्रीय कृषि धम सलाहकार समिति की सलाह पर 50 लाख एकड़ भूमि पर 7 लाख परिवारों को बसाने की योजना बनाई गई । मार्च 1967 में अगस्त तक काम में प्राप्त 42.7 एकड़ भूमि में से 12 लाख एकड़ भूमि का वितरण कर दिया गया है ।\*

सन् 1951 की जनगणना में कृषि धमिक उन्हें माना गया जो सेजों पर मजदूरी लेकर काम करें ।

कृषि धमिक जाँचों के परिणाम—कृषि धम की प्रथम जाँच सन् 1950-51 में व द्वितीय जाँच सन् 1956-57 में व एक अन्य जाँच सन् 1963 में सम्पन्न हुई ।

कृषि धमिकों की तरफा में वृद्धि के कारण—

(i) जनसंख्या में वृद्धि (ii) भूमि पर कम भार में वृद्धि—उप

विमात्रन (iii) कुटीर उद्योगों का पतन (iv) सामाजिक कारण (v) शिक्षा का अभाव (vi) अन्य कारण ।

कृषि श्रमिकों की समस्याएँ—

देकारी एवं अर्द्ध-देकारी, नीची मजदूरी, निम्न जीवन स्तर, अल्प प्रसूता, अशिक्षा, बेवार, कृषक दासता, काम के अनियमित घंटे, संगठन का अभाव, आवास समस्या ।

कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिये—

कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय करनी हैं—

(i) औद्योगिक विकास (ii) वैज्ञानिक एवं गहरी कृषि (iii) मूल-तक मजदूरी का निर्धारण (iv) श्रमिकों के संगठन (v) श्रमिक रोजगार (vi) कार्य दलानों से सुधार (vii) शिक्षा व प्रशिक्षण (viii) सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था (ix) भूदान (x) सामुदायिक विकास का विस्तार ।

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि श्रमिक—

प्रथम पंचवर्षीय योजना में—कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं,

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में—कृषि श्रमिकों की रूढ़िवाह्यता दूर करने के लिये चार सूची कार्यक्रम हाथ में लिया गया ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में—विभिन्न कार्यक्रमों पर गौर किया गया ।

### प्रश्न

1. 'कृषि श्रमिक' से क्या समझते हैं । वर्तमान में कृषि श्रमिकों की समस्या क्यों बढ़ रही है ?
2. कृषि श्रमिक जांच आयोगों द्वारा विभिन्न समस्याओं पर जो जांच की गई है उसकी आलोचना कीजिये ।
3. भारत में कृषि श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव दीजिये ।



## अध्याय 14

### भारतीय औद्योगिक विकास का सामान्य सर्वेक्षण

#### GENERAL SURVEY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF INDIA

“ऊन, सूत या रेशम से निर्मित वस्तुएं जो अनेक महिलाओं के  
घरों से लगाकर उनके पर्जीवर एवं घरों की सजावट से सम्बन्ध  
रखती थीं वे भारतीय उद्योगों द्वारा ही निर्मित थीं।”

बीकली रिम्पू

“उद्योगों के बिना कोई भी देश अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित नहीं  
रख सकता।”

—श्री जवाहरलाल नेहरू

किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का अत्यन्त महत्वपूर्ण  
स्थान होता है। भारत एक अत्यन्त सुमध्य एवं प्राचीन देश है, जिसके  
प्राकृतिक साधन अतुल्य एवं विशाल हैं। जब विश्व के उन देशों में, जो  
आज सबसे अधिक विकसित माने जाते हैं, जंगली आदिवासी निवास  
करती थीं भारतवासी उद्योग एवं कला-कौशल में बहुत आगे बढ़े हुये थे।

भारत का औद्योगिक अतीत—भारत का औद्योगिक अतीत हमारे  
लिए गौरव की वस्तु है। यहाँ के उद्योग अनेक अद्भुत विकसित अवस्था  
में थे। हम अपने यहाँ से कई देशों को माल भेजते थे जिसका मुआवजा  
स्वर्ण में मिलता था इसीलिए भारत को ‘सोने की चिड़िया’ कहा जाता  
था। किन्तु अनेक कारणों से हमारे उद्योग अनेकों का पतन हो गया।  
ब्रिटिश सरकार की स्वतन्त्र व्यापार नीति (Free trade Policy)  
के परिणामस्वरूप हमारे यहाँ विदेशों से अनेक वस्तुएं आने लगीं। इस  
लिए हमारे वस्तुओं की माँग में कमी हो गई और विदेशों से आने  
वाले वस्तुओं का आयात बढ़ गया। राजा महाराजाओं

का संरक्षण ■ रहने के कारण भी उद्योगों का पतन हुआ । हमारे विश्व प्रसिद्ध उद्योग धीरे-धीरे नष्ट होते गए और हमारा देश कृषि प्रधान देश बन गया । उद्योग चर्चों के समाप्त में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ।

अब यह बात सर्वसाम्य है कि घट-विकसित देशों की उन्नति के लिए औद्योगिक विकास ही एक महत्वपूर्ण साधन है । भारत में भी उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में कुछ उद्योग प्रारम्भ किये गये, किन्तु औद्योगिक विकास का असली प्रारम्भ प्रथम महायुद्ध काल में हुआ ।

प्रथम महायुद्ध (1914-19) में युद्ध की विभीषिका के कारण जनसाधारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए कठिनाई महसूस करने लगा । भारत में यह अनुभव किया जाने लगा कि विदेशी उद्योगों पर निर्भरता बुरी है । सन् 1916 में नियुक्त औद्योगिक आयोग (Industrial Commission) ने भी भारत में औद्योगिक विकास का सुझाव दिया । सन् 1917 में भारत सरकार ने म्युनिशन बोर्ड (Munition Board) की नियुक्ति की जिसने भारतीय उद्योगों की प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किये । युद्धकाल में भारतीय बपड़ा, दूट, बमड़ा, लोहा व इस्पात, तेल, तेजान, सीमेंट, रॉय, कार्बन आदि के कारखाने बने ।

युद्ध समाप्त होने के पश्चात् कीमतों के कम होने से उद्योगों एवं कृषि का ह्रास हुआ । विश्वव्यापी मंदी (Depression) के कारण भारतीय उद्योगों को आपात आदि देशों के बने माल से स्पर्दा करनी पड़ी । सन् 1930 में सूती वस्त्रोद्योग तथा सन् 1924 में लोहा तथा इस्पात उद्योगों की संरक्षण (Protection) प्रदान किया गया ।

सन् 1930 से 1939 तक की अवधि में भारतीय उद्योगों में नये जीवन का संचार हुआ । बपड़ा, सीमेंट, लोहा-इस्पात एवं दूट के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । संरक्षण नीति, नए कारखानों का निर्माण, स्वदेशी आंदोलन आदि कारणों से भारतीय उद्योगों का विकास हुआ ।

**द्वितीय महायुद्ध—(1939-45)** के प्रारम्भ हो जाने से भारतीय मशीनों की माँग बढ़ी। युद्ध सम्बन्धी सामग्री का निर्माण बहुतायत से किया जाने लगा। सरकार ने उद्योगों की सहायता के लिए औद्योगिक अनुसन्धान कोष की स्थापना की। मार्लेट कमेटी की सिफारिश पर औद्योगिक प्रशिक्षण (Industrial Training) की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध काल में पुराने उद्योग बनने, नए प्रारम्भ हुए, नई प्रशिक्षण बना या विनाश हुआ, मशीन के कल-बुलों के कारणाने मजदूरों से जम गये। • सन् 1940 में एक बोर्ड ऑफ साइंटिफिक एंड इन्डस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना हुई। कुल मिलाकर द्वितीय महायुद्ध के काल में भी भारतीय उद्योगों का विकास हुआ।

**युद्धोत्तर काल में औद्योगिक विकास**

**(Post-war Industrial Development)—**

युद्धकाल में कारखानों में समता से अधिक कार्य होने से बनेक व्यवसायों में लगी मशीनें ओहो-ओहो व्यवस्था में पहुँच गई। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आने के साथ-साथ मुद्रा-स्फीति (Inflation) के प्रभाव स्पष्ट मजबूत आने लगे। इसी समय देश का विभाजन (Partition) हुआ जिसने भारतीय औद्योगिक इकाई पर गहरा प्रभाव डाला। दिसम्बर सन् 1947 में त्रिपक्षीय सम्मेलन (Tri partite conference) बुलाया गया (उद्योगपति, मजदूर व सरकार) जिसमें औद्योगिक समस्याओं पर विचार किया गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक सुनिश्चित योजना के आधार पर औद्योगिक विकास करने हेतु 6 अप्रैल सन् 1948 को भारत सरकार की औद्योगिक नीति (Industrial Policy) की घोषणा की गई। इस नीति ने औद्योगिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) का आधार स्पष्ट कर दिया।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन में 38 प्रतिशत की**

वृद्धि हुई। इस अवधि में वायुमान, डी. डी. टी., पेन्सिलीन, रेल के डिब्बों आदि का निर्माण प्रारम्भ किया। सार्वजनिक क्षेत्र (Public sector) में वितरजन का कारखाना, सिन्दरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इण्डियन टेलीफोन इण्टरस्ट्रीज आदि की प्रगति संतोषजनक रही।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मूल एवं भारी (Basic and heavy) उद्योगों के विस्तार पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के तीन कारखाने, भारी बिजली के सामान, भारी मशीन आदि के निर्माण कार्य सम्पन्न हुए। सीमेंट, कागज, रासायनिक उद्योग, टेलीफोन एवं अन्य उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। योजना के अन्त में सन् 1950-51 की तुलना में 94 प्रतिशत उत्पादन अधिक होता था। इस योजना में निर्धारित औद्योगिक उत्पादन के सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। इसका मुख्य कारण विदेशी विनिमय (Foreign Exchange) का संकट था।

तृतीय योजना में औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों का उद्देश्य आगामी 15 वर्षों में तीव्र औद्योगीकरण की नींव डालना था। इस योजना में आधारभूत पूंजी एवं उत्पादक उद्योगों की प्राथमिकता दी गई। इस योजना में तकनीकी प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। इस योजना में उद्योग एवं सनित्र विकास के लिए 2,993 करोड़ (सार्वजनिक क्षेत्र में 1,808 तथा निजी क्षेत्र में 1,185 करोड़) रुपये की व्यवस्था की गई। इस राशि में से 1,338 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी विनिमय की व्यवस्था की गई। तृतीय योजना की अवधि में अनेक उद्योगों के उत्पादन में उत्तेजनीय वृद्धि हुई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक एवं सनित्र विकास योजनाओं पर लगभग 3090 करोड़ रुपये विनियोग करने की व्यवस्था है।\* इस योजना में इस्पात, मशीन उत्पादन, ज्वेलर्य, मशीनी जोहार, रासायनिक पदार्थ आदि के उत्पादन विस्तार के लक्ष्य रखे गये।

औद्योगीकरण की आवश्यकता (Need for Industrialisation) कृषि प्रधान अर्द्ध-विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए उद्योगों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। अब यह सभी प्रकार माना जा चुका है कि उद्योगों के बिना देश के आर्थिक विकास की बात सोचनी ही व्यर्थ है। आज विश्व के सभी विकसित देश (Developed countries) औद्योगीकरण के ही बल पर विश्व में अपना जैसा स्थान बन पाए हैं। भारतवर्ष जैसे अर्द्ध-विकसित और निर्धन राष्ट्र के लिए भी उद्योगों द्वारा ही आर्थिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।

भारत में कृषि पर जनसंख्या का जो अत्यधिक भार है उसे हल करने, प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, बेरोजगारी एवं अर्द्ध-बेकारी को समाप्त करने, कृषि विकास के लिए आवश्यक योजना, कीटाणुनाशक दवाइयाँ एवं रासायनिक उर्वरक जुटाने, पूँजी निर्माण और विनियोग को प्रोत्साहन देने, लोगों के उपयोग एवं जीवन-स्तर को बढ़ाने, देश की सुरक्षा के प्रयत्नों को प्रबल बनाने, देश को आत्म-निर्भर बनाने, विदेशों पर निर्भरता समाप्त करने, भुगतान समुत्थान को अनुकूल बनाने एवं देश का सर्वांगीण विकास करने हेतु यह आवश्यक है कि हम बड़े उद्योगों का विकास करें।

**उद्योगों के भेद (Kinds of Industry) —**

उद्योगों को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा जाता है\* (अ) कुटीर उद्योग (Cottage Industry), (ब) लघु उद्योग (Small Scale Industry) तथा (स) बृहत् स्तरीय उद्योग (Large Scale Industry)।

---

\* कुटीर एवं लघु उद्योगों के विस्तृत वर्णन एवं प्रकार के माध्यम में नवमी कक्षा की पुस्तक में विस्तार से पढ़ चुके हैं।

(अ) कुटीर उद्योग—कुटीर उद्योग वे हैं जो गाँवों में स्थित हैं, जो कृषि के सहायक धन्य हैं तथा जिनमें अधिकतर कार्य हाथ से ही परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाता है ।

(ब) सघु स्तरीय उद्योग—सामान्यतः सघु उद्योग वे उद्योग हैं जिनकी पूंजी 5 लाख रुपये से कम है और जहाँ यंत्रों की सहायता से 10 से 50 तक अधिक\* कार्य करते हैं । भारतवर्ष में अब ये उद्योग काफी विकसित हो रहे हैं ।



कुटीर उद्योग

(ग) गृह उद्योग—ये वे उद्योग हैं जिनमें बहुत-सी ( 5 लाख रुपये से अधिक ) पूंजी के साथ अत्यधिक संख्या में श्रमिक द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है । भारतवर्ष में सूती वस्त्रोद्योग, लोह एवं इस्पात उद्योग तथा चीनी उद्योग कई वर्षों से बड़े पैमाने पर चलाने जा रहे हैं । देश की अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्ध करने की दृष्टि से ये उद्योग महत्वपूर्ण हैं ।

यहाँ एक ओर उद्योग कुटीर रोजगार प्रदान करने, कम पूंजी में काम चलाने, औद्योगिक विकेन्द्रीकरण, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण भूमि पर जनसंख्या के भार में कमी करने, उत्तम कोटि की वस्तुओं के निर्माण करने एवं सरल कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं, वहीं दूसरी ओर गृह उद्योग अर्थ-व्यवस्था को गतिमान करने, देश में उत्पादन

बढ़ाने, उदासन की लागत कम करने, निर्यात की आवश्यकताओं को पूरा करने, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, दीर्घकाल में बेरोजगारी व धर्म-रोजगारी को समाप्त करने, कृषि विकास के लिए आवश्यक उपकरण एवं दवाइयाँ जुटाने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। बड़े उद्योगों की स्थापना के बिना वर्तमान आर्थिक स्पर्धा के युग में किसी भी देश का आगे बढ़ना सम्भव नहीं है। स्वर्णय नेहरू के अनुसार "देश में भारी उद्योगों के विकास का महत्व है। मैं तो कहूँगा कि भारी उद्योगों के बिना कोई भी देश अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित नहीं रख सकता। भारी उद्योग ही बुनियादी चीज है, बाकी सब उद्योग तो उनके बच्चे हैं।" इस प्रकार किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था में तीनों ही प्रकार के उद्योगों का स्थान महत्वपूर्ण होता है किन्तु आज के इस वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के युग में वृहत् उद्योगों का ही महत्व अधिक है।

**भारत में औद्योगिक पिछड़ापन (Industrial Backwardness in India) —**

औद्योगिक विकास का महत्व सर्व विदित होते हुए भी भारतवर्ष अभी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यद्यपि हमारे देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता देखते हुए औद्योगिक विकास की सम्भावनाएं बहुत हैं फिर भी हम इस दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। हम यहाँ उन समस्याओं का सन्तुलन करेंगे जो औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी हैं—

1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव (Lack of Scientific outlook)—भारतवासी प्राचीनकाल से ही वाणिज्यवादी रहे हैं। वे अब भी नये उद्योगों में विनियोग करने की अपेक्षा वाणिज्य (Commerce) को अधिक सामदारी समझते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि की प्रधानता, ग्रामों की व्यापकता आदि कारणों से भी उद्योगों के पक्ष में उचित वातावरण का निर्माण नहीं हो पाया।

## 2. पूंजी की समस्या (Problem of Capital)—

हमारे देश में राष्ट्रीय आय कम होने से पूंजी निर्माण की समता कम है। बिना अधिक पूंजी के बड़े उद्योगों की स्थापना सम्भव नहीं है। यही कारण है भारत में शीघ्र औद्योगीकरण का अभाव है।

3. मशीनों के मशीनीकरण एवं प्रविधि सम्बन्धी समस्याएँ (Problems of techniques and modernisation of machines)—हमारे देश में मशीनों की हालत अत्यन्त असन्तोषप्रद है। पिसी-पिटो इन मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है जिसे उत्पादन की लागत (Cost of productions) बढ़ जाती है।

(Techniques) तथा मशीनों की पुनर्स्थापना (Replacement) सम्भव नहीं है। इसलिए भारतीय उद्योगों का विकास रुका हुआ है।

4. कच्चे माल की समस्या (Problem of Raw material)—यद्यपि अधिकांश उद्योगों के लिए कच्चा माल हमारे देश में ही उपलब्ध हो जाता है फिर भी उत्तम किस्म का कच्चा माल हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। दूधरी और कच्चे माल की मुख्य सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण भी उद्योगों को राति रुकनी पड़ती है।

## औद्योगिक समस्याएँ

1. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव
2. पूंजी की समस्या
3. मशीनों के मशीनीकरण एवं प्रविधि सम्बन्धी समस्या
4. कच्चे माल की समस्या
5. विदेशी पूंजी की समस्या
6. व्यक्तियों की समस्या
7. सरकारी नीति
8. प्रबन्ध अधिकर्ता प्रणाली के दोष
9. असन्तुलन की समस्या
10. औद्योगिक अक्षमता
11. श्रुति के साधनों की समस्या
12. प्रबन्ध की समस्या



5. विदेशी पूँजी की समस्या (Problem of foreign capital)—उद्योगों के धमिनवीकरण तथा विदेशों से सात्र सामान मँगाने के लिये पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूँजी की आवश्यकता होती है। भारत में पिछले 10-12 वर्षों से विदेशी पूँजी का मरट आया हुआ है। हम पर पहले ही विदेशी ऋण भार अधिक है। इसलिए और अधिक पूँजी हमें विदेशों से नहीं प्राप्त हो पा रही है।

6. कुशल धमिकों की समस्या (Problem of skilled Labour)—औद्योगिक विकास के लिए जहाँ एक ओर अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है वहाँ कुशल धमिकों की महता भी कम नहीं है। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ अब भी अनेक व्यवसायों में प्रशिक्षित धमिकों एवं कर्मचारियों का अभाव है।

7. सरकारी नीति (Government Policy)—औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल औद्योगिक नीति, कर नीति, अम नीति एवं लटकर नीति का होना आवश्यक है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति अब भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीयकरण का मय भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विकास योजनाओं के निर्माण में बाधा है। प्रगतिशील अम एवं कर नीतियों से पूँजीपतियों द्वारा किए जाने वाले पूँजी के वित्तियोग में कटौती हुई।

8. प्रबन्ध अमिकर्ता प्रणाली के दोष (Evils of managing Agency System)—प्रबन्ध अमिकर्ताओं द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास में दिया गया योग मुनाया नहीं जा सकता किन्तु वर्तमान औद्योगिक ढाँचे में प्रबन्ध अमिकर्ता प्रणाली के दोष सुविदित हैं। इनकी दीपपूर्ण कार्यप्रणाली औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है।

9. असन्तुलनों की समस्या (Problem of Imbalances)—भारतीय उद्योगों में अनेक प्रकार के असन्तुलनों की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्षेत्रीय (Regional), निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में असन्तुलन (Sectoral imbalance) उत्पादक व उपभोग उद्योगों में असन्तुलन (Imbalance in Producers & Consumers Industries), आदि समस्याएँ भी दीप औद्योगीकरण के मार्ग में बाधाएँ हैं।

10. औद्योगिक अशान्ति (Industrial unrest)—बड़े उद्योगों की स्थापना के साथ साथ औद्योगिक अशान्ति में वृद्धि हुई है। मजदूरों और मालिकों में मधुर सम्बन्ध न होने के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

11. शक्ति के साधनों की समस्या (Problem of Power)—विश्व के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय उद्योगों को उत्पादन लागत कम करना आवश्यक है। बिना पर्याप्त मात्रा में सस्ते शक्ति के साधनों के भारतीय उद्योगों का विकास कठिन है। यद्यपि भारत में शक्ति के साधनों की सम्भावनाएं (Potentialities) बहुत हैं फिर भी उनके अनेक उचित विद्योहन (utilization) के अभाव में उद्योगों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

12. प्रबन्ध की समस्या (Problem of Organisation)—प्रबन्ध परिणतियों की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के साथ-साथ योग्य व प्रशिक्षित प्रबन्धियों का भी अभाव है। प्रबन्धक की योग्यता का उद्योगों के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में प्रचलित उद्योगों में भी कुशलता की कमी (Inefficiency) दृष्टिगोचर होती है।

भारत में तीव्र औद्योगीकरण (Rapid Industrialisation) के लिए सुझाव—

हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक सनित्र पदार्थ, कृषि अन्य कच्चा भास, शक्ति के साधनों की समत, विस्तृत बाजार एवं जनशक्ति पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। तीव्र औद्योगीकरण के लिए निम्नांकित उपाय काम में लाये जाने चाहिए—

1. प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग—सनित्र पदार्थों का उपयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। विस्तृत जनशक्ति एवं वन सम्पदा का भी अधिकतम उपयोग कर औद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।

2. पूंजी का मुक्तव्य—वर्तमान अवस्था को विनिमय के लिए आकर्षण देने के माध्यम-माध्य पूंजी निर्माण की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रमत्तता की बात है कि पञ्चवर्षीय योजनाओं में पूंजी निर्माण की दर बढ़ाकर उद्योगों के लिए अधिकाधिक पूंजी जुटाने की व्यवस्था की जा रही है।

3. विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मूल और भारी उद्योगों के लिए विदेशों से साज सामान मँगाने के लिए अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित किया जाना चाहिए। सीमित विदेशी पूंजी का अधिकाधिक लाभदायक उपयोग करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. अभिनवीकरण (Modernisation) के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन की लागत में प्रभावपूर्ण कमी की जा सके। पिछले कुछ वर्षों से देश में अनेक वित्त नियम इस कार्य के लिए कारगरों को साधन प्रदान कर रहे हैं।

5. सरकारी उद्योगों में दक्षता लाने के लिए प्रयत्न की अधिक प्रभावी (Effective) बनाया जाना चाहिये।

6. औद्योगिक प्रशिक्षण—की समुचित व्यवस्था के लिए देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, मजदूर शिक्षण केन्द्र, आदि स्थापनों का संचालन किया जाना चाहिए। भारत सरकार इस ओर बहुत प्रयत्नशील है।

7. उचित औद्योगिक धम एवं कर नीति—सरकार की नीतियों में निम्नी प्रकार की अनिवार्यता को स्थान नहीं होना चाहिए। मई 1956 की औद्योगिक नीति ने अनेक अनिवार्यताओं को समाप्त कर भारतीय उद्योगपतियों में फिर से विश्वास को प्रतिक्रिया दिया है।

8. श्रम प्रयत्न—औद्योगिक विकास के लिए श्रम प्रयत्नों के अति-उत्प्रेरक औद्योगिक शक्ति स्थापित करने के लिए श्रम कल्याण (Labour Welfare) कार्यक्रमों का संचालन दिया जाना चाहिए। शारीरिक

व निम्नी क्षेत्रों के मध्य उचित समन्वय एवम् सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। यातायात के साधनों के विकास के प्रतिरिक्त क्षेत्रीय एवम् उद्योगों के मध्य विषमताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। कुटीर एवम् सधु.उद्योगों का क्षेत्र सुस्पष्ट निर्धारित कर दिया जाना चाहिए।

प्रसन्नता की बात है कि आर्थिक नियोजन के विद्यमान 17 वर्षों में औद्योगिक विकास के सराहनीय प्रयत्न किये गये हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि भारत विकासशील (Developing) देशों में सबसे अधिक विकसित (Developed) है।\* विकास की गति तीव्र करने के लिए हमें उद्योगों का और विस्तार करने की आवश्यकता है।

**भारत सरकार की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of Government of India)**

यहाँ भारतीय उद्योगों के विकास के सदर्भ में भारत सरकार की औद्योगिक नीति का उल्लेख करना उचित ही होगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय उद्योगों के विकास के लिये सरकार की कोई उल्लेखनीय औद्योगिक नीति नहीं रही। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद ही हमारी राष्ट्रीय सरकार ने उद्योगों के विकास की नीति की घोषणा की। इस नीति में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किये गये।

**सन् 1948 की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of 1948) —**

सन् 1948 में भारत सरकार द्वारा अपनी औद्योगिक नीति (Industrial Policy) की घोषणा की गई। इस नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

1. दृष्ट उद्योग—इन्हें चार भागों में बांटा गया—(अ) राज्य

---

\*Indian Economy since Independence, H. Venkatasubbiah, p. viii

अधिकृत क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उद्योग रहे गए जिन पर सरकार का एकाधिकार होता ।

(ब) राज्य नियंत्रित (Controlled) क्षेत्र—इनमें छः आयात-भूत उद्योग रहे गए जिनके राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के बारे में सरकार 10 वर्ष बाद फिर से विचार करेगी ।

(ग) 'सी' श्रेणी में वे 20 उद्योग रहे गये जो उद्योगाधिकारों द्वारा चलाये जायें और जिन पर सरकार का सामान्य नियन्त्रण एवम् नियमन रहेगा ।

(द) शेष सभी उद्योग निजी क्षेत्र (Private) में रहेंगे ।

2. सड़क बुटीर उद्योग—इस नीति के अन्तर्गत बुटीर व सड़क उद्योगों को विवक्षित करने एवम् समन्वय के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की घोषणा की गई ।

औद्योगिक समन्वय—मजदूरों एवम् मालिकों में अच्छे संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर भी इस नीति में जोर दिया गया ।

4. विदेशी पूँजी—इस नीति में विदेशी पूँजी की सुरक्षा एवम् विनियोग की सुविधाओं का आश्वासन दिया गया ।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि इस नीति मिश्रित अर्थ व्यवस्था (Mixed Economy) के विचार को स्पष्ट किया । किन्तु इस नीति की घोषणा से औद्योगिक क्षेत्र में अनिश्चितता एवम् भय का वातावरण उत्पन्न हो गया । इसीलिए सन् 1956 में नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई ।

सन् 1956 की नवीन औद्योगिक नीति (New Industrial policy 1956)—

प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा से उत्पन्न भय एवम् अनिश्चितता के वातावरण को दूर करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम

बठाये। इनमें औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1951 केन्द्रीय (बोद्योगिक) सलाहकार समिति, 1952 का गठन तथा औद्योगिक (विकास एवं नियन्त्रण) अधिनियम संशोधन 1953 तथा 1955 की व्यवस्थाएं उल्लेखनीय हैं। इतना सब होने के बावजूद भी भारतीय गणराज्य के संविधान एवं द्वितीय योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप नई औद्योगिक नीति की घोषणा करना बांछनीय हो गया। तदनुसार 30 अप्रैल सन् 1956 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य विशेषताएं ये हैं—

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व—नवीन नीति में राज्य के नीति में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (Directive principles) के अनुसार समाज की रचना करने के उद्देश्य से इस नीति में भारी उद्योगों व मशीन उद्योगों का विकास करने के लिए, जहां आवश्यक हो, सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जाने का संकल्प रखा गया।

2. उद्योगों का वर्गीकरण, (Classification of Industries)—  
(अ) बहुस्तरीय उद्योगों को चार के स्थान पर नवीन नीति में तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया। प्रथम अनुसूची (Schedule 'A') में उन 17 उद्योगों को सम्मिलित किया गया जिनके विकास का सम्पूर्ण दायित्व सरकार पर होगा। द्वितीय अनुसूची में वे बारह उद्योग सम्मिलित किये गये जिनके भारी विकास का उत्तरदायित्व सरकार पर होगा।

(ब) सघु तथा कुटीर उद्योग—नई नीति में इन उद्योगों को पूर्वी, शक्ति के साधन एवं तकनीकी सहायता देकर स्वावलम्बी बनाने की व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया।

3. सन्तुलित विकास—सभी क्षेत्रों में माताप्राप्त, जल एवं शक्ति के साधनों की सुविधाएं प्रदान कर क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

4. कार्यवाहियों का प्रतिपाद—नवीन नीति में औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिपाल सेवाओं के विस्तार की अनिवार्यता को महसूस किया गया।

5. औद्योगिक शान्ति—(Industrial rest) के लिए मजदूरों को भी विकास कार्य में सम्भेदार मानने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया ।

6. विदेशी पूँजी—सन् 1948 की ही नीति के सम्बन्धित अंश को दोहरा दिया गया ।

यद्यपि नवोन औद्योगिक नीति के विषय में भी अनेक ठके दिये जाते हैं फिर भी इस नीति की घोषणा के बाद भारतीय उद्योग एक नुई आधार पर विद्यमान हो रहे हैं । भारत की औद्योगिक नीति में अमिकों के प्रशिक्षण (Training), मशीन आदिकों के संग्रहण (Collection of data) एवम् प्रबंध में अमिकों को हिस्सा देने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

### मार्गदर्श

विभी भी देश के सामाजिक विकास के उद्योगों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होता है ।

भारत का औद्योगिक इतिहास—भारत में वर्तमान के उद्योग अन्य बहुत विद्यमान अवस्था में थे । प्रथम महायुद्ध के कारण उन सामान्य ईनिक उद्योगों की वस्तुओं के लिए कठिनाई महसूस करने लगे । मुद्रास्फीय उद्योगों का ह्रास हुआ । सन् 1930 से 1939 तक में उद्योग में नये जीवन का विकास हुआ । द्वितीय महायुद्ध काल में पुराने उद्योग नये, नये उद्योग प्रारम्भ हुये ।

संघर्षपूर्ण योजनाओं से औद्योगिक विकास—

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में—औद्योगिक उत्पादन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में—मूल व मापी उद्योगों के विकास पर ध्यान दिया ।

कृषीय पंचवर्षीय योजना में—आधारभूत पूँजी एवं उत्पादक उद्योगों की प्राथमिकता दी गई ।

औद्योगीकरण की आवश्यकता—बड़े उद्योगों के बिना आर्थिक विकास की बात सोचना ही व्यर्थ है ।

उद्योगों के स्तर—( 1 ) कुटीर उद्योग ( 2 ) मध्य स्तरीय उद्योग ( 3 ) बृहत् स्तर के उद्योग ।

भारत में औद्योगिक विद्यमान—हमारे उद्योग पिछड़े हुए हैं क्योंकि—

( 1 ) वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव ( 2 ) पूँजी की समस्या ( 3 ) मशीनों के मशीनीकरण एवं प्रबन्ध सम्बन्धी समस्या ( 4 ) कच्चे माल की समस्या ( 5 ) विदेशी पूँजी की समस्या ( 6 ) श्रमिकों की समस्या ( 7 ) सरकारी नीति ( 8 ) प्रबन्ध अशिक्षता प्रणाली के दोष ( 9 ) अव्यवस्था की समस्या ( 10 ) औद्योगिक अक्षमता ( 11 ) गवित के साधनों की समस्या ( 12 ) प्रबन्ध की समस्या ।

भारत में तीव्र औद्योगीकरण के लिए सुझाव—

( 1 ) प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग ( 2 ) पूँजी का गुणवत्ता ( 3 ) विदेशी पूँजी को प्रोत्साहन ( 4 ) श्रमिकीकरण ( 5 ) उचित प्रबन्ध ( 6 ) औद्योगिक प्रशिक्षण ( 7 ) उचित औद्योगिक धर्म एवं नैतिकता ( 8 ) स्वयं प्रयत्न ।

भारत सरकार की औद्योगिक नीतियाँ—

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कोई उल्लेखनीय नीति नहीं थी—

सन् 1948 की नीति—बृहत् उद्योगों को चार भागों में बाँटा गया । मध्य उद्योगों के लिए विशेष समस्याओं को सोलने की धोरण की गई । संक्षेप में इनमें विभिन्न दलों व्यवस्था के विचार को स्पष्ट किया । 1956 की नवीन औद्योगिक नीति—

विशेषताएँ—( 1 ) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का महत्व ( 2 ) उद्योगों का वर्गीकरण—बृहत् उद्योगों को तीन भागों में बाँटा ( 3 ) साधन विकास ( 4 ) बयेंचारियों का प्रशिक्षण ( 5 ) औद्योगिक नीति ( 6 ) विदेशी पूँजी ।



## प्रश्न

1. "किसी भी देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान होता है"—क्या आप इस कथन से सहमत हैं ?  
हाँ तो क्यों ?
  2. भारत में पंचवर्षीय योजना काल में हुये औद्योगिक विकास पर निबन्ध लिखिये ।
  3. उद्योग किन्ने प्रकार के होते हैं ? तृपुस्तरीय उद्योग से आप क्या समझते हैं ? ऐसे कुछ प्रमुख उद्योगों का वर्णन कीजिये ।
  4. भारत के उद्योगों में पिछड़ापन क्यों है ? इन्हें दूर करके सीधे औद्योगिकीकरण हेतु भारत को क्या करना चाहिये ? सुझाव दीजिये ।
  5. संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—
    - ( i ) 1948 की औद्योगिक नीति
    - ( ii ) 1956 की औद्योगिक नीति
    - ( iii ) औद्योगिक समस्याएँ ।
-

## आधुनिक भारतीय उद्योग

### MODERN INDIAN INDUSTRIES

"ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने पूर्वी द्वीप समूह में जमी हुई अपनी डच इतिहास का ही अनुसरण किया। इसने देश के उद्योगों तथा व्यापार को चौपट कर दिया तथा भारतीय पदार्थों को यूरोप के बाजार से बाहर निकाल कर भारतीय चर्मों, हाथ करवे तथा उसके पहियों को बरतना शुरू कर दिया।"

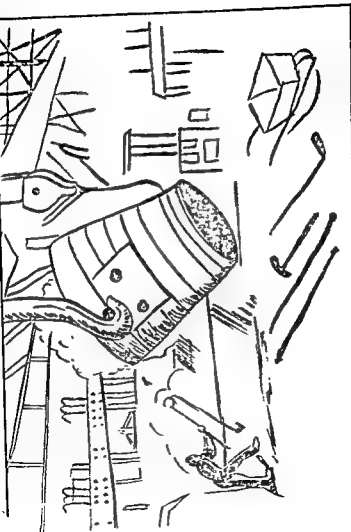
— कार्ल मार्क्स

वर्तमान बृहत् भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र, लोहा व इस्पात, चीनी, दूध, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, उर्वरक आदि का नाम उल्लेखनीय है। यहां हम कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की प्रगति, वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का अध्ययन करेंगे।

#### लोहा व इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry)

लोहा व इस्पात उद्योग किसी भी देश के तीव्र औद्योगीकरण के लिए आवश्यक है। इसे औद्योगिक व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी (Back Bone) कहा जाता है। देश की सुरक्षा, कृषि, उद्योग व माता-पिता के विकास में इस उद्योग का बहुत योगदान होता है।

इतिहास—भारतवर्ष में यह व्यवसाय अत्यन्त प्राचीनकाल से ही किया जाता है। कहा जाता है कि ईसा से 5,000 वर्ष पूर्व भी भारत वासी इस उद्योग का संरक्षण बहुत कुशलता पूर्वक किया करते थे। दिल्ली की खुतब-नामा के पास बनी मोहो की कीली 1,500 वर्ष पूर्व सगाई गई थी। बलोच की साट भी हमारे लोहा और इस्पात उद्योग के प्राचीन मील की प्रतीक है। परन्तु लोहा तथा इस्पात का बड़े पैमाने पर कार्य सन् 1907 में हुआ जबकि 'टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी



के बिहार में कारखाना खोला । सन् 1908 में बंगाल में वास्तवशोल के निकट 'इन्डियन आयरन तथा स्टील कम्पनी' और सन् 1923 में मद्रास की (मैसूर) में मैसूर आयरन वर्क्स की स्थापना की गई । सन् 1924 में इन उद्योगों को सुरक्षा (Protection) प्राप्त हो गया जो सन् 1924 तक कमता रहा । इसी बीच सन् 1937 में 'बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन' की स्थापना हुई । सन् 1952 में 'बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन' और 'इन्डियन आयरन तथा स्टील कम्पनी' का विलीनीकरण हो गया ।

**वर्तमान स्थिति**—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सांख्यिक क्षेत्र में जोड़ा गया उत्पाद उद्योग का क्षेत्रीय विकास किया जा रहा है । द्वितीय योजना काल में सरकारी कम्पनी 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' के प्रारम्भ से तीन कारखाने बनाए गये—

1. करकेला स्टील प्लांट (Rourkela Steel Plant)—उड़ीसा में पश्चिमी बर्मनी की भुविभ्यात चर्म 'कूच' के सहयोग से बनाया गया । यह कारखाना अब 12 लाख टन उत्पाद उत्पादन की क्षमता रखता है । 1968-69 में इसने 12.43 लाख टन कच्चा लोहा तथा 11.61 लाख टन उत्पाद पिह का उत्पादन किया । सन् 1962 में उत्पाद कारखाने के निकट रासायनिक कार का एक कारखाना भी खाना किया गया । करकेला स्टील प्लांट की उत्पाद पिह क्षमता सन् 1968 में बढ़ाकर 18 लाख टन कर दी गयी ।

2. बिलाई (Bhilai) स्टील प्लांट—सोडियल कम के सहयोग से राज्य प्रदेश में बनाये गये इस कारखाने में सन् 1968-69 में 19.33 लाख टन कच्चा लोहा तथा 17.33 लाख टन उत्पाद पिह का उत्पादन किया ।

3. दुर्गापुर स्टील प्लांट (Durgapur Steel Plant)—यह उत्पाद का कारखाना पश्चिमी बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर सन् 1962 में बन कर तैयार हुआ । 1968-69 में इस कारखाने के 9.58 लाख टन लोहा तथा 7.5 लाख टन उत्पाद पिह तैयार किया ।

गृहीत योजना नाम में इन कारखानों की उत्पादन क्षमता में बहुत विस्तार किया गया। 1965 में मोविपत रुम के साथ सम्मोदा किया गया जिसके धनमय बोचारी (बिहार) में एक नया स्टील प्लांट बनाया जा रहा है। इस कारखाने का प्रथम चरण मार्च 1971 में बन कर तैयार होगा। रुम की सरकार ने 20 करोड़ रुपये का न्यून विदेशी से शायद सामान मंगाने के लिए स्वीकार किया है।

## भारत लोहा और स्पात उद्योग केन्द्र

कुल्लू • आसनसोल  
जमशेदपुर • दुर्गापुर  
भिलाई • सरकेला

भद्राचली

● लगभग 166-6 करोड़ रुपये।

अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में लोहा तथा इस्पात के छोटे-बड़े 167 कारखाने हैं जिनमें लगभग 131 करोड़ रुपये की धातु पूंजी लगी हुई है। इन कारखानों में लगभग 93 हजार व्यक्ति काम करते हैं। सन् 1967 में 70.10 लाख टन कच्चा लोहा तथा 41.35 लाख टन इस्पात तैयार किया गया। सन् 1967-68 में भारत ने 54.83 करोड़ रुपये के मूल्य का लोहा तथा इस्पात निर्यात (Export) किया।\*

हमारे लोहा और इस्पात व्यवसाय की सार्वजनिक क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। उद्योग में उन्नत उत्पादन विधियों का प्रयोग भी प्रारम्भ कर दिया गया है। सन् 1949 में लाइटिया में प्रतिपादित एल० डी० प्रक्रिया (L.D Process) का प्रयोग हमारे यहाँ भी प्रारम्भ कर दिया गया है, जो उत्पादन लागत में कमी करती है। वर्तमान वर्षों में इस उद्योग द्वारा विभिन्न वस्तुओं का निर्माण बढ़ा है। पिछले कुछ वर्षों में रेल की भारी पटरियाँ, टिन, प्लेटें, तार, चद्दर, पहिये, एक्सल आदि अनेक वस्तुओं का भारी संख्या में निर्माण हुआ। इतना होते हुए भी यह उद्योग हमारी सभी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता।

उद्योग की समस्याएँ, उपचार एवं प्रगति—देश में इस उद्योग से सम्बन्धित सारी प्राकृतिक सुविधाएँ उपलब्ध होते हुए भी इस उद्योग में सामने निम्न समस्याएँ हैं—

(1) कोयले की कमी—अच्छी किस्म के कोयले की कमी के कारण घटिया किस्म का कोयला प्रयोग में लाया जाता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अतः घटिया कोयले को उन्नत करने अथवा संपन्न भंडार वाले लिग्नाइट के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिये। इस सम्बन्ध में कोयला साफ करने के लिए कारखाने खोले जा रहे हैं।

कच्चे भास की कठिनाई—उद्योगों के लिए अच्छी कोटि का कच्चा भास, जैसे उत्तम धूने का पत्थर आदि कारखानों के निकटवर्ती भागों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने से उन्हें दूर के सेगों से मगाना

पड़ता है, जिससे उत्पादन सागत में वृद्धि हो जानी है। अतः यातायात का विकास आवश्यक है। सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत यातायात के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।

### समस्याएँ

1. कोयले की कमी
2. कच्चे माल की कमी
3. पूँजी का अभाव
4. कुशल धमिकों तथा विशेषज्ञों की कमी
5. आधुनिक यंत्रों की कमी
6. श्रम सम्बन्धी कठिनाइयाँ
7. मूल्य सम्बन्धी कठिनाइयाँ
8. यातायात के साधनों का अभाव

### (3) पूँजी का अभाव—

इस्पात उद्योग के विस्तार एवं अग्निवीकरण के लिए बहुत पूँजी की आवश्यकता है। भारत में पूँजी निर्माण की क्षमता कम होने से हमें अधिकतर विदेशी सहायता पर ही निर्भर रहना पड़ता है और पूँजी के अभाव में पुगनी मशीनों से ही काम लेना पड़ता है। देश में पूँजी संचय को प्रोत्साहन देना चाहिये। सरकारी तथा विदेशी सहायता बढ़ाना आवश्यक है।

(4) कुशल धमिकों तथा विशेषज्ञों की कमी—एक उद्योग को अधिक कुशल और लाभदायक बनाने के लिए (expert) एवं कुशल धमिकों की आवश्यकता है। विदेशों से अनेक विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा की समस्या उत्पन्न होती है। अतः हमारे विदेशों को बाहर प्रतिष्ठान के लिए अधिक संख्या में भेजना चाहिये और देश में धमिकों के लिए सोच गति प्रतिष्ठान केन्द्र लोपे बाने चाहिये। अब तकनीकी प्रतिष्ठान (technical training) के विचारम हेतु प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(5) आधुनिक यंत्रों की कमी—पूँजी तथा विशेषज्ञों की कमी के कारण अनेक संसाधन और इन्पुट कारखानों में आधुनिक तकनीकी बाँके एवं प्रयोग में नहीं आये जाने जिससे उत्पादन क्षमता कम रहनी है।

अतः उत्पादन की नवीन विधियों व आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना आवश्यक है ।

(6) घम सम्बन्धी कठिनाइयाँ—श्रीयोगिक अग्रान्ति का कारण उत्पादन पर युग प्रभाव पड़ता है । सरकार को घम कल्याण के सर्वपक्ष में नियम पारित कर घम और पूंजी में मोहान्तरण कायम करना चाहिये । इस सम्बन्ध में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है ।

(7) मूल्य सम्बन्धी कठिनाई—भारतीय इस्पात का 'निर्धारित मूल्य' समय-समय पर बदलता रहता है, जिसमें इस्पात की कीमतें अनिश्चित रहती हैं ।

(8) धाताधातु के सामग्रियों का अभाव—कच्चा माल, कोयला आदि आवश्यक सामान कारखानों तक पहुँचाने व निर्मित माल को विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने के लिए सुयम और सस्ते साधन उपलब्ध न होने से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । सरकार धाताधातु के विकास पर बहुत ध्यान दे रही है ।

अन्त में कहा जा सकता है कि भारतीय लोहा एवं इस्पात उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि हमारे यहाँ उद्योग के लिए आवश्यक सामग्रियाँ, जैसे कच्चा लोहा, मैंगनीज, डोलोमाइट (Dolomite) आदि बहुतायत में पाई जाती हैं ।

### सूती वस्त्र उद्योग

#### COTTON TEXTILE INDUSTRY

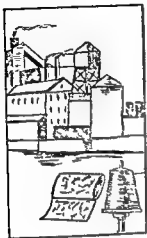
“सूती उद्योग भारत के प्राचीन युग का गौरव, वर्तमान एवं भविष्य का सदेह, किन्तु सदा की आशा है ।” — बुकनेन

यह उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है । सूत और वस्त्र उत्पादन की भाँसा देखते हुए भारत संसार में तीसरे स्थान पर और सूत उपभोग की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है ।

इतिहास—भारत का वस्त्रोद्योग प्राचीन काल में बहुत उन्नत था । भारत कई देशों को अपने यहाँ के बने हुए वस्त्र भेजता था । यह व्यवसाय



उस समय मशीन उद्योगों के रूप में चलाया जाता था। भारत में सर्व-प्रथम संगठित रूप में सूती वस्त्र के कारखाने की स्थापना सन् 1818 में



## सूती वस्त्र उद्योग

आघात में कमी हुई और देश में बने कपड़े की माँग में वृद्धि हुई।

प्रथम महायुद्ध काल—प्रथम महायुद्ध काल में अन्य उद्योगों में साथ साथ सूती वस्त्र का भी बहुत विकास हुआ। युद्धकाल में इस उद्योग की सफलता के पीछे सैनिक कपड़े की बड़ी हुई माँग और विदेशों से आघात न होने के कारण देशी कपड़ों की माँग में वृद्धि हुई थी। युद्धकाल की यह समृद्धि अधिक दिनों तक न चल सकी। मंदी और जापान की बढ़ती हुई स्पर्धा के कारण भारतीय सूती कपड़े के व्यवसाय को बहुत प्रभाव लगा। इस काल में उद्योगपतियों एवं अधिकारियों के अनेक भगड़े हुए। सरकार ने उद्योग की सहायता करने के लिए सन् 1926 में वस्त्रों पर से उत्पादन शुल्क (Excise duty) हटा दिया कुछ समय बाद सरायवा की माँग भी की गई। सन् 1927 में संरक्षण (protection) नीति

बलवत्ता में हुई। किन्तु इस उद्योग की वास्तविक नींव सन् 1854 में पड़ी, जब कि बम्बई में सूती वस्त्र का कारखाना स्थापित किया गया। इसके बाद बम्बई महमदाबाद, नागपुर तथा शोलापुर में कई कपड़े बनाने के कारखाने खोले गए। प्रारम्भिक काल में इस उद्योग की प्रगति बहुत धीमी रही। सन् 1881 से प्रथम महायुद्ध के काल तक भारतीय सूती वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ा। स्वर्गीय राहु-बिगा महाराम गांधी के 'स्वदेशी आंदोलन' से उद्योग पर बहुत प्रभाव प्रभाव पड़ा। विदेशी कपड़े के

बपनाई गई, जिसमें विदेशी वस्त्र के आयात पर बर लगाना गया ।

द्वितीय महायुद्ध काल—द्वितीय महायुद्ध काल में भारतीय वस्त्रोद्योग को विकसित करने का मुनहरा अवसर मिला, बुकि इंग्लैंड और जापान भारत को वस्त्र भेजने वाले दोनों ही देश, युद्ध के मंचर में पड़े हुए थे अतः इस काल में बपड़े के उत्पादन और मूल्य दोनों में ही वृद्धि हुई । सन् 1943 में बस्त्रों का मूल्य चरम सीमा तक पहुँच गया । सरकार ने मूल्य-वृद्धि रोकने के कई प्रयत्न किए । मूल्य नियंत्रण के अतिरिक्त वितरण पर भी नियंत्रण कर दिया गया । सन् 1947 में देश के विभाजन के परिणामस्वरूप बपास उत्पादन करने वाले कई क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये इससे कच्चे माल की कमी अनुभव हुई । सन् 1947 में उद्योग की स्थिति कुछ सुधार आने से सरक्षण नीति को समाप्त कर दिया गया ।

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रगति—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सूत और वस्त्र उत्पादन के निर्धारित लक्ष्यों से अधिक सफलता मिली । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वस्त्र निर्मात और प्रति व्यक्ति वस्त्र उपभोग के महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए । इस योजना में 91.44 करोड़ मीटर वार्षिक वस्त्र निर्मात का लक्ष्य रखा गया था । योजना के अंत तक सूती वस्त्र के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य 775 करोड़ मीटर पर निर्धारित किया गया था जो पूरा हो गया है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सूती वस्त्र उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 865 करोड़ मीटर रखा गया था । वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के अतिरिक्त 25 हजार स्थापित करके लगाने का लक्ष्य रखा गया है ।

चौथी योजना में 40 लाख लघुए, 25 हजार बड़े लदाने का निश्चित किया गया है । देश में बपड़े की बस्तीयों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जायगा । बपड़े के उत्पादन तथा निर्यात को भी प्रोत्साहन दिया जायगा । योजना की धारा में अग्निबीबरण के लिए 132.5



सूत कातने वाले हैं) जिनमें 174.5 लाख तकुए (Spindles) तथा 289 लाख करपे (Looms) लगे हुए हैं। प्रतिवर्ष 25 से 40 नए कारखानों की स्थापना होती है। इस क्षेत्र में सहकारी कारखाने भी स्थापित हो रहे हैं।

सन् 1968 में कारखानों द्वारा 436.61 करोड़ मीटर कपड़ा तथा 96.09 किलोघाम सूत (Yarn) का उत्पादन हुआ।

उद्योग की समस्याएँ उपचार एवं प्रगति—

यद्यपि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का अविष्य उज्ज्वल है तथापि इसके सामने वर्तमान समय में कुछ गम्भीर समस्याएँ हैं। इन समस्याओं को दूर किये जाने पर ही सूती वस्त्र उद्योग के विकास की आशा की जा सकती है। ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

1. कच्चे माल की समस्या—कपास की कमी उद्योग की सबसे गम्भीर समस्या है। भारत कपास में भारत निर्भर नहीं है। देश

विनाशन ने इस समस्या को और गम्भीर बना दिया। लम्बे रेलों वाली उत्तम कपास हमें विदेशों से मगानी पड़ती है।

भारत सरकार कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयत्न उठा रही है। पंचवर्षीय

योजनाओं के अन्तर्गत कपास उत्पादन के निम्न विधेय लक्ष्य रखे गए हैं।

सन् 1967-68 में 55-62 लाख मीट कपास का उत्पादन हुआ।

2. आधुनिकीकरण (Modernisation) की समस्या—आंध्र-प्रदेश सूती बगों के कारखानों में लगी हुई मशीनें पिसी हुई हैं। उत्पादन बढ़ाने तथा उत्पादन लागत कम करने के लिए आधुनिकीकरण आवश्यक है। योजना आयोग ने उद्योग में आधुनिकीकरण को पूर्ण

#### वस्त्रोद्योग की समस्याएँ

1. कच्चे माल की समस्या
2. आधुनिकीकरण की समस्या
3. विवेकीकरण की समस्या
4. निर्माण बढ़ाने की समस्या
5. उत्पादन समन्वय की समस्या

लागत का अनुमान 360 करोड़ रुपये लगाया है, जो देश के सामर्थ्य से बाहर है। भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम' की स्थापना की है जो आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत खरीदने के लिए ऋण देता है।

3. विवेकीकरण (Rationalization) की समस्या—भारतीय सूती वस्त्रोद्योग का विकास विवेकपूर्ण वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ है। इससे वस्त्र की उत्पादन लागत बढ़ती है। लगभग 125 कपड़े की छोटी अनाधिक मिलों को पुनः संगठित करके उनमें विवेकीकरण अर्थात् संगठन और मशीनों से सम्बन्धित सुधार करने चाहिये। बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए विवेकीकरण धीरे-धीरे करना होगा।

4. निर्यात बढ़ाने की समस्या—सूती वस्त्रों की निर्यात वृद्धि की समस्या गम्भीर रूप धारण कर रही है। जापान और पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा निरन्तर बढ़ रही है। कई कपास उत्पादन करने वाले देश भी अपने देशों में सूती वस्त्र के निजी कारखाने खोलना चाहते हैं जिससे हमारे कपड़े की विदेशों में माँग और कम हो जाएगी। अतः उत्पादन लागत कम करके नये-नये डिजाइन निकालकर विज्ञापन द्वारा निर्यात बढ़ाना चाहिये।

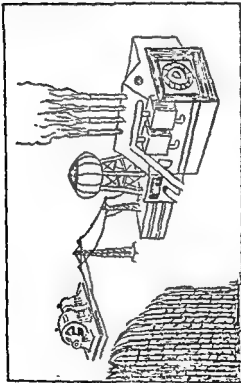
5. उत्पादन समन्वय की समस्या—सूती वस्त्र का उत्पादन कारखानों, हाथ करघों तथा शक्ति करघों द्वारा किया जाता है। इनमें समन्वय का अभाव है। अतः इन तीनों की स्पर्धा के स्थान पर समन्वय (Co-ordination) इस प्रकार दिया जाय कि किसी भी क्षेत्र के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

संक्षेप में, सूती वस्त्र उद्योग को बनवाने के लिए उत्पादन लागत को कम करना अति आवश्यक है। ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जबकि आधुनिकीकरण एवं विवेकीकरण कार्यक्रमों को तेजी से अपनाया जाय।

### चीनी उद्योग (SUGAR INDUSTRY)

चीनी उद्योग भारतीय मण्डित उद्योगों के क्षेत्र में दूसरा स्थान

रखता है। हमारा देश शाकाहारी अथवा (Vegetarian) होने के कारण हमारे भोजन में चीनी का बहुत महत्व है। साथ ही चीनी विदेशी मुद्रा कमाने का भी महत्वपूर्ण साधन है।



शेक-कर उद्योग

इतिहास—ऐसा समझा जाता है कि भारतवर्ष का चीनी व्यवसाय बहुत पुराना है। किन्तु पहले कुछ और साइकल उद्योग ही थे और

आधुनिक यंत्रों वाले कारखानों का मूत्रपात मन् 1930 के बाद ही अधिक ठंडों में हुआ। इस समय भारत सरकार ने उद्योग के विकास के लिए संरक्षण (Protection) प्रदान किया। संरक्षण के परिणामस्वरूप बाहर से आने वाली चीनी की मात्रा में कमी हुई। संरक्षण के कारण ही अन्य उद्योगों की प्रवेष्टा चीनी उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि 'भारतीय चीनी उद्योग संरक्षण का बालक है।' (Indian Sugar Industry is the child of protection)

द्वितीय महायुद्ध काल में चीनी उद्योग को पुनः संरक्षण प्रदान किया गया। इस समय चीनी की कीमत बहुत बढ़ गई। अतएव सरकार ने चीनी के मूल्य और वितरण पर नियंत्रण करना स्वीकार किया। यह उद्योग सन् 1950 तक सरकारी संरक्षण प्राप्त करता रहा। सन् 1931 से 1950 तक लगभग सारी अवधि में चीनी उद्योग को संरक्षण मिलता रहा। जहाँ सन् 1931 में चीनी मिलों की संख्या 32 और उत्पादन 5 लाख टन था, वहाँ 1951 में यह संख्या बढ़ कर बसतः 141 और 14.2 लाख मी. टन हो गई।

#### पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत प्रगति—

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चीनी उत्पादन का लक्ष्य 15.2 लाख मी. टन प्रतिवर्ष रखा गया, किन्तु मौसम बढ़ जाने के कारण इसमें संशोधन करके 19.2 लाख मी. टन कर दिया गया। मद् कारखाने खोले गये और चीनी उद्योग के विकास एवं नियंत्रण के लिए 'चीनी विकास परिषद्' की स्थापना की गई। योजना के अन्त में चीनी का उत्पादन 18.9 लाख मी. टन प्रतिवर्ष हो गया। इस अवधि में लगभग 15 करोड़ रुपये की पूंजी का और विनियोग (investment) इस व्यवसाय में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में चीनी की क्षमता बढ़ा कर 25.4 लाख मी. टन कर देने का लक्ष्य था। उत्पादन बढ़ाने के लिए सहकारी चीनी मिलों (Co-operative Sugar Mills) की स्थापना के लक्ष्य रखे गये। इस अवधि में चीनी मिलों में आधुनिक

कीकरण एवं विवेकीकरण को प्राथमिकता (Priority) दी गई। योजना के अन्तिम वर्ष में चीनी का उत्पादन 26.4 लाख मी. टन हुआ। इस अवधि में चीनी उद्योग विकास पर 10 करोड़ रुपये खर्च किया गया। इस अवधि में उत्पाति बढ़ जाने से चीनी का निर्यात भी किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—के अन्त में चीनी के उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य 35.6 लाख मी. टन पर निर्धारित किया गया था। योजना समीप ने यह तय किया है कि चीनी के निर्यात को बढ़ाया जाय।

वर्तमान स्थिति—सन् 1967-68 में भारतवर्ष में चीनी मिलों की संख्या 200 थी। अनुमान है कि इस उद्योग में 1½ लाख अधिक काम कर रहे हैं। इस उद्योग से सरकार को 65 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है और हमने 100 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी लगी हुई है। सन् 1967-68 में सरकार का उत्पादन 22.48 लाख टन हुआ।\* इसी वर्ष में देश से सरकार का निर्यात सन् 1966-67 की अपेक्षा 1.70 लाख टन कम किया गया। यह उद्योग लगभग 2 करोड़ कुश्कों से गन्ना खरीद कर राष्ट्रीय आय में 5% योगदान देता है। सन् 1963 में चीनी उत्पादन और बन्ने के मुख्य की कठिनाइयों के कारण चीनी का राशन कर दिया गया था। अब आर्थिक नियंत्रण की नीति अपनाई गई है। इस उद्योग का लगभग एक चौथाई भाग सहकारी क्षेत्र (Co-operative Sector) में है। यह उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में केन्द्रित है।

उद्योग की समस्याएँ एवं उपचार

चीनी उद्योग की कुछ गंभीर समस्याएँ हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है।

---

\*India 1969, p. 324



### चीनी उद्योग की समस्याएँ

1. गन्ने की कमी
2. गन्ने की कीमत सम्बन्धी कठिनाइयाँ
3. गन्ने की घटिया किस्म
4. गन्ना पेरने का अल्प समय
5. गन्ने का दोषपूर्ण विवरण
6. कृषि पक्ष और निर्माण पक्ष में अन्तर
7. अन्तर्गत उत्पादन इकाइयाँ
8. प्राधुनिकीकरण की समस्या
9. ईंधन की समस्या
10. उद्योग का स्थानीकरण
11. उपोत्पत्ति के उपयोग का अभाव
12. चीनी का संकट

1. गन्ने की कमी—अन्य देशों की तुलना में यहाँ गन्ने का उत्पादन बहुत कम है। भारत में गन्ने की प्रति हेक्टर मात्र 35.4 मी. टन है। यह चीन तुलना में एक तिहाई, जावा की तुलना में एक चौथाई तथा हवाई (Hawaii) की तुलना में पाँचवा भाग है। गन्ने की कमी का सीधा प्रभाव चीनी उद्योग पर पड़ता है।

अतः गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयत्न किये जाने चाहिए। इसके लिए सिंचाई की सुविधाएँ उत्तम बीज, खाद, औजार, कीटाणु नाशक औषधियाँ, भूमि जल की

रोक आदि सुविधाएँ आवश्यक हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में गन्ना उत्पादन वृद्धि पर ध्यान दिया जा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में की कृषि विकास पर बहुत बल दिया जाएगा।

2. गन्ने की कीमत सम्बन्धी कठिनाइयाँ—हमारे यहाँ जावा और अन्य चीनी उत्पादक देशों की तुलना में गन्ने की कीमत अधिक है। परिणामस्वरूप उत्पादन सागत बढ़ जाती है। क्योंकि गन्ने की कीमत में कमी होना खेती के विकास पर निर्भर करता है, इसलिये इस दिशा में सहायरी प्रयत्न करने चाहिए।

3. गन्ने की घटिया किस्म—गन्ने की कीमत तो अधिक है ही साथ ही साथ गन्ने से प्राप्त होने वाली चीनी का प्रतिशत भी बहुत कम

। भारत में 100 बी. टन गन्ने से 6 बी. वर्षा 6% चीनी प्राप्त होती है, जबकि आस्ट्रेलिया में 14% जावा में 11% क्यूबा और पैरिस में गन्ने से 12% चीनी प्राप्त होती है। गन्ने की स्थिर मुदाने के लिए यदुरी सेलो, उत्तम खाद, बीज, बीमार, सिंचाई आदि विधायें दी जानी चाहिए। सरकार इस ओर प्रयत्नशील है।



4. गन्ने पैरने का उत्तम समय—हमारे यहाँ वर्ष में दो बार

110 दिन का गन्ना पेरने का कार्य होता है, जबकि अन्य देशों में 240-250 दिनों तक गन्ना पेरने का कार्य होता है। इससे भारतीय चीनी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। अतः अनुसंधान करके गन्ना पेरने की अवधि में वृद्धि की जानी चाहिए। इसके लिए जापे-पीछे फसल उगाने पर खोज की जानी चाहिए।

5. गन्ने का क्षेत्रपूर्ण वितरण—कई कारखाने ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ गन्ना बहुत कम पैदा होता है। फलस्वरूप उन कारखानों को दूर-दूर से गन्ना मंगाना पड़ता है, जिससे दुल्हाई सर्व बढ़ जाता है अतः उन्नत यातायात के साधनों के प्रतिरिक्त देश के सभी भागों में गन्ना उत्पादन के विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।

6. हृषि पक्ष और निर्माण पक्ष में अन्तर—हमारे यहाँ गन्ना उत्पादन एवं चीनी निर्माण कार्य अलग-अलग पक्षों द्वारा किया जाता है। चूँकि इन दोनों में समन्वय की कमी है, इसलिए कारखाने गन्ने की मात्रा एवं उत्तमता को नियमित नहीं कर सकते। अतः विश्व के अन्य चीनी उत्पादक देशों की प्रगति दोनों पक्षों में उचित तालमेल बिठाना चाहिए, सहकारी चीनी मिलों द्वारा यह कार्य अधिक सरलता से हो जायगा।

7. अनावधिक उत्पादक इकाइयाँ (Uneconomic Units)—कई चीनी कारखाने ऐसे हैं जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है और वे चीनी उत्पादन लागत को बढ़ा देने हैं। एकीकरण, विलीनीकरण तथा विवेकीकरण पद्धतियों द्वारा इन केव क्षेत्र को दूर करना चाहिए।

8. आधुनिकीकरण की समस्या—भारत में अधिकांश मिलें अनावधिक इकाइयों के रूप में हैं। पुरानी उत्पादन पद्धतियों और घिसी हुई मशीनों के प्रयोग से उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप निर्यातों को भारतीय चीनी बहिरी पड़ती है जिससे निर्यात में कमी आती है। अतः इनमें आधुनिकीकरण आवश्यक है। "राष्ट्रीय उद्योग विकास विभाग" इस ओर प्रयत्नशील है।

9. ईंधन (Fuel) की समस्या—चीनी मिलों में बहुधा गन्ने का छिलका (bagasse) जलाया जाता है। किन्तु यह अपर्याप्त मात्रा में है। अतः विद्युत के प्रयोग को बढ़ाया देना चाहिए। योजनाओं के अन्तर्गत जल विद्युत शक्ति के विकास पर बल दिया जा रहा है।

10. उद्योग का स्थानीयकरण—समूचे उद्योग के लगभग 75 प्रतिशत कारखाने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थित हैं तथा उनमें चीनी की खपत बहुत कम है; जबकि बम्बई व मद्रास में चीनी की माँग अधिक है, लेकिन वहाँ चीनी उत्पादन के कारखाने नगण्य हैं। कारखानों के एक ही स्थान पर केन्द्रीयकरण होने से यातायात व्यय बड़ जाता है। अतः देश के सभी भागों में चीनी के कारखानों का विस्तार करना चाहिए। सहकारी क्षेत्र में इस उद्योग की प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

11. उपोत्पत्ति के उपयोग का अभाव—चीनी कारखानों की उपोत्पत्ति (by products) का समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत बढ़ी हुई है। गन्ने का छिलका (bagasse) कागज तथा गन्ना बनाने के काम में सिपा जा सकता है। इसके अलावा भारी मात्रा में जमा होने वाला शीरा (Molasses) को एल्कोहल (alcohol), उर्वरक (fertilizers), औरों के भोजन व अन्य उपयोग में लाया जा सकता है।

12. चीनी का संकट—पिछले कुछ वर्षों से घरेलू उपयोग के लिए चीनी का संकट चल रहा है। मुख्य भी बढ़ गए हैं। सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए चीनी का मुख्य नियन्त्रण तथा राजस्व कर दिया है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि चीनी उद्योग को उन्नत दिशाओं में विकसित करने पर ही निर्भर बढ़ाया जा सकेगा। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति चीनी का उपयोग 3.2 कि. ग्राम प्रति वर्ष है जबकि अन्य देशों में इससे कई गुनी खपत है।

#### 4. जूट उद्योग (Jute Industry)—

इस उद्योग की उपयोगिता राष्ट्र के जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे लिये विदेशी विनिमय भी प्राप्त करवाता है। भारत को प्रारम्भ से ही इस उद्योग में एकाधिकार (monopoly) प्राप्त रहा है। वस्तुओं को पैक करने, नौकाओं व जलपोतों पर पात का काम करने, मोटे-मोटे रस्सों के द्वारा वस्तुओं को बाँधने में जूट का प्रमुख स्थान है।

प्रारम्भिक काल—जूट के अधिकृत करवाने हुगली के तट पर कलकत्ता के चारों ओर केन्द्रित है। यद्यपि जूट की खेती प्राचीनकाल से होती आ रही है, किन्तु इसका निर्यात व्यापारिक रूढ़िमाने पर 16 वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के साथ प्रारम्भ होता है। सन् 1854 में जब रूसी पाट का निर्यात बन्द हो गया तो एक अंग्रेज उद्योगपति आर्कलेण्ड ने तेरामपुर के पास रिशारा नामक जगह पर जो बंगाल में है, पहली जूट की मिल की नींव डाली। इससे अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिला और फिर बोनियों कम्पनी की स्थापना सन् 1859 में हो सकी। पहले 30 वर्षों में विकास की गति मन्द रही। सन् 1868 से सन् 1873 तक मिलों ने खूब लाभ कमाये, इसलिये और भी मिलें खुलने लगी और 30 मिलों में मजदूरों की संख्या 20,000 तक पहुँच गयी। इनमें से 16 मिलें बम्बई के पास केन्द्रित थीं। निर्यात बढ़े और सन् 1885 में जूट के थोरों की जगह जूट के कपड़ों का उत्पादन बढ़ा। सन् 1900 के बीच एक अकाल पड़ा, जिससे उद्योग को घबका लगा लेकिन 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ में कृषि की उन्नति के साथ-साथ इस उद्योग ने भी उन्नति की। सन् 1906 में फिर उद्योग में शिथिलता आई क्योंकि जर्मनी और अमेरिका में जूट और पाट के कई स्थानाग्न (Substitutes) ढूँढे जाने लगे।

प्रथम महायुद्ध व उद्योग—युद्ध काल में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया और रूसी रजत का निर्यात बन्द हो गया। अब भारत के इस उद्योग को लाभ पहुँचा व प्रोत्साहन मिला। सन् 1918 तक जूट की खपत 55 लाख गॉठ प्रतिवर्ष हो गयी, जब कि यह माँघ युद्ध के पहले

44 साल लोड थी। इस अवधि में उद्योगपतियों ने 55% से 60% तक लाभ कमाया।

युद्ध के बाद मांग गिरने से निर्यात कम हुए। मजदूरों ने मजदूरी की वृद्धि की मांग की और अवसाद (Depression) का समय आया। सन् 1929 की महान् आर्थिक मंदी का संकट भी आया लेकिन संगठन बढ़ा होने के कारण उद्योग इस संकट को झेल सका।

द्वितीय महायुद्ध काल में उद्योग—युद्ध से उद्योग को एक बार फिर प्रोत्साहन मिला। यूट की मांग बढ़ने से आर्थिक उत्पादन सन् 1939 में 90,700 टन से बढ़कर सन् 1940 में 1,25,760 टन हो गया। यह उद्योग का नया रिकार्ड था। युद्ध के प्रथम वर्ष में मिलों की संख्या 107 तक पहुँच गयी जिनमें 98 बंगाल, 3 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 2 मद्रास और एक अन्य प्रदेश में स्थित थी।

विभाजन में उद्योग—सन् 1947 में देश के विभाजन ने इस उद्योग पर सबसे अधिक मारी प्रभाव डाला। पाकिस्तान को 63.4% बच्चे यूट उत्पादन का भाग मिला और भारत में 113 मिलें रह गयीं। बाद में बिहार, उड़ीसा में उत्तर प्रदेश की मिट्टी पर परीक्षण हुए और वहाँ उत्पादन एवं प्रचार हुआ। इस समय देश में 88 यूट मिलें हैं।

यूट उद्योगों की वर्तमान स्थिति—प्रथम योजना में उद्योग ने आशाशील सफलता प्राप्त की और यूट के सामान्य वार उत्पादन 11.1 लाख टन था। सन् 1955-56 में यूट के सामान्य वार निर्यात 8,75,000 टन था। सन् 1951-52 में कोरिया के युद्ध ने निर्यात को प्रोत्साहन दिया। सन् 1960 में 84,000 टन बच्चे यूट का निर्यात किया गया। द्वितीय योजना में बच्चे यूट का उत्पादन वार 40 लाख टॉन्स रखा गया था। तृतीय योजना में 72 लाख तथा चौथी योजना में 110 लाख टॉन्स रखा गया है। अभी उद्देश्य से 21 जिलों में दहरी सेही बार्डचम प्रारम्भ हो चुका है। सन् 1966-67 में 283.53 करोड़

रूपरे के मूल्य की वृद्ध वस्तुओं का निर्यात हुआ १० लाख 1968 में वृद्ध निर्यात मात्रा का उत्पादन 10-85 लाख टन हुआ १।

उद्योग की समस्याएँ तथा सुझाव (Problems and Suggestions)

1. कच्चे माल का अभाव (Shortage of raw material)—

कच्चे माल का अभाव देश-विभाजन के साथ ही प्रारम्भ हुआ । इस अभाव को दूर करने के लिये नये क्षेत्र उत्पादन के लिए खूँटे गये । किन्तु अलगाव एवं मिट्टी की विविधता के कारण आभासिक संकलन में विघ्न । वृद्ध का उत्पादन बढ़ा तो अभाव किन्तु निर्यात निम्न कोटि की हो रही । यतः उच्च कोटि का वृद्ध अब भी आयात करना पड़ता है । वृद्ध आयोग (Jute commission) ने उत्पादकों को उचित मूल्य देने की सिफारिश की ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिल सके । परमन सचिव के अध्यक्ष श्री एन सी. श्रीवास्तव ने कहा कि वृद्ध सामान की वर्तमान दरों को देखते हुए यह आशा की जाती है कि वर्ष 1970-71 तक 10 लाख 41 हजार टन और सामान की गत होने लगेगी ।

2. निर्यात सम्बन्धी समस्या (Problem of export)—

उद्योग की दूसरी समस्या निर्यात के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि भारत अपने कुल वृद्ध के निर्यात का 8-9% अकेले पश्चिमी यूरोप को निर्यात करता है । यतः गत बढ़ाने के लिए इन देशों की महायत्ना से एक अच्छी अवधि का निर्यात कार्यक्रम तैयार करना चाहिये । साथ ही साथ बांग्ला, थाईलैंड, बर्मा, माल, हाईलैंड और केम्बोडिया में वृद्ध विभिन्न की स्थापना और उत्पादन विद्या का रहा है । विदेशों में वृद्ध के स्थापना निम्न पड़े हैं । स्वयं पाकिस्तान वृद्ध सबसे प्रतिद्वन्द्वी के रूप में हमारी टाइट में लड़ा है । इन सब परिस्थितियों में आशा करना इन बात की है कि निर्यात बढ़ाया जाए और उच्च कोटि का आयात तैयार हो । इसके ठीके परमन सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छी वृद्ध की ऐसी स्थापना की जावे जिसके अनुसार किसी आयात या निर्यात की परमन का अधिकार वृद्ध करने का काम होता जाय ।

• India 1969, p. 370

† India 1969, p. 323

**3. अमिनवीकरण की समस्या (Problem of modernisation)—**अमिनवीकरण की समस्या जो भारत के सभी उद्योगों के साथ दिखलाई पड़ती है, बड़ी गम्भीर है। नई मशीनों द्वारा बनाया हुआ माल सस्ता और अच्छा होने के कारण ग्राहकों को जल्दी आकर्षित कर लेता है। अतः इस उद्योग में अमिनवीकरण आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

### सीमेन्ट उद्योग (Cement Industry)

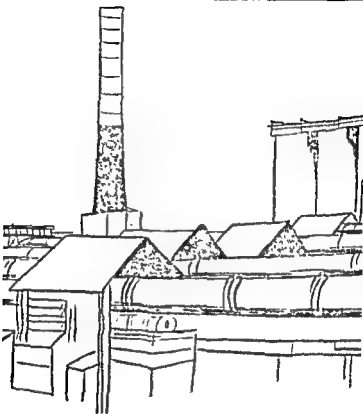
मानव की तीन प्रमुख आवश्यकताएँ हैं—भोजन, वस्त्र तथा मकान। भवन निर्माण कार्य के लिए सीमेन्ट की आवश्यकता होती है। बाँध, सड़कें एवं अन्य निर्माण कार्यों में भी सीमेन्ट का महत्व सुविधित है।

**इतिहास—**सीमेन्ट उद्योग बहुत प्राचीन व्यवसाय नहीं है। सर्व प्रथम सीमेन्ट बनाने का कार्य सन् 1904 में मद्रास में हुआ किन्तु इसका वास्तविक प्रारम्भ सन् 1912-13 में हुआ जब विशाल पैमाने पर तीन कम्पनियों का निर्माण हुआ। प्रथम महायुद्ध से इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। सन् 1923 तक भारत में 10 सीमेन्ट कम्पनियाँ खुल गईं। इसी समय सीमेन्ट उद्योगपतियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए "इण्डियन सीमेन्ट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन" की स्थापना की। सन् 1936 में व्यवसायिक स्पर्धा के निवारणार्थ एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनीज (A.C.C.) लि० का गठन हुआ। द्वितीय महायुद्ध काल में इस व्यवसाय की उन्नति हुई।

विभाजन (1947) के समय भारत में 18 कारखाने रह गये। प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के अन्त में सीमेन्ट का उत्पादन 47 लाख टन हुआ।

**द्वितीय योजना—**के अन्त में सीमेन्ट का उत्पादन 79 लाख टन तथा तृतीय योजना के अन्त में 110 लाख टन हो गया। सन् 1965 में





सीमेंट उद्योग

सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान, प्राविधिक सलाह तथा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए 'सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया' का गठन किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सीमेंट की उत्पादन क्षमता लगभग 230 लाख टन हो जाने का अनुमान है। सन् 1962 में बिलावट रोकने के लिए अध्यादेश जारी किया गया। सन् 1966 के प्रारम्भ में मूल्य एवं वितरण पर से सरकारी नियन्त्रण हटा दिया गया। पुनः नियन्त्रण लगाया गया परन्तु सन् 1970 में नियन्त्रण हटा देने का निश्चय किया गया है।

वर्तमान स्थिति—इन समय सीमेंट उद्योग में लगभग 55 हजार श्रमिक काम करते हैं। उद्योग में लगभग 115 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक प्रयोग केवल 18 ग्राम है जिसकी अधिकता से काफी बढ़ जाने की सम्भावना है। सन् 1968-69 में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन 122 लाख टन था।

भारतीय सीमेंट उद्योग को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कुछ मुख्य समस्याएं हैं—मूल्य सम्बन्धी, पूंजी की कमी, प्रतिस्थापित क्षमता (Installed Capacity) का अपूर्ण उपयोग, कच्चे माल व दानावात की कठिनाइयाँ।

इन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य नियंत्रण, आवधिक सहयोग कमीनों के मायात की व्यवस्था, विस्म नियन्त्रण, कोयले की नियमित पूर्ति तथा सरकार की लाइसेन्सिंग पद्धति को व्यवहारिक बनाया जाना चाहिये।

देसी बरसोद्योग (Silk Industry)—एटपि यह 19 वीं मरी

● कुछ अन्य देशों में यह औद्योग है—ब्रिटेन 206 कि. घान, जापान में 226 कि. घा., जर्मनी में 259 कि. घा., अमेरिका में 272 कि. घा. तथा स्विट्जरलैण्ड में 386 कि. घा.

† India 1969, p. 324

भीरे शक्ति प्राप्त करीर, प्रमाण के २७ से गुणाई, मान १०० दिया  
 २० की गयी है। होकर वायुमंडल का ऊँचाई के २०० मी. परमाणु  
 गया है। इसके परिणति मान, वायुमंडल का ऊँचाई, मान, मान  
 भंडार, निरुद्ध कीर, प्रमाण के २०० है। इन बाकी का निरुद्ध कीर  
 निरुद्ध मान है। यह निरुद्ध निरुद्ध कीर है।

७. कृषि प्रमाण (Agricultural Production) - भारत में  
 भूमिगत प्रमाण के २०० कृषि मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 से हुआ प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान के मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 प्रमाण के मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 प्रमाण के मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 प्रमाण के मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 प्रमाण के मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००

८. प्रमाण प्रमाण (Agricultural Production) - भारत में  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००

९. प्रमाण (Agricultural Production) - भारत में  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००  
 मान, प्रमाण के २०० मान, प्रमाण के २०० मान, मान १००

अब तक हम चमड़ा और सातों निर्माण करते थे किन्तु अब देश में ही चमड़े का सामान बनाने का धन्दा विकसित हो जाने के कारण यह निर्माण धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मद्रास में यह व्यवसाय अधिक उन्नत है। यह व्यवसाय निजी क्षेत्र के ही नियन्त्रण में है।

11. कागज उद्योग (Paper Industry)—देश में पहला कारखाना 1870 में खोला गया। यह व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाता है। पच्छिम प्रदेश का मेसनस म्यूक प्रिंट एण्ड पेपर मिल, नैपानगर सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। सन् 1968 में कागज तथा बोर्ड का उत्पादन लगभग 6.35 लाख टन हुआ।\*

12. वनस्पति तेल उद्योग (Vegetable oil Industry)—वनस्पति तैलों का वार्षिक उत्पादन लगभग 29 लाख टन माना जाता है। देश में लगभग 55 कारखाने, महाराष्ट्र, गुजरात, पं० बंगाल, मैसूर आदि राज्यों में स्थित हैं। यह व्यवसाय भी निजी क्षेत्र के अधिकार में ही है।

13. कोयला उद्योग (Coal Industry)—सन् 1814 में बंगाल के दुर्गापूर क्षेत्र में कोयले की खान खोदी गई। यह व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों में ही किया जाता है। सन् 1967-68 में कोयले का उत्पादन 685.2 लाख टन हुआ। इस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार बढ़ता जा रहा है।\*\*

14. पोत निर्माण (Ship Building) सार्वजनिक क्षेत्र में विलासापट्टनम् अहाजी बड़े निर्माण के कारखाने के घनिष्ठ कोषीन में भी एक कारखाना खोला जा रहा है। अब हमारे देश में प्राधुनिक सिस्टम के उत्तम चार बड़ाज प्रनि बने बनाये जा सकते हैं। तटीय एवं आन्तरिक जल यातायात के लिए आवश्यक साधनों का उत्पादन निजी क्षेत्र में ही होता है।

\*India 1969, p. 325

\*\*India 1969, p. 340

15. रेल के डिब्बे का निर्माण (Railway Coach Industry)—सार्वजनिक क्षेत्र में वेराप्पूर (मद्रास) की इन्स्ट्रल कोच फैक्ट्री तथा हिन्दुस्तान एयर क्रफ्ट लिमिटेड के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी जजिफ नामक कम्पनी रेल डिब्बों का निर्माण करती है।

16. रेल इंजिन बनाने का उद्योग (Locomotives)—सार्वजनिक क्षेत्र में चित्तूरजन सोकोमोटिव रेल इंजिन बनाने का कार्य 1950 से कर रहा है। इस कारखाने ने मार्च सन् 1969 तक 2,251 रेल के इंजिनों का निर्माण किया था। निजी क्षेत्र में टाटा इंजिनियरिंग एंड सोकोमोटिव कम्पनी (TELCO) भी लोकोमोटिव के इंजिनों का निर्माण कर रहा है। अब सार्वजनिक क्षेत्र में एक लोकोमोटिव इंजिनों का निर्माण करने वाले कारखाने का निर्माण वाराणसी में कर दिया गया है।

17. वायुयान (Air Craft) उद्योग—वायुयान का निर्माण वा कार्य एक मात्र सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार में है। 'हिन्दुस्तान एयर क्रफ्ट लिमिटेड' की विभिन्न इकाइयाँ विंग, गुजर सोनिक वेट, लड़ाऊ-HF-27, भारकेउम-703 एवरो-747, 'कृष्ण' एवं 'पुष्पक' आदि वायुयान बना रही हैं। इनके विभिन्न कारखाने नासिक, हैदराबाद, बंगलूर, कानपुर आदि में स्थित हैं।

18. ऑटोमोबाइल, मोटर साइकिलें तथा स्कूटर बनाने का उद्योग कुछ वर्षों पहले तक हमारे देश में ये सभी वस्तुएँ विदेशों से आती थीं। अब हमारे देश में ही विभिन्न प्रकार की मोटरें, कारें, जीपें, ट्रकें आदि बनाई जाने लगी हैं। इनकी बनाने वाले कारखाने निजी क्षेत्र में ही हैं। इन उद्योग में विदेशी सहयोग भी प्राप्त किया गया है। हमारे देश में लगभग 57 हजार मोटरों तथा 25 हजार मोटर साइकिलों तथा स्कूटरों का उत्पादन प्रति वर्ष होता है।

19. भारी औद्योगिक एवं कृषि मशीनों का निर्माण—इन क्षेत्र में मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र कर रहा है। रांची का ईरो मशीनरी प्लांट, दुर्गापुर का भार्गव मशीनरी प्लांट, रांची जो रो ईरो मशीन टूल्स प्रिवेट तथा कोयंबूर जोर्ज ऑटो, बंगलूर का हिन्दुस्तान मशीन



ਘੋੜੇ ਪੀੜਾਗੀ ਸੀ—ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਾਲੀਸ਼ 2121 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਚੜ੍ਹਾਇਸ਼  
 124 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ।

ਘੋੜਾਮ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ—ਫੇਰ ਦੇ ਸੰਮਤਿਓਂ ਘੋੜਾਮਾਂ ਦੇ ਫੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ  
 ਘੋੜੇ ਦੇ ।

ਘੋੜਾਮ ਦੀ ਘੋੜਾਮ, ਚੜ੍ਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਘੋੜਾਮ—

ਘੋੜਾਮ—(1) ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਘੋੜਾਮ (2) ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਘੋੜਾਮ  
 ਘੋੜਾਮ (3) ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਘੋੜਾਮ (4) ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਘੋੜਾਮ

(5) ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਘੋੜਾਮ ।

3. ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ—ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ।

ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ  
 10 ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ

ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ  
 10 ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ

ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ

ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ ਘੋੜੇ

1. 'ମାଟି'ର ଲୋକାଳୋଚନା ଲେଖି ଏହି କଥାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।  
2. ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।  
3. ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।  
4. ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।  
5. ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।

ଅନ୍ତରାଳ

1. ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।  
2. ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।  
3. ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।  
4. ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।  
5. ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ । ଏହା ଏକ ଲେଖନୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖିତ ।



का मुद्रा कायम रखी का निश्चित स्थापना की थी ।  
 गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है । गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है ।  
 गोपबंदोपेक्षा (Trade and Commerce) का स्वरूप है ।  
 गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है । गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है ।  
 गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है । गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है ।

गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है । गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है ।  
 गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है । गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है ।  
 गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है । गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है ।  
 गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है । गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है ।

## INDIAN FOREIGN TRADE

गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है । गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है ।

गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है । गोपबंदोपेक्षा का स्वरूप है ।

2. **ಮಾನ್ಯತೆ (Respect)** - ಇತರರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು, ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.

1 121 2 155 3 182

1. *Exports of Exports* (Exports of Exports) — in 1961

(Alma Festrer)

APR 1979

[illegible]

15 12/3

[illegible]

• 19 12 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2

4. *Explain the importance of the following factors in the development of a country:*

**ה'תשנ"ב**

3. ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ଠିକଣା ଲେଖାଯାଇଛି ।

§ 121.12(b)(1)

1. 1975-76 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई 'प्रतिरक्षण नीति' (Protection Policy)

[illegible]

(ग) प्रतिकूल काल (Postwar period) — द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक संकट का कारण बन गया था। इस अवधि में अमेरिकी सरकार ने भारत को ऋण प्रदान किया और व्यापार को बढ़ावा दिया।

[illegible]



[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible][illegible]

3. **वृद्ध वर सहायता (Devaluation of the Rupee) —**

2 व्यापार का सन्तुलन (Balance of Trade)—यहाँ के निर्यात व्यापार का सन्तुलन वर्ष 1950 की शीतल रकम निम्न में है।

| वर्ष    | रकम (रु.)   |
|---------|-------------|
| 1947-48 | 1,00,00,000 |
| 1948-49 | 1,50,00,000 |
| 1949-50 | 1,50,00,000 |
| 1950-51 | 1,50,00,000 |
| 1951-52 | 1,50,00,000 |
| 1952-53 | 1,50,00,000 |
| 1953-54 | 1,50,00,000 |
| 1954-55 | 1,50,00,000 |
| 1955-56 | 1,50,00,000 |
| 1956-57 | 1,50,00,000 |
| 1957-58 | 1,50,00,000 |
| 1958-59 | 1,50,00,000 |
| 1959-60 | 1,50,00,000 |
| 1960-61 | 1,50,00,000 |
| 1961-62 | 1,50,00,000 |
| 1962-63 | 1,50,00,000 |
| 1963-64 | 1,50,00,000 |
| 1964-65 | 1,50,00,000 |
| 1965-66 | 1,50,00,000 |
| 1966-67 | 1,50,00,000 |
| 1967-68 | 1,50,00,000 |
| 1968-69 | 1,50,00,000 |
| 1969-70 | 1,50,00,000 |
| 1970-71 | 1,50,00,000 |
| 1971-72 | 1,50,00,000 |
| 1972-73 | 1,50,00,000 |
| 1973-74 | 1,50,00,000 |
| 1974-75 | 1,50,00,000 |
| 1975-76 | 1,50,00,000 |
| 1976-77 | 1,50,00,000 |
| 1977-78 | 1,50,00,000 |
| 1978-79 | 1,50,00,000 |
| 1979-80 | 1,50,00,000 |
| 1980-81 | 1,50,00,000 |
| 1981-82 | 1,50,00,000 |
| 1982-83 | 1,50,00,000 |
| 1983-84 | 1,50,00,000 |
| 1984-85 | 1,50,00,000 |
| 1985-86 | 1,50,00,000 |
| 1986-87 | 1,50,00,000 |
| 1987-88 | 1,50,00,000 |
| 1988-89 | 1,50,00,000 |
| 1989-90 | 1,50,00,000 |
| 1990-91 | 1,50,00,000 |
| 1991-92 | 1,50,00,000 |
| 1992-93 | 1,50,00,000 |
| 1993-94 | 1,50,00,000 |
| 1994-95 | 1,50,00,000 |
| 1995-96 | 1,50,00,000 |
| 1996-97 | 1,50,00,000 |
| 1997-98 | 1,50,00,000 |
| 1998-99 | 1,50,00,000 |
| 1999-00 | 1,50,00,000 |
| 2000-01 | 1,50,00,000 |
| 2001-02 | 1,50,00,000 |
| 2002-03 | 1,50,00,000 |
| 2003-04 | 1,50,00,000 |
| 2004-05 | 1,50,00,000 |
| 2005-06 | 1,50,00,000 |
| 2006-07 | 1,50,00,000 |
| 2007-08 | 1,50,00,000 |
| 2008-09 | 1,50,00,000 |
| 2009-10 | 1,50,00,000 |
| 2010-11 | 1,50,00,000 |
| 2011-12 | 1,50,00,000 |
| 2012-13 | 1,50,00,000 |
| 2013-14 | 1,50,00,000 |
| 2014-15 | 1,50,00,000 |
| 2015-16 | 1,50,00,000 |
| 2016-17 | 1,50,00,000 |
| 2017-18 | 1,50,00,000 |
| 2018-19 | 1,50,00,000 |
| 2019-20 | 1,50,00,000 |
| 2020-21 | 1,50,00,000 |
| 2021-22 | 1,50,00,000 |
| 2022-23 | 1,50,00,000 |
| 2023-24 | 1,50,00,000 |
| 2024-25 | 1,50,00,000 |
| 2025-26 | 1,50,00,000 |
| 2026-27 | 1,50,00,000 |
| 2027-28 | 1,50,00,000 |
| 2028-29 | 1,50,00,000 |
| 2029-30 | 1,50,00,000 |
| 2030-31 | 1,50,00,000 |
| 2031-32 | 1,50,00,000 |
| 2032-33 | 1,50,00,000 |
| 2033-34 | 1,50,00,000 |
| 2034-35 | 1,50,00,000 |
| 2035-36 | 1,50,00,000 |
| 2036-37 | 1,50,00,000 |
| 2037-38 | 1,50,00,000 |
| 2038-39 | 1,50,00,000 |
| 2039-40 | 1,50,00,000 |
| 2040-41 | 1,50,00,000 |
| 2041-42 | 1,50,00,000 |
| 2042-43 | 1,50,00,000 |
| 2043-44 | 1,50,00,000 |
| 2044-45 | 1,50,00,000 |
| 2045-46 | 1,50,00,000 |
| 2046-47 | 1,50,00,000 |
| 2047-48 | 1,50,00,000 |
| 2048-49 | 1,50,00,000 |
| 2049-50 | 1,50,00,000 |
| 2050-51 | 1,50,00,000 |
| 2051-52 | 1,50,00,000 |
| 2052-53 | 1,50,00,000 |
| 2053-54 | 1,50,00,000 |
| 2054-55 | 1,50,00,000 |

1. Զ Լեւ ին Լեւ ք (որտա լուսւոր) յիմեա անշարին  
 ք Լեւին ան իմեա Լեւ ան Լեւ 2. Ե Եւեւ ին Եւեւ 'ճի  
 ին Եւեւ Լեւին 1. Զ Լեւ Եւեւ Եւեւ (Լ Ե Եւեւ անշարին  
 ք Եւեւ ք Եւեւ Եւեւին 1. Զ Լեւ ին ք Եւեւին Եւեւ  
 ին 2. Զ Լեւ Լեւին ք Լեւին Լեւ (Լ Եւեւ ին Եւեւ  
 '2. Լեւ Լեւ Եւեւ Եւեւին 1. Լեւ Եւեւ Եւեւ Եւ Եւեւ

[illegible]

(Pattern and Direction of Foreign Trade)

100% 100% 100% 100% 100%

1 Dec 2014

8. व्यापार की दिशा (Direction of Trade) से परिवहन—  
द्वारे व्यापार की दिशा में स्थिति महत्व के कारण महत्वपूर्ण परि-  
वहन है। पहले जहाँ उत्पादन को (Empire Counties) से  
की आवश्यकताएँ होती थीं, वही अब गैर-उत्पादन क्षेत्रों (Non-  
empire Counties) से व्यापार बढ़ रहा है; यहाँ स्थानीय व्यापार  
में इस दिशा की बदलावों के साथ-साथ बहुत राजस्व परिवर्तन का  
कारण एवं व्यापारिक संभव बन रहे हैं। वर्ष 1967-68 में यह  
दिशा की 229.03 करोड़ रुपये के मूल्य के निर्यात करने वाले देश  
समूह राज्य परिवहन की 207.43 करोड़ रुपये के मूल्य की परिवहन

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

[illegible]

१. १५३३ २५५५

6. **खाद्य (Food grains)** का विश्व अभाव—1945 तक  
 अनाज की संख्या में अत्यंत कमी के कारण खाद्यान्न की आवश्यकता  
 निर्धारित अभाव 125 करोड़ क्वार्टर तक बढ़ गई है। खाद्यान्न की  
 आवश्यकता के कारण अनाज की कीमतें अत्यंत बढ़ गई हैं।  
 खाद्यान्न की कीमतें अत्यंत बढ़ गई हैं। खाद्यान्न की कीमतें अत्यंत बढ़ गई हैं।



















9. मूल्य वृद्धि (Devaluation of India)—6 1/2 % 1966 के मूल्य वृद्धि (Rate)

1. What is the main purpose of the document?

8. **Export Risk Insurance**—

የጋራ ጥራት ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ ማረጋገጫ

7. **व्यापार कर (Commercial Agreement)**—

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[illegible]





18 नवम्बर 1964  
 18 नवम्बर 1964  
 18 नवम्बर 1964

● 18 नवम्बर 1964

- राष्ट्रीय निर्यात निगम (National Export Corporation) की स्थापना की गई है। इस निगम की स्थापना 18 नवम्बर 1964 को हुई थी।
- (अ) निर्यात निगम (National Export Corporation), 1964
- (ब) निर्यात निगम (National Export Corporation), 1962
- (ग) निर्यात निगम (National Export Corporation), 1956
- (घ) निर्यात निगम (National Export Corporation), 1956

है। यह है—

(Barter deals) के माध्यम से निर्यात निगम की स्थापना की गई है। इस निगम की स्थापना 18 नवम्बर 1964 को हुई थी।

निर्यात निगम की स्थापना 18 नवम्बर 1964 को हुई थी।

निर्यात निगम (National Export Corporation)

की स्थापना 18 नवम्बर 1964 को हुई थी।

निर्यात निगम की स्थापना 18 नवम्बर 1964 को हुई थी।

निर्यात निगम (National Export Corporation)

10. निर्यात निगम की स्थापना 18 नवम्बर 1964 को हुई थी।

है। यह है—

निर्यात निगम की स्थापना 18 नवम्बर 1964 को हुई थी।

निर्यात निगम (National Export Corporation)

निर्यात निगम की स्थापना 18 नवम्बर 1964 को हुई थी।

निर्यात निगम (National Export Corporation)





2. भारत के मुख्य भाषाओं व लिपियों का विवरण दीजिये और बताइये कि किस भाषा से आगे बढ़कर हमारे परिवर्तन कृति हो गयी है ?  
(रा. बी. ई. वी. 1961)
3. भारत की आजाद भूत लिपि का प्रमुख संशुद्धि का प्रयोग प्रदर्शित कीजिये ।  
(रा. बी. ई. वी. 1966)
4. संक्षिप्त लिपिबद्ध लिखिये—  
( i ) भारत के भाषाओं के मुख्य प्रकार  
( रा. बी. ई. वी. 1967-1968 )  
( ii ) सरकार की लिखित आचार्य की लिपि  
( iii ) लिख आचार्य
5. भारत के भाषाओं की मुख्य भूत संशुद्धि । भारत सरकार ने लिपि को परिवर्तन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?  
(रा. बी. ई. वी. 1969)

## PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN INDIA

“बेरोजगारी का सबसे बड़ा दृष्टिकोण मौलिक ढंग में विकास है। यह आवश्यकताओं की पूर्ति है नहीं बल्कि पूरा मनुष्य की क्षमता है।”

—हर्षनाथ

विषय की वृद्धि के अनवरत न केवल सामाजिक एवं आर्थिक

समस्याओं को उत्पन्न करता है। वृद्धि के अनवरत को उत्पन्न करता है।

मजदूर, बर्तन एवं अन्य सामान की मूल आवश्यकता पूर्ण होना (full

employment) की समस्या से ही उत्पन्न है। किन्तु विकास

में मात्र बेरोजगारी की समस्या से नहीं निकल कर निकल कर रहता

है। बेरोजगारी की समस्या अर्थ व्यवस्था के लिए एक रूप में सामान

बानी जाती है। यह समस्या छोटे छोटे अर्थ व्यवस्था एवं विकास, विशेष

तौर पर विकास के अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है। यह अर्थ में होती है।

संख्या (working population) 42.98 प्रतिशत  
 वर्ष 1961 की जनसंख्या के अनुसार प्रतिशत की संख्या

| वर्ष | 100-0 |
|------|-------|
| 11-5 |       |
| 1-6  |       |
| 4-1  |       |
| 10-6 |       |
| 2-7  |       |
| 69-5 |       |

संख्या (working population) 42.98 प्रतिशत  
 वर्ष 1961 की जनसंख्या के अनुसार प्रतिशत की संख्या

संख्या (working population) 42.98 प्रतिशत  
 वर्ष 1961 की जनसंख्या के अनुसार प्रतिशत की संख्या

संख्या (working population) 42.98 प्रतिशत  
 वर्ष 1961 की जनसंख्या के अनुसार प्रतिशत की संख्या

संख्या (working population) 42.98 प्रतिशत

| କ୍ର. ସଂ. | ନାମ   | ମାତ୍ରା   |
|----------|---|----------|
| 1.       | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ           | 1,53,058 |
| 2.       | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ           | 4,364    |
| 3.       | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ           | 94,316   |
| 4.       | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ           | 9,702    |
| 5.       | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ           | 2,481    |
| 6.       | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ           | 62,159   |
| 7.       | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ           | 1,95,323 |
| 8.       | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି) | 99,536   |
| 9.       | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି) | 1,03,371 |
| 3-9      |   |          |

- 1981-82 212 100000 212000 100000

[illegible][illegible]





की शकल है। फल्य वीर्यवान् य एवम् अस्माकं की शकल है।  
 • फल्यवान् य एवम् अस्माकं की शकल है।

उत्पत्ति य एवम् अस्माकं की शकल है।  
 5. Technical unemployment —

उत्पत्ति य एवम् अस्माकं की शकल है।  
 4. Unemployment among educated class —

(chale) अस्माकं की शकल है।  
 3. Seasonal unemployment —

उत्पत्ति य एवम् अस्माकं की शकल है।  
 2. Unemployment among uneducated class —



करते हैं। गरीबों की बेरोजगारी सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करने का साधन है।

राज्य सचिव के अनुसार पिछले पचास वर्षों में देश के 70 लाख लोग बेरोजगार थे। पिछले बीस वर्षों में लगभग 145 लाख रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। इस वर्ष में लगभग 170 लाख रोजगारों की संख्या है। इस वर्ष में 95 लाख रोजगारों के लिए।

बेरोजगारी के कारण—

18

यहां से बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं—

1. सामाजिक कारण—भारतीय समाज की विशेषता पिछेपिछेपन है। बेरोजगारी की समस्या को अज्ञान कारण है। बहुत अधिक न्याय के अभाव में समाज के लोग नए नए काम शुरू करते हैं। सामाजिक कारणों के कारण समाज के लोग नए नए काम शुरू करते हैं। सामाजिक कारणों के कारण समाज के लोग नए नए काम शुरू करते हैं।

सामाजिक कारणों के कारण समाज के लोग नए नए काम शुरू करते हैं। सामाजिक कारणों के कारण समाज के लोग नए नए काम शुरू करते हैं। सामाजिक कारणों के कारण समाज के लोग नए नए काम शुरू करते हैं। सामाजिक कारणों के कारण समाज के लोग नए नए काम शुरू करते हैं। सामाजिक कारणों के कारण समाज के लोग नए नए काम शुरू करते हैं।

2. सरकार की नीति—

देश में रोजगार के अवसरों में अंतर है।

1. सामाजिक कारण—संस्कृत, पुरानी भाषा, गांधी भाषा, फिजिकल शिक्षा
2. सरकार की नीति—
3. उद्योग उद्योगों का विकास
4. रोजगार के अवसरों का विकास
5. शिक्षा का विकास
6. रोजगार के अवसरों का विकास
7. नए नए काम

में वह रही है। मजदूर 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। भारत में मजदूरों (मजदूर 125 लाख) की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है।

3. प्रतिवर्ष बढ़ रही है—मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है।

4. प्रतिवर्ष बढ़ रही है—मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है।

5. प्रतिवर्ष बढ़ रही है—मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है।

6. प्रतिवर्ष बढ़ रही है—मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है।

7. प्रतिवर्ष बढ़ रही है—मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या बढ़ रही है।

[illegible][illegible][illegible]

अध्यास १११ : प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझाओ और प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझाओ। (Challenger) है।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥  
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



1. जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) के लिए प्रस्ताव  
 तालुका (Family Planning), देर से फैलाव (Late marriages)  
 अधिक फैलाव, फैलाव का खर्च, यदि उपाय किए जाने चाहिये  
 फैलाव से रोकथाम के लिए प्रस्ताव का ही प्रस्ताव है ।

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 2. गिरमि से रोकथाम                  | गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव |
| 3. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव  | गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव |
| 4. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव  | गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव |
| 5. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव  | गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव |
| 6. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव  | गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव |
| 7. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव  | गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव |
| 8. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव  | गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव |
| 9. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव  | गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव |
| 10. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव | गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव |

4. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव  
 गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव  
 गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव  
 गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव  
 गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव

5. गिरमि से रोकथाम के लिए प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव





—(1) ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, (2) ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, (3) ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, (4) ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, (5) ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା

151

የጋራ ጥያቄዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነዶች እና ሰነዶችን በቅርቡ ለማግኘት ማስታወሻዎችን ያነቡ፡

1 Feb 1951

આચાર્યશ્રીના આશ્રિત સ્વરૂપે આજીવન સેવા કરવાનો માર્ગદર્શક બન્યા હતા. આજીવન સેવા કરવાનો માર્ગદર્શક બન્યા હતા.

— ԿՈՒՆ ԵՔ ԽԱՆԻՆԵՅ ԴԱՆԵԱՆԵՔ ԵՔ ԴԱՆԵԱՆԵՔ ԵՔ ԴԱՆԵԱՆԵՔ —

1. 1991-92 (7), 1992-93 (8), 1993-94 (9)

[illegible]

የጥቅምት ፩ ቀን ፳፭ ፳፭ (፳፭ ፳፭)

'In Date of Birth 1950—Indians in Village is 1000

[illegible]

(2) જાહેર સ્થાનો પર, (3) જાહેર સ્થાનો પર, (4)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

13. **प्रश्न** : निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए :

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

Let the value of  $\alpha$  be such that  $\alpha \leq \alpha_0$  and  $\alpha \geq \alpha_1$  and let  $\alpha_0$  and  $\alpha_1$  be

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

સાદર આભાર

全12册



।

( ॥ ) एतेषां वेदेषां ।

( १ ) अथवा वेदेषां ।

4. अथवा वेदेषां । अथवा —

को एतेषां वेदेषां ।

3. वेदेषां को एतेषां वेदेषां । अथवा वेदेषां ।

अथवा वेदेषां ।

2. अथवा वेदेषां । अथवा वेदेषां ।

वेदेषां ?

1. वेदेषां को एतेषां वेदेषां ? अथवा वेदेषां ।

अथवा

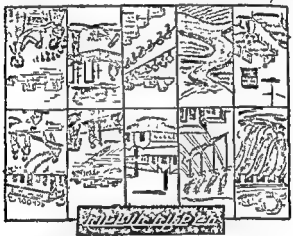
( 10 ) अथवा वेदेषां को एतेषां ।

अथवा, ( 8 ) अथवा वेदेषां । ( 9 ) अथवा वेदेषां ।

अथवा, ( 6 ) अथवा वेदेषां । ( 7 ) अथवा वेदेषां ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।  
 ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।



# ECONOMIC PLANNING IN INDIA-1

## ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ-1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ପରିଭାଷା (Definition) :  
 'ମାନବ ସମ୍ବଳ'ର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଯାହା ଏକ ସଂଗଠନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯାହାକି ସେହି ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରିପାରେ ।

፤ ይኸው ምክር ቤት ለፌዴራል ፖሊስ ስራው ላይ ለሚሳተፍ የሚችል ሰው ሊሆን ይችላል፤  
፡፡ ለዚህም ምክር ቤት ለሚሰጥ ማስረጃ ላይ ለሚመሰረት ሰው ሊሆን ይችላል፤  
፡፡ ለዚህም ምክር ቤት ለሚሰጥ ማስረጃ ላይ ለሚመሰረት ሰው ሊሆን ይችላል፤

Page 19 of 19

1. በጥንቃቄ ለሰላም ስሜት ማሳደግ ማድረግ፡፡  
2. ለሰላም ስሜት ማሳደግ ማድረግ፡፡  
3. ለሰላም ስሜት ማሳደግ ማድረግ፡፡

1. भाषिक समझ को एक अवधि
2. समझ को भाषिक समझ
3. भाषा एवं वैज्ञानिक भाषा-शास्त्री का संबंध
4. भाषिक व भाषाशास्त्र के अर्थ
5. भाषाशास्त्र के भाषा के अर्थ
6. भाषाशास्त्र के अर्थ
7. भाषाशास्त्र के अर्थ

(Characteristics of Economic Planning)

11/11/2019 12:00 PM 11/11/2019 12:00 PM

1. የገንዘብ ምንጭ የገንዘብ ምንጭ ለገንዘብ

Economic objects) की प्रति के लिए देश के वाणिज्य मंत्राली पर विविध वस्तुसमूह (maximum) समान रूप फैलित (Exploitation) और वर्गीकृत किए गए हुए (National Income) को संभव क्रियारूप करने में। किसी निश्चित उद्देश्य की प्रति होने वाली

3. **संस्था (Statutes)** का अर्थ—किसी राज्य का शासन करने के लिये बनाए गए कानून, नियम, आदेश, आदि।

સિદ્ધિ કે અસિદ્ધિ માટેની જોઈએ તેવા માહિતીની સંગ્રહણ (collection of statistics) અત્યંત જરૂરી છે. જો માહિતી અસિદ્ધિ હોય તો આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે.

4. ગુણ-માત્રાના સંદર્ભમાં જોઈએ તો આપણને જાણવું પડે છે કે ગુણ કે માત્રા કેટલાંક સંદર્ભમાં (resources), આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે. આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે.

5. સિદ્ધિ અસિદ્ધિ—અસિદ્ધિ કે સિદ્ધિ માટે, આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે. આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે.

6. સિદ્ધિ અસિદ્ધિ—અસિદ્ધિ કે સિદ્ધિ માટે, આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે. આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે.

7. સિદ્ધિ (Public) અને સિદ્ધિ (Private) માટે, આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે. આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે.

8. સિદ્ધિ અને સિદ્ધિ (Publicity)—અસિદ્ધિ કે સિદ્ધિ માટે, આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે. આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે.

9. સિદ્ધિ અને સિદ્ધિ માટે, આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે. આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે.

(10) આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે. આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે.

(Need of Economic Planning)  
માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે. આપણને માનવ સંસાધનના વ્યવસ્થાપનમાં મર્યાદા પડે છે.

मन्त्र रत है। भारत में प्रेरित उपाय अधिकांश के अधिकांश राज-  
नियम एवं अधिनियमों अधिकांश विद्यमान के लिए हैं। इस विषय में  
कृपादेव की महिला सरकार ने (Mrs Barbara Woolton) ने  
'विद्यमान क्यों?' (Why Plan) नामक किताब लिखी। भारत  
में क्या उठता है कि विद्यमान क्यों बनाया गया? इसका दो उत्तर  
हैं। पहला कि योजना बनाना, और दूसरा, और अधिक योजना,  
बड़े-बड़े, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन—एक योजना बनाने की आवश्यकता  
है। यह कारण है कि भारत में योजना बनाने के परिणामस्वरूप  
हम अपने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी आवश्यकता यह है कि  
हमें अपनी सरकारों अधिकांश विद्यमान की ओर आकर्षित हैं। विद्य-  
मान की योजनाओं के एक उच्च आवश्यकता करने में विद्यमान  
हम की योजनाओं के एक उच्च आवश्यकता करने में विद्यमान

1. दुनिया के दोष (Evils of Capitalism)—दुनिया  
राष्ट्र की दुनिया अधिकांश (Capitalist Economy) में  
उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्थागत रूप करने की अधिकांश  
की। पर इससे एक अधिक लाभ है अधिक लाभ करने के लिये  
हमारे की प्रत्येक नहीं करने की। हमें अधिक से अधिक लाभ-  
मूल (Economic and social inequalities), प्रोत्साहन की योजना,  
विद्यमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। हमें विद्यमान के लिए

2. व्यापार चक्र (Trade Cycles)—वित्तविकार व्यवस्था में-  
उत्पादन में अधिकतर उत्पादन और लाभ की मात्रा लक्ष्य है।  
राष्ट्र की दुनिया अधिकांश (Capitalist Economy) में  
उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्थागत रूप करने की अधिकांश  
की। पर इससे एक अधिक लाभ है अधिक लाभ करने के लिये  
हमारे की प्रत्येक नहीं करने की। हमें अधिक से अधिक लाभ-  
मूल (Economic and social inequalities), प्रोत्साहन की योजना,  
विद्यमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं। हमें विद्यमान के लिए

3. विश्व मंद (Economic Depression)—सन् 1929 में  
प्रारंभ में विश्व मंद (Economic Depression) का प्रारंभ हुआ।





ה' תשנ"ב (מחצית השנייה) - תשנ"ג - תשנ"ד  
ה' תשנ"ה (מחצית השנייה) - תשנ"ו - תשנ"ז

5. *Mathematical model of the system* (Social Science & Technology) - 10

4. *Definition of unemployment*—Unemployment is defined as the condition of persons who are not employed in any of the productive sectors of the economy.

3. Proper utilization of national resources—(Maximum marks 10)

**३. समता का स्थापन (Establishment of Equality)**

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809



1. 11-11-11 2011 11-11-11 (5)

(c) (3) and (4) of the Privacy Act, 5 U.S.C. 552a, and the Freedom of Information Act, 5 U.S.C. 552, apply to this document.

(2) THE UNITED STATES OF AMERICA

ՀԱՅԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

• የፋይናንስ ሚኒስትር ዶ/ር ሀይለማርያም ሀይለሰለሰ ለጋራ ጥሪ

1. The following information is being furnished to you for your information:

Shri M. Vasudeva (Shri M. Vasudeva) ३५५

[illegible]

(लपण) का ईशान्यदिश १० मीटर)

109 11111 12 13111 14 15111

( Feb 1951 ) 12:15

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Plan) यह प्रस्ताव फरवरी में ही १९४७ में बना

‘महात्मा’ (People's Plan) और ‘महात्मा’ (Gandhi)

આચાર્યશ્રીના અવસાનના ૧૦૦ વર્ષોના અંકે ૧૯૧૪-૧૯૧૫ના વર્ષમાં બોમ્બે પ્રેસ

ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀ, ଗର୍ବିତା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ଦେବସିଂହ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ନାୟକ

[illegible]

बुधवार ११ मार्च १९७१ ई. ११.३०.००

भारत के राष्ट्रीय (Planning in India)

„Ist die Welt nicht schön?“

[illegible][illegible]

**የታሪክ ምዕራፍ**      **የጥያቄው ዓይነት**      **የተሰጠበት ቀንና ሰዓት**

• 此類數據性 統計 數據 性

APR 26 1962 11:20 AM FILED FBI, NEW YORK



1. **साम्यवाद (Democratic Planning)**—साम्यवाद (Democratic Planning) का अर्थ है समाज के सभी सदस्यों के बीच समानता और समुदाय के हितों को प्राथमिकता देना। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ समाज के सभी सदस्यों को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों। साम्यवाद का उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों के बीच समानता और समुदाय के हितों को प्राथमिकता देना है। साम्यवाद का अर्थ है समाज के सभी सदस्यों के बीच समानता और समुदाय के हितों को प्राथमिकता देना। साम्यवाद का उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों के बीच समानता और समुदाय के हितों को प्राथमिकता देना है।



[illegible]

1. 1944

[illegible]

1. Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել այդ տեղին և ինչպե՞ս  
 2. Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել այդ տեղին և ինչպե՞ս  
 3. Ինչպե՞ս կարող եմ հասնել այդ տեղին և ինչպե՞ս

1971 年 12 月 1 日

பிழைப்புக் கல்வியை அறிவிக்கும் திட்டம் (1)

[illegible]

11/25/2015 12:12 PM 11/25/2015 12:12 PM 11/25/2015 12:12 PM (3)

[illegible]

1129 1125 1116 1111

[illegible]

—: എല്ലാത്തരം ജനങ്ങളും ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം ആകട്ടെ







և էն նման էն եղբայր—ընտանիքն էն եղբայր անուն

Եղբայր ևս ևս (01) անուն  
ևս ևս (6) անուն ևս ևս ևս ևս ևս ևս (9)  
ևս (12) ևս (1) ևս (6) ևս (9) ևս (5)  
ևս (4) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (2) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)

ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)

ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)

## Եղբայր

ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)

ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)  
ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1) ևս (1)

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| भारतीय भाषाओं की            | भाषाएँ                        |
| 1. आधुनिक भाषाएँ            | 1. Modern Languages           |
| 2. प्राचीन भाषाएँ           | 2. Ancient Languages          |
| 3. अपभ्रंश भाषाएँ           | 3. Apabhramsha Languages      |
| 4. प्राचीन साहित्यिक भाषाएँ | 4. Ancient Literary Languages |
| 5. ऐतिहासिक भाषाएँ          | 5. Historical Languages       |
| 6. अपभ्रंश भाषाएँ           | 6. Apabhramsha Languages      |
| 7. प्राचीन भाषाएँ           | 7. Ancient Languages          |
| 8. आर्य भाषाओं की भाषाएँ    | 8. Aryan Languages            |

आर्य भाषाओं की भाषाएँ (Aryan Languages) की श्रेणी में प्राचीन भाषाएँ, ऐतिहासिक भाषाएँ, अपभ्रंश भाषाएँ, प्राचीन साहित्यिक भाषाएँ, आर्य भाषाओं की भाषाएँ आदि शामिल हैं।

प्राचीन भाषाएँ (Ancient Languages) की श्रेणी में संस्कृत, पाली, अपभ्रंश आदि शामिल हैं।

ऐतिहासिक भाषाएँ (Historical Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाएँ, प्राचीन यूनानी भाषाएँ, प्राचीन रोमन भाषाएँ आदि शामिल हैं।

अपभ्रंश भाषाएँ (Apabhramsha Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के अपभ्रंश शामिल हैं।

प्राचीन साहित्यिक भाषाएँ (Ancient Literary Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के साहित्यिक रूप शामिल हैं।

आर्य भाषाओं की भाषाएँ (Aryan Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के आर्य भाषाओं की भाषाएँ शामिल हैं।

7. भौतिक (Physical) और भाषा (Linguistic) भाषाएँ—  
 भौतिक भाषाएँ (Physical Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के भौतिक रूप शामिल हैं।  
 भाषा (Linguistic) भाषाएँ (Linguistic Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के भाषा शामिल हैं।  
 प्राचीन भारतीय भाषाओं के भौतिक रूप (Physical Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के भौतिक रूप शामिल हैं।  
 प्राचीन भारतीय भाषाओं के भाषा (Linguistic Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के भाषा शामिल हैं।  
 प्राचीन भारतीय भाषाओं के भौतिक रूप (Physical Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के भौतिक रूप शामिल हैं।  
 प्राचीन भारतीय भाषाओं के भाषा (Linguistic Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के भाषा शामिल हैं।

8. आर्य भाषाओं की भाषाएँ (Aryan Languages) भाषाएँ—  
 आर्य भाषाओं की भाषाएँ (Aryan Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के आर्य भाषाओं की भाषाएँ शामिल हैं।  
 प्राचीन भारतीय भाषाओं के आर्य भाषाओं की भाषाएँ (Aryan Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के आर्य भाषाओं की भाषाएँ शामिल हैं।  
 प्राचीन भारतीय भाषाओं के आर्य भाषाओं की भाषाएँ (Aryan Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के आर्य भाषाओं की भाषाएँ शामिल हैं।  
 प्राचीन भारतीय भाषाओं के आर्य भाषाओं की भाषाएँ (Aryan Languages) की श्रेणी में प्राचीन भारतीय भाषाओं के आर्य भाषाओं की भाषाएँ शामिल हैं।







(ପ୍ରଫ. ଶ୍ରୀ. ଶ୍ରୀ. ବି. ୧, 1969)

- (୧) ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
- (୨) ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
- (୩) ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
- (୪) ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
- (୫) ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

୧. ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ—

୧. ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
୨. ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
୩. ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
୪. ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
୫. ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ

ଶ୍ରୀମତୀ

1. 1951-52

2. 1952-53

3. 1953-54

4. 1954-55

5. 1955-56

6. 1956-57  
7. 1957-58  
8. 1958-59  
9. 1959-60  
10. 1960-61  
11. 1961-62  
12. 1962-63  
13. 1963-64  
14. 1964-65  
15. 1965-66  
16. 1966-67  
17. 1967-68  
18. 1968-69  
19. 1969-70  
20. 1970-71  
21. 1971-72  
22. 1972-73  
23. 1973-74  
24. 1974-75  
25. 1975-76  
26. 1976-77  
27. 1977-78  
28. 1978-79  
29. 1979-80  
30. 1980-81  
31. 1981-82  
32. 1982-83  
33. 1983-84  
34. 1984-85  
35. 1985-86  
36. 1986-87  
37. 1987-88  
38. 1988-89  
39. 1989-90  
40. 1990-91  
41. 1991-92  
42. 1992-93  
43. 1993-94  
44. 1994-95  
45. 1995-96  
46. 1996-97  
47. 1997-98  
48. 1998-99  
49. 1999-00  
50. 2000-01  
51. 2001-02  
52. 2002-03  
53. 2003-04  
54. 2004-05  
55. 2005-06  
56. 2006-07  
57. 2007-08  
58. 2008-09  
59. 2009-10  
60. 2010-11  
61. 2011-12  
62. 2012-13  
63. 2013-14  
64. 2014-15  
65. 2015-16  
66. 2016-17  
67. 2017-18  
68. 2018-19  
69. 2019-20  
70. 2020-21  
71. 2021-22  
72. 2022-23  
73. 2023-24  
74. 2024-25  
75. 2025-26  
76. 2026-27  
77. 2027-28  
78. 2028-29  
79. 2029-30  
80. 2030-31  
81. 2031-32  
82. 2032-33  
83. 2033-34  
84. 2034-35  
85. 2035-36  
86. 2036-37  
87. 2037-38  
88. 2038-39  
89. 2039-40  
90. 2040-41  
91. 2041-42  
92. 2042-43  
93. 2043-44  
94. 2044-45  
95. 2045-46  
96. 2046-47  
97. 2047-48  
98. 2048-49  
99. 2049-50  
100. 2050-51

—

1. 1951-52  
2. 1952-53  
3. 1953-54  
4. 1954-55  
5. 1955-56  
6. 1956-57  
7. 1957-58  
8. 1958-59  
9. 1959-60  
10. 1960-61  
11. 1961-62  
12. 1962-63  
13. 1963-64  
14. 1964-65  
15. 1965-66  
16. 1966-67  
17. 1967-68  
18. 1968-69  
19. 1969-70  
20. 1970-71  
21. 1971-72  
22. 1972-73  
23. 1973-74  
24. 1974-75  
25. 1975-76  
26. 1976-77  
27. 1977-78  
28. 1978-79  
29. 1979-80  
30. 1980-81  
31. 1981-82  
32. 1982-83  
33. 1983-84  
34. 1984-85  
35. 1985-86  
36. 1986-87  
37. 1987-88  
38. 1988-89  
39. 1989-90  
40. 1990-91  
41. 1991-92  
42. 1992-93  
43. 1993-94  
44. 1994-95  
45. 1995-96  
46. 1996-97  
47. 1997-98  
48. 1998-99  
49. 1999-00  
50. 2000-01  
51. 2001-02  
52. 2002-03  
53. 2003-04  
54. 2004-05  
55. 2005-06  
56. 2006-07  
57. 2007-08  
58. 2008-09  
59. 2009-10  
60. 2010-11  
61. 2011-12  
62. 2012-13  
63. 2013-14  
64. 2014-15  
65. 2015-16  
66. 2016-17  
67. 2017-18  
68. 2018-19  
69. 2019-20  
70. 2020-21  
71. 2021-22  
72. 2022-23  
73. 2023-24  
74. 2024-25  
75. 2025-26  
76. 2026-27  
77. 2027-28  
78. 2028-29  
79. 2029-30  
80. 2030-31  
81. 2031-32  
82. 2032-33  
83. 2033-34  
84. 2034-35  
85. 2035-36  
86. 2036-37  
87. 2037-38  
88. 2038-39  
89. 2039-40  
90. 2040-41  
91. 2041-42  
92. 2042-43  
93. 2043-44  
94. 2044-45  
95. 2045-46  
96. 2046-47  
97. 2047-48  
98. 2048-49  
99. 2049-50  
100. 2050-51

ECONOMIC PLANNING IN INDIA-II

1. 1951-52

19





1,960

420  
188  
91  
304  
205  
752

1960-61  
1961-62  
1962-63  
1963-64  
1964-65  
1965-66

(1960-61)

(Source) 1960-61

1960-61  
1961-62  
1962-63  
1963-64  
1964-65  
1965-66

1,100

1,960

1960-61

23

459

1960-61

27

523

1961-62

1

74

1962-63

2

43

1963-64

13

260

1964-65

16

310

1965-66

13

291

1966-67

1960-61

1960-61

1960-61

(1960-61)

1960-61

1960-61

प्रथम योजना की उपलब्धियाँ (Achievements of the First Plan) प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्द्ध सफल रही। योजना आकार में बहुत बढ़ी। देश के अन्दर रहने वाले आसानी से पैसे बन जाते हैं।

हरी हरे हुए उपलब्धियाँ पर प्रकाश करते हैं—

1. राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि (Increase in National and per Capita Income) प्रथम योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय 10,240 करोड़ रुपये थी, जो योजना के अन्त में बढ़कर 12,130 करोड़ रुपये हुई। प्रति व्यक्ति आय 284 रुपये से बढ़कर 306 रुपये हुई। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2. रोज़गार—योजनाकाल में बहुत सारी नए उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकी हैं। आसानी से नए उपकरण बने 1949-50 की योजना के अन्त में 15 प्रतिशत बढ़ गए। औद्योगिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। राष्ट्रीयकृत उद्योगों में प्रयोग होने वाले औद्योगिक सामानों की योजनाओं का भी प्रसार हुआ। इससे भी देश का औद्योगिकीकरण में प्रगति हुई।

3. औद्योगिक मशीन—इस औद्योगिक उपकरण में इस वर्ष में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रेलवे मशीन, मशीनों की मरम्मत, मशीनरीकरण में वृद्धि हुई।

4. परिवहन एवं संचार—योजना में औद्योगिक कार्य करने में परिवहन एवं संचार के अभाव में बाधाएँ उत्पन्न हुईं। (Technical) प्रसार हुआ। औद्योगिक प्रसार के अभाव में बाधाएँ उत्पन्न हुईं। (Technical) प्रसार हुआ।

परन्तु उपलब्धियाँ के अभाव में देश में बाधाएँ उत्पन्न हुईं। (Technical) प्रसार हुआ।

हरी हरे हुए उपलब्धियाँ पर प्रकाश करते हैं—

1. ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Employment) ਦੀ ਟਿੰਡੇ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-ਵਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

3. ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-ਵਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

4. ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ-ਵਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

## ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

## SECOND FIVE YEAR PLAN

(ਸਾਲ—1 ਸਾਲ, 1956 ਤੋਂ ਸਾਲ 1961)

ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

1. ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।



જાતી હિત (Private Sector)

જાતીય ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત જાતી હિત (Private Sector) હિત 2,400 કરોડ રૂપિય થઈ કરોડ હિત સુધારા હિત 1 રૂપિય હિત હિત જાતીય ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,400 કરોડ રૂપિય થઈ કરોડ હિત સુધારા હિત 1 રૂપિય હિત હિત જાતીય ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,400 કરોડ રૂપિય થઈ કરોડ હિત સુધારા હિત 1 રૂપિય હિત હિત

જાતીય ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,400 કરોડ રૂપિય થઈ કરોડ હિત સુધારા હિત 1 રૂપિય હિત હિત

રૂપિય (કરોડ રૂપિય હિત)

ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 575

ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત (કરોડ રૂપિય હિત) 105

ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 1,000

ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 300

ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 400

2,380

ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380  
ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380  
ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380  
ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380  
ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380  
ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380  
ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380  
ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380  
ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380  
ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 2,380

| ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત | ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત | ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત |
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|

|  |            |           |
|--|------------|-----------|
| 1. ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત હિત ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત | 1,052-50 = | 23-1 = 22 |
| 2. ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત                        | 150        | 1         |
| 3. ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત                        | 780        | 17        |
| 4. ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત                        | 570        | 12        |
| 5. ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત                        | 60         | 2         |
| 6. ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત                        | 948        | 20        |
| 7. ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત                        | 1090       | 24        |

ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 100

ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 4600

ધિત્તા ક્ષેત્ર હિત 100







कृषि विकास की योजना थी। द्वितीय योजना ने जोड़ी अधिक बल दिया और तीसरी योजना ने कृषि एवं उद्योग-सम्बन्धित विकास पर बल दिया।

1. तृतीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य (Objects)

तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करते समय उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया था—

1. तृतीय योजना काल में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत से अधिक में वृद्धि प्राप्त करना, जिससे विनियोग की स्थिति में सुधार आए।
2. साधनों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता तथा में वृद्धि प्राप्त करना जिससे उद्योगों तथा निर्यात की मात्रा में वृद्धि प्राप्त की जा सके।

3. आठवीं दस वर्षों में देश के औद्योगीकरण की दिशा में देश में ही पुरी की जा सकें इसके लिए मूल उद्योगों तथा उद्योगिक उद्योग, ईंधन तथा सक्ति के साधनों का विकास करना।

| 100   | 7,500 | 5th year |
|-------|-------|----------|
| 30    | 2,200 | 1960-61  |
| 7     | 550   | 1961-62  |
| 3     | 275   | 1962-63  |
| 12    | 865   | 1963-64  |
| 11    | 800   | 1964-65  |
| 6     | 450   | 1965-66  |
| 1     | 100   | 1966-67  |
| 7     | 550   | 1967-68  |
| 23    | 1,710 | 1968-69  |
| Total |       | 11,600   |

— 1960-61

1960-61

1960-61

1960-61

1960-61

1960-61

1960-61

1960-61

1960-61

1960-61

1960-61

1960-61

कुल विनियोग 10,400 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 6,309 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

कुल व्यय 11,600 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 7,500 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

उपरोक्त सामान्य को देखने से पता लगता है कि द्वितीय योजना की तुलना में कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा शक्ति पर व्यय का अनुपात बढ़ा है। निधार्द, लघु उद्योग तथा संगठित उद्योग व मन्त्रि पर व्यय का अनुपात कम हुआ है। पर यह बात उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मर पर सार्ध की जाने वाली राशि में काफी वृद्धि हुई।  
द्वितीय सामान्य\*

तृतीय योजना के प्रास्तावित कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली राशि का प्रथम निम्नान्वित श्रेणियों से निम्ने जाने की व्यवस्था थी—

| साधन                           | राशि(करोड़ ₹) | प्रतिशत |
|--------------------------------|---------------|---------|
| अतिरिक्त ऋण                    | 1,710         | 23      |
| राजस्व के धातु गाने से बचत     | 330           | 7       |
| रेल्वी द्वारा समतान            | 100           | 1       |
| सार्वजनिक उद्योगों व ग्राम सभा | 450           | 6       |
| सार्वजनिक भू-स                 | 800           | 11      |
| अल्प बचत एवं अन्य स्रोत        | 865           | 12      |
| अल्प वृत्तीय स्रोत             | 275           | 3       |
| कानूनी एवं व्यवसाय             | 350           | 7       |
| विदेशी ऋण                      | 2,360         | 30      |
| कुल योग                        | 7,500         | 100     |

\* Third Five Year Plan-Final Draft.



कुल विनियोग 10,400 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 6,309 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

कुल व्यय 11,600 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 7,500 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

उपरोक्त तालिका को देखने से पता लगता है कि द्वितीय योजना की तुलना में कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा शक्ति पर व्यय का अनुपात बढ़ा है। सिंचाई, लघु उद्योग तथा संगठित उद्योग व शनित्र पर व्यय का अनुपात कम हुआ है। पर यह बात उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मद पर सफ़र की जाने वाली राशि में काफी कृत्रिमता है।  
द्वितीय तालिका\*

तृतीय योजना के प्रास्तावित कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली राशि का प्रबन्ध निम्नांकित स्रोतों से रिचे जाने की व्यवस्था की—

| साधन                              | राशि(करोड़ ₹) | प्रतिशत    |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| अनिरिक्त कर                       | 1,710         | 23         |
| राजस्व के वास्तु भाते से बचत      | 550           | 7          |
| रेलों द्वारा भण्डान               | 100           | 1          |
| सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त भाग | 450           | 6          |
| सार्वजनिक ऋण                      | 800           | 11         |
| भात बचत एवं अन्य ऋण               | 865           | 12         |
| अन्य पुर्जीगत भाग                 | 275           | 3          |
| बाटे की संप्र व्यवस्था            | 550           | 7          |
| विदेशी सहायता                     | 2,200         | 30         |
| <b>कुल योग</b>                    | <b>7,500</b>  | <b>100</b> |

• Third Five Year Plan-Final Draft.

सार्वजनिक क्षेत्र पर होने वाले खर्च में से 6,000 करोड़ रुपये राष्ट्रीय सरकार द्वारा और शेष राशि राज्य सरकारों की जानी थी।

#### 4. तृतीय योजना के विभिन्न कार्यक्रम

यहाँ हम विकास व उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रमों को देखेंगे—

1. कृषि—कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विकास पर 950 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई, जबकि द्वितीय योजना में केवल 950 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। योजना के अन्तर्गत उत्पादन 30 प्रतिशत से बढ़ाने का लक्ष्य था। उत्पादन की प्राप्ति हेतु सिंचाई का विकास किया जाना था। तृतीय योजना के प्रारम्भ में 282 लाख हेक्टर (700 करोड़ रुपये) बढ़कर 362 लाख हेक्टर (900 लाख रुपये) हो जायेगी। 88.5 लाख हेक्टर (220 लाख रुपये) भूमि

कुल विनियोग 10,400 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 6,309 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

कुल व्यय 11,600 करोड़ रुपये (सार्वजनिक क्षेत्र 7,500 + निजी क्षेत्र 4,100 करोड़ रुपये)

उपरोक्त सान्निध्य की देखने से पता लगता है कि द्वितीय योजना की तुलना में कृषि तथा सामुदायिक विकास तथा शक्ति पर व्यय का अनुपात बढ़ा है। सिंचाई, लघु उद्योग तथा संगठित उद्योग व शक्ति पर व्यय का अनुपात कम हुआ है। पर यह बात उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मद पर व्यय की जाने वाली राशि में काफी वृद्धि हुई।  
वित्तीय साधन\*

तृतीय योजना के प्रास्तावित कार्यक्रमों पर व्यय की जाने वाली राशि का प्रक्षेप निम्नांकित स्रोतों से किये जाने की आवश्यकता थी—

| साधन                             | राशि(करोड़ ₹) | प्रतिशत    |
|----------------------------------|---------------|------------|
| अनिरिक्त ऋण                      | 1,710         | 23         |
| राजस्व के पानू स्रोतों से बचत    | 550           | 7          |
| रेलों द्वारा भण्डान              | 100           | 1          |
| सार्वजनिक उद्योगों से प्राप्त धन | 450           | 6          |
| सार्वजनिक ऋण                     | 800           | 11         |
| अल्प बचत एवं अन्य ऋण             | 865           | 12         |
| अन्य पुंजीगत धन                  | 275           | 3          |
| बाटे की व्यय व्यवस्था            | 550           | 7          |
| विदेशी सहायता                    | 2,200         | 30         |
| <b>कुल योग</b>                   | <b>7,500</b>  | <b>100</b> |

\* Third Five Year Plan-Final Draft.

सार्वजनिक क्षेत्र पर होने वाले खर्च में से 6,038 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार द्वारा और शेष राशि राज्य सरकारों की ज़ामनी थी।

#### 4. तृतीय योजना के विभिन्न कार्यक्रम

यहाँ हम विकास व उत्पादन के विभिन्न कार्यक्रमों पर—

1. कृषि—कृषि, सिंचाई और सामुदायिक विज्ञान के करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई, जबकि द्वितीय योजना पर केवल 950 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। योजना का उत्पादन 30 प्रतिशत से बढ़ाने का लक्ष्य था। उत्पादन की प्राप्ति हेतु सिंचाई का विकास किया जाना था जो योजना के प्रारम्भ में 282 लाख हेक्टर (700 लाख अकर) से बढ़कर 362 लाख हेक्टर (900 लाख अकर) हो जाने की थी। 88.5 लाख हेक्टर (220 लाख अकर) भूमि पर (Dry Farming) बढ़ाई देने के लक्ष्य थे।



करना था जो सर्व-व्यवस्था को स्वावलम्बन की ओर ले जाते हों, जैसे—लोहे और इस्पात, मशीन औजार तथा उत्पादक उद्योगों में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का विकास निजी क्षेत्र द्वारा सम्पन्न होने का लक्ष्य था। इन सब के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन 70 प्रतिशत तक बढ़ने की सम्भावना थी। सार्वजनिक क्षेत्र में एक इस्पात का कारखाना बोकरो स्टील प्लांट, रूस की साहपता से लीने जाने की व्यवस्था थी। योजना काल में धातु-उद्योग, औद्योगिक मशीनरी अल्पूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ताँबा, जस्ता, सीमेंट, दवाइयाँ, रंगों का समान, कपड़ा, कापज, चीनी, तेल, थड़ियाँ, साइकिलें, रेडियो, कपड़ा, सिलाई मशीनों आदि के उत्पादन के अधिक लक्ष्य निर्धारित किये गये।

3. प्राचीन एवं सधु उद्योग—योजना के अन्तर्गत 264 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई। इन उद्योगों को विकसित करने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने का अनुमान था। सधु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने की व्यवस्था भी की गई। ह्रास करपा, शक्ति करपा, रोजगार खाती के बपड़े में उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य रखे गये। इन उद्योगों में विद्युत तथा छोटे पवन प्रयोग में जाने से उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयत्न किये गये।

4. यातायात—देश में औद्योगिक विकास के लिए यातायात की महत्ता समी-मिति समझ ली गई है। इसीलिए प्रत्येक योजना में इसे अर्वाधिक महत्व दिया गया है। तीसरी योजना में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यातायात का विकास करने हेतु 1,486 करोड़ रुपये खर्च किये जाने की व्यवस्था थी। योजना काल में 1,930 कि. मी. (1,200 मील) नई रेलवे लाइन बिछाने, 40,300 कि. मी. (23,000 मील) सतह वाली (surfaced) सड़कें बनाने, जहाजी-मार समुद्र तथा बन्दरगाहों की समाना में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य था। पोस्ट आफिस तथा तारघरों की संख्या में वृद्धि की गई।

5. सामाजिक सेवाएँ—तृतीय योजना में सामाजिक सेवाओं के

विस्तार के लिए, 13,00 करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई। वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण पर अधिक खर्च दिया गया, 11 से 16 वर्ष के बच्चों को निशुल्क व परिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था योजना की विशेषता है। स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या इस अवधि में 204 लाख (अर्थात् 435 लाख से बढ़कर 639 लाख) बढ़ जाने का अनुमान है।

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार नियोजन (Family planning) कार्यक्रमों का विस्तार किया गया। ग्रामीण जल प्रदाय तथा निर्माण योजनाओं के अतिरिक्त आवास (Housing) सुविधाओं का विस्तार भी किया गया। समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाल-कल्याण, महिला कल्याण, समाज सुरक्षा, विधवापिता को बसाने, आदि कार्यक्रम भी रहे गये।

6. राष्ट्रीय आय (National Income)—यह माना की गई कि योजना में लक्षित सभी कार्यक्रम पूरे हो जाने पर राष्ट्रीय आय में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। सन् 1960-61 में जो राष्ट्रीय आय 14,500 करोड़ रु० थी वह सन् 1965-66 में बढ़कर 19,000 करोड़ रु० हो जाने की आशा थी। प्रति व्यक्ति आय 300 रुपये से बढ़कर 385 रुपये हो जाने की संभावना थी।

7. रोजगार (Employment)—अनुमान है कि तृतीय योजना काल में 145 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस अवधि में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 170 लाख होने का अनुमान था। इसलिए अब रोजगार के अधिक अवसर ढूँढने चाहिये। इस संबंध में स्थानीय संगठनों द्वारा जन सहयोग के आधार पर कार्यक्रम बनाए जाने चाहिये।

तृतीय योजना का मूल्यांकन—

तृतीय योजना काल में हमें आशातीत सफलता नहीं मिली। मोमम की प्रतिफलता, शक्ति के साधनों-विशेषतः कोयले और जलविद्युत की

कमी, बीबी चाकमक, पाकिस्तान से दुध आदि कारणों से हम योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। यही हम योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित उल्लेखों पर विचार करेंगे—

1. योजना व्यय (Plan Expenditure)—हम योजना में वर्षी मार्गदर्शक क्षेत्र में 7,500 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गयी। वास्तविक व्यय लगभग 8,623 करोड़ अर्थात् प्राथमिक क्षेत्र में 1,128 करोड़ रुपये अधिक खर्च हुआ। इस व्यय की वृद्धि का मुख्य कारण मुद्रा प्रसार (Inflation) है।

2. योजना के निम्नलिखित उल्लेख—हम योजना में प्राथमिक क्षेत्रों के विकास पर कहीं अधिक व्यवस्था की गयी। योजना कार्य में 2,200 करोड़ रुपये के विकास पर विदेशी सहायता के रूप में 2,435 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। बाटे की अर्थ व्यवस्था का अनुमान वर्षी 510 करोड़ रुपये का लगाना तथा वा कहीं इस में से 1,151 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। योजना कार्य में निर्धारित कार्य में 2,833 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। 800 करोड़ रुपये के विकास पर मार्गदर्शक क्षेत्रों में 916 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। प्राथमिक क्षेत्रों में कार्य की पूर्णता में कमी पाते हुए बालू बरत, रेलों में अद्यतन तथा मार्गदर्शक क्षेत्रों में से से।

3. राष्ट्रीय आय—वर्षी आय में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र 5 अर्थात् वर्षी वर्षी वृद्धि के विकास पर केवल 2-3 अर्थात् क्षेत्र में ही वृद्धि हुई। वर्ष 1960-61 के कुल आय का विकास के आय में (1959-60) राष्ट्रीय आय 15,930 करोड़ रुपये की तथा वर्षी आय में (1959-60 के कुल आय का) 323 करोड़ की। राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में उन विद्यमान का कारण वृद्धि एवं उद्योगों के उत्पादन में कमी

4. रोजगार—योजना के प्रारम्भ में बेरोजगारों की संख्या 70 लाख थी। योजना की अवधि में 145 लाख लोगों को रोजगार दिया गया किन्तु इसी दौरान 170 लाख नए व्यक्ति श्रमशक्ति में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार तृतीय योजना के अन्त में लगभग 95 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे।

5. कृषि—योजना के अधिकांश वर्षों में प्रकृति की प्रतिकूलता के कारण कृषि उत्पादन के सम्पूर्ण स्तरों को प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ। योजना के अन्तिम वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन 72.29 मिलियन टन हुआ। इस योजना में कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता के विकास पर 1,104 करोड़ रुपये खर्च किए गये।

6. उद्योग—योजना की अवधि में मूल औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भी अधिक बढ़ा। आर्थिक एवं सुरक्षा संकटों के कारण औद्योगिक विकास के सम्पूर्ण स्तरों की प्राप्ति सम्भव नहीं हुई। जिन परियोजनाओं का कार्य अधूरा रह गया था वे अब शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। योजना काल में संचालित उद्योगों, तमिज विकास कार्यक्रमों, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर 1,959 करोड़ रुपये खर्च हुआ जो प्रस्तावित व्यय से लगभग 175 करोड़ रुपये अधिक है।

7. सिंचाई एवं शक्ति—योजनाकाल की बढ़ी एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से सिंचित क्षेत्र 5.5 मिलियन एकड़ से बढ़कर 13.1 मिलियन एकड़ हो गया। लगभग 28,100 गांवों की ओर बिजली भी गई। योजना काल में जल विद्युत निर्माण की क्षमता 4.6 मिलियन किलोवाट से बढ़ गई। सिंचाई एवं शक्ति के विकास पर 1,920 करोड़ रुपये खर्च हुए।

8. मातामृत एवं समाज सेवाएँ—तीनरी योजना में इन पर 3,645 करोड़ रुपये खर्च हुआ जो प्रस्तावित व्यय से 859 करोड़ रुपये अधिक है। स्कूलों की संख्या 4 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई। परिवार नियोजन केन्द्र 1,649 से बढ़कर 11,474 हो गये।

मगदहार गहरों की गम्माई 255 हजार रिमो मीटर से बढ़कर 284 हजार रिमोमीटर हो गई ।

इन तथ्यों की देखने में पता चलता है कि तृतीय योजना में निर्धारित सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकी । इसके अतिरिक्त इस योजना की मुख्य कमजोरी मुद्रा प्रसार अथवा मूल्य वृद्धि है । बेरोजगारी की समस्या का विक्राम रूप, राष्ट्रीय आय में वर्धन वृद्धि न होना, कर भार में वृद्धि आदि कुछ अन्य बातें हैं जो योजना की कमियों में गिनी जाती हैं ।

यद्यपि तृतीय योजना के परिणाम अधिक आशाप्रद नहीं रहे फिर भी देश चतुर्थ योजना में अधिक तेजी से विकास के लिए कटि-बद्ध है । आर्थिक विकास के लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है । फिर आर्थिक विनाश तो राजनीतिक स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, इसके लिए हमें त्याग और कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए ।

### भारत की वार्षिक योजनाएँ (Annual Plans in India)

योजना लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है । योजनाओं का वास्तविक महत्व उसी अवस्था में पूर्णरूप से वार्षिकीय होता है जबकि दीर्घकालीन दृष्टिकोण के सन्दर्भ में हमेशा अल्पकालीन योजनाएँ बनती रहें । कभी-कभी बदलती हुई राष्ट्रीय एबम् अन्तराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण योजना को बनाए रखना कठिन हो जाता है तब कुछ समय के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण के स्थान पर अल्पकालीन दृष्टिकोण से ही कार्य करना होता है । भारत में भी चतुर्थ योजना के स्थान पर वार्षिक संगठनात्मक योजनाएँ बनाने का यही उद्देश्य है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल सन् 1961 से 31 मार्च सन् 1966) को अनेक विषय-परिस्थितियों के मध्य गुजरना पड़ा । दो-दो युद्ध और सूखों (Draughts) को पार करने में इस योजना की शक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति की अपेक्षा इससे निपटने में अधिक लगी ।

दृतीय योजना की असफलता ने हमारी सहायता करने वाले देशों के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया। आज कोई भी अर्थ विकसित राष्ट्र बिना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व सहायता के विकास नहीं कर सकता। भारत भी इन बदली हुई परिस्थितियों में अपनी चतुर्थ योजना को प्रभावशाली रूप से लागू करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। इसीलिए परिस्थितियों के अनुकूल बनाने तक वार्षिक संगठनात्मक योजनाएँ बनाई गईं। यहाँ हम दो वार्षिक संगठनात्मक योजनाओं का अध्ययन करेंगे।

### वार्षिक योजना सन् 1966-67

वार्षिक योजना (सन् 1966-67) के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2,221 करोड़ रुपये व्यय करने का सकल रस्ता गया। इस वार्षिक योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्य (Targets) इन प्रकार हैं—

**विद्युत—**सन् 1966-67 के लक्ष्य यह सकल रस्ता गया था कि बीस वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 2 मिलियन किलोवाट की वृद्धि होगी किन्तु वास्तविक वृद्धि 1.2 मिलियन किलोवाट से ही हुई।

**कृषि—**सन् 1949-50 की आधार वर्ष मान कर जो कृषि उपज निर्देशन इस वार्षिकी योजना में बनाया गया वह 135.7 के बराबर रहा, उपज में 4 अंकों की वृद्धि हुई।

**खनिज—**देश में औद्योगिक उत्पादन में विगत कुछ वर्षों से गिरावट आ रही थी। जहाँ सन् 1963-64 में औद्योगिक उत्पादन 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा वहीं औद्योगिक उत्पादन में सन् 1964-65 में 7 प्रतिशत व सन् 1965-66 में 3.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। इसी के अनुरूप सन् 1966-67 में (इस वार्षिक योजना में) औद्योगिक उत्पादन वृद्धि की दर तीन प्रतिशत रही। इस गिरावट का मुख्य कारण कृषि उपज में गिरावट था।

**यातायात—**भारत में रेलों की भारवहन क्षमता का अनुमान तीसरी योजना के अन्त में 230 मिलियन टन लगाया गया था।

सन् 1966-67 के लिए जहाँ भारयहन लमता 216 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान था वहीं वास्तविक वृद्धि 203 मिलियन टन से हुई

राष्ट्रीय भाव—सन् 1966-67 में राष्ट्रीय भाव का अनुमान (वर्तमान मूल्य स्तर पर) 22,900 करोड़ रुपए लगाया गया था सन् 1965-66 में यह राशि 20,250 करोड़ रुपए थी । सन् 1966-67 में अत्यधिक मूल्य वृद्धि के कारण ही थोक मूल्य निर्देशांक (Wholesale Price Index) 165.1 में बढ़कर 191 हो गया ।

वार्षिक योजना सन् 1967-68 Annual Plan (1967-68)—

प्रस्तावित चतुर्थ योजना के द्वितीय वर्ष (सन् 1967-68) की वार्षिक योजना के लिए कुल 2,246 करोड़ रुपए की राशि व्यय के लिए निर्धारित की गई । सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय की जाने वाली राशि का आवंटन इस प्रकार किया गया—

| भेद                               | व्यय (करोड़ रु० में) |
|-----------------------------------|----------------------|
| कृषि                              | 296.65               |
| सिंचाई                            | 46.77                |
| सामुदायिक विकास व सहकारिता        | 79.85                |
| शक्ति                             | 384.78               |
| संगठित उद्योग                     | 520.19               |
| क्षुद्र व घामीय उद्योग            | 43.55                |
| मातामठ व संचार                    | 418.75               |
| शिक्षा                            | 111.66               |
| स्वास्थ्य व परिवार नियोजन         | 75.84                |
| असंपूर्ण                          | 39.96                |
| (अन्य अनुसंधान व लोक कल्याण सहित) | 228.00               |
| योग                               | 2,246.00             |

उपरोक्त तालिका में वर्णित मदों में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस वार्षिक योजना में मध्यम व बृहत् सिनाई मक्ति, उद्योग व साधनाएँ पर जो व्यय की राशियाँ रखी गई हैं वे क्रमशः निर्धारित योजना के अनुरूप ही हैं।

इन वार्षिक योजना के वित्तीय प्रबन्ध की स्थिति निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जायेगी।

| मद                                | करोड़ रुपये |
|-----------------------------------|-------------|
| बामू राजस्व लाते से अन्त          | 212         |
| रेलों द्वारा अंशदान               | -29         |
| सार्वजनिक उद्योगों से अतिरिक्त आय | 239         |
| अतिरिक्त कर                       | 360         |
| वन भूख                            | 204         |
| दल्ल भवन                          | 136         |
| स्वर्ण बाण                        | -3          |
| वार्षिक अनाई                      | 12          |
| अवोदीय भवन                        | 11          |
| विशेष पुंजी प्राप्ति              | -50         |
| घाटे की व्यवस्था (बैंक में)       | -1          |
| घाटे की व्यवस्था (राज्यों में)    | 15          |
| काम्य भवन (P. L. 480 गहिन)        | 1001        |
| कुल दोष                           | 2,192       |

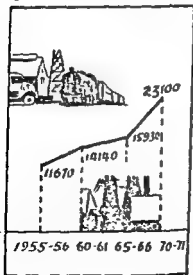
इन प्रकार से कुल अनुमानित वार्षिकी एवं व्यय से 54 करोड़ रुपए का अन्तर रहा (2,246-2,192=54)।



## तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भारत की आर्थिक प्रगति की समीक्षा

(A REVIEW OF THE ECONOMIC PROGRESS  
INDIA UNDER THE THREE FIVE YEAR PLANS)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक विभाग के निम्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। देश में विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न गावियों के पुनर्वास (Rehabilitation) से लेकर चीन और पाकिस्तान से सम्बन्धित सम्पूर्ण तक होने तक समस्याओं का हमने सामना किया। देश की आर्थिक प्रगति का रूप (Chariot) निरन्तर घटते चढ़ता जा रहा। यही हम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में हुई आर्थिक प्रगति का अध्ययन करेंगे—



राष्ट्रीय आय में वृद्धि

### 1. राष्ट्रीय आय

(National Income)

सन् 1950-51 से

1964-65 तक राष्ट्रीय आय

में 69 प्रतिशत से वृद्धि हुई

इस सम्पूर्ण अवधि में औसत

वृद्धि लगभग 3.8 प्रतिशत

प्रतिवर्ष से हुई। प्रथम

योजना के प्रारम्भ में राष्ट्रीय

आय 9,850 करोड़ रुपये थी

सन् 1964-65 में बढ़कर 16,630

करोड़ रुपये (सन् 1960-61 के मूल्य स्तर) हो गई

है। यह वृद्धि आर्थिक विकास

के प्रतीक है।

1-8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की

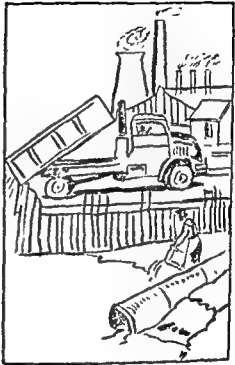
वृद्धि हुई क्योंकि इस अवधि में लगभग 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई। सन् 1965-66 में प्रति व्यक्ति बाघ 325 रुपये भी।

2. कृषि—योजना के प्रथम चौदह वर्षों में कृषि उत्पादन में लगभग 65 प्रतिशत वृद्धि हुई। खाद्यान्नों, तिलहनो, गन्ने, कपास, जूट आदि के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सन् 1950-51 में जहाँ प्रति एकड़ खाद्यान्नों का उत्पादन 12.8 बीस होता था वह सन् 1964-65 में बढ़कर 15.4 बीस हो गया। योजनाकाल में प्रति व्यक्ति उपलब्ध केलोरी 1,759 से बढ़कर 2,145 हो गई। कपड़े का उत्पादन 11 मीटर प्रति व्यक्ति से बढ़कर 15 मीटर प्रति व्यक्ति हो गया। प्रथम तीन योजनाओं में छोटी, मध्यम एवं बड़ी सिंचाई योजनाओं से 4.54 करोड़ एकड़ भूमि पर प्रतिरिक्त सिंचाई होने लगी।

3. उद्योग शक्ति व वातावात—इन योजनाओं से उद्योग, शक्ति एवं वातावात के क्षेत्रों में काफी प्रगति हुई। उद्योगों के उत्पादन में लगभग 152 प्रतिशत वृद्धि हुई। उद्योगों में विनिर्माण की शक्ति में भारी वृद्धि हुई सन् 1950-51 में जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में 55 करोड़ तथा निजी क्षेत्र में 233 करोड़ की पूंजी लगी हुई थी वहाँ पृथीय योजना के अन्त में यह राशि क्रमशः—520 करोड़ तथा 1,050 करोड़ रुपये हो गई।

विद्युत-शक्ति में चार गुनी वृद्धि हुई। सन् 1950-51 में जहाँ विद्युत निर्माण की प्रतिस्थापित क्षमता 23 लाख किलोवाट थी वह सन् 1965-66 में बढ़कर 102 लाख किलोवाट हो गई। बिजली वाले गाँवों की संख्या 3,700 से बढ़कर 52,300 हो गई।

सड़क-सड़कों की संख्या 1,56,000 कि० मी० में बढ़ कर 2,84,000 कि० मी० हो गई। रेलों की मरम्मत क्षमता दुगुनी से भी अधिक हो गई।



ઉદ્યોગ



## यातायात उद्योग

4. समाज सेवाएँ (Social Service)—पिछले पन्द्रह वर्षों में यात्रा सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई है। स्कूलों की संख्या 2-31 लाख से बढ़कर 5-05 लाख हो गई है। प्रशिक्षण, बिदिस्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, एक परिवार नियोजन पिछले वर्षों का विकास, औद्योगिक यमियों के लिए मकानों की व्यवस्था यादि सुविधाओं का बड़ी गुना विस्तार हुआ है। मलेरिया रोग का सम्पूर्ण निराकरण हो गया है। जीवन आयु 32 से बढ़कर 50 वर्ष हो गई है।



उपरोक्त उपलब्धियों से हमारे आर्थिक विकास के प्रदर्शनों में जानकारी मिलती है ।

कमियाँ—

हमारे देश में तीन पंचवर्षीय योजनाओं की कतिपय उपलब्धियाँ (achievements) की जानकारी उपरोक्त तथ्यों से मिलती है । किन्तु आज भी समाजवादी योजनाओं के प्रति सार्वजनिक उत्साह का प्रदर्शन नहीं करना । योजनाओं में अनेक कमियाँ रही हैं जिसका विस्तृत वर्णन (कारणों सहित) प्रत्येक योजना के साथ निम्नलिखित पृष्ठों में किया गया है । यदि विशिष्ट योजनाओं की कमियों को संकलित किया जाए तो निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

1. मुख्य शहर में वृद्धि हो रही है ।
2. खरपा घर का घर में वृद्धि हो रही है ।
3. बेरोजगारी में वृद्धि होनी या रही है ।
4. योजनाओं की निर्धारित प्राथमिकताएँ (Priorities) देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं ।
5. सरकार की नीति, योजना निर्माण, योजना का निष्पादन एवं उन्हें पूरी से कार्यान्वयन नहीं है ।
6. समाजवादी समाज की संरचना लक्ष्य नहीं है ।
7. कृषि, उद्योग, राष्ट्रीय स्तर आदि के क्षेत्रों की प्रगति में कमी रही है ।
8. निजी क्षेत्र की रणनीति नहीं ।
9. विकास व्यय (Development Expenditure) का नहीं अनुमान नहीं लगाया गया । प्रत्येक योजना में निर्धारित राशि में कम तथा दूसरी व तीसरी योजनाओं में अधिक व्यय हुआ है ।

1. वित्तीय साधनों (Financial Resources) सम्बन्धी कठिनाइयाँ रही हैं।
2. विदेशी विनिमय का संकट बना रहा है।
3. आवश्यक तकनीकी (Technical) ज्ञान एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव रहा है।
4. सार्वजनिक क्षेत्र में कुशलता का अभाव रहा है।
5. उचित प्रशासनिक व्यवस्था की कमी रही है।
6. जनसहयोग (Public-co-operation) की कमी योजनाओं का सबसे बड़ी असफलता रही है।
7. योजनाओं से प्राप्त सफलताओं एवं विफलताओं का सूक्ष्मकर्म करने के लिए उचित व्यवस्था का अभाव रहा है।
8. देश में हृदय बिश्वास की भावना एवं दृष्टि से सम्बन्ध की कमी भी नियोजन की असफलता के लिए उत्तरदायी है।

भारत में सार्वजनिक नियोजन की सफलता के मार्ग में उपस्थित बाधाओं की सरकार की नीति में परिवर्तन लाकर दूर किया जा सकता है।

योजनाओं की सफलता के लिए सुझाव (Suggestions)—

योजना की सिद्धि पर देश की समृद्धि निर्भर करती है। इसलिए इसे हर सम्भव प्रयत्न करने चाहिये। निम्नांकित सुझाव इस दिशा में आवश्यक योगदान दे सकते हैं—

(अ) वित्तीय साधनों संबंधी—भारत जैसे अर्द्ध-विकसित राष्ट्र में निर्यात, बचत की कमी एवं कम विनियोग का मुख्य ब्याप्त है। इसी कारण है हमारी योजनाओं के लिए उचित साधनों का अभाव होता है।

1. आन्तरिक साधन (Internal Resources)—उत्पादन वृद्धि एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए बढ़ते हुए विनियोग की आवश्यकता होती है। आन्तरिक वित्तीय साधन मुख्यतः घरेलू बचत (Domestic Savings) तथा वित्तीय नीति (Fiscal Policy) पर निर्भर करते हैं।

सुझाव—

(घ) वित्तीय साधनों का विस्तार—

1. आंतरिक साधन विशेषतः बचत
2. बाह्य साधन

(च) प्रशासन सम्बन्धी—

1. नीति व उद्देश्यों में समानता
2. कुशल प्रशासन व्यवस्था तथा उचित क्रियान्वयन
3. ईमानदार कर्मचारी
4. मूल्यवाचन

(स) जनसहयोग—

1. योजना भावना का प्रसार
2. मूल आवश्यकताओं की वृत्ति
3. कार्य परिचोजनाएं

(द) साधन—

1. मूल्य नीति, तकनीकी साधन व महयोग आदि।

हमारे यहाँ सन् 1950-51 में परेसू बचन का प्रतिशत कुल राष्ट्रीय आय का 5½ प्रतिशत था। यह प्रतिशत सन् 1965-66 में बढ़कर 10½ प्रतिशत हो गया। किन्तु इस अवधि में विनियोग किये जाने वाली राशि तीन गुनी हो गई। इस प्रकार विनियोग की तुलना में बचत की वृद्धि का अनुपात कम रहा।

देश में 'बचत' का बहुत बड़ा महत्व है। एक ओर जहाँ इससे देश के आर्थिक विकास के लिए सपना मिलता है वहाँ दूसरी ओर यह जनता की कमजोरी (Purchasing Power) में कमी लाकर मुद्रा प्रसार या मूल्य वृद्धि को रोकती है।

आंतरिक साधनों के रूप में सार्वजनिक उद्योगों से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस लिए हमें अधिक से अधिक आंतरिक बचनों को प्रोत्साहित एवं गहरी दोनों ही छेदों में बढ़ाना चाहिये।

यथा सार्वजनिक उद्योगों में कुशलता से बढ़ाकर योजनाओं के लिए प्रतिष्ठित साधन प्राप्त करने चाहिये।

2. बाह्य साधन (External Resources)—किसी भी देश के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत ने भी विदेशों से अपनी पञ्चवर्षीय योजनाओं के लिए बहुत सहायता प्राप्त की है। किन्तु आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic nationalism) के जन्म तथा गुट बन्धियों के कारण बहुत लम्बे समय तक भारतवर्ष बिना कर्त के विदेशी सहायता प्राप्त कर सकेगा। इसमें संदेह है। इसलिए हमें विदेशों मुद्रा कमाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन (Export promotion) की ओर ध्यान देना चाहिए। विद्युत् कुछ वर्षों में सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं किन्तु उनसे अधिक लाभ नहीं मिला है। इसलिए सरकार इस सम्बन्ध में किराने प्रयत्न करे और हमारी योजनाओं की आवश्यकताओं तथा प्राण धुक्काने के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा जुटावे। इस सम्बन्ध में आयात नियन्त्रण नीति एवं विदेशी साधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

(ब) योजना के क्रियान्वयन एवं प्रशासन से सम्बन्धित—विद्युत् वर्षों में इस क्षेत्र में जो कमियाँ अनुभव की गई हैं उनके निराकरण हेतु निम्नांकित उपाय किये जाने चाहिए।

1. नीति व उद्देश्यों में समानता—सरकारी नीति व योजना के उद्देश्यों में समानता लाने की दिशा में आवश्यक प्रयत्न किये जाने चाहिए। उदाहरणार्थ समाजवादी समाज की स्थापना का आदर्श प्राप्त करने के लिए योजनाओं में आर्थिक व सामाजिक विषयताओं को दूर करने के लिए योजनाओं में आर्थिक व सामाजिक विषयताओं को दूर करने के निश्चित उद्देश्यों का उल्लेख किया जाना चाहिये।

2. योजना के क्रियान्वयन की उचित व्यवस्था के बिना कोई भी योजना चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, सफल नहीं हो सकती। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार योजना आयोग का पुनर्गठन तो हो चुका है किन्तु केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के स्तर पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए उचित व्यवस्था का अभाव है। अत्येक राज्य में समन्वय समितियाँ (Co-ordination



Committees) की स्थापना भी की जानी चाहिए । जिला व सत्र ( District and Block ) स्तर पर भी व्यवस्था में प्रभावशाली परिवर्तन लाने की आवश्यकता है ।

3. ईमानदार कर्मचारियों—हमारी योजनाएँ बहुत अच्छे एवम् उच्च आदर्शों को लेकर बनायी जाती हैं किन्तु कर्मचारियों के आवरण एवं कार्यप्रणाली से उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता । सम्बन्धित न कार्यप्रिय कर्मचारियों के बिना योजनाएँ मूलतः कागजी योजनाएँ बनकर रह जाती हैं । राष्ट्रीय चारित्रिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि भ्रष्ट एवं बेईमान कर्मचारियों को दंडित किया जाए । योजनाओं को क्रियान्वित करने में जो बाधाएँ उत्पन्न करें उनको उचित मार्ग बताने हेतु आवश्यक साधार संहिता (Code of conduct) का निर्माण किया जावे । कर्मचारियों का उचित व्यवहार ही जन साधारण को योजना के प्रति आकर्षित कर सकेगा ।

4. मूल्यांकन की उचित पद्धति के बिना योजनाओं की उपलब्धियों एवं असफलताओं की सही जानकारी हासिल नहीं की जा सकती । हमारे योजना आयोग ने पिछले वर्षों में कुछ अध्ययन दलों (Study groups) की स्थापना की है जो विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं ।

(स) जनसहयोग (Public Co-operation)—हमारी योजनाओं का मुख्य आधार जन सहयोग है । किन्तु अभी तक जन साधारण इनके प्रति उदासीन है । अधिकाधिक जनसहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नांकित उपाय काम में लाये जाने चाहिए—

1. योजना जागरूकता (Plan consciousness) का प्रसार मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में किया जाना चाहिए । ग्रामीण जनता को सरल दृश्य एवं ध्वनि (Audio-visual) साधनों का प्रयोग कर योजनाओं के सम्बन्ध में अधिकाधिक जानकारी दी जानी चाहिए । इस क्षेत्र के

महाविद्यालयों के योजना मंच (Planning Forms) अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं ।

2. ग्रामीण जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयत्न किये जाने चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधाएँ, आवास सुविधाएँ एवं सिंचाई एवं कृषि विकास की सुविधाएँ जुटा कर निवासियों को योजनाओं के प्रति अधिक चेतन्य बना कर जन सहयोग के लिए प्रेरित किया जा सकता है ।

3. कार्य परियोजनाओं (Work projects) —के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समूहों की सहायता की जानी चाहिए जिससे सरकार और जनता के बीच सहयोग का विस्तार हो सके । यद्यपि पिछली तीन योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा इन परियोजनाओं में जनसहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की गई किन्तु अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना बाकी है । विस्तृत जन सहयोग के बिना योजनाएँ जनसाधारण को प्रभावित नहीं कर पाएँगी ।

(६) भाग्य सुझाव—योजनाओं की कार्यनिधि, वित्तीय साधनों एवं जनसहयोग के क्षेत्र में प्रयत्न करने के साथ साथ प्रभावशाली मूल्य नीति, आर्थिक विपन्नताओं को दूर करने के लिए उचित कर प्रणाली, कुशल अभिनों की व्यवस्था, विदेशों से तकनीकी सहयोग, शैक्षिक साधनों का उचित उपयोग आदि कुछ उपाय हैं जिन्हें योजनाओं के माध्यम से परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं ।

श्री अशोक मेहता के अनुसार “योजना के प्रमुख उद्देश्यों तक पहुँचने के लिए संगठित तथा निश्चित प्रयत्न अनिवार्य हैं । इसके लिए व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण, सही मूल्यांकन, निश्चित संस्थाओं एवं व्यक्तियों से दायित्व की माँगना तथा अधिक्यशीलता आवश्यक है ।”

### सारांश

भारत में आर्थिक नियोजन—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही भारत में संगठित प्रयत्न प्रारम्भ किये गये । 1950 में पठित भारतीय

योजना आयोग ने भारत की योजनाओं के निर्माण व मन्तव्यन में महत्वपूर्ण योग दिया ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) — योजना का मुख्य उद्देश्य विमानन तथा दुग्ध उद्योग व्यवस्तुजन को दूर करना था । योजना पर 1960 करोड़ रुपये खर्च हुये यह योजना कृषि विकास की मुख्य योजना थी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)—उद्देश्य—1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि, 2. छोटीनीकरण, 3. रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा 4. आर्थिक विषमताओं में कमी ।

योजना पर 4,600 करोड़ रुपये खर्च किये गये । यह योजना औद्योगिक विकास के लिये महत्वपूर्ण थी ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना—(1961-66) : उद्देश्य—1. राष्ट्रीय आय में वृद्धि, 2. गाछाओं में आय निर्भरता व कृषि उत्पादन में वृद्धि, 3. मूल उद्योगों का विकास, 4. रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा 5. आर्थिक विषमताओं को दूर करना ।

योजना में तार्थिक श्रेण में अनुमानित 7500 करोड़ रुपये की अपेक्ष लगभग 8628 करोड़ रुपये खर्च हुये । योजना में कृषि, उद्योग एवं यातायात के विकास पर अधिक धन दिया गया है ।

भारत की वार्षिक योजनाएँ—

चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना के मध्य विभिन्न विधम परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप अनुसंध योजना के स्थान पर भारत में वार्षिक योजनाएँ बनाई गईं ।

वार्षिक योजना 1966-67—इस अवधि में 2221 करोड़ रु० व्यय करने का लक्ष्य था । विद्युत, कृषि उद्योग, यातायात, राष्ट्रीय आय आदि में भी विभिन्न लक्ष्य रसे गये ।

वार्षिक योजना—1967-68—इसमें 2248 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान था । जिसमें सबसे ज्यादा राशि संगठित उद्योगों पर

ध्य करने का अनुमान था । इससे अनुमानित प्राप्तिमें व व्यय में 54 करोड़ रु० का अन्तर रहा था ।

छीन पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की आर्थिक प्रगति—राष्ट्र में तीन योजनाओं के माध्य आणातीत सफलता प्राप्त हुई है । विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त सफलता—

1. राष्ट्रीय आय—सन् 1950-51 से 1964-65 तक राष्ट्रीय आय 69 प्रतिशत ज्यादा हुई ।

2. कृषि—कृषि उत्पादन में 65 प्रतिशत वृद्धि हुई । सभी प्रकार की सिंचाई योजनाओं से 4.54 करोड़ एकड़ भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई होने लगी ।

उद्योग शक्ति व आतायात—उद्योगों का उत्पादन 152 प्रतिशत ज्यादा हुआ । विद्युत शक्ति में चार गुना वृद्धि हुई । रेलों की भार वाहन सामर्थ्य दुगुनी हो गई ।

3. समाज सेवाएँ—मनुष्य की औसत उम्र 32 वर्ष से बढ़कर 50 वर्ष हो गई । मलेरिया का निराकरण हो गया ।

कमियाँ—(1) मुख्य शहर में वृद्धि, (2) घर घर में वृद्धि, (3) बेरोजगारी में वृद्धि, (4) प्राथमिकताओं का देश की आवश्यकताओं के अनुकूल न होना, (5) सरकार की अस्पष्ट नीति, (6) समाजवादी समाज की संरचना का न होना, (7) लक्ष्यों की प्राप्ति का न होना, (8) निजी क्षेत्र की उम्मेदारी की गई, (9) विकास व्यय का दलदल अनु-दान लगाया गया, (10) विदेशी साधनों का उपयोग न होना, (11) विदेशी विनिर्देश का संघट, (12) प्रसिद्धि के बर्णनारिदों का अभाव, (13) अनुकूलता, (14) अनुचित प्रशासनिक व्यवस्था, (15) जनता के सहयोग का अभाव, (16) सुनियोजन का अभाव, (17) विभाग का अभाव ।

योजनाओं की सफलता के लिए सुझाव—

(क) विदेशी साधनों का विस्तार—







